Service and a service and a service and a service as a se

हिन्दी निदेशिका

(दिसम्बर, १६५५)





1948

Se cooleans

म्रधीक्षक मुद्रण तथा लेखन-सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, द्वारा मुद्रित । १९४४

हिन्दी निर्देशिका

--:0:---

(दिसम्बर, १९५५)





मुद्रकः

भ्रघीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत । १६५५ मुद्रित दिसम्बर, १९४४ प्रथम बार पुनर्मुद्रित श्रप्रैल, १९४६ द्वितीय बार पुनर्मुद्रित श्रगस्त, १९४९

भूमिका

हिन्दी को इस प्रदेश की राजभाषा का स्थान ग्रक्तूबर, १६४७ में दिया गया जब कि उत्तर प्रदेश शासन ने इस ग्राशय की घोषणा की। तब से हिन्दी को राजकीय कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में समय-समय पर ग्रादेश निकाले गये। यद्यपि सरकारी कामों में हिन्दी के उपयोग में ग्रब तक काफी प्रगति हुई है फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि इन ग्राठ वर्षों में हिन्दी की पूर्णतया सन्तोषजनक उन्नति नहीं हुई है। इसके कई कारण थे। एक कारण यह था कि शासन की ग्रोर से कोई ऐसा संकलन प्रकाशित नहीं हुग्रा था जो हिन्दी-सम्बन्धी शासकीय नीति को कार्यान्वित करने में यथेष्ट रूप से सहायक हो ग्रौर साथ ही उससे सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने में उपयोगी हो। इसी कमी को पूरा करने के लिए यह पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है।

२--इसमें सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी-प्तम्बन्धी सामग्री संगृहीत मिलेगी। यह तीय भागों में विभाजित है। पहले भाग में हिन्दी की पृष्ठभूमि, राजभावा संबंधी घोषणा, राजभावा ग्रायोग तथा राजकीय क्षेत्र में हिन्दी की वर्तमान स्थित पर प्रकाश डाला गया है ग्रीर सरकार द्वारा जारी किये गये हिन्दी संबंधी परिपत्रों का सारांश दिया गया है। मुख्य मन्त्री के उस भाषण का उद्धरण भी इसमें दे दिया गया है जो उन्होंने १८ फरवरी, १८५४ को विधान परिषद् में हिन्दी भाषा संबंधी प्रस्ताव पर दिया था। इससे यह ज्ञात होगा कि राजकीय कार्यों में साधारणतया किस प्रकार की हिन्दी प्रयोग करनी चाहिए। दूसरे भाग में टिप्पण, ग्रालेखन तथा श्रनुवाद पर कुछ सुझाव दिये गये हैं। पुस्तिका के तीसरे भाग में परिशिष्ट हैं जिनमें विधिक तथा प्रशासकीय शब्दावली, राजकीय पत्रव्यवहार में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांश तथा विभिन्न राजकीय पत्रों के कुछ प्रतिमित प्रपत्र (फार्म) दिये गये हैं।

३--- श्राशा है कि यह पुस्तिका सरकारी काम में हिन्दी की प्रगति बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग, लखनऊ। दिनांक १ दिसम्बर, १६५५

म्रादित्यनाथ झा,

मुख्य सचिव ।

•

विषय सूची भाग १ हिन्दी की प्रगति

१स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व स्थित				पुष्ट
(क) न्यायालय की भाषा				9
(ख) सरकारी पत्र-व्यवहार की भाषा				8
२स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् हिन्दी को रा	जभाषा	मानने की घो	षणा—	,
उत्तर प्रदेश के लोगों की भाषा हिन्दी है				8
सन् १९४७ के निश्चय का व्यौरा				2
३संविधान में भाषा संबंधी व्यवस्था				7
संघ की भाषा				
राजभाषा के लिए श्रायोग ग्रौर संसद की	समिति			
राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं				2 2
राज्यों के बीच संचार के लिए राजभाषा				3
उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की भाषा				3
हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश	• •		Today.	3
४राज्य में हिन्दी की वर्तमान स्थित				
हिन्दी के बारे में विधायन			•	7
उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक तथा ग्रिधि	नियम)	ग्रधिनियम, १६	٧٠	3
उत्तर प्रदेश राजभाषा ग्रिधिनियम, १९५१				3
विधान सभा का हिन्दी में सम्पूर्ण कार्य				8
हिन्दी गजट				8
वार्षिक रिपोर्टे , नियमावलियां तथा उपनिय	यम			8
प्रख्यापन पुस्तिकायें, प्रेस विज्ञिन्तियां स्नादि	• •			8
सेवा सम्बन्धी नियमावलियां तथा प्रपत्र			14-14-	8
विभाग जिनमें सरकारी काम पूर्णतया हिन्द	री में होत	त है		8
जनता से पत्र-व्यवहार				8
हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था				8
जिलों में हिन्दी की प्रगति				8
लोक सेवा श्रायोग द्वारा सुंचालित सभी परी	क्षाम्रों में	हिन्दी का एक प्र	(निवार्य	
विषय कर दिया जाना	••			×
स्टेनोग्राफर श्रौर टाइपिस्ट				×
टाइपराइटर	• •	••		×

Committee of the Commit	पृष्ठ
सार-संग्रह	1
उत्तर प्रदेश शासन ग्रौर ग्रन्य राज्य शासनों के बीच हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का करारनामा	
श्रंग्रेजी प्राविधिक शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित करने के लिए तदर्थ समिति १शिक्षा-क्षेत्र में हिन्दी	3
शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम	
हिन्दी इन्स्टीट्यूट	5
	8
त्रसरकारी संस्थाएं जो हिन्दी के प्रसार में योग दे रही हैं ६—हिन्दी साहित्य कोष—	ξ
७देवनागरी लिपि सुधार समिति	
देवनागरी लिपि सुधार सिमिति	
समिति की सिफारिशें	9
देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन	5
५राजभाषा ग्रायोग	5
राजभाषा श्रायोग की नियुक्ति तथा उस के विचारणीय विषय	5
, समय-श्रनुसूची	3
त्र्यायोग द्वारा सम्पादित कार्य तथा उसका भावी कार्य-ऋम	3
त्र्यायोग का दौरा	3
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा व्यक्त विचारों का सारांश	3
शासन की हिन्दी संबंधी नीति	3
श्रंग्रेजी के संबंध में शासन की नीति	3
प्रगाढ़ रूप से हिन्दी संबंधी कार्यवाहियों का कार्यान्वित किया जाना	१०
हिन्दा के विकास के लिए कार्यवाहियां	80
ग्रन्य कार्यवाहियों के लिए स्थायी सिमिति की नियुक्ति का समर्थन	28
सस्कृत का श्रध्ययन	88
सामान्य सुझाव	88
६हिन्दी की प्रगति बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश	
(क) परिपत्र जो स्रक्तूबर, १६५५ तक निकाले गये	88
(१) = ग्रक्तूबर, १६४७ का परिपत्र राजभाषा की घोषणा	
(२) ४ जून, १६४८ का परिपत्र भर्ती की परीक्षात्रों में हिन्दी	88
एक ग्रनिवार्य विषय होगा	22
र न्यायालय की नोटिसें तथा सम्मन	
हिन्दी में प्रकृतित में	0.5
(४) १८ दिसम्बर, १६४८ . हिन्दी में प्रकाशित हों हिन्दी से तात्पर्य देवनागरी लिपि	१२
में लिखित राज्य की जनता	
की भाषा से है	१२

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

	पृष्ठ
(४) ६ फरवरी, १९४९ ऐसे कर्मचारियों के नाम	•
भेजें जायं जो हिन्दी से	
ग्रनिभज्ञ हों (६) = ग्रगस्त, १९५० चरित्रपंजियों में प्रविष्टियां	१३
(७) १० जुलाई, १९५२ हिन्दी तार सेवा का उपयोग	83
(७) १० जुलाई, १९५२ हिन्दी तार सेवा का उपयोग किया जाय	0.5
(=) २६ ग्रवत्वर, १६५२ यथासम्भव सभी कार्य हिन्दी	83
में किये जायं	१३
(६) २१ अप्रैल, १६५४ हिन्दी तार सेवा का अधिका-	14
धिक उपयोग किया जाय	१३
(१०) ५ सितम्बर, १६५४ सरकार द्वारा इस प्रस्ताव का	17
माना जाना कि दिन्दी में	
ऐसे शब्द प्रयुक्त किये जायं	
जा सब समझ सकत हा	१३
(११) १ नवम्बर, १६५४ ग्रंग्रेजी टाइपराइटरों की मांग	
्रिको न की जायगी	१३
(१२) ३० नवम्बर, १९५४ ऐसे कर्मचारियों के नाम सर-	
कार को सूचित किये जायं	
(१३) ११ जुलाई, १९५५ . कार्य-मुची तथा कार्यवाही	88
लिखने में हिन्दी का ही प्रयोग किया जाय	88
(ख) नवम्बर, १६५५ के परिपत्र के नमें गारित	
(१) सरकार द्वारा भेजे जाने वाले परिपत्र	88
(२) द्वतगामी पत्र	88
	88
(३) श्रनुस्मारक ग्रौर स्वीकार-प्राप्ति पत्र	88
° (४) सामान्य प्रकार के पत्र-व्यवहार, निर्वेश तथा टिप्पण । ।	१५
(५) जनता से प्राप्त ग्रावेदन-पत्रों का उत्तर	१५
(६) त्रसेम्बली के प्रश्नों के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार तथा टिप्पण	१५
' (७) हिन्दी में प्रपत्र ः ः ः ः ः ः ः । ः	१५
(८) कर्मचारियों के ग्रावेदन-पत्र िक तकार्त, किस्मान कर	१४
(६) रीतिक ग्रवसरों पर निमंत्रण-पत्र	१६
(१०) दौरे का कार्य-क्रम	१६
(११) कलेन्डर तथा छुट्टियों की सूची	१६
(१२) लिफाफों पर पैते	
(१३) टाइपराइटर	१६
A S C C C C C C C C C C C C C C C C C C	१६
and the state of t	819

				पृष्ठ
	(१५) चपुरासियों ग्रादि के बिल्ले	• •		१७
	(१६) हिन्दी के लिए एक पदेन ग्रधिकारी			१७
	(१७) प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी पुस्तकालय की र	थापना		१७
	(१८) हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा हिन्दी टाइप सीखने			१८
	(१६) हिन्दी की प्रगति में विशेष सहायता देने		ii	
	को प्रोत्साहन	••	••	१८
	१०भारत सरकार के राजकीय कार्यों में हिन्दी	भाषा का प्र	योग	
	राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया संविधान	(राजकीय प्र	योजनों व	हे लिए
	हिन्दी भाषा) स्रादेश, १९४५	••	••	१८
	श्रादेश की मुख्य बातें	••	••	38
	श्रादेश का स्पष्टीकरण	••	••	38
	ग्रादेश सम्बन्धी ग्रन्य ग्रनुदेश	••	••	२०
	हिन्दी के सम्बन्ध में भारत सरकार का भावी कार्य-क्रम			7 -
				२०
	११हिन्दी के संबंध में भारत सरकार की ग्रद्या	वाव अगात-		
	वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा प्रशासकीय शब्दावली	··. 	•••	२०
	हिन्दी साहित्य की वृद्धि तथा उसके विकास के लिए हिन्दी में प्रामाणिक व्याकरणों श्रौर कोबों का प्रका	गारव ग्रथा का	प्रकाशन	२१ २१
	राज्यों के माध्यमिक स्कूलों में अनिवार्य विषय के रू	प में हिन्दी को	चलाना	22
	म्रहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रसार के लिए कार्यवा			22
	गृह तथा श्रम मन्त्री (ग्रब मुख्य मन्त्री) का हिन्दी भा	and the same of th		
	प्रस्ताव पर भाषण (नत्थी)		२३-	-28
	भाग २			
	टिप्पण, ग्रालेखन तथा ग्रनुवाद			
	सामान्य • •	••	••	२७
	टिप्पण ••	••	••	२८
	ग्रालेखन • •	• •	-35.	-₹0
	ग्रनुवाद	••	••	38
	श्री होरमसजी पेरोशा मोदी की नियुक्ति का ग्रिधिपत्र	• • •	• •	38
	श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी की नियुक्ति का श्री	धपत्र	••	३५
	भाग ३			
	परिशिष्ट १			
	हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष परिपत्रो	के उत्रम		
	१(देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को राजभा			
पारपत्र स०	करने का निर्णय)	• •	:.	35
4			THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY	

•		
परिपत्र सं० २(देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को राजभाषा के रूप में चलाने की त्यानगर।		वृष्ठ
	10.0	
परिपत्र सं०३(राजकीय कार्यों में हिन्दी की प्रगति)		88
	:	80
परिशिष्ट २		
शासकीय परिपत्र, नियमावली ग्रादि		
परिपत्र संख्या १(गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में उत्सव)		-
परिपत्र संख्या २(खादी हुंडी)	THE DESIGNATION OF THE PARTY OF	४८
परिपत्र संख्या ३(स्थानीय विकासों ने क्या कि	••	६०
परिपत्र संख्या ३(स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की मंत्रियों इत्यादि त पहुंच)	क	
परिपत्र संख्या ४ (पत्र-व्यवहार हिन्दी में हो)	• •	६२
परिपत्र संख्या ५—(उत्तर प्रदेश शासन ग्रौर बिहार राज्य, मध्य प्रदेश राज्य भारत राज्य शासन है जीन जेने जा	B C Deput	६४
मध्य भारत राज्य शासन के बीच होने वाले शास पत्र-व्यवहार में केवन रिक्ति अपन	ज्य तथा	
" " " ५ - (उत्तर प्रदेश राज्य शासन न गरम	i=i) } =} -	६६
	० बाच	
(पचायत ग्रपन को ग्रिधिक उपयोगी बना सकती हैं)		६द
(गासवधन जाच समिति का पठित पवितेत्व)	Charles and an artist of	६१
भाषालय स्मृति-पत्र		60
राज्यपाल का संदेश		98
नियमावली के नमूने		68
(१) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रतिथि नियमावली, १९५४		
(२) सेवा नियम		७५
स्यायो समिति की कार्यवाही		७इ
770	• 5 6 Stap 23	न१
परिशिष्ट ३		
प्रतिमित श्रालेख्य प्रपत्र		
शासकीय भ्रादेश (१) (दक्षता-भ्रगंल पर रोके गये कर्मचारियों के		
मामलों का वार्षिक पुनरावलोकन)	•	28
" (२) (सहायक जिला पंचायत श्रधिकारियों का स्थायीकरण)		
" " (३) (पेंशन के बारे में)		5 ¥
		50
अद्धेशासकीय पत्र . (भारत सरकार की सेवा में पदाधिकारियों को रहने दिये जाने के संबंध में)		
विज्ञाप्त (नियुक्ति के बारे में)		50
- तमृति पत्र		55
		EF

		पुष्ड
		32
१——द्रुतगामी पत्र ••		0.3
६तार		83
७		83
दस्वास्थ्य-परीक्षा प्रपत्र		₹3
६चैकित्सिक मत का प्रपत्र		83
१०संसर्ग रोध प्रपत्र		EX
११दौरे का कार्य-क्रम		
परिशिष्ट ४		
टिप्पण केंद्वकतियय नमूने		
संख्या १(समथर के राज मंदिर की समुचित व्यवस्था के संबंध में)		६६
संख्या २(पिछड़ी जातियों के संबंध में)		03
संख्या ३(जिला पंचायत ग्रधिकारियों के स्थायीकरण के संबंध में)	••	800
संख्या ४(मैरिस कालिज, लखनऊ के स्तर को उठाने के संबंध में)		808
संख्या ५(गांधी स्मारक निधि के हिसाब के संबंध में)		१०६
संख्या ६(सरकारी पत्र समाप्त करने के रूप के संबंध में)		१०५
संख्या ७(ग्रग्रिम यात्रिक भत्ता के संबंध में)	•••	308
संख्या ७ (अप्रिम यात्रिक मता क त्या क		
परिशिष्ट ५		
	11	
कतियय ग्रंग्रेजी पदनामों के हिन्दी पर्याय		222
१राज्यपाल, मंत्री इत्यादि		222
२विधान मंडल के पदाधिकारी		222
३सचिवालय के पदाधिकारी		222
४विभागाध्यक्ष ग्रादि	••	111
परिशिष्ट ६		
उत्तर प्रदेश सिववालय के विभागों के नामों के हिन्दी पर्याय		११४
GHC A44 III 4 III 4		
परिशिष्ट ७	8)	
रीतिक अवसरों के कार्यक्रम और निमंत्रण-पत्र के नमूने		388
गांघी जयन्ती उत्सव		१२१
द्यापथ ग्रहण करने का कार्य-क्रम		१२३
निमंत्रण-पत्र • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

छ

	परिशिष्ट ८	1	
प्रशासकीय शब्दावली	••		पृष्ठ १२४
कार्यालयों के प्रयोग के लिये वाक्यांश	परिशिष्ट ह		14.
			१३७
हिन्दी निर्देश पुस्तकों की सूची	परिज्ञिष्ट १०		१४५

भाग १ हिन्दी की प्रगति

१--स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व स्थिति

श्रक्तूबर, १६४७ में उत्तर प्रदेश में हिन्दी के राजभाषा घोषित होने के पूर्व स्थिति यह थी:

न्यायालय की भाषा

क—सर्वोच्च न्यायालय में गवर्नमेंट स्राफ इंडिया ऐक्ट, १६३४ की उपधारा २१६ (१) तथा २२७ के स्रनुसार स्रंग्रेजी ही प्रयुक्त की जाती थी। स्रवीनस्थ न्यायालयों में भी साक्ष्य, निर्णय एवं न्यायालय की स्रन्य कार्यवाहियों के लिखने में स्रंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था यद्यपि भाषा तथा लिपि के सम्बन्ध में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की थी। रेवेन्यू बोर्ड स्रौर कमिश्नरों की स्रवालतों में भी सारा काम स्रंग्रेजी में ही किया जाता था स्रौर उसी भाषा में कार्यवाहियां लिखी जाती थीं। वास्तव में बोर्ड ने यह स्रतुवेश वे रखे थे कि उसके स्रवीन सभी स्रवालतों में कार्यवाहियां लिखने का माध्यम स्रंग्रेजी ही हो।

ख—- ग्रलबत्ता मैनुग्रल ग्राफ गवर्नमेंट ग्रार्डर्स के पैराग्राफ ३८४ के ग्रनुसार फौजदारी, दीवानी ग्रौर माल की ग्रदालतों में दरख्वास्तें या शिकायतें नागरी ग्रथवा उर्दू में की जा सकती थीं।

ग--जहां तक सरकारी पत्र-व्यवहार एवं सरकारी कार्य का संबंध था भाषा संबंधी कोई उपबन्ध नहीं थे। किन्तु रूल्स ग्राफ बिजनेस ऐन्ड सेकेटेरियट इन्स्ट्रकान्स के नियमों में एक यह व्यवस्था थी कि वैभागिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में टिप्पणियां तथा ग्रादेश लिखने में श्रंग्रेजी ही का प्रयोग किया जायगा।

सरकारी पत्र-व्यवहार की भाषा

२--स्थतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् हिन्दी को राजभाषा मानने की घोषणा

२—प्रारम्भ से ही इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोग बोलने में हिन्दी
भाषा का प्रयोग करते ग्राये हैं। सन् १८३७ तक न्यायालयों में फारसी लिपि
श्रौर फारसो भाषा प्रयुक्त होती थी। तदुपरान्त न्यायालय की भाषा हिन्दुस्तानी हो गयी यद्यपि लिपि फारसी ही रही। जनता ने देवनागरी लिपि के लिए
अने में बार ग्रावेदन-पत्र दिये किन्तु सन् १६०० तक लिपि में कोई परिवर्तन नहीं
किया गया। सन् १६०० में उत्तरी-पश्चिमी प्रांत के लेफ्टोनेंट गवर्नर ग्रौर ग्रव्य के
किया गया। सन् १६०० में उत्तरी-पश्चिमी प्रांत के लिए, उदाहरणार्थ ग्रावेदन-पत्र,
शिकायत, सम्मन ग्रादि में, इस्तेमाल करने का निश्चय किया। इस संबंध में ग्रादेश
जारी किये गये जिनका मुख्यतः उद्देश्य हिन्दी जानने वाली ग्रिधकांश जनता को
हिन्दी के प्रयोग में सुविधा प्रदान करना था। ग्रादेश यह थे कि फौजदारी, दीवानी
सथा लगान ग्रौर मालगुजारी की सभी श्रदालतों में:

उत्तर प्रदेश के लोगों की भाषा हिन्दी है

(१) सब लोग ग्रयने ग्रावेदन-पत्र ग्रथवा ग्रपनी शिकायतें वेवनागरी लिपि में या फारसी लिपि में देंगे।

- (२) जनता के नाम ख्रदालतों या माल के अफसरों की स्रोर हो जारी किये जाने वाले सभी सम्मन, घोषणा तथा इस प्रकार के अन्य कागज देवनागरी या फारसी लिपि में होंगे।
- (३) किसी भी श्रंग्रेजी दफ्तर में कोई व्यक्ति इन श्रादेशों के जारी होने के एक वर्ष पश्चात् क्लर्क की जगह पर नियुक्त न किया जायगा, जब तक कि वह हिन्दी श्रौर उर्द्दोनों न जानता हो श्रौर यदि कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया हो जो उसमें से केवल एक ही भाषा जानता हो तो उसे नियुक्ति के एक वर्ष में दूसरी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा।

३--इस राज्य के लोगों की भाषा हिन्दी थी श्रौर है। इसकी यथाविधि स्वीकृति सरकार ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् १६४७ में हिन्दी को राजभाषा घोषित करके दे दी।

सन् १६४७ के निश्चय का ज्योरा ४— श्रम्तूबर, १६४७ में जब हिन्दी राजभाषा घोषित की गई, सरकारी कर्मचारियों के पथ-प्रदर्शन के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किये गये। इन अनुदेशों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि "हिन्दी" शब्द के प्रयोग से अभिप्राय उस भाषा से है जो उत्तर प्रदेश की जनता की भाषा है श्रीर जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरे परिपत्र में "हिन्दी" की व्याख्या की गई श्रीर बताया गया कि "हिन्दी के माने उस सरल जवान से है जो देश में श्रीर इस प्रदेश में बोली जाती है। हिन्दी की लिपि नागरी होगी श्रीर जवान श्रासान तथा सरल होगी।"

३--संविधान में भाषा संबंधी व्यवस्था

संघ की भाषा

५—संविधान के अनुच्छेद ३४३ (१) में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। उस अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था है कि संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालाविध के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी।

६--परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में श्रादेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए श्रंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा तथा भारतीय श्रंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

राजभाषा के लिए श्रायोग श्रीर संसद की समिति ७— त्रप्रतृच्छेद ३४४ में यह व्यवस्था है कि संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति श्रादेश द्वारा एक श्रायोग गठित करेगा जो राजभाषा हिन्दी के प्रयोग तथा तत्सम्बन्धी श्रन्य विषयों पर सिकारिश करेगा।

राज्य की राजभाषा या राजभाषायें द—िकसी राज्य का विधान मंडल संविधान के अनुच्छेद ३४४ और ३४७ के उपबंधों के अथीन रहते हुए विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोगार्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अगीकार कर सकेगा और जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा इसके अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी। ६-- प्रमुच्छेद ३४६ में व्यवस्था है कि यदि दो या प्रिषक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

राज्यों के बीच संचार के लिये राजभाषा

१०—उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में तथा श्रिधिनियमों, विधेयकों श्रादि में प्रयोग की जाने वाली भाषा श्रंग्रेजी रखी गयी है किन्तु यह व्यवस्था है कि किसी राज्य का राज्यपाल या राज्यप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मित से हिन्दी भाषा का प्रयोग उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की भाषा

११--श्रनुच्छेद ३५१ में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निम्न निदेश है:

हिन्दी भाषा के विकास के लिये निदेश

''हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की ग्रिभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी ग्रात्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी ग्रौर ग्रब्टम ग्रनुसूची में उल्लिखित ग्रन्य भारतीय भाषाग्रों के रूप, शैली ग्रौर पदाविल को ग्रात्मसात करते हुए तथा जहां ग्रावश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाग्रों से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

४--राज्य में हिन्दी की वर्तमान स्थिति

१२--राज्य में सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी किस सीमा तक प्रयुक्त हो रही है इस पर प्रकाश निम्न पैराग्र कों में डाला गया है।

१३—-भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अन्तर्गत विधान मंडल ने उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक तथा अधिनियम) अधिनियम, १९४० पारित किया जिसके अन्तर्गत विधान मंडल में सभी विधेयक देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में प्रस्तुत किये जाने लगे और सभी अधिनियम उसी भाषा में पारित होने लगे।

उत्तर प्रदेश भाषा (विषेयक तथा श्रिधिनियम) श्रिधितियम, १९५०

हिन्दी के बारे में

विघायन

१४— संविधान के अनुच्छेद ३४५ में, श्रौर विषयों के श्रितिरिक्त, यह व्यवस्था है कि राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा देवनागरी लिपि में हिन्दी को श्रंगीकृत कर सकताहै। इस श्रनुच्छेद के श्रनुसार उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने १६५१ में "उत्तर प्रदेश राजभाषा श्रिधिनयम, १६५१ ई०" पारित किया। इस श्रिधिनयम की धारा २ के श्रन्तर्गत, एक विज्ञित जारी करके श्री राज्यपाल ने घोषित किया कि १ नवस्वर, १६५२ से निम्नलिखित के सम्बन्ध में देवनागरी लिपि में हिन्दी का प्रयोग होगा:

उत्तर प्रदेश राज-भाषा श्रिध-नियम, १९५१

- (१) संविधान के अनुच्छेद २१३ के अबीन प्रचारित अध्यादेश,
- (२) भारत के संविधान के प्रधीन प्रथवा संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के प्रधीन राज्य सरकार द्वारी प्रचारित प्राज्ञा, नियम, विनियम ग्रौर उपविधि।

इस विज्ञाप्ति के फलस्वरूप श्रव सभी श्रध्यादेश, श्राजाएं, नियम, विनियम सादि हिन्दी में जारी होते हैं।

विधान सभा का हिन्दी में सम्पूर्ण कार्य

१५--राज्य विधान सभा की पूरी कार्यवाही हिन्दी में होती है। कार्यावलि, प्रान तथा उत्तर भी हिन्दी में तैयार होते हैं।

हिन्दी गजट

१६——जहां तक सरकारी सूचनात्रों, विज्ञान्तियों, घोषणात्रों स्न्रादि का संबंध है, जनता गजट को ही देखती है। इसिलये स्रंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी गजट प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार साधारण स्नौर स्नसाधारण दोनों ही गजट हिन्दी में प्रकाशित हो रहे हैं। ज्योंही केन्द्रीय सरकार स्नपने कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ कर देगी स्नौर भारत संघ के प्रत्येक राज्य में पत्र-व्यवहार हिन्दी में होने लगेगा, स्नंग्रेजी में गजट का छपना बिल्कुल बन्द कर दिया जायगा। पुलिस गजट का भी एक हिन्दी संस्करण निकलता है।

वार्षिक रिोटें, नियमावलियां तथा उपनियम

प्रख्यापन पुस्तिकाएं, प्रेस विज्ञप्तियां श्रादि १७--सिचवालय के विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्टें हिन्दी में प्रकाशित होती हैं। हिन्दी ग्रिधिनियमों के ग्रन्तर्गत निर्मित सभी नियमाविलयां ग्रीर उपनियम हिन्दी में तैयार ग्रीर प्रकाशित किये जाते हैं।

१८--सूचना विभाग का सारा प्रख्यापन-कार्य हिन्दी में होता है। यह विभाग सिचवालय के विभिन्न विभागों के कार्य पर हिन्दी में पुस्तिकाएं निकालता है। उपयोगी रिसाले नामक पुस्तिकाएं भी इसी विभाग द्वारा प्रकाशित होती हैं। प्रेस विज्ञाप्ति, विज्ञापन स्नादि हिन्दी में भी तैयार किये जाते हैं।

सेवा सम्बन्धी नियमावलियां तथा प्रपत्र (फार्म) १६—-कुछ विभागों की सेवा संबंधी नियमाविलयां भी हिन्दी में प्रकाशित हुई हैं तथा सिववालय में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रपत्र हिन्दी में छप चुके हैं। कुछ ग्रन्य विभागों, जैसे पुलिस, गृह, न्याय ग्रादि के भी प्रपत्र हिन्दी में तैयार हो चुके हैं। श्री राज्यपाल तथा माननीय मन्त्रियों के भाषण, ब्राडकास्ट, ग्रपीलें ग्रादि हिन्दी में तैयार की जाती हैं।

विभाग जिनमें सरकारी काम पूर्णतया हिन्दी में होता है २०---सिचवालय के निम्नलिखित विभागों में सारा काम हिन्दी ही में होता है:---

(१) शिक्षा विभाग,

(२) सूचना विभाग,

(३) पंचायत राज विभाग, ग्रौर

(४) विधान सभा विभाग।

जनता ते पत्र-व्यवहार २१--जनता से पत्र-व्यवहार करने में सभी विभाग हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। स्रावेदन-पत्रों, सामान्य पत्रों स्रादि का उत्तर हिन्दी ही में दिया जाता है।

हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था २२—सन् १९५२ में भारत सरकार के डाक व तार विभाग द्वारा हिन्दी टेलीग्राफ सर्विस प्रारम्भ किये जाने पर, राज्य सरकार ने सभी विभागों को ग्रादेश जारी किये कि वे उन नगरों से, जहां हिन्दी टेलीग्राफ सर्विस हो, हिन्दी में तार भेज सकते हैं। ग्रव उत्तर प्रदेश शासन ने ग्रादेश जारी कर दिये हैं कि कोड एवं साइफर संदेशों के ग्रातिरिक्त, ग्रन्य सभी प्रकार के तार यथासम्भव हिन्दी में भेजे जायं।

जिलों में हिन्दी की प्रगति २२--जिला दफ्तरों में ग्रधिकतर क्राम हिन्दी में होता है जैसा कि नीचे बताया गया है:

(१) जिला दफ्तर—सभी कर्मचारियों ने हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लिया है ग्रीर दफ्तर का ग्रधिकांश काम उसी भाषा में किया जाता है। नियोजन, पंचायत, जमींदारी उन्मूलन कार्यालय ग्रादि में हिन्दी में ही हाम होता है।

- (२) तहसील--यहां भी श्रिधकांश काम हिन्दी में किया जाता है।
- (३) नगरपालिका--यहां भी श्रधिकतर हिन्दी का ही प्रयोग होता है ।
- (४) गांव--गांवों में सम्पूर्ण काम हिन्दी में होता है।

२४--लोक सेवा म्रायोग द्वारा संचालित सभी परीक्षाम्रों में हिन्दी एक म्रिनवार्य विषय कर दिया गया है। परीक्षार्थियों को म्रंग्रेजी के प्रश्न-पत्रों को छोड़ कर म्रन्य प्रश्न-पत्रों को हिन्दी के म्रितिरिक्त म्रन्य भाषा में उत्तर देने की म्रनुमित केवल विशेष म्रवस्था में ही दी गई है।

लोक सेवा श्रायोग द्वारा संचालित सभी परीक्षाश्रों में हिन्दो का एक श्रनिवार्य विषय कर दिया जाना

२५--लगभग सभी कर्मचारी हिन्दी सीख गये हैं ग्रौर वे हिन्दी में कार्य कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों के लिये ग्रानिवार्य कर दिया गया है कि वे ऐसे स्टेनोग्राफर नियुक्त करें जो मुख्यतया हिन्दी के स्टेनोग्राफर हों। इसी प्रकार उनके लिये ग्रावश्यक है कि वे प्रधानतया हिन्दी टाइपिस्टों को ही नियुक्त करें।

स्टनोग्राफर श्रौर टाइपिस्ट

२६---विशेष ग्रवस्थाय्रों को छोड़कर सामान्यतया हिन्दी के ही टाइपराइटर खरीदे जाते हैं।

टाइपराइटर

२७--कुछ वैभागिक सार-संग्रहों का श्रनुवाद हिन्दी में हो गया है श्रौर श्रन्य सार-संग्रहों के हिन्दी श्रनुवाद का प्रश्न विचाराधीन है।

सार-संग्रह

२८—-संविधान के श्रनुच्छेद ३४६ के प्रतिबन्धात्मक खंड के श्रनुसार तथा बिहार राज्य, मध्य प्रदेश राज्य श्रीर मध्य भारत राज्य शासन की सहमित से उत्तर प्रदेश शासन ने श्रभी हाल ही में उक्त राज्य शासनों से यह करार किया है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश राज्य शासन तथा उक्त राज्य शासनों के बीच होने वाले समस्त पत्र-व्यवहार में हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जायगा।

उत्तर प्रदेश सरकार श्रौर श्रन्य राज्य सरकारों के बीच हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का समझौता

२६—- प्रक्तूबर, १६४८ में डा० सम्पूर्णानन्द जी की श्रध्यक्षता में एक तदर्थ समिति सचिवालय में तैयार किये गये प्रशासकीय तथा प्राविधिक शब्दों और हिन्दी प्रपत्रों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गयी।

श्रंप्रेजी प्राविधिक शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित करने के लिए तदथं समिति

यह तदर्थ समिति १६५४ में पुनः निर्मित की गई भ्रौर इस	क सतस्य
निम्नलितित हैं:	
१डाक्टर सम्पूर्णानन्द, मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश	चेयरमैन
२श्रा क० ए० सुब्रमानया श्रय्यर, डोन, फॅकल्टी श्राफ	
म्रार्ट्स, लखनऊ विश्वविद्यालय	सदस्य
३श्री ए० एन० झा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश	
सरकार	"
४न्याय सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	"
५श्री कुलदीप नारायण सिंह, सचिव, उद्योग, श्रम,	
ग्राबकारी ग्रौर समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	

६--श्री कन्हैयालाल मिश्र, एडवोकेट जनरल, उत्तर प्रदेश सरकार ७--श्री कुबेर नाथ शुक्ल, संचालक, पेडागाजिकल

६--श्री गोपाल चन्द्र सिंह, विशेष कार्याधिकारी, सदस्य सिंचव । यह नविर्मित सिमिति सरकारी कार्यालयों ग्रौर सिंचवालय के विभिन्न विभागों में प्रयुक्त ग्रंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों पर विचार कर रही है ग्रौर उन्हें प्रमाणीकृत करेगी ।

५--शिक्षा क्षेत्र में हिन्दी

शिक्षण तथा परीक्षा माध्यम ३०---सन् १९४७ में हिन्दी के राजभाषा घोषित होने से शिक्षा क्षेत्र में भी इस बात का प्रभाव पड़ा।

प्रारम्भिक तथा जूनियर हाई स्कूल की कक्षाग्रों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी ही है। बोर्ड ग्राफ हाई स्कूल ग्रीर इन्टरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश ने माध्यमिक कक्षाग्रों में भी शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम हिन्दी रक्खा है। इन्टरमीडियेट कक्षाग्रों तक हिन्दी को एक ग्रनिवार्य विषय कर दिया गया है। भाषा के प्रश्न-पत्र को छोड़कर ग्रन्य विषयों के सारे प्रश्न-पत्र हिन्दी में तैयार किये जाते हैं ग्रीर परीक्षार्थियों को हिन्दी में उत्तर लिखना होता है। स्कूलों ग्रीर कालेजों की पाठ्य पुस्तकें भी ग्रधिकाधिक संख्या में हिन्दी में लिखी जा रही हैं।

न्दी स्टीट्यूट

३१—विश्वविद्यालयों में भी बी० ए० तथा एम० ए० में हिन्दी ग्रध्ययन का विषय है। ग्रागरा विश्वविद्यालय ने तो हिन्दी का एक इंस्टीट्यूट स्थापित कर दिया है जहां हिन्दी में गवेषणा की विशेष सुविधा प्राप्त है। कुछ समय पश्चात् सभी विश्वविद्यालयों में ग्रानवार्य रूप से शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो जायगा। ग्राभी भी उन विश्वविद्यालयों में जहां विद्यार्थी हिन्दी में पढ़ना ग्रधिक पसन्द करते हैं, कक्षात्रों में हिन्दी में व्याख्यान दिये जाते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षात्रों में प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी में लिखने की ग्रनुमित है।

श्रसरकारी संस्थाएं जो हिन्दी के प्रसार में योग दे रही हैं ३२—सरकारी शिक्षा संस्थाग्रों तथा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाग्रों में हिन्दी में शिक्षा देने के ग्रतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद; प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद; प्रयत्तर्राट्रीय विद्यापीठ, लखनऊ; काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, जैसी ग्रन्य संस्थाएं भी हैं, जो हिन्दी के प्रसार में महत्वपूर्ण योग दे रही हैं। पहली तीन संस्थाग्रों ने तो हिन्दी

में परीक्षाओं की व्यवस्था भी की है श्रीर उनके परीक्षा केन्द्र साे देश में हैं जहां सहस्रों विद्यार्थी प्रति वर्ष परीक्षा देते हैं। इन में से कुछ संस्थाओं द्वीरा प्रदत्त डिग्नियों को शासन ने मान्यता भी प्रदान की है।

६--हिन्दी साहित्य-कोष

३२--हिन्दो को प्रोत्साहित करने के लिये उत्तर प्रदेश शासन ने एक हिन्दो साहित्य कोथ भो स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य :---

हिन्दी साहित्य कोष

- (१) साहित्यिक श्रयवा वैज्ञानिक ग्रंथों या विशिष्ट प्रकार की रचनाश्रों के लिये पुरस्कार देना, तथा
- (२) लेखकों एवं विद्वानों को वित्तीय सहायता देना है। उक्त कोष में से निम्न दो प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं:
 - (क) कला, विज्ञान ग्रोर साहित्य के क्षेत्र में हिन्दो के मौलिक ग्रन्थों की रचनाग्रों के लिये पुरस्कार देते; हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में उनको सेवाग्रों को मान्यता प्रदान करने के लिये हिन्दी साहित्यकारों को नकद पुरस्कार देते; कला, साहित्य या विज्ञान सम्बन्धो मौलिक रचनाग्रों के प्रकाशन को वित्त पोषित करने के लिए; तथा
 - (ख) ऐसे लेखकों या विद्वानों को वित्तीय सहायता देने के लिये जिनको वित्तीय दशा बीमारो के कारण या किन्हीं श्रन्य कारणों से बहुत खराब हो गई हो।

उपर्युक्त पैराग्राफ (१) के ग्रजोन १६४८-४६ से लेकर १६५४-५५ तक कुल २,६०,७०० रुग्ये पुरस्कार-स्वरूप दिये गये हैं ग्रीर ३८३ हिन्दी ग्रन्थकारों तथा लेखकों को उससे लाभ पहुंचा है। उप-पैराग्राफ (२) के श्रधीन, १६४७-४८ ई० से लेकर १६५४-५५ तक ५३ हिन्दी विद्वानों को लगभग ३८,४४० रु० की वित्तीय सहायता दी गई है।

७--देवनागरी लिप सुधार समिति

३४—स्वतंत्रता-प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् समय की स्रावश्यकतास्रों को देवते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने दिसम्बर, १६४७ में स्राचार्य नरेन्द्र देव की श्रध्यक्षता में देव नागरो लिपि सुवार सिमिति का निर्माण किया। इसके विचारणीय विषय निम्नलिखित थे:

देवनागरी लिपि सुधार समिति

- (१) नागरी अक्षरों को ढालने, टाइव करने तथा सामान्य प्रयोग के लिये उनको उपयुक्तता पर आख्या प्रस्तुत करना,
- (२) काशो नागरो प्रचारिणो सभा, वाराणसो द्वारा प्रस्तुत लिपि सम्बन्धो सुझावों को छान-बोन करना,
- (३) संस्कृत लिखने के मगोजनों के लिये उस लिपि की उपयुक्तता पर भ्राख्या प्रस्तुत करना,
- (४) वर्तमान देवनागरो लिपि में परिवर्तन करने की वांछनीयता पर विचार करना, ग्रीर

(४) यह विचार करना कि परिष्कृत लिपि हिन्दी के स्रतिरिक्त मराठी ग्रादि जैसी ग्रन्य भाषाग्रों के लिखने के लिये कितनी उपयुक्त तथा सुविधाजनक होगी।

समिति की सिफारिशें

३५—इस समिति ने ग्रावश्यक छानबीन करने के उपरान्त तथा इस समस्या से सम्बद्ध देश के गण्यमान्य विद्वानों से विचार-विमर्श करके, वर्तमान देवनागरी लिपि में श्रावश्यकतानुसार परिवर्तन करने की ग्रपनी श्राख्या १९४९ में प्रस्तुत की । सिमिति की कुछ नुख्य सिफारिशें नीचे दी जाती हैं:

- (१) टाइपराइटर, टेलोपिंटर ग्रीर प्रेस से संबंधित कठिनाइयों को देवते हुए ग्रीर देव नागरो लिपि को ग्रधिक उपयोगी बनाने के लिये वर्तमान लिपि को जहां तक सम्भव हो यथारूप रखते हुए उसमें सुवार ग्रावश्यक हैं।
- (२) सिमिति द्वारा प्रस्तावित संशोधित लिपि को हिन्दी के स्त्रितिरक्त ऐसी स्रन्य भाषास्रों को भी लिखने के लिये इस्तेमाल की जानी चाहिये, जिनमें नागरी लिपि प्रयुक्त की जाती है।
- (३) केवल ह्रस्व "इ" को मात्रा में परिवर्तन करना चाहिये।
- (४) "क्ष" ग्रोर "त्र" के स्थान पर "क्ष" ग्रोर "त्र" लिखना चाहिये।
- (५) "फुलस्टाप" ग्रौर "कोलन" को छोड़कर शेव विरामादि चिन्ह वही ग्रहण कर लिये जायं जो ग्रंग्रेजी में प्रचलित हैं।

देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन

३६—समिति की आख्या पुनः सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिये देश के विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई। शासन को जो इस प्रकार सम्मितियां प्राप्त हुईं उनमें उस समिति को सिकारिशों का समर्थन था। यह विषय अखिल भारतीय महत्व का था और राष्ट्र भाषा से इसका अभिन्न सम्बन्ध था। श्रातः सुधार समिति को सिकारिशों पर विचार करने के लिए २८ व २६ नवम्बर, १६५३ को भारत के उप-राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में प्रावेशिक मुख्य मन्त्रियों, शिक्षा मन्त्रियों, केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों तथा भाषा विशेषज्ञों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

सरकारी परिपत्र संख्या क (१) १३०६/१५—— १६४६—५४, दिनांक ३ मई, १६४४

३७—-राज्य सरकार ने देवनागरी लिपि सुवार सम्मेलन द्वारा लिपि में स्वीकृत संशोधनों तथा परिवर्तनों को मान लिया ग्रीर यह ग्रादेश दिया कि भविष्य में समस्त सरकारी कागजों, पत्र-व्यवहार ग्रीर प्रकाशन में इस नवीन प्रतिमित देवनागरी लिपि का हो प्रयोग किया जायगा। शिक्षा विभाग को भी ग्रादेश दिये गये कि समस्त हिन्दी पुस्तकें ग्रीर प्रकाशन इसी संस्कृत लिपि में हों। नागरी ग्रक्षरों के ढालने वालों तथा टाइपराइटर कम्पनियों को भी यह सुझाव दिया गया कि वे इन ग्रक्षरों को ग्रपनायें। नागरी देश की राजलिपि होने के कारण ग्रन्य प्रादेशिक सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को भी संबोधित किया गया कि वे इस निर्णय के ग्रनुसार शोद्रातिशोद्र ग्रपने-ग्रपने क्षेत्रों में देवनागरी की इस प्रतिमित लिपि को प्रयोग में लाना प्रारम्भ कर दें।

५--राजभाषा श्रायोग

राजभाषा श्रायोग की नियुक्ति तथा उसके विचारणीय विषय ३८—राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद ३४४ (१) के अधीन ज्न, १९४५ में राजभाषा आयोग का निर्माण किया है। इसके अध्यक्ष श्री बार्जी के लेर हैं। इस आयोग के २० अन्य सदस्य है जो भारत के संविधान की अष्टम सूची में उल्लिखित सभी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ३६—— ग्रन्य बातों के ग्रांतिरिक्त, इस ग्रायोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ग्रप्रैल, १६५६ के ग्रन्त तक संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा का ग्रांधिकाधिक प्रयोग करने के उपायों पर ग्रुपनी सिकारिशें प्रस्तुत कैरे तथा एक ऐसी समय-ग्रनुसूची (time schedule) निर्धारित करे जिसके ग्रनुसार हिन्दी शनैः—शनैः ग्रौर यथा संभव १६६५ तक, संघ की राजभाषा के रूप में ग्रौर संघ ग्रौर किसी राज्य के बीच तथा एक राज्य ग्रौर दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा के रूप में ग्रोंजी का स्थान ले ले।

की भाषा के रूप में श्रंग्रेजी का स्थान लेले ।

४०—राजभाषा श्रायोग ने जुलाई, १६५५ से श्रंपना कार्य प्रारम्भ कर
दिया है । सर्व प्रथम उसने ३४ प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार करके उसे
जमस्त राज्य सरकारों, विशिष्ट हिन्दी विद्वानों तथा श्रन्य व्यक्तियों के पास
उनके विचार जानने के लिए भेजा है । तदनुसार इस शासन ने भी श्रभी हाल में
श्रंपने विचार श्रायोग को भेज दिये हैं । इन विचारों का सारांश नीचे पैराग्राफ
४३ में दिया हुग्रा है । इस सारांश में केवल उन्हीं विचारों का समावेश है जिनका

४१—-राजभाषा आयोग ने श्रब विभिन्न राज्यों का दौरा करना प्रारम्भ कर दिया है। इस दौरे के श्रन्तर्गत आयोग सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य भी संगृहीत करेगा।

संबंध सीधे शासन की हिन्दी संबंधी नीति से है ।

४२---- श्रायोग श्रागामी मार्च मास में इस प्रदेश में श्रायेगा श्रौर यु:ां की हिन्दी की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगा ।

४३—उत्तर प्रदेश शासन द्वारा व्यक्त विचारों की मोटी-मोटी वार्ते नीचे दी जाती हैं (जहां तक उनका संबंध सीधे शासन की हिन्दी—संबंधी नीति ने है):—

(१) शासन ने पुनः इस बात पर जोर दिया है कि उसकी सदैव यह नीति रही है और श्रव भी है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी ही इस राज्य की एक मात्र राजभाषा है। इस निश्चय को शासन ने श्रपने दिनांक द श्रक्तूबर, १६४७ के परिपत्र में घोषित किया था। तभी से इस नीति को शनै:-शनैः सभी राजकीय प्रयोजनों के निमित्त कार्यान्वत किया जा रहा है क्योंकि उसी परिपत्र में इस बात की भी व्यवस्था है कि इस नीति को इस प्रकार कार्यान्वत किया जाय जिससे राजकीय कार्यों में सब से कम बाधा पड़े तथा श्रमुविधा हो।

ग्रागे, हिन्दी की श्रपनी भावी नीति स्पष्ट करते हुये, शासन ने कहा है कि उसने श्रपने श्रिधकार-क्षेत्र के भीतर ऐसी सभी कार्यवाहियां कर ली हैं जिनसे राजकीय कार्यों में पूर्ण रूप से हिन्दी चलाने में जो किठनाइयां पड़ रही हैं, वे यथासंभव दूर हो जायं ग्रीर जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, यदि उन कार्यवाहियों को, जिन्हें इस समय तक इस प्रदेश में कार्यीन्वत किया जा चुका है ग्रीर ग्रिधक प्रगाढ़रूप से कार्यीन्वत किया जाय, तो साधारणतया ग्रागामी कुछ ही वर्षों के भीतर, इस राज्य के राजकीय कार्यों में हिन्दी के व्यापक प्रयोग के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

(२) इस बात पर फिर जोर देते हुये कि सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए केवल हिन्दी को ही स्थान देना ग्रनिवार्य है, यह मत प्रकट किया गया है कि हिन्दी को राजभाषा मान लेने के यह ग्रर्थ नहीं होते कि देश व ग्रंग्रेजों के ग्रध्ययन को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाय। ग्रागे

समय ग्रन्सूची

श्रायोग द्वारा संपादित कार्य तथा उसका भावी कार्यक्रम

श्रायोग का दौरा

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा व्यक्त विचारों का सारांश

शासन की हिन्दी संबंधी नीति

श्रंग्रेजी के संबंध में शासन की नीति यह भी कहा गया है कि वास्तव में भाषा के रूप में (न कि अंग्रेजी साहित्य के रूप में) श्रंग्रेजी के श्रध्ययन को, कुछ सीमा तक शिक्षा के उच्च क्तरों में श्रर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर, श्रिनवार्य कर देना चाहिये। ऐसा करने से वे विद्यार्थी, जो वैज्ञानिक श्रथवा वाणिज्य संबंधी श्रध्ययनों में लगे हुये हैं, इन विषयों में श्रयना ज्ञान बढ़ाने में समर्थ हो जायेंगे। साथ ही वे श्रध्यापकगण भी जो अंततः इन्हीं विद्यार्थियों में से बनेंगे, विदेशों में होने वाली नयी बातों से श्रनभिज्ञ न रहेंगे।

श्रागे चल कर, श्रंग्रेजी के सम्बन्ध में यह मत प्रकट किया गया है कि श्रंग्रेजी, शासकीय रूप से मान्य, कोई एसी श्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जो सभी श्रन्य भाषात्रों से श्रिधिक उत्तम हो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी श्रपना-श्रपना कार्य पहिले समान स्तर की, श्रथांत् श्रंप्रेजी, फ्रान्सीसी, स्पेनिश तथा चीनी भाषात्रों से श्रारम्भ किया था श्रोर श्रव तो उन्हें रूसी भाषा को भी बराबरी का स्थान देना पड़ा है। राज्य सरकार के मत में, यदि भारत केवल हिन्दी को ही श्रपनाने में श्रइ जाय तो भारत-वासियों को श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा श्रीर इसके साथ ही साथ यदि यह ेश हिन्दी के मामले में दृढ़ता दिखाये, तो एक दिन वह भी श्रा सकता है, जब हिन्दी एक श्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप पें स्वीकार कर लो जाय। भारत में श्रंग्रेजी का श्रध्ययन जारी रहे; किन्तु ऐसा करना इसलिये श्रावश्यक नहीं है कि श्रंग्रेजी के श्रध्ययन से भारत को श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्वपूर्ण सहायता मिल सकेगी।

प्रगाढ़ रूप से हिन्दी-संबंधी कार्यवाहियों का कार्यान्वित किया जाना (३) एक ग्रन्य प्रश्न के उत्तर में यह मत प्रकट किया गया है कि यि शासन द्वारा संपादित कार्यवाहियों को ग्रौर ग्रधिक प्रगाढ़ रूप से कार्यान्तित किया जाय तो राज्य की सभी लोक सेवायें १६६४ तक हिन्दी में उपयुक्त कार्य-क्षमता प्राप्त कर लेंगी। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि भविष्य में वर्तमान उपायों से प्राप्त ग्रनुभव के ग्राधार पर, किन्हीं ग्रन्य उपायों के किये जाने की ग्रावश्यकता पड़ सकती है, परन्तु इन नए उपायों को, राज्य द्वारा स्थापित एक ऐसी स्थायी समिति के ग्रथीन कर देना चाहिए जिसे राज्य में हिन्दी की प्रगति बढ़ाने का कार्य सौंपा गया हो।

हिन्दी के विकास के लिये कार्य-वाहियां (४) राज्य में हिन्दी भाषा के विकास के लिए जो कार्यवाहियां की जा चुकी हैं, उनका भी उल्लेख किया गया है, ग्रर्थात्

- (क) हिन्दी में मौलिक ग्रंथ तैयार करने के लिए पुरस्कार देने की व्यवस्था;
- (ख) राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विधिक, प्रशास-कीय तथा पारिभाषिक ग्रंग्रेजी शब्दों की हिन्दी शब्दाविलयां तैयार कराने की ब्यवस्था;
- (ग) हिन्दी के ऐसे प्रतिष्ठित लेखकों तथा विद्वानों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था, जो घनाभाव के कारण कठिनाई में हों;
- (घ) जिन प्रकाशकों को हिन्दी के मूल ग्रंथों को मुद्रित करने में कठिनाई हो उन्हें वित्तीय सहायता देना;
- (ङ) हिन्दी की वर्तमान ग्रावश्यकताग्रों को देखते हुए हिन्दुस्तानी एकडेमी का पुनस्संगठन करना; ग्रौर

(च) जो गैर-सरकारी संस्थाएं इस राज्य में हिन्दी के विकास-कार्य में लगी हुई हैं उन्हें वित्तीय सहायता देना ।

(५) हिन्दी के विकास के सम्बन्ध में और श्रागे क्या कार्यवाहियां की जानी चाहिये इस प्रसंग में यह राय प्रकट की गई है कि जो कुछ भी कार्यवाहियां इस समय की जा रही हैं उन्हें श्रीर श्रागे बढ़ाया जाय तथा उनकी प्रगति की देख-भाल किसी उचित श्रिधकारी द्वारा कराई जाय । श्रायोग के इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है कि राज्य में एक स्थायी या स्थायी-कल्प (Quasi-permanent) संस्था जिसे केवल परामर्शदात्री शक्तियां ही प्राप्त हों इस प्रयोजन के लिये बनाई जाय ।

श्चन्य कार्यवाहियों के लिये स्थायी समिति की नियुक्ति का समर्थन

(६) राज्य में संस्कृत के श्रध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाय इसका भी समर्थन किया गया है। इसका कारण यह दिया गया है कि संस्कृत के श्रध्ययन से हिन्दी भाषा श्रौर समृद्ध बनेगी। संस्कृत के श्रध्ययन से श्रन्य प्रादेशिक भाषाएं, जिनमें हिन्दी भी सम्मिलित है, एक दूसरे के श्रौर निकट श्रा जायंगी।

संस्कृत का भ्रघ्ययन

(७) शासन ने हिन्दी की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ सामान्य मुझाव भी दिये हैं। उसने इस बात पर जोर दिया है कि केन्द्र तथा राज्य दोनों ही में, हिन्दी सम्बन्धी कार्य में सामन्जस्य लाने के हेतु समन्वय प्राधिकारी (Co-ordinating authority) की नियुक्ति की जाय। समन्वय प्राधिकारी की नियुक्ति इसलिये स्रावश्यक है जिससे संघ के विभागों में किये गये हिन्दी सम्बन्धी कार्य तथा राज्यों में किये गये इसी प्रकार के कार्य में सामन्जस्य लाया जा सके। इस प्राधिकारी के रूप में एक भाषा विभाग स्थापित किया जा सकता है।

सामान्य सुझाव

- (द) शासन ने यह मत भी प्रकट किया है कि केन्द्र तथा राज्य दोनों ही में, हिन्दी परामर्शदात्री परिषद् स्थापित किये जायं। इन परिषदों का यह उद्देश्य होगा कि वे केन्द्र तथा राज्यों में गैर-सरकारी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करके हिन्दी के विकास-कार्य तथा उसका प्रचार बढ़ाने में शासन को उपयुक्त सहायता पहुंचायें।
- (६) इस बात की सिफारिश की गई है कि हिन्दी चलाने के सम्बन्ध में अच्छा कार्य संगदित करने वाले सरकारी कर्मचारी को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।
- (१०) राजभाषा आयोग से कहा गया है कि यथासम्भव वह अपना प्रति-बेदन (रिपोर्ट) हिन्दी में भी तैयार करावे जिससे भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को हिन्दी चलाने में प्रोत्साहन मिले।

E—हिन्दी की प्रगति बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश

(क) परिपत्र जो श्रक्तूबर, १९५५ के श्रन्त तक निकाले गये ४४--श्रक्तूबर, १९५५ तक निकाले गये परिपत्रों का सारांश इस प्रकार है :---

ऋम-संख्या परिपत्र का दिनांक

परिपत्र का ग्राशय

(१) ८ श्रक्तूबर, १६४७

यह घोषित किया गया कि देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी उत्तर प्रदेश की राज-भाषा होगी । भविष्य में सरकारी । नौकरियों में भर्ती करते समय श्रीर सब बातों के समान

कम-संख्या परिपत्र का दिनांक \

परिपत्र का आशय

होते हुये हिन्दी का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को स्रिधिक पसन्द किया जायगा स्रोर स्रन्य नौकरियों में भर्ती के लिये भी हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान रखना स्रावश्यक होगा। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये राज्य लोक सेवा स्रायोग द्वारा निर्धारित परीक्षास्रों में हिन्दी को स्रनिवार्य विषय बनाया जायगा।

- (२) सभी वर्तमान सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लें जिससे कि वे श्रपना वर्तमान कार्य हिन्दी में कर सकें।
- (३) व्यवहार प्रिक्रिया संग्रह की धारा १३७ ग्रौर दंड प्रिक्रिया संग्रह की धारा ५५८ के अधीन इस ग्राज्ञय की घोषणा सम्बन्धी विज्ञित्तियां जारी की गईं कि दीवानी ग्रौर फौज-दारी ग्रदालतों की भाषा हिन्दी होगी।
- (४) मैनुग्रल ग्राफ गवर्नमेंट ग्रार्डर्स, खंड १ (पुराना संस्करण) का पैराग्राफ ३८५ निम्न रूप में परिष्कृत किया गया :—
 - (क) जनता के नाम ग्रदालतों या माल के ग्रफसरों की ग्रोर से जारी किये जाने वाले सभी सम्मन, घोषणा तथा इस प्रकार के ग्रन्य कागज देवनागरी लिपि में होंगे।
 - (ख) फौजदारी, दीवानी तथा लगान ग्रौर मालगुजारी की श्रदालतों में सब लोग ग्रपने श्रावेदन-पत्र ग्रथवा श्रपनी शिकायतें देवनागरी लिपि में ग्रौर यदि वे हिन्दी न जानते हों, तो फारसी लिपि में देंगे।
- (४) सरकारी कार्यालयों के लिये मान्य भाषा हिन्दी होगी ग्रौर सरकारी कार्य तथा पत्र-व्यवहार में इसका उपयोग किया जायगा । १ दिसम्बर, १६४७ से सभी प्रपत्र ग्रादि हिन्दी में मुद्रित होंगे ग्रौर सरकारी कार्यालयों में सभी साइन बोर्ड, नोटिसें ग्रादि हिन्दी में होंगी।
- (२) ४ जन, १६४८
- (६) सभी विभागाध्यक्ष ग्रौर कार्यालयाध्यक्ष को यह निदेश **दिये**गये कि वे ग्रपने ग्रधोनस्थ सेवाग्रों में भर्ती के लिये ली जाने
 वाली परीक्षाग्रों में हिन्दी को एक ग्रनिवार्य विषय रखें।
 इस प्रकार इस राज्य की समस्त प्रतियोगिता परीक्षाग्रों
 में हिन्दी एक ग्रनिवार्य विषय कर दिया गया।
- (३) १८ जन, १६४८
- (७) न्यायालय की नोटिसें तथा सम्मन देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में प्रकाशनार्थ जारी किये जाने चाहिये।
- (४) १८ दिसम्बर, १६४८ (८) यह स्पष्ट किया गया कि शब्द "हिन्दी" से तात्पर्य देवनागरी लिपि में लिखित इस राज्य की जनता की भाषा से हैं।

ऋम-संख्या परिप	त्र का दिनांक	परिपत्र का ऋाँुशय
		विभागाध्यक्षों त्रादि से पूछा गया कि राज्य की विभिन्न सेवाग्रों की परीक्षाग्रों में हिन्दी को एक ग्रनिवार्य विषय बनाने में ग्रब तक क्या कार्यवाही की गई।
(४) ६ फरवरी	t, १६४६ (E) समस्त विभागाध्यक्षों को निदेश किया गया कि वे ऐसे कर्मचारियों के नाम जो ३१ मार्च, १६४६ तक हिन्दी से ग्रनभिज्ञ हों, सरकार को भेजें।
(६) द ग्रगस्त,	86%0 (8	 यह स्रादेश दिया गया कि यदि चरित्रपंजी में प्रविष्टियां हिन्दी में की जायें स्रोर उन्हें महालेखापाल को भेजना हो तो उनके साथ स्रंग्रेजी का श्रनुवाद भी भेजा जाना चाहिये।
(७) १० जुलाः) सभी विभागाध्यक्षों को यह निदेश किया गया कि वे राजकीय तार भेजने के प्रयोजनार्थ राज्य के कई जिलों में प्रारम्भ की गई हिन्दी तार सेवा का उपयोग करें।
(=) २६ ग्रक्तृब	ार, १६४२ (१२)) यह ग्रादेश दिया गया कि यथासम्भव सभी कार्य हिन्दी में किये जायं ग्रीर जिन सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान न हो ग्रीर हिन्दी में काम न कर सकते हों वे कुछ समय तक तो ग्रंथेजी में ही काम करते रहें किन्तु उन्हें शीघ्र ही काम चलाऊ हिन्दी सीख लेना चाहिये।
	(१३)	भविष्य में केवल हिन्दी टाइप राइटर ही खरीदे जायं स्रौर जो स्टेनोग्राफर ग्रौर टाइपिस्ट भर्ती किये जायं वे प्रधानतया हिन्दी के ही हों।
(६) २१ स्रद्रैल,	SEXR (SR)	
(१०) ५ सितम्बर		इसमें समस्त विभागाध्यक्षों ग्रादि को सूचित किया गया कि सरकार ने विधान परिषद् के इस ग्राशय के गैर-सरकारी प्रस्ताव को मान लिया है कि "हिन्दी भाषा को जीवित व जाग्रत बनाये रखते के लिये उसके शब्द-कोष में वृद्धि करने के लिये ऐसे प्रचलित शब्दों को जो सभी ग्रासानी से समझ सकते हैं सम्मिलत कर लिया जाय ग्रौर जहां तक हो राजकीय कार्य में वही शब्द काम में लाये जायं जो सरल हों"। विधान परिषद् में १८ फरवरी, १९५४ को डा० सम्पूर्णानन्द ने हिन्दी भाषा से सम्बन्धित प्रस्ताव पर जो भाषण विया उसका उद्धरण इस ग्रध्याय के ग्रन्त में कर्मचारियों के पथ-प्रदर्शन के लिये दिया गया है। (भाग १ के ग्रंत में संलग्न नत्थी देखिये)।
(११) १ नवम्बर,	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि सभी सरकारी कार्य यथासम्भव हिन्दी में ही किये जायं ग्रौर यह बताया गया कि पुराने ग्रंग्रेजी टाइपराइटरों के स्थान पर नये ग्रंग्रेजी टाइपराइटरों की मांग स्वीकार न की जायगी।

क्रम-संख्या परिपत्र का दिनांक ।

परिपत्र का ग्राशय

- (१७) यह भी आदेश दिया गया कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में की गई प्रगति की छःमाही रिपोर्ट सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को १ जनवरी और १ जुलाई को भेजी जाय।
- (१२) ३० दिसम्बर, १६५४ (१८) स्रादेश दिया गया कि यदि ऐसे कोई कर्मचारी हों जो स्रब भी हिन्दी से स्रनभिज्ञ हों तो सरकार को सूचित किया जाय ।
- (१३) ११ जुलाई, १६५५ (१६) सभी विभागाध्यक्षों ग्रौर कार्यालयाध्यक्षों को यह निदेश किया गया कि वे सरकार द्वारा निर्मित समितियों की, जिनमें गैर-सरकारी सदस्य भी हों, कार्यसूची तैयार करने में ग्रौर कार्यवाही लिखने में हिन्दी का ही प्रयोग करें। यह भी व्यवस्था की गई कि यदि किसी कारण से उक्त किसी समिति की कार्यसूची ग्रौर कार्यवाही ग्रंग्रेजी में ही रखना हो तो इस सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(ख) दिसम्बर, १९५५ के परिपत्र के नये आदेश

४५--दिसम्बर, १९५५ के परिपत्र में दिये गए ग्रादेशों का विवरण इस प्रकार है :---

(१) सरकार द्वारा भेजे जाने वाले परिपत्र—सरकार द्वारा श्रव से जो भी परिपत्र भेजे जायंगे वे हिन्दी में होंगे। यदि कोई ऐसा पत्र भेजना हो जिसका सम्बन्ध वित्तीय मामलों से हो तो भी उसे हिन्दी में ही भेजने का प्रयत्न किया जायगा। श्रलवत्ता साथ में उसकी एक श्रंग्रेजी प्रति लगा दी जायगी।

इस प्रकार प्रत्येक विभागाध्यक्ष ग्रयने ग्रधीनस्य कार्यालयों को जो परिपत्र भेजे वे हिन्दी में हों। वित्त सम्बन्धी परिपत्रों की दशा में उनका ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद संलग्न कर दिया जाय ।

यद्यपि ऐसे परिपत्र जिनमें वित्त सम्बन्धी प्रश्नों का उल्लेख हो ग्रंग्रेजी में भेंजे जा सकते हैं, किन्तु श्रच्छा तो यह होगा कि वे हिन्दी में ही तैयार किये जायें ग्रौर उनका ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद संलग्न कर दिया जाय। इससे यह लाभ होगा कि वित्त सम्बन्धी परिपत्र भी हिन्दी में बनाने का ग्रम्यास हो जायगा।

- (२) द्रुतगामी पत्र—इस प्रकार के ग्रादेश पहले से ही मौजूद है कि राजकीय तार भेजने के प्रयोजनार्थ राज्य के कई जिलों में प्रारम्भ की गई हिन्दी तार सेवा का ग्रधिकाधिक उपयोग किया जाय। (देखिये परिपत्र दिनांक १० जुलाई, १९५२ ग्रौर २१ ग्रप्रैल, १९५४)। चूंकि द्रुतगामी पत्र का ग्रालेख्य तार जैसा होता है इसलिय इनको भी हिन्दी में भेजने में कोई ग्रापित न होनी चाहिये। फिर सामान्य पत्रों की ग्रपेक्षा इनकी संख्या भी बहुत कम होती है।
- (३) श्रनुस्मारक (रिमाईडर) श्रौर स्वीकार-प्राप्ति。(एकनालेजमेंट) पत्र—इस समय श्रनुस्मारक हिन्दी श्रौर श्रंग्रेजी दोनों ही में भेजे जाते हैं। उनको श्रव हिन्दी में ही भेजने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार स्वीकार-प्राप्ति पत्र भी हिन्दी ही में भेजे जायें। यह श्रादेश निम्न प्रकार के श्रनुस्मारकों श्रौर स्वीकार-प्राप्ति पत्रों पर लागू होंगे:

- (क) सिचवालय से उसके विभिन्न विभागों तथा विभागाध्यक्षों इत्यादि को भेजे जाने वाले ग्रीर विभिन्न विभागों तथा विभागाध्यक्षों इत्यादि से सिचवालय को ग्राने वाले ;
- (ल) ग्रघीनस्य कार्यालयों से परस्पर ग्राने-जाने वाले ;
- (ग) ऐसे राज्यों को जिनके साथ इस शासन का संविधान के श्रनुच्छेद ३४६ के श्रन्तगंत हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का करार हुआ है, भेजे जाने वाले [इस सम्बन्ध में श्रापको श्रलग से श्रादेश परिपत्र सं० १२०५२/३--१७०-(३)- १६५०, दिनांक १६ नवम्बर, १६५५ में भेजे जा चुके हैं]।

श्रनुस्मारक श्रीर स्वीकार-प्राप्ति-पत्र के कुछ नमूने "हिन्दी निर्देशिका" में, जिसका उल्लेख नीचे के परिच्छेद में किया गया है, श्रापकी सुविधा के लिये दे दिये गये हैं। श्रावश्यकतानुसार इन प्रपत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है।

- (४) सामान्य प्रकार के पत्र-व्यवहार, निर्देश तथा टिप्पण--सामान्य प्रकार के जो भी पत्र-व्यवहार तथा निर्देश किये जायें वे हिन्दी में ही किये जायें। उनसे सम्बन्धित टिप्पण भी हिन्दी में लिखे जायें ग्रौर दैनिक प्रयोग के ग्रपेक्षण-पत्र भी हिन्दी में भरे जायं, उदाहरणार्थ:
 - (क) पुस्तकालय तथा ग्रभिलेख कक्ष से पुस्तकें व पत्राविलयां मंगाने के ग्रपेक्षण-पत्र ग्रीर लेखन-सामग्री के ग्रपेक्षण-पत्र हिन्दी में भरे जायं।
 - (ख) पत्रों की प्रतिलिपि मांगने से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाय ।
 - (ग) सूचनार्थ तथा स्रावश्यक कार्यवाही के लिये प्रतिलिपि भेजने के पृष्ठांकन हिन्दी में किये जायें।
- (४) जनता से प्राप्त ग्रावेदन-पत्रों का उत्तर—जनता से प्राप्त सभी प्रकार के ग्रावेदन-पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाय। ग्रभी केवल उन ग्रावेदन-पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है जो हिन्दी में प्राप्त होते हैं, किन्तु ग्रव उन ग्रावेदन-पत्रों का भी, जो देवनागरी लिपि में न हों, उत्तर हिन्दी में दिया जाय।
- (६) स्रसेम्बजी के प्रश्नों के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार तथा टिप्पण (नोटिंग)—यथासम्भव स्रसेम्बली के प्रश्नों के सम्बन्ध में सारा पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाय स्रौर टिप्पण-कार्य भी हिन्दी में हो ।
- (७) हिन्दी में प्रयत्र—पह भी ग्रावश्यक है कि वे समस्त प्रयत्र जो ग्रभी ग्रंग्रेजी में ही प्रयुक्त होते हैं हिन्दी में ग्रनूदित हों। इनके ग्रनुवाद के लिये सरकार प्रबन्ध कर रही है। ग्रतएव भिवष्य में कोई भी कार्यालय, वित्त सम्बन्धी प्रपत्रों को छोड़ कर, ग्रन्य प्रपत्र ग्रंग्रेजी में मुद्रित न करायेंगे। जब विद्यमान ग्रंग्रेजी प्रपत्र समाप्त होने लगें तो इसकी सूचना सरकार को दी जाय जिससे कि उन्हें उन प्रपत्रों का हिन्दी रूपान्तर शीघ्र ही उपलब्ध हो सके। जब तक उनको हिन्दी में मुद्रित प्रपत्र नहीं मिलते वे उन प्रपत्रों का हिन्दी रूपान्तर करा लें ग्रौर साइक्लोस्टाइल करके उन्हें प्रयुक्त करें। यह सुनिश्चित करने के लिये कि वित्त सम्बन्धी प्रपत्रों को छोड़ कर सामान्यतया दैनिक प्रयोग के ग्रन्य प्रपत्र ग्रंग्रेजी में फिर से मुद्रित न हों, ग्रधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री को ग्रादेश दिये जा रहे हैं कि वे भविष्य में किसी भी ग्रवस्था में ग्रंग्रेजी में प्रपत्र न छापें। यदि ग्रंग्रेजी में ही छपा कोई प्रपत्र प्रयुक्त करना हो तो वह भी हिन्दी में भरा जाय। उदाहरणार्थ, उपस्थित तथा ग्राकिस्मक छुट्टी की पंजी हिन्दी में, भरी जाय। इसी प्रकार प्राप्ति, प्रेषण तथा पत्रावली पंजियां भी हिन्दी में भरी जायं।
- (८) कर्मचारियों के आवेदन-पत्र--पथासम्भव कर्मचारी अपने आवेदन-पत्र हिन्दी में ही दें। इसी प्रकार उनका उत्तर भी हिन्दी में ही देने का प्रयत्न किया जाय।

- (६) रीतिक ग्रवसरों पर निमंत्रण-पत्र—-रीतिक ग्रवसरों पर राज्य सरकार द्वारा भेजे जाने वाले निमंत्रण-पत्र हिन्दी में हों। इसी प्रकार विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों द्वारा जो भी निमंत्रण-पत्र भेजे जायं वे भी हिन्दी में ही छने हों।
- (१०) दौरे का कार्यक्रम—दौरे के कार्यक्रम हिन्दी में ही बनाये जायं। कितपय राज्य से दौरे के कार्य-क्रम हिन्दी में प्राप्त होते हैं। सुविधा के लिये ऐसे कार्यक्रम का एक नमूना हिन्दी निर्देशिका के परिशिष्ट ३ में दे दिया गया है।
- (११) कलेंडर तथा छुट्टियों की सूची—सरकार द्वारा प्रकाशित समस्त प्रकार के कैलेंडर तथा पैंड हिन्दी में हो । इसी प्रकार छुट्टियों की सूची भी हिन्दी में हो । निगोशियेबुल इन्सट्ट्र मेन्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत छुट्टियों की विज्ञान्ति हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होंगो, किन्तु कार्यालयों अगैर अधिकारियों के प्रयोग के लिगे अतिरिक्त प्रतियां केवल हिन्दी में ही छुपेंगी। गवर्नमेंट प्रेस द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित १९४४ के कितप्य कैलेंडर अंग्रेजी ही में थे अब से जितने भी कैलेंडर अधीक्षक, मुद्रण तथा लखन-सामग्री द्वारा छापे जायं व हिन्दी में हों।
- (१२) लिफाफों पर पते—लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही होने चाहिये। किन्तु कार्यालयों के अंग्रेजी नाम व अधिकारियों के अंग्रेजी पद नाम अंग्रेजी में ही होने चाहिये। ऐसा करना कुछ समय तक इसलिये आवश्यक है कि अभी डाक व तार विभाग इन अंग्रेजी नामों के हिन्दी पर्यायों से भली-भांति परिचित नहीं है और यह हो सकता है कि पत्र संबोधित व्यक्ति के पास न पहुंच कर अनिधकृत व्यक्ति को मिले। कुछ दिन पूर्व बिहार में ऐसा ही हुआ था जिसका फल यह हुआ कि जिन अधिकारियों के पास चिट्ठियां पहुंचनी थीं, उन्हें न मिल कर दूसरे अधिकारियों के पास पहुंच जातो थीं। कुछ मसय बाद जब हिन्दी के पर्याय पूर्ण रूप से प्रचलित हो जायंगे तब हिन्दी के शब्द प्रयोग में लाये जा सकेंगे।
- (१३) टाइपराइटर—परिपत्र संख्या ६४६४/३—१७०—(७)—१९४२, दिनांक २९ ग्रक्तूबर, १९४२ तथा परिपत्र संख्या ८७६३/३—१७०—(३)—१९४२, १ नवम्बर, १९४४ में ये ग्रादेश दिशे गये थे कि नये टाइपराइटर ग्रब हिन्दी लिपि के ही खरीदे जायं। उसमें यह भी बताया गया था कि ग्रंप्रेजी के नये टाइपराइटर खरीदने के प्रस्ताव शासन को ग्रव न भेजे जायें। फिर भी समय-समय पर ग्रंप्रेजी टाइपराइटर खरीदन की मांगें ग्रा रही हैं। इन मांगों के समर्थनों में ग्राधिकतर तीन तर्क दिये जाते हैं
 - (क) पारिभाषित शब्दों के हिन्दी पर्यायों का श्रमाव ;
 - (ख) हिन्दी टाइपिस्टों की कमी ; ग्रीर
 - (ग) दैनिक प्रयोग के प्रपत्रों का ऋंग्रेजी में होना।
- (क) के सम्बन्ध में यह बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि हिन्दी के पत्र में ग्रंग्रेजी पारिभाषिक शब्द हिन्दी लिपि में लिखे जा सकते हैं। इसके ग्रतिरिक्त ग्रव ग्रंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित हो रहे हैं ग्रौर इसकी पुस्तिकार्ये कुछ ही समय म उपलब्ध हो जायंगी।
- (ख) के विषय में स्थायी अनुदेश यह है कि अब जो भी टाइपिस्ट नियुवत किये जायंगे वे प्रधानतया हिन्दी के ही हों। यही नीति स्टेनोग्राफरों के सम्बन्ध में भी है।
- (ग) के सम्बन्ध में उपर्यु क्त उप पैराग्राफ ७ में उल्लेखन कर दिया गया है कि श्रंग्रेजी में मुद्रित प्रथत्र श्रव प्रयुक्त न होंगे। समस्त प्रपत्रों के हिन्दी रूपान्तर तैयार हो रहे हैं श्रौर शीध्र ही उपलब्ध हो जायेंगे।

ऐसी श्रवस्था में श्रंग्रेजी टाइपराइटर खरींदना श्रावश्यक नहीं कहा जा सकता। श्रतः शासन ने निश्चय किया है कि श्रव श्रंग्रेजी टाइपराइटरों की मांग न की जानी चाहिये। शासन के लिये श्रव इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करना सम्भव न होगा। श्रलबत्ता इस श्रादेश के निम्निलिखित श्रपवाद हैं:---

- (क) उच्च-न्यायालय में न्यायिक प्रयोजनों के लिये तथा किसी विशेष स्थित में प्रशा-सकीय प्रयोजनों के लिये ;
- (ख) अन्य न्यायिक अधिकारियों के ऐसे कार्यों के लिये, जिन्हें भ्रंग्रेजी में करना अनिवार्य हो ;
- (ग) लोक सेवा श्रायोग के ऐसे कार्य के लिये जिनका श्रंग्रेजी में किया जाना श्रनिवार्य हो, उदाहरणार्थ, परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न-पत्र श्रादि ;
- (घ) महालेखापाल से सम्बन्धित ऐसे कार्य के लिये जिनका श्रंग्रेजी में ही करना श्रभी श्रावत्थक है ;
- (ङ) यदि कोई नया कार्यालय स्थापित हो, जिसमें श्रंग्रेजी में कुछ हद तक काम करना श्रावश्यक हो ; तथा
- (च) इसी प्रकार के किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिये।

इन दशास्रों में भी स्रंग्रेजी टाइपराइटरों के खरीदने की स्रनुमति उसी समय दी जायगी जब काम की मात्रा पर्याप्त हो ।

- (१४) कार्यालय की मोहरें तथा रवर मुद्रायें—कार्यालय की मोहरें तथा रवर मुद्रायें हिन्दी में हों। जहां ऐसा न हो, ग्रधिकारियों को चाहिये कि वे ऐसी व्यवस्था कर लें। पदनाम ग्रंग्रेजी में हो सकते हैं किन्तु लिपि देवनागरी हो।
- (१४) चपरासियों ग्रादि के बिल्ले—सिचवालय के चपरासियों, जमादारों तथा पुलिस, होमगार्ड के सिपाहियों व ग्रन्य सरकारी कार्यालयों के चपरासियों ग्रादि के बिल्ले हिन्दी में होना चाहिये। जहां ऐसा न हो रहा हो, वहाँ ग्रब इस प्रकार की व्यवस्था कर ली जाय।
- (१६) हिन्दी के लिये एक पदेन ग्रिधिकारी—सिचवालय, विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों के कार्यालयों ग्रादि में हिन्दी की प्रगित समुचित रूप से हो रही है या नहीं यह देखने के लिये प्रत्येक कार्यालय में एक ग्रिधिकारी मनोनीत किया जाय जो ग्रपने सामान्य कार्य के ग्रितिस्त यह भी देखे कि उस कार्यालय में सुचार-रूप से हिन्दी का व्यवहार हो रहा है ग्रौर हिन्दी के विषय में सरकारी ग्रादेश पूर्णतया पालन किये जा रहे हैं। ग्रितः प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष ग्रपने ग्रिधीनस्थ एक कर्मचारी को जो राज्य सेवा (State service) के ग्रेड से निम्नग्रेड का न हो इस कार्य के लिये मनोनीत कर देंगे। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रक्खा जाय कि इसके लिये वही पद्मिकारी मनोनीत किया जाय जो ज्येष्ठ (Senior) हो ग्रौर हिन्दी में ग्रिभिरुचि रखता हो जिससे कि उसके परामर्श के ग्रनुसार ग्रन्य ग्रिधिकारी ग्रौर कर्मचारी सुगमता से काम कर सकें।

कार्यातयों के प्रधान निरीक्षक ग्रौर उनके ग्रधीनस्थ निरीक्षक भी कार्यालयों का निरीक्षण रते समय यह देखेंगे कि हिन्दी सम्बन्धी ग्रादेशों का पालन हो रहा है।

(१७) प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी पुैस्तकालय की स्थापना—प्रत्येक कार्यालय में धीरे-गिरे एक हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किया जाय, जहां कर्मचारियों को हिन्दी के प्रमाणीकृत कोष, प्रेजी-हिन्दी के कोष, हिन्दी की निर्देश पुस्तकें, हिन्दी की वे पुस्तकें जो राजकीय कार्य करने में त्यक्ष ग्रथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों, हिन्दी ग्रास्थायें, हिन्दी बजट तथा गजट की प्रतियां, हिन्दी म्रालेखन की पुस्तकें म्रादि उपलब्ध हो सकें । ये पुस्तकालय हिन्दी भ्रध्ययन केन्द्र का भी काम करेंगे म्रोलेखन कर सकेंगे । यह पुस्तकालय कर्म-करेंगे म्रोलेख कर सकेंगे । यह पुस्तकालय कर्म-करेंगे म्रोलेखन कर सकेंगे । यह पुस्तकालय कर्म-चारियों में न केवल हिन्दी पढ़ने म्रोलेखन की म्रालिखन कर सकेंगे में के पास जो धनराज्ञि प्रासंगिक व्यय बढ़ाने में सहायक होंगे । विभागाध्यक्षों म्रोलेखन म्रालिखन करेंगे के पास जो धनराज्ञि प्रासंगिक व्यय के लिये है उसमें से समय-समय पर इन पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें खरीदनी चाहिये । इसके म्रालिखन का समय होंगे है उसमें से समय-समय पर इन पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें खरीदनी चाहिये । इसके म्रालिखन का सम्बाद्य होंगे हुई पुस्तकें एकत्रित करनी चाहिये ।

- (१८) हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा हिन्दी टाइप सीखने की सुविधा— उन सरकारी कर्म-चारियों को जो हिन्दी स्टेनोग्राफी या हिन्दी टाइप राइटिंग सीखना चाहें तथा उन टाइपिस्टों व स्टेनो-ग्राफरों को जो श्रपनी स्पीड बढ़ाना चाहें निम्न सुविधायें दी जायं:—
 - (क) दफ्तर के घंटों में हिन्दी टाइप सीखन की सुविधा;
 - (ख) कार्यालय के टाइपराइटरों पर टाइप सीखने की सुविधा ;
 - (ग) स्टेनोग्राफरों को दफ्तर के घंटों में स्टेनोग्राफी का श्रभ्यास कायम रखने व बढ़ाने की सुविधा ;
 - (घ) हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखने वालों को दफ्तर में देर से ग्राने तथा जल्दी दफ्तर छोड़ने की ग्रनुमित देना ;
 - (ङ) हिन्दी टाइप व हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखनें, के लिये अध्ययन छट्टी (study leave) दिये जाने की व्यवस्था । फन्डामेन्टल रूत्स के नियम ५४ के म्रन्तर्गत निर्मित नियमावली (subsidiary rules) के नियम १४६-ए में यह व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारियों को वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक (Technical) तथा ग्रन्य प्रकार के विशिष्ट शिक्षण के लिये ग्रतिरिक्त छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है । साधारणतया यह छट्टी खास विभागों, जैसे जन-स्वास्थ्य विभाग, पश-चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वन विभाग के कर्मचारियों को दो जाती है, किन्तु सरकार को अधिकार है कि अन्य कर्मचारियों को भी यह सुविधा दिये जाने का आदेश दे, यदि सरकार के विचार में विशिष्ट पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये उसको ऐसी छट्टी देना सार्वजनिक हित में हो । अतः सरकार न यह निश्चय किया है कि हिन्दी टाइप व हिन्दी स्टेनी प्राफी सीखने के लिये जो प्रस्ताव सरकार के पास स्रायेंगे उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा स्रीर लोक सेवा के हित को ध्यान में रखते हुये यथासम्भव उनको स्वीकार करने का प्रयत्न किया जायेगा । सिचवालय के प्रशासकीय विभाग उन प्रस्तावों को यथा-शीघ्र वित्त विभाग से परामर्श लेकर तय करेंगे ग्रीर यदि श्रावश्यकता होगी तो सामान्य प्रशासन विभाग से भी परामर्श करेंगे
- (१६) हिन्दी की प्रगति में विशेष सहायता देने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन—जो कर्मचारी हिन्दी में श्रच्छी टिप्पणी लिखें या श्रालेख्य तैयार करे उनको प्रोत्साहन दिया जाय । उदाहरणार्थ उनकी चरित्रपंजियों (Character Rolls), में इस श्राशय की प्रविष्टि करना कि वे हिन्दी की प्रगति में विशेष सहायता दे रहे हैं । इस प्रकार उन कर्मचारियों को भी जो हिन्दी की प्रगति में श्रयवा सरकारी काम के लिये उसके प्रचार में विशेष योग दें, प्रोत्साहन दिया जाय । हिन्दी सम्बन्धी इन प्रविष्टियों पर पदोन्नति के समय विशेष रूप से ध्यान विया जाय ।

४६--राजकीय कार्य में हिन्दी के प्रयोग के विषय में तीन विशेष हिन्दी के प्रयोग क वरिपत्र निकाले गये हैं। पहिला परिपत्र संख्या ४६८६/३--१७०-४७, दिनांक द अक्तूबर, १६४७, देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को राजभाषा स्वीकृत करने के निर्णय के विषय में था ग्रौर उस निर्णय से सम्बन्धित ग्रादेश उसमें दिये हुये थे। उसके बाद दूसरा परिपत्र संख्या ४६६४/३--१७० (७)-१९५२, दिनांक २९ म्रक्तूबर, १९५२ जारी हुम्रा था। म्रन्त में परिपत्र संख्या ११८७६/३--१७० (२२)-१९४४, दिनांक १ दिसम्बर, १९४४ निकाला गया। अन्य परिपत्रों के साथ इन मूल परिपत्रों का आशय भी पैराग्राफ ४४-४५ में दे दिया गया है। फिर भी ये परिपत्र कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण हैं स्रतः वे स्रक्षरशः परिशिष्ट १ में उद्धृत कर दिये गये हैं।

सम्बन्ध में तीन विशेष परिपन्न

१०--भारत सरकार के राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग

४७---भारत सरकार ने भी श्रव श्रपने राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने की व्यवस्था की है और इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद ३४३ के खंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके एक आदेश (order) जारी किया है। इसका नाम "संविधान (राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा) आदेश, १९५५" है। इस आदेश के उपवन्धों के ग्रन्तर्गत ग्रब भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा सम्बद्ध विभाग निम्न कार्यों में ग्रंग्रेजी के ग्रतिरिक्त हिन्दी भाषा का भी प्रयोग कर सकेंगे:

राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया (राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा) ग्रादेश, १६५५ को मुख्य बार्ते।

- (१) जनता के सदस्यों के साथ पत्र-व्यवहार।
- (२) प्रशासकीय रिपोर्टे, सरकारी पत्रिकाएं तथा व रिपोर्टे जो संसद को दी जाने वाली हों।
- (३) सरकारी प्रस्ताव तथा संसदीय विधि।
- (४) उन राज्य शासनों के साथ पत्र-व्यवहार जिन्होंने राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार कर लिया है।
- (५) संधि-पत्र तथा करारनामे।
- (६) विदेशी राज्यों, उनके राजदूतों तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ पत्र-व्यवहार।
- (७) ग्रन्तर्राजनैतिक तथा वाणिज्य दूत ग्रिधिकारियों तथा ग्रन्तर्रा-ष्ट्रीय संस्थाय्रों के भारतीय प्रितिनिधियों को जारी होने वाले रीतिक लेख्य।

४८--उपर्युक्त राष्ट्रपति के ग्रादेश को ग्रीर ग्रागे स्पष्ट करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय हूँने ग्रयने दिनांक ४ दिसम्बर, १६५४ पत्र-संख्या ५६/(२) /५४ (पब्लिक)-१ में बताया है कि--

- (१) जनता के साथ पत्र-व्यवहार--जनता के सदस्यों से जो भी पत्र प्राप्त हों उन सब का उत्तर यथासम्भव सरल हिन्दी में ही दिया जाय।
 - (२) प्रशासकीय रिपोर्टें, सरकारी पत्रिकाएं तथा ऐसी रिपोर्टें जो संसद को प्रस्तुत की जाने वाली हों, इत्यादि--यथा-संभव इन सभी प्रकार के लेख्यों को हिन्दी और श्रंग्रेजी बोनों में ही प्रकाशित किया जाय।

श्रादेश का स्पष्टी-करण

- (३) सरकारी प्रस्ताव तथा संसद द्वारा पारित श्रिधिनियम—
 सरकारी प्रस्तावों तथा ग्रिधिनियमों में श्रंग्रेजी के स्थान
 पर शनै:-शनै: हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से तथा
 जनता के उपयोग के लिए, इस प्रकार के लख्यों को,
 जहां तक संभव हो, उनके मूल श्रंग्रेजी प्रतियों के साथ,
 हिन्दी में भी जारी किया जाय ग्रौर साथ ही यह बात स्पष्ट
 कर दी जाय कि श्रंग्रेजी की प्रति ही श्रिधकृत प्रति समझी
 जायगी।
- (४) उन राज्य शासनों के साथ पत्र-व्यवहार जिन्होंने राजभाषा

 के रूप में हिन्दी को स्वीकार कर लिया है—इस सम्बन्ध

 में यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि पत्र-व्यवहार
 श्रंग्रेजी ही में होना चाहिए परन्तु वैधानिक कठिनाइयों
 की सम्भावना को बचाने के उद्देश्य से ऐसे राज्य शासनों
 को भेजे जाने वाले पत्रों के साथ उनका हिन्दी अनुवाद
 भी साथ में भेजा जायगा।

षादेश सम्बन्धी श्रन्य श्रनुदेश ४६--उपर्युक्त स्पष्टीकरण के साथ-साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी व्यवस्था की है कि--

- (१) इस बात का निर्णय कि उपर्युक्त राजकीय कार्यों में हिन्दी का प्रयोग किस हद तक किया जाय, भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय तथा सम्बन्धित विभाग स्वयं करेगा, ग्रीर
- (२) यदि राष्ट्रपति के श्रादेश को कार्यान्वित करने में किसी श्रितिरक्त कर्मचारिदर्ग की श्रावश्यकता पड़े तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक मंत्रालय तथा सम्बद्ध श्रौर श्रधीनस्थ कार्यालय, वित्त विभाग से परामर्श करके, श्रावश्यक श्रितिरक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेंगे।

हिन्दी के सम्बन्ध में भारत सरकार का भावी प्रति-बंधित कार्यक्रम ५०—यह सुनिश्चित करने के लिये कि १५ वर्ष बाद भारत सरकार के राजकीय कार्यों में श्रंग्रेजी के स्थान पर पूर्णतया हिन्दी प्रयुक्त होने लगे एक ऐसे कार्यक्रम का श्रायोजन किया गया जिससे यह परिवर्तन सुगमता से हो सके। भारत सरकार ने १५ वर्ष के इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये पांच-पांच वर्ष की तीन प्रावस्थाएं निर्धारित की हैं। इन तीनों प्रावस्थाग्रों का कार्यक्रम इस प्रकार है ——

- (१) प्रथम पांच वर्ष ग्रर्थात् १६५०-१६५५ का कार्यक्रम---
 - (क) हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण।
 - (ख) सभी ग्रहिन्दी भाषी क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी को ग्रनिवार्य विषय बनाने का ग्रान्दोलन।
 - (ग) म्रहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रसार।
- (२) द्वितीय पांच वर्ष प्रार्थात् १६५५-१६६० का कार्यक्रम---
 - (क) इस अविध में हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली तैयार हो जायगी।
 - (ख) ग्रहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को हिन्दी का ज्ञान कराया जायगा।

- (ग) म्रहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रौढ़ों को हिन्दी पढ़ाने का कार्यक्रम चलाया जायगा।
- (३) तृतीय पांच वर्ष १६६०-१६६५ का कार्यक्रम-इस प्रविध में केन्द्रीय सरकार के प्रशासन कार्यों में ग्रीर केन्द्र तथा राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार में ग्रंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भी प्रयुक्त की जायगी।
- ११—हिन्दी के सम्बन्ध में भारत सरकार की अद्यावधि प्रगति ५१--संक्षेप में भारत सरकार की हिन्दी की अद्यावधि प्रगति इस प्रकार है--
 - (क) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा प्रशासकीय शब्दावली— इस सम्बन्ध म जा कार्य ग्रप्रैल, १६४४ तक हुन्ना है उसका व्योरा निम्न प्रकार है:--
 - (१) हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दों के कोष का सम्पादन—इस
 कार्य के लिए एक वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली
 बोर्ड का निर्माण किया गया था। १६५० से लेकर
 प्रव तक माध्यमिक स्कूलों के लिए गणित,
 वनस्पति-शास्त्र, रासायनिक-शास्त्र ग्रौर सामाजिक
 शास्त्र तथा डाक, तार, रेलवे, परिवहन, रक्षा तथा कृषि
 शब्दाविलयां ग्रन्तिम रूप से प्रकाशित हो चुकी हैं।
 प्रव तक २६,४०० पारिभाषिक शब्द हिन्दी में
 तैयार हो चुके हैं।
 - (२) हिन्दी में वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तकें तैयार करना—उपर्युक्त शब्दाविलयों के आधार पर पाठच पुस्तकें तथा दूसरी लोकप्रिय पुस्तकें तैयार करने के लिए एक समिति बना दी गई है और यह कार्य शीझ ही प्रारम्भ किया जाने वाला है।
 - (ख) हिन्दी साहित्य की वृद्धि, उस के विकास के लिए गौरव ग्रन्थों, ग्रमारतीय तथा दूसरी भारतीय भागाग्रों के ग्रनुवादों तथा हिन्दी के नए सृजनात्मक साहित्य के नथे सस्ते संस्करण का प्रकाशन तथा उन के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है:

(१) हिन्दी की सर्वोत्तम पुस्तकों पर पुरस्कार।

(२) हिन्दी विश्वकोष बनाने की योजना । विश्वकोष का प्रकाशन पांच-पांच सौ पृष्ठों के दस खंडों में होगा।

(३) नवच्छात्र -प्रौढ़ों के लिए उचित साहित्य के उत्पादन को प्रोत्साहन देना।

(४) एक लोक विश्वकोष को तैयार करना।

(प्र) हिन्दी के गौरव ग्रन्थों के मुलभ संस्करणों के प्रकाशन के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी को २४,००० रु० का श्रनुदान। (६) जरूरतमंद हिन्दी लेखकों को सहायता देने की योजना।
(१) हिन्दी में प्रामाणिक व्याकरणों ग्रौर कोओं को तैयार करना।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्य प्रारम्भ किया गया है:--

(१) नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा एक प्रामाणिक हिन्दी कोष की तैयारी।

(२) हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी द्वारा कैन्साइज स्राक्स-फोर्ड डिक्शनरी के ढंग पर संक्षिप्त हिन्दी कोष बनाने का काम।

(३) हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा श्रंग्रेजी-हिन्दी कोष की तैयारी।

(४) हिन्दी ग्रौर दूसरी प्रादेशिक भाषाग्रों में समान रूप से पार्य जाने वाले शब्दों के कोष की तैयारी!

(५) हिन्दी भाषा के व्याकरण की तैयारी।

- (घ) राज्यों के माध्यमिक स्कूलों में श्रिनिवार्य विषय के रूप म हिन्दो को चलाना तथा विश्वविद्यालयों श्रौर दूसरी उच्च संस्थाग्रों में हिन्दी को प्रोत्साहित करना।
- (ङ) म्रहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रसार के लिए कार्यवाहियां करना म्रोर केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले कर्म-चारियों को हिन्दो पढ़ाने की सुविधा प्रदान करना।

इस सम्बन्थ में जो कार्य हो चुका है उसका व्योरा इस प्रकार है :—

- (१) हिन्दी शिक्षा समिति का पुनर्गठन ग्रौर उसकी सिफा-रिशों पर श्रनुदान देना।
- (२) राज्यों को हिन्दी के प्रसार के लिए अप्रैल, १९५५ तक कुल २,७९,००१ रुपये के अनुदान दिये गये।
- (३) दस हिन्दी कक्षाएं खोली गईं जिनमें करीब ६६० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। इनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी की शिक्षा दी जाती है।

(४) हिन्दी की उन्नति के लिये विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं को तदर्थ श्रनुदान।

इन संस्थाओं में निम्निलिखित उल्लेखनीय हैं——
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद।
हिन्दी भवन, नई दिल्ली।
हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी, इलाहाबाद।
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई।
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्षा।
हिन्दुस्तानी प्रहन्दो सभा, हैदराबाद।
मेसूर रियासत हिन्दी प्रचार समिति, गिलौर।
प्रिल्ल भारतीय हिन्दी परिषद्, श्राग ।
संसदीय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली।

नत्थी

[जिसका उल्लब पैराप्राफ ४४ (१५) में किया गया है।]
गृह तथा श्रम मंत्री (श्रब मुख्य मंत्री) डा॰ सम्पूर्णानन्द के उस भाषण
का उद्धरण जो उन्होंने विधान परिषद् में १८ फरवरी, १९५४
की बैठक में हिन्दी भाषा से सम्बन्धित प्रस्ताव पर दिया था

श्रीमती शिवराजवती नेहरू का प्रस्ताव इस प्रकार था--

"यह परिषद् सरकार से अनुरोध करती है कि हिन्दी भाषा को जीवित व जागृत बनाये रखने और उसके शब्द कोष में वृद्धि करने के लिये आजकल के प्रचलित शब्दों को जिनको कि सब शिक्षित व अशिक्षित आसानी से समझ सकते हैं ज्यों का त्यों सरकारी काम में प्रयोग होने वाली हिन्दी भाषा में सम्मिलित कर लिया जाय।"

जिस प्रस्ताव को श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने सदन के सामने रिखा है उसे स्वीकार करने में गवर्नमेंट को कोई ग्रापित नहीं हो सकती है, इसिलए नहीं कि उसको इस प्रस्ताव में कोई नई चीज मिलती हो बिल्क इसिलये कि इस प्रस्ताव में वही चीज दोहराई गई है, जो हम बराबर कर रहे हैं। बहरहाल इस विचार से हम इसका विरोध करना नहीं चाहते हैं या यों कहिये कि हम स्वीकार करते हैं।

इस स्थान पर कोई नहीं कह सकता है कि प्रचिलत शब्दों का विहिष्कार किया गया है। श्रंग्रेजी के शब्द स्टेशन, रेल श्रौर वारन्ट जैसे न जाने कितने शब्द हैं जो श्रभी मौजूद हैं। इस तरह से गवाही शब्द हैं जो कि हिन्दी में हैं। बहुत से फारसी के शब्द हैं जो कि हिन्दी में हैं।

जो शब्द व्यवहार में है वे हैं। हां, एक बात जरूर है ग्रौर वह यह है कि ग्रगर यह कहा जाये कि वे ज्यों के त्यों रखे जाये तो इसका में ठीक मतलब नहीं समझा। जिस रूप में उस भाषा से ये शब्द आये हों उस रूप में थ्राना कठिन है। हर भाषा की अपनी ब्रात्मा होती है। जैसा कि किसी जमाने में हिन्दुस्तानी भाषा के स्राचार्य लोग कहते थे कि उर्दू में 'देश' शब्द नहीं लिखा जाता है बल्कि 'देस' शब्द लिखा जाता है। तो इस तरह से उर्दू में जो शब्द 'देस' लिखा जाता है तो हर भाषा की श्रपनी रूह होती है। लैन्टर्न को देखिये वह ज्यों की त्यों नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि लोग उसको लालटेन कहते हैं। से अंग्रेजी में लैम्प कहा जाता है, लेकिन लोग उसको लम्प कहते हैं। जैसे उर्दू के फे, काफ और ग्रैन हैं वे मं ह से कहने में अच्छे लगते हैं। मुझे सन्देह नहीं है कि "सफ़ी" का "सफी" ही रहेगा और "गरीव" का "गरीब" रहेंगा। लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि मजदूर ग्रब मजूर हो गया है। जब दूसरी भाषा के शब्द लिये जाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है और यह प्राचीन काल से होता आया है। आज से कई सौ वर्ष पहले ग्रीस में केन्ड्रास शब्द सेंटर के लिये कहा जाता था ग्रीर केन्ड्रास का केन्द्र हमारे संस्कृत में हो गया। अभी तीन या चार दिन हुये कि मैंने अंग्रेजी का एक शब्द अनाकाटी देखा। मैंने इस शब्द की देखने के लिये चैम्बर की इंगलिश डिक्शनरी खोली तो उस में लिखा हुआ था कि यह शब्द हिन्दुस्तानी भाषा से लिया गया है और इसका असली रूप अन्नकुटी है। तो ज्यों का त्यों कहना कठिन है। जिस रूप में हमारी भाषा में चल सकते हैं उस रूप में चलेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम अपनी भाषा को जिद्दन कठिन नहीं बनाना चाहते हैं भ्रौर न कोई साहित्यकार ही ऐसा चाहता है भ्रौर न यह सरकार ही जिद्दन ऐसा करना चाहती है। कहा गया कि "बैठक" से काम चल सकता है भ्रौर सत्र शब्द नहीं होना चाहिये। यह गलत बात है बैठक शब्द हम दो जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रंग्रेजी में सेशन श्रौर सिटिंग दो श्रलग-श्रलग शब्द होते हैं। एक सेशन में कई सिटिंग हो सकती हैं इस-लिये दोनों के लिये हम बैठक शब्द का ही प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सत्र शब्द हमको लाना ही पड़ेगा। श्रगर हम को दूसरे शब्द नहीं मिलते हैं तो हमको संस्कृत का शब्द लाना ही पड़ेगा। में इस बात को मानता हूं कि बहुत से शब्द श्रप्रचलित मालूम होते हैं। हम लोग जो हिन्दी जानने का दावा करते हैं उनको भी उन शब्दों के समझने में कठिनाई होती है। लेकिन एक जमाना ऐसा श्रायेगा कि वही शब्द हमारे लिये त्रासान हो जायेंगे। यूरोप में जब लैटिन भाषा का प्रचार हुन्ना तो वहां के बड़े-बड़े विद्वानों ने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई। लेकिन प्राज वही शब्द हैं जो बहुत सुन्दर मालूम होते हैं श्रौर जिनका काफी

प्रचार भी हो गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहिले कहा कि बहुत स शब्द श्राज जो ग्रप्रचितित हैं वह धीरे-धीरे प्रचित्त हो जायों।

हमको सभी स्वतंत्रता मिली है स्रौर हम एक बीच के मार्ग से गुजर रहे हैं इसलिय हमको थोड़ी हमको सभी स्वतंत्रता मिली है स्रौर हम एक बीच के मार्ग से गुजर रहे हैं इसलिय हमको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा । यह बात स्रवश्य है कि कानून की भाषा नहीं है जहां होता है जिसको हर एक नहीं समझ सकता है। हम देखते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जहां पर कानून की भाषा को हर एक समझ सकता हो, लेकिन "ला" में उनका प्रयोग होता है। हम लोग पर कानून की किताब के बहुत से शब्द नहीं समझ सकते हैं। उन शब्दों को स्रच्छी तरह से कानून का खुद कानून की किताब के बहुत से शब्द नहीं समझ सकते हैं। उन शब्दों को स्वलित हो ले लाजिए। यह शब्द जानने वाला हो समझ सकता है। उदाहरण के लिये स्राप एप्रोप्रिएशन बिल को हा ले लाजिए। यह शब्द जानने वाला हो समझ सकता में प्रचलित नहीं है। संस्कृत में भा हम को इसकी जगह पर कोई ऐसा सब्द नहीं मिलता है जो स्राम जनता में प्रचलित हो इतिलए हम को इसा शब्द को स्रथनाना पड़ा।

श्रुपनी भाषा को प्रचलित करने में राष्ट्र श्रुपना गौरव समझता है । बहुत से लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश को भाषा संस्कृत था, लेकिन राजनैतिक कारणों से श्रव उसका रिवाज उठ गया है श्रौर सैफड़ों वर्षों से उतका कोई प्रयोग नहीं करता है । श्रायरलैन्ड को एक पुराना भाषा श्रस्ं है, जिसको थोड़ से श्रादमो जानते थे। लेकिन उसा श्रम्स भाषा का वहां पर प्रचार किया गया। एक राष्ट्र के लिये यह गौरव की बात होतो है वह श्रुपना शान समझता है। श्राज बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हमको कठिन मालूम होते हैं, लेकिन समय के साथ-साथ वे हम को श्रासान मालूम होने लगेंगे।

इसके ग्रलावा एक चीज को ग्रीर ले लाजिये जैसे कि कार्रोरेशन शब्द है ग्रीर में नहीं जानता कि कापारेशन शब्द के सही-सही क्या अर्थ हैं, इस देश के शहरों के लोग या देहातों के लीग आमतौर से नहीं समझ सकते हैं और नेरा तो विचार है कि जो पढ़े-लिखे लोग है वह भी इसकी सही-सही न सम-झते होंगे। स्राज कई स्थानों ने कार्पोरेशन का काम होने जा रहा है, लेकिन में पूछता हूं कि स्राज हमारे यहां कितने श्रादमी ऐसे हैं जो कि स्युतिति मैलिटी श्रौर कार्पोरेशन में सही-सही भेद बता सकते हैं। लेकिन पुराने समय में भो कार्पोरेशन हुआ करते थे और उस समय उनको दूसरे नामों से पुकारा जाता था। गुप्त साम्राज्य जिसको कि इतिहासकार ''गोल्डेन एज'' भी कहते हैं उसे जमाने में भा देश का काम होता था और उस समय के अर्थशास्त्र शक नाति का संग्रह अब भा हमें देखने की मिलता ह। उस जमाने में भो म्युनितिपैलिटियां हुम्रा करती थीं भ्रौर उनकी बंड़ा-बंड़ा "श्रागेनाइजेशन" हुम्रा करती थीं। उनको भो सब-कनेटियां होता थीं ग्रौर उनके क्या-क्या ग्रिविकार होते थे, क्या-क्या "फंक्शन" होते थे इन सब का रिकार्ड इस समय भी देखने को मिलता है। तो ग्रगर हम उसमें से शब्दों को लेते हैं तो क्या बुरा करते हैं। चाह वह कितना ही पुराना शब्द हो, लेकिन वह उस जमाने का शब्द है जब कि इस देश में "लोकल बाडोज़" भा हुन्ना करता थीं, क पौरेशन हुन्ना करते थे श्रीर इस देश में प्रयना राज्य स्थापित था। स्रगर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम स्रच्छा ही करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह तो हमारा सम्बन्ध अपनी हमारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जोड़ता है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिये कि जो हमारी संस्कृति समाप्त हो चुका थी और जिसको हम लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं उससे फिर सम्बन्ध स्थापित करने का ग्रवसर मिला है तो यदि ग्रपनी पुराना सम्यता से हम ग्रपना संबंध स्थापित करने जा रहे हैं तो कौन-सा बुरा कर रहे हैं।

हम अपनी भाषा की क्लिब्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने व्यवहार के लिये हमें उन शब्दों को लाना होगा। जब हमारी भाशा को समस्या आती है तो इसके अलावा और चारा ही क्या रह जाता है? इसके अतिरिक्त हमें इन्टरनेशनल तरीका भी अपनाना पड़ता है, हमें बाहरी मुक्तों से अपना सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है। अभी कुछ वर्ष पहले टर्की और हिन्दुर नन में ट्राटी का प्रस्ताव हुआ जो कि हिन्दी भाशा में भी लिशी गई और हमने उसकी हिन्दी रूप दिया है। टर्का में और अंग्रेजों में उस को लिशा गया। जो हिन्दी में लिशा गया उसके लिये बहुत से प्राचान शब्दों का आसरा लिया गया, जो कि अन्तर्राब्दों को बों से शब्द मिले, उन्हों के आधार पर ट्रोटा लिशी गई।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

टिप्पण, ग्रालेखन तथा ग्रनुवाद

१--सामान्य

२-- डिप् स

३--ग्रालेखन ४---ग्रनु गद

भाग २

टिप्पण, ग्रालेखन तथा ग्रनुवाद

१--सामान्य

४२—प्रत्येक कार्यालय में, चाहे वह सरकारो हो स्रथवा स्यानीय निकाय का हो या किसी व्यापारिक संस्था का हो, टिप्पण तथा स्रालेखन का विशेष स्थान होता है। व्यापारिक संस्थाओं में टिप्पण कार्य प्रिक्षिक नहीं होता स्रोर कार्यकारी स्रिक्षकारी स्वयं स्रालेख्य तैयार कर लेते हैं, स्रलबत्ता टिप्पण सरकारी कार्यालयों का एक स्रभिन्न स्रंग होता है स्रोर उच्चतर कार्यालयों, जैते विभागाध्यक्ष तथा लोक सेवा स्रायोग के कार्यालय स्रोर सचिवालय में तो इस विषय का महत्व स्रोर स्रिक्षक बढ़ जाता है। इन कार्यालयों में स्रालेखन भी समानरूप से महत्व रखता है।

४३—िटिप्पण तथा आलेखन कला, श्रन्य कलाओं की तरह, निरन्तर श्रभ्यास तथा अनुरिक्त से ही श्राती है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पुस्तकों के श्रध्ययन से श्राये। हां, इस कला को सीखने में पुस्तकों से सहायता निस्तंदेह मिल सकता है, किन्तु आवश्यक यह है कि एकाप्रचित्त से इस कला का अभ्यास किया जाय। अतएव यहां टिप्पण तथा श्रालेखन के विषय पर स्थूलरूप से ही कुछ बातें बताई जा सकती हैं।

२--टिप्पण

५४—- ग्रधीनस्थ कार्यालयों में, सामान्यतया, टिप्पण-कार्य केवल सहायक कर्मचारिवर्ग ही करते हैं। वहां उनके द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियां पर श्रधिकारी केवल श्रादेश देते हैं। बड़े कार्यालयों में टिप्पण-कार्य केवल सहायक हो नहीं श्रपितु श्रधिकारी भी करते हैं, विशेषकर उन प्रकरणों में जो निर्णय के लिये उससे उच्च श्रधिकारियों के पास भेजे जाते हैं।

४५—िटप्पण का उद्देश्य उन बातों को, जिन पर निर्णय लेना होता है, स्पष्ट रूप से तथा तर्कानुसारेण प्रस्तुत करना है। साथ हो वह उन बातों को ग्रोर भी संकेत करता है जिनके श्राधार पर उक्त निर्णय सम्भवतः लिया जा सकता है। कुछ दशाश्रों में उसके इतिहास तथा उन परिस्थितियों पर, जिनके कारण वह वाद विषय उपस्थित हो गया है, प्रकाश डालना श्रावश्यक हो जाता है। टिप्पण में प्रश्न सम्बन्धो पूर्व दृष्टांत तथा पूर्व निर्णय भी दिये जा सकते हैं। उसमें वे नियम, जो उस पर लागू हो सकते हैं, देने होते हैं तथा प्रकरण सम्बन्धो नीति की ग्रोर भी संकेत करना होता है। यह सब इसलिये करना होता है जिससे कि श्रादेशाधिकारी को वाद विषय का पूर्ण ज्ञान हो जाय ग्रौर वह त्यायोचित श्रादेश दे सके।

४६—सामान्य प्रकार के प्रकरणों में कोई विस्तृत टिप्पणी लिखने की स्रावश्यकता नहीं होती। ऐसा प्रकरण संक्षिप्त टिप्पणी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है स्रौर कभी-कभी टिप्पणी के स्थान पर स्रालेख्य ही इस मुझाव के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है कि उसमें दी हुई बातों के स्राधार पर उस प्रकरण को निस्तारित किया जाय। ऐते प्रकरणों में, जिनका सम्बन्ध नई योजनास्रों से, नीति के प्रश्नों से स्रथवा जटिल समस्यास्रों से हो, विस्तृत टिप्पणियां लिखी जाती है स्रौर उनमें ही लेखक की योग्यता का परिचय मिलता है।

१७—किसी प्रकरण की यथार्थ प्रस्तुति, लेखक के व्यक्तित्व तथा मानसिक विकास पर निर्भर होती है। इस विषय पर काँई विशेष नियम या उपदेश नहीं है स्रोर न हो सकते हैं। इतना हो कहा जा सकता है कि प्रकरण को स्पष्ट रूप से निपुगता के साथ प्रस्तुत करना चाहिये जिससे कि स्रादेशाधिकारों को प्रकरण सम्बन्धी स्रावश्यक बातों को जानकारी हो जाय स्रौर वह यह भी जान जाये कि उसे सम्भवतः क्या करना होगा।

४८—ग्रलबत्ता कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें टिप्पणी लिखते समय नवच्छात्र ग्रपने ध्यान में रख सकते हैं:

- (१) टिप्पणी की भाषा संयत और विनीत होनी चाहिये चाहे उसमें श्रधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किसा प्रस्ताव को श्रालोचना करना श्रावश्यक हो क्यों न हो। टिप्पणी श्रीर ग्रालेख्य दोनों में श्रातशयोक्ति का प्रयोग दोष समझा जाता है और उस समय तक उसे प्रगुक्त न करना चाहिये जब तक कि किसो प्रसंग विशेष में ऐसा करना वास्तव में श्रावश्यक न प्रतीत हो।
- (२) टिप्पणी अकृतक भाव से लिखी जानी चाहिये। वस्तुतः टिप्पण-विषय में टिप्पणीक का कोई स्वार्थ निहित नहीं होता और इसिलये तर्कानुसारण आलोचना करते समय अथवा सुझाव देते समय उसे किसी दृढ़ोक्ति का प्रग्रोग न करना चाहिये जिससे यह समझा जाय कि वह उसमें अनुचित रूप से कोई दिलचस्पी रखता है। उसका कर्तव्य केवल न्यायोचित और पक्षपात रहित ढंग से प्रकरण के सभी दृष्टिकोणों पर अपने विचार प्रस्तुत करना है। पूर्व दृष्टांत देना है, उस विषय से सम्बन्धित विधि, नियमों तथा आजाओं का उल्लेख करना है और यह बताना है कि क्या वित्त विभाग अथवा किसी अन्य विभाग से कोई परामशं आवश्यक है, जिससे कि उच्च अधिकारी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। यदि टिप्पणीक द्वारा प्रस्तुत सुझाव के अनुसार अधिकारी निर्णय नहीं भी लेता तो इसके यह अर्थ नहीं होते कि टिप्पणी को वैवता दूषित हो गई है या टिप्पणीक की योग्यता पर कोई आक्षेप किया गया है। ऐसा उसी समय सम्भव है जबकि टिप्पणी अकृतक भाव से लिखी गई हो।
- (३) कभी-कभी टिप्पणी को कृतिपय उपभागों में विभाजित करना उपयोगी सिद्ध होता है। प्रत्येक उपभाग प्रकरण के किसी विशिष्ट दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। इस विभाजन कम की प्रयुक्ति विस्तृत टिप्पणी में सुविधाजनक पायी जाती है।
- (४) सामान्यतया यह देखा गया है कि यदि वाद प्रश्न टिप्पणी के प्रारम्भ में दे दिया जाय तो वाद के भागों को पूर्णकरण समझने में सहायता मिलती है। इसके विपरीत यदि वाद प्रश्न टिप्पणी के ग्रन्त में दिया जाय ग्रीश उसके प्रारम्भिक तथा मध्य भाग में वाद विषय के इतिहास का ही उल्लेख हो तो पाठक के लिये उस टिप्पणी का पूर्णतः समझना कष्टकर होता है। ग्रतएव ग्रच्छा होगा यदि टिप्पणी के प्रारम्भ में वाद विषय का उल्लेख हो, फिर उसमें प्रकरण का इतिहास दिया हो, तत्यश्चात् विभिन्न दृष्टिकोणों से उस पर प्रकाश डाला गया हो ग्रीर ग्रन्त में उसके विस्तारण के लिये विशिष्ट सुझाव दिये गये हों।

४६--टिप्पणो के सम्बन्ध में सामान्यतया निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखना उचित होगा :--

- (क) किसी भी टिप्पणी में प्रथम परिच्छेद को छोड़कर श्रन्य परिच्छेदों को संख्याबद्ध कर देना चाहिये। इससे श्रादेशाधिकारी को सहायता मिलती है क्योंकि वह प्रस्तावित परिच्छेद को देख कर ही टिप्पणी के किसी भी भाग का सुगमता से श्रवलोकन कर सकता है।
- (ख) निर्देश (ग्रर्थात् टिप्पणी में उद्धृत ग्रंश) टिप्पणी के पार्श्व में लिखते चाहिये न कि उसके मूल में। क्योंकि ऐसान करने से पाठक का ध्यान विषय से हट जाता है। इसी प्रकार पत्रावली के क्रमांकों या पतांकित पत्रों का निर्देश पार्श्व में देना चाहिये।
- (ग) टिप्पणी में किसी पत्र से परिच्छेद शब्दशः उद्धृत न किये जाने चाहिये जब तक कि मूत्र शब्दों की श्रोर विशिष्ट रूप से ध्यान श्राकृष्ट करने का श्रभिप्राय न हो।

(घ) टिप्पणो में किसी भी विषय का ग्रितिविस्तर उल्लेखन होना चाहिये ग्रौर न उसकी ग्राविक्यकता से ग्रिविक व्याख्या ही होनी चाहिये। दूसरे शब्दों में टिप्पणी में लेखन पद्धित को उपदेशक का रूप न ग्रहण कर लेना चाहिये। यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि उच्च ग्रिविकारों में तर्कानुसारेण प्रस्तुत विषय को ग्रच्छी तरह समझ लेने की बुद्ध तथा क्षमता होती है।

६०--इस विषय में ग्रौर ग्रनुदेशों के लिये वंभागिक सार संग्रहों को देखना चाहिये।

३---म्रालेखन

६१—शासकीय स्रालेखन स्रर्थात् स्राज्ञास्रों, प्रस्तावों, पत्रों, स्राख्यास्रों स्रादि के स्रालेख्य तैयार करना एक विशिष्ट कला है।

६२--- प्रालेख्य तैयार करने में निम्नलिखित बात सहायक सिद्ध होंगी :---

- (१) सर्व प्रथम उस विषय का प्रकार ग्रीर ग्राशय समझ लेना ग्रावश्यक है जिसके सम्बन्ध में ग्रालेख्य तै गर करना हो। ग्रालेख्य के प्रारम्भ में वाद-विषय को संक्षेप में दे देना, ग्रालेख्य तैयार करने वाले तथा पाठक दोनों के लिये ही, सुविधाजनक होता है। कभो-कभी विषय की विविधूर्वक रचना सरल नहीं होती ग्रीर उस दशा में ग्रालेख्य में वाद-विषय को उद्धृत न करने की सम्भावना बनो रहती है। किन्तु जैसा उत्पर कहा जा चुका है यदि वाद-विषय को प्रारम्भ में सुनिश्चित कर लिया जाय तो ग्रालेख्य तैयार करने में बड़ी सहायता मिलती है।
- (२) विशिष्ट प्रकार के भ्रालेख्यों को छोड़कर भ्रन्य भ्रालेख्यों को सामान्यतया तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, भ्रथात्—
 - (क) प्रथम भाग, जिसमें पूर्व पत्र-व्यवहार, यदि कोई हों, का निर्देश होता है या जिसमें तिक्षित रूप से विषय पुरःस्थापित किया जाता है जिससे कि पाठक ग्रालेख्य के कम का ग्रनुसरण कर सकें,
 - (ख) प्रकरण वक्तव्य, जिसमें व्यक्त विचारधारा के समर्थन में तर्क विये होते हैं,
 - (ग) निष्कर्ष, जिसमें सिफारिशें दी होती हैं।
- (३) सामान्य म्रालेख्यों का कई भागों में विभाजित करना म्रावश्यक नहीं है किन्तु लम्बे म्रालेख्यों को विशिष्ट वैभागिक शार्षकों में बांटना वांछनीय होगा। जिंदल म्रावश्य लम्बे म्रालेख्य के मन्त में उन बातों को संभेय में दे देना लाभकर होगा जिनकी सिफारिश की गई हो या जो विचारार्थ प्रस्तुत किये गये हों।
- (४) म्रालेख्य को सुविधानु कूल परिच्छे हों में विभाजित करना श्रेयस्कर होगा यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं है। म्रालेख्य का परिच्छे हों में विभाजन व्यवहृत विषय पर निर्भार है मौर यह हो सकता है कि उसी म्रालेख्य में कुछ परिच्छे हा लम्बे हों म्रोर कुछ छाड़े। विचारकन के म्रनुसार ही विषय परिच्छे हों में विभाजित किया जाता है।
- (प्र) प्रयन परिच्छेन को छोड़कर शेन को संख्याबद्ध करना हितकर होगा। श्रंत्रेनो के [(1), (b), (c)] त स्थान पर क,ल,ग......िललना चाहिये। इतो प्रतार (i), (ii) ग्रादि के स्थान पर (१), (२) लिखना श्रविक उपयुक्त होना। कृत्या इत सम्बन्ध ने तैंवियान का श्रनुच्छेन ३४८ देखिने।
- (६) स्त्रालेख्य को भाग संयत होनो चाहिये स्रोर उसमें स्रतिशयोक्ति का प्रयोग न होना चाहिये। यदि किसो बात पर जोर देना हो तो उसके समर्थन में तर्क देना चाहिये

या यह बताना चाहिये कि कोई विशेष बात करने अथवा न करने से क्या परि-णाम होंगे। दढ़ोक्ति तथा विशेषणों के प्रयोग का वहिष्कार करना चाहिये। उदाहरणार्थ वाक्य "यह अत्यन्त वांछनीय है कि पशुधन की गणना की जाय" के स्थान पर वाक्य "इन विचारों से यह वांछनीय प्रतीत होता है कि पशुघन की गणना की जाय" प्रयक्त करना भ्रधिक सन्दर होगा।

- (७) किसी प्रकरण में भ्रावेशाधिकारी ने श्रावेश देते समय जिस भाषा तथा वाक्य का प्रयोग किया हो या उच्चाधिकारी ने जो 'मिनट' लिखा हो उसकी भाषा को ग्रालेख्य में यथातमभव समाविष्ट करना चाहिये, यदि ऐता करना उचित प्रतीत हो।
- (प्) श्रालेख्य की भाषा ऐसी न होनी चाहिये कि उससे किसी भी प्रकार का मिण्या-बोध हो। साथ ही उसमें पुनरुक्तियों, ग्रतिरेक, वक्रोक्तियों ग्रथवा ग्रत्युक्तियों का कोई समावेश न होना चाहिये। उसमें लम्बे वाक्य भी न होने चाहिये।
- (E) स्रालेख्य की भाषा स्रपभंश शब्दों तथा वाक्यों से रहित होनी चाहिये।
- (१०) मूलपत्र का पृष्ठांकन सभी स्वच्छ प्रतियों पर व्यक्त होना चाहिये जिससे गृहीता को मालम हो सके कि किन-किन व्यक्तियों को उसकी प्रतियां भेजी गई हैं। यदि किसी प्रकरण विशेष में मुख्य गृहीता को यह सूचना देना उचित न जान पड़े तो ऐसा करने की भ्रावश्यकता नहीं है।
- म्रालेख्य में वे सभी संलग्न-पत्र दिये जाने चाहिये जो स्वच्छ प्रति के साथ भेजने हों। यदि स्रालेख्य के बीच में किसी संलग्न-पत्र का निर्देश हो (जैसा कि सर्वथा होगा) तो पाइवं में एक खड़ी रेखा खींचकर उसकी स्रोर ध्यान स्राकृष्ट करना चाहिये। स्वच्छ प्रति में टंकक उस पंक्ति के सामने जिसमें संलग्न पत्र का निर्देश किया गया है पार्क्व में एक बेड़ी रेखा खींच देगा। ग्रन्त में संलग्न-पत्रों की सूची दे देनी चाहिये।

४-- प्रनवाद

६३--हिन्दी के राजभाषा घोषित हो जाने के पश्चात् अब आशा यह की जाती है कि कर्म-चारिगण प्रवानत्रा हिन्दी में ही सोवेंगे श्रीर उती भाषा में श्रपने विचार व्यक्त करेंगे जिससे कि विचार में मौलिकता बनी रहे और भावों का ऋम टूटने न पाये। किन्तु ऐसे भी ग्रवसर श्रा सकते हैं जब किसी विशेष प्रयोजन के लिये अंग्रेजो से हिन्दी में भ्रतुवाद करता स्रतिवार्य हो जाय । ऐसी परिस्थिति में अनुवाद में कर्मचारियों को सावधानी रखने की आवश्यकता है।

(१) श्रनुवाद वस्तुतः वही श्रच्छा होता है जिसमें मूल की सब बातें ज्यों की त्यों ब्रा जायं। न तो मूल की कोई बात छूटने पाये और न बिगड़ने या बदलने पाये। जिस ग्रनुवाद में मूल के भावों का ग्रंग-भंग हुन्ना हो या उनका विकृत ग्रथवा ग्रस्पष्ट रूप उपस्थित किया गया हो वह ग्रच्छा नहीं कहा जा सकता।

(२) अनुवाद में दूसरा गुण यह होना चाहिये कि वह कहीं से अनुवाद न जान पड़े। इस सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र वर्मा द्वारा लिखित "ग्रच्छी हिन्दी" नामक पुस्तक

से निम्न उद्धरण देना उपयोगी होगा--

"जब हम अनुवाद करने लगते हैं तो प्रायः अपनी भाषा की प्रकृति की सत्ता या स्वरूप भूल जाते हैं। जिस भाषा से हम अनुवाद करते हैं वही भाषा हमें जिघर बहा ले जाती है उघर ही हम बह जाते हैं। उस दशा में पग-पग पर

हमारी दुर्बलता प्रकट होती है। स्रंप्रेजी में संसार भर की प्रायः सभी भाषास्रों के प्रयों के स्रतुवाद हैं। पर कोई स्रतुवाद देख कर हम सहसा यह नहीं कह सकते कि यह किस भाषा का स्रतुवाद है। उनकी वाक्य-रचना, किया प्रयोग, मुहावरे, भावव्यं जन की प्रणालियां स्रादि सभी स्वतंत्र स्रौर स्रपनी होती हैं स्रौर यही वे सब तत्व हैं जो किसी स्रतुवाद की उत्तनता प्रकट करते हैं।

- (३) अनुवाद अस्पष्ट अथवा भ्रामक न होना चाहिये। उसका स्राशय या भाव विशद होना चाहिये।
- (४) अनुवाद की वाक्य-रचना अथवा भाव-व्यंजन की प्रणाली मूल को दृष्टि में रखते हुय होना चाहिये।
- (५) अनुवाद करते समय केवल मूल के शब्दों श्रौर शब्दार्थों पर ही नितान्त ध्यान नहीं देना चाहिये। शब्दों के स्थान पर शब्द श्रौर वाक्यों के स्थान पर वाक्य विना समझे न रखना चाहिये। उनका भावार्थ भी समझना चाहिये। उदाहरणार्थ 'Trans'er' के दो श्र्यं होते हैं, 'हस्तांतरण' श्रौर 'स्थानान्तरण'। पहले का सम्बन्ध सम्पत्ति श्रादि से श्रौर दूसरे का बदली से होता है। इसी प्रकार 'Flying visit' का अनुवाद "हवाई जहाज से जाना" करना श्रशुद्ध होगा तथा 'White ants' को 'सफेद चोंटी' कहना हास्यास्पद होगा।
- (६) प्रत्येक भाषा की एक स्वतंत्र प्रकृति होती है ग्रौर उसमें भाव-व्यंजन की विशिष्ट प्रणाली होती है। ग्रतएव ग्रंपेजी से हिन्दी में ग्रनुवाद करते समय हिन्दी भाषा की ही प्रणाली का ग्रनुसरण करना चाहिये।
- (७) अनुवाद करते समय अंग्रेजी की कियायें, किया-प्रयोग श्रीर मुहावर भी ज्यों के त्यों न ले लेना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से प्रायः अनुवाद दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ यह वाक्य कि ''इंजन के बाद वाला डिब्बा टेलेंस्कोप की तरह चकनाचूर हो गया'' अशुद्ध है।
- (८) ग्रनुवाद करते समय ग्रावश्यकता तथा सुविधानुसार वाक्यों को तोड़ा ग्रथवा घटाया-वढ़ाया जा सकता है।
 - (६) जहां तक ग्रिधिनियमों, नियमों, विधि ग्रादि का सम्बन्ध है, उनका शब्दशः ग्रनुवाद करना ग्रावश्यक है।

६५-- कुछ अनुवाद के नमूने दिये जाते हैं जो उपयोगी सिद्ध होंग :

(Seal of the Government of India)

BY VIRTUE of the power vested in me by Section 48 of the Government of India Act, 1935, I, Chakravarti Rajagopalachari, Governor General of India, do hereby appoint Shri HormasJi Peroshaw Mody to be Governor of the United Provinces with all the powers, rights, privileges and advantages to the said office belonging or appertaining.

II. And I do hereby further authorize and direct the said Shri Homasji Peroshaw Mody to cause this Order to be read and published in the presence of the Chief Justice or in his absence other Judge of the High Court of the Province.

III. And I do hereby further authorize and direct the said Shri Hormasji Peroshaw Mody to take the Oath of Allegiance and for the due execution of the Office of Governor of the United Provinces and for the due and impartial administration of justice, in the form hereto appended, which oath the Chief Justice or in his absence any Judge of the High Court, shall, and is hereby required to, tender and administer to him.

IV. And I do hereby further authorize and require the said Shri Hormasji Peroshaw Mody by himself, or by any other person to be authorized by him in that behalf, to administer to every person appointed by him to hold office as a Minister the oaths of office and of secrecy hereto appended.

V. And I do further direct that every person who under this Order shall be required to take an oath may make an affirmation in place of an oath if he has any objection to making an oath.

Given at Government House, New Delhi, this eighteenth day of April in the year one thousand nine hundred and forty-nine.

Seal

C. RAJAGOPALACHARI, Governor General of India.

JAWAHARLAL NEHRU,

Prime Minister.

(गवर्नमेंट श्राफ इंडिया की मोहर)

गवर्नमेंट स्नाफ इंडिया एक्ट, १६३५ की घारा ४८ स दिय गय स्रिधकार क बमूजिब में, चक्रवर्ती राजगोतालाचारी, गवर्नर जनरल, इस स्नाज्ञा से श्री होरमसजी पेरोशा मोदी को युक्त प्रांत का गवर्नर नियुक्त करता हूं। उन्हें इस पद की या इससे संबंध रखने वालो सब शक्तियां, स्निधकार, विशेष स्निधकार और सुविधार्य मिलेंगी।

२--ग्रौर में इस ग्राज्ञा से श्री होरमसजी पेरोज्ञा मोदी को यह भी ग्रधिकार दता हूं ग्रौर ग्रादेश करता हूं कि वे प्रात के चीफ जस्टिस के या उनक न होने पर हाई कोर्ट के दूसरे जज क साजने इस ग्राज्ञा को पढ़वार्ये ग्रौर प्रकाशित करायें।

३---ग्रौर मैं इस ग्राज्ञा से श्री होरमसजी पेरोज्ञा मोदी को यह भी श्रिधिकार देता हूं श्रौर ग्रादेज्ञ करता हूं कि वे साथ में लगे हुये फार्म के ग्रनुसार राजनिष्ठा की ग्रौर युक्त प्रान्त के गर्वार के पद का काम उचित रीति से करने ग्रौर उचित ग्रौर बिना भेद-भाव के न्य य करने की ज्ञापथ लें। यह ज्ञापथ चीफ जिल्दिस या उनके न होने पर हाई कोर्ट के कोई दूसरे जज उनके सामने पेज्ञ करेंगे श्रौर दिलायेंगे ग्रौर इस ग्राज्ञा से उनको भी ऐसा करने का ग्रादेश दिया जाता है।

४--- श्रौर में इस श्राज्ञा से श्री होरमसजी परोज्ञा मोदी को यह भी श्रधिकार दता हूं श्रौर श्रादेश करता हूं कि वे स्वयं या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जिसे वे इसका श्रधिकार दें, हर एक व्यक्ति को जिन्हें वे मिनिस्टर के पद पर नियुक्त करें साथ में लगे लेखों के श्रनुसार पद श्रौर रहस्य-रक्षा की शपथ दें या विलायें।

५--ग्रौर में यह भी ग्रादेश देता हूं कि ग्रगर किसी व्यक्ति को जिस इस ग्राज्ञा क बमूजिब द्यापथ लेना ग्रावश्यक हो, शपथ लेने में ग्रापत्ति हो तो शपथ की जगह वह प्रतिज्ञा कर सकता है।

यह ग्राज्ञा-पत्र गवर्ननेंट हाउस, नई दिल्ली में १८ ग्रप्रैल सन् १९४९ ई० को दिया गया।

(मोइर)

सी० राजगोपालाचारी, इंडिया के गवर्नर जनरल ।

जवाहरताल नेहरू, प्रधान मंत्री । CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

WARRANT OF THE PRESIDENT OF INDIA APPOINTING SRI K. M. MUNSHI TO BE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH

BY VIRTUE of the power vested in me by Article 135 of the Constitution of India, I, Rajendra Prasad, President of India, hereby appoint SRI KANIALAL MANEKLAL MUNSHI to be Governor of Uttar Pradesh in succession to Sri Hormasji Peroshaw Mody.

Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this twenty-fourth day of May in the year one thousand nine hundred and fifty-two.

RAJENDRA PRASAD, President of India.

भारत के राष्ट्रपति का श्री कनैयालाल माणिकलाल मुन्शी को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त करने के श्रधिपत्र का हिन्दी रूपान्तर

--:0:--

भारत के संविधान के ग्रनुच्छेद १३५ द्वारा मुझ में निहित शक्ति के ग्राधार पर मैं, राजेन्द्र प्रसाद, भारत का राष्ट्रपति, श्री होरमसजी पेरोशा मोदी के उत्तराधिकार में श्री कनैयालाल माणिकलाल मुन्शो को एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करता हूं।

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, में दिनांक २४ मई सन् एक हजार नौ सौ बावन को दिया गया।

राजेन्द्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति । भाग ३

परिशिष्ट

भाग इं

परिशिष्ट १

(जिसका उल्लेख पैराग्राफ ४६ में किया गया है।) हिन्दी के विशेष परिपत्र प्रर्थात :

१--संख्या ४६८६/३--१७०-४७, दिनांक ८ ग्रवतूबर, १६४७। २--संख्या ६४६४/३--१७०(७)-१६४२, दिनांक २६ ग्रवतूबर, १६४२। ३--संख्या ११८७६/३--१७०(२२)-१६४४, दिनांक १ दिसम्बर, १६४४ (१)

परिपत्र संख्या ४६८६/३---१७०-४७

प्रेषक,

श्री बी॰ एन॰ झा, श्राई॰ सी॰ एस॰, चीफ सेकेटरी, संयुक्त प्रान्तीय सरकार ।

सेवा में,

संयुक्त प्रान्त के समस्त विभागों के ग्रध्यक्ष, डिवीजनों के किमश्नर, जिला ग्रकसर तथा ग्रन्य प्रमुख दफ्तरों के ग्रधिकारी। लखनऊ, द ग्रक्तूबर, १६४७ ई०।

विषय--देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को संयुक्त प्रान्त की राज्य भाषा स्वीकृत करने का निर्णय।

महोदय,

प्रशासन प्रशासन विभाग मुझे श्रापको यह विदित करने का श्रादेश हुश्रा है कि संयुक्त प्रान्तीय लेजि-स्लेटिव काउन्सिल के पिछले श्रधिवेशन में स्वीकृत निम्नलिखित गैर-सरकारी प्रस्ताव को सरकार ने मान लिया था:—

"यह काउन्सिल सिफारिश करती है कि हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि को इस प्रान्त की राजभाषा तथा लिपि स्वीकार किया जाय।"

सरकार से इस प्रस्ताव को स्वीकृत हो जाने से श्रब इसकी सिद्धि के लिये श्रावश्यक कार्रवाई करनी है।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि यह कार्रवाई इस प्रकार की जाय कि परिवर्तन-काल में बेकार ग्रव्यवस्था न होने पावे ग्रौर ग्रसुविघा भी कम से कम हो। जो कार्रवाई तुरन्त करनी है उसका निर्वेश ग्रागे के पैराग्राफों में किया गया है।

२--इस पत्र में आगे चल कर "हिन्दी" शब्द के प्रयोग से अभिप्राय उस भाषा से हैं जो संयुक्त प्रान्त की जनता की भाषा है और जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ३—सरकारी नौकरियों में भर्ती:—भविष्य में सरकारी नौकरियों में भर्ती करते समय यदि और बातें समान हों, तो उन उम्मीदवारों को विशेषता दी जायगी जिनको हिन्दी में काम करने का जान होगा। यदि किसी पद के लिये साक्षरता की योग्यता जरूरी है तो उस पद पर कोई ऐसा उम्मीदवार जो हिन्दी नहीं जानता अथवा जो देवनागरी लिपि में काम नहीं कर सकता, नियुक्त न किया जायगा। यदि असाधारण परिस्थित में किसी ऐसे उम्मीदवार को भर्ती करना अनिवार्य हो जो हिन्दी नहीं जानता तो नियुक्त करने वाले अफतर को उस विशेष परिस्थित को लिपिबढ़ करना होगा और उस उम्मीदवार का चुनाव कच्चे तौर पर होगा। ऐसी दशा में उम्मीदवार को साफ-साफ यह सूचित कर दिया जायगा कि उस पद पर उसकी पक्की नियुक्त एक अविध के बाद होगी। यह अविध ६ महीने से अधिक न होगी और इस समय के अवदर उसके लिये यह जरूरी होगा कि वह इतनी हिन्दी सीख ले कि वह सरलतापूर्वक और वेरोकटोक लिख पढ़ सके। ऐसे उम्मीदवार को उसके पद पर नियुक्त करने की अनुमति देने के पूर्व उससे इस आश्राय की एक प्रतिज्ञा लिखा ली जायगी। निर्धारित अविध के बाद उसकी परीक्षा ली जायगी और यदि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो उसकी कच्ची भर्ती रद्द कर दी जायगी, परन्तु ऐसा करने के पूर्व अविध ४ मास तक और बढ़ाई जा सकती है।

सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिये जो परीक्षायें श्रभी तक निर्धारित हैं, उनमें हिन्दी को एक ग्रनिवार्य विषय बनाने के लिये कार्रवाई की जायगी। इसके निमित्त सरकारी विभागों के श्रध्यक्षों को चाहिये कि जिन-जिन नौकरियों से उनका सम्बन्ध है उनके लिये वह सरकार को श्रथने निश्चित प्रस्ताव भेज दें।

४—वर्तमान सरकारी कर्मचारी— प्रापके प्रयोग वर्तमान सभी सरकारी कर्मचारियों को यह सूचना दे देनी चाहिये कि हिन्दी अब प्रान्त की राज भाषा स्वीकार हो गई, इससे अन्ततः सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने सरकारी काम में हिन्दी ही का प्रयोग करना होगा, तथा जब तक और आदेश जारी नहीं होते तब तक उन कर्मचारियों के लिये, जो इस भाषा को या तो जानते नहीं या कम जानते हैं, यह अच्छा होगा कि वह अपने खाली समय में इस भाषा को सीखना शुरू कर दें। इस विषय पर आगे चल कर आपकों विस्तारपूर्वक संदेश भेजा जायगा, किन्तु इस बीच में हर एक दफ्तर के अफतर को चाहिये कि तीन महीने के अन्दर अपने दफ्तर के सब सरकारी कर्मचारियों की ऐसी गणना कर लें जिससे यह विदित हो जाय कि उनमें से कितने इतनी काफी हिन्दी जानते हैं कि अपना वर्तमान काम हिन्दी में कर सकते हैं। सूचना-संग्रह का काम फौरन शुरू कर देना चाहिये। इसके लिये हर एक दफ्तर के कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करना चाहिये—

- (क) पहिले जो सेकेटरी आफ स्टेट की सर्वितेज कहलाती थीं, उनके ग्रौर प्रथम क्लास सर्वितेज के सदस्य,
 - (ख) प्राविशियल सिवसेज के सदस्य,
 - (ग) अपर सर्वाङिनेट एक्जीक्यूटिव सर्विसेज के सदस्य,
 - (घ) लोग्रर सर्वाडिनेट एक्जीक्यूटिव सर्विसेज के सदस्य,
 - (ङ) स्पेशलिस्ट सर्विसेज के सदस्य, ग्रौर
 - (च) मिनिस्टीरियल कर्मचारी।

एक सूची में प्रत्येक कर्मचारी का नाम ग्रौर पद लिखा जायगा ग्रौर उसके सामने एक कालम में यह बात लिख दी जायगी कि उक्त कर्मचारी को हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान है या नहीं। यह सूची तीन भागों में होनी चाहिये। पहले भाग में उन कर्मचारियों के नाम होंगे जिन्हें हिन्दी का पूर्ण ज्ञान है, दूसरे भाग में उन लोगों के नाम होंगे जिन्हें काम चलाऊ ज्ञान है ग्रौर तीसरे भाग में उनक नाम होंगे जो हिन्दी बिल्कुल नहीं जानते। सरकारी कर्मचारियों के लिये विभागों की परीक्षात्रों के नियमों में हिन्दी को ग्रव एक ग्रनिवार्य विषय बनाने की कार्रवाई की जायगी। विभागों के ग्रध्यक्षों को चाहिये•िक जिन नौकरियों से उनका सम्बन्ध हो उनके लिये इसके निमित्त सरकार को ग्रपने निश्चित प्रस्ताव भेज दें।

५--- श्रदालतों की भाषा-- (१) प्रान्तीय सरकार हिन्दी को इस प्रान्त की दीवानी और फौजदारी श्रदालतों की भाषा घोषित करने के लिये जाब्ता दीवानी की धारा १३७ श्रौर जाब्ता फौजदारी की धारा ५५८ में दिये गये श्रधिकारों के श्रनुसार कार्रवाई कर रही है। विज्ञप्तियों की प्रतिलिपि सम्बद्ध है।

- (२) सन् १६३६ के संयुक्त प्रान्तीय टेनेन्सी ऐक्ट की २४३वीं धारा के अनुसार उस ऐक्ट की कार्रवाइयों पर जाब्ता दीवानी लागू है, अतएव यह विज्ञिप्तयां टेनेन्सी ऐक्ट की कार्रवाइयों पर स्वतः लागू होंगी। लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अवीन कार्रवाइयां हिन्दी में कराने के लिये भी कार्रवाई की जायगी।
- (३) मैनुग्रल ग्राफ गवर्नमेंट ग्रार्डर्स प्रथम भाग का पैराग्राफ ३८४ संशोधित होकर ग्रव निम्नलिखित रूप में होगा—
 - ''(क) जनता के नाम श्रदालतों या माल के श्रफसरों की श्रोर से जारी किये जाने वाले सभी सम्मन, घोषणा श्रौर इस प्रकार के श्रन्य कागज देवनागरी लिपि में होंगे।
 - (ख) फौजदारी, दीवानी तथा लगान भ्रौर मालगुजारी की भ्रदालतों में सब लोग भ्रपने प्रार्थना-पत्र भ्रथवा शिकायतें देवनागरी लिपि में, भ्रौर यदि वे हिन्दी न जानते हों तो फारसी लिपि में दे सकेंगे।"
- (४) जब तक उपर्युक्त विज्ञिष्तियों को वास्तिविक ग्रौर पूर्णरूप से कार्यान्वित करने के लिये ज्यापक प्रवन्ध नहीं कर लिया जाता तब तक हिन्दी न जानने वाले विचारपित तथा ग्रन्य कर्मचारी, जब तक दूसरी ग्राज्ञा न निकले तब तक, उसी तरह ग्रदालती कार्रवाइयों को लिख सकते हैं जिस तरह वे ग्रव तक वर्तमान कानून ग्रौर नियमों के ग्रनुसार लिखते ग्राये हैं। हिन्दी के प्रयोग में सम्प्रति इस बात की ग्रनुमित रहेगी कि ग्रंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द नागरी या रोमन लिपि में लिखे जायं।

इस उप-पैराग्राफ पर सन् १६०८ के जाब्ता दीवानी की १३८ वीं घारा श्रौर सन् १८८७ के अवध लाज ऐक्ट की १६वीं घारा के प्रतिबन्ध लागु हैं।

६--सरकारी दफ्तरों की भाषा--(१) ग्रब से सरकारी कामों ग्रौर पत्र-व्यवहार के लिये सरकारी दफ्तरों की मान्य भाषा हिन्दी होगी।

जब तक इस आदेश को वास्तविक और पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने का विस्तृत प्रबन्ध न कर लिया जायगा तब तक हिन्दी न जानने वाल सरकारी कर्मचारी और वे, जिनके लिये हिन्दी प्रयोग करने का प्रबन्ध पूरा न हो पायेगा, उस भाषा का प्रयोग कर सकेंगे जिसका व्यवहार वे इस स्राज्ञा के निकलने के पहिले करते रहे हैं।

- (२) सरकारी दपतरों को पत्र हिन्दी में लिखे जायंगे। जो हिन्दी नहीं जानते उन्हें श्रंग्रेजी या उर्दू में पत्र-व्यवहार करने की श्रनुमृति रहेगी।
- ७--छपे हुए फार्म--पहिली दिसम्बर सन १६४७ से सभी फार्म हिन्दी में छापे जायेंगे। जो फार्म किसी श्रन्य भाषा में छपे हुए रखे हैं, उनका प्रयोग होता रहेगा। किन्तु हिन्दी जानने वाले कर्मचारी उन्हें हिन्दी में परिवर्तित कर लेंगे।

द-विविध-सरकारी दपतरों के सभी साइन बोर्ड, नोटिस इत्यादि जो आज कल हिन्दी मे नहीं है, यथाशीच्र हिन्दी में कर दिये जायं।

> ग्रापका परम विनीत सेवक. बी० एन० झा, चीफ सेकेटरी।

संख्या ४६८६ (१)/३--१७०-४७

- (१) रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट ग्राफ जुडीकेचर, इलाहाबाद ग्रवध चीफ कोर्ट. लखनऊ
 - (२) सेकेटरी, पब्लिक सर्विस कमीशन,

को यह प्रतिलिपि इस ग्राग्रह के साथ भेजी जाती है कि यदि (१) माननीय कोर्ट को ग्रापत्ति न हो तो अपने अधीनस्य कर्मचारियों के लिये उपरोक्त प्रकार के उचित आदेश, जहां तक लागू हो सकते हों, कृपया जारी कर दें।

संख्या ४६८६ (२)/३--१७०-४७

हर एक्सेलेंसी गवर्नर के सेकेटरी को यह प्रतिलिपि इस ग्राग्रह के साथ भेजी जाती है कि हर एक्सेलेंसी की श्रनुमित से उपरोक्त प्रकार के ग्रादेश, जहां तक लागू हो सकते हों, हर एक्सेलेंसी के सेकेटेरियट ग्रौर उनके निजी कर्मचारियों के लिये जारी कर दिये जाये।

संख्या ४६८६ (३)/३--१७०-४७

प्रतिलिपि सेक्टेरियट के सभी विभागों को स्रावश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

संख्या ४६८६ (४)/३--१७०-४७ संयुक्त प्रान्त के एकाउन्टेन्ट जनरल को भी प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या ४६८६ (४)/३--१७०-४७ (१) संयुक्त प्रान्त के सभी म्युनिसियल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी श्रौर नोटीफाइड एरिया कमेटी के चेयरमैनों,

(२) लखनऊ ग्रौर इलाहाबाद के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के चेयरमैनों, (३) कानपुर डेंबलपमेंट बोर्ड के प्रेसीडेंट को भी एक प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।

बो॰ एन॰ झा,

विज्ञिष्तयों की प्रतिलिपि

[देखिये पैराम्राफ ४ (१)]

[संख्या ४६८६(६)/३--१७०-४७, तारीख ८ प्रक्तूबर, १६४७, सामान्य प्रशासन विभाग]

संयुक्त प्रान्त की गवर्नर उन श्रिधिकारों के अनुसार जो उन्हें जाब्ता दीवानी १६०८ (ऐक्ट ५, सन् १६०८ का) की घारा १३७ की उपघाराश्रों (१) ग्रौर (२) से प्राप्त हैं, तत्सम्बन्धी ग्रन्य पूर्व घोषणात्रों को रद्द करके, यह घोषित करती है कि इलाहाबाद स्थित हाई कोर्ट ग्राफ जुडिकेचर तथा श्रवध के चीफ कोर्ट के श्रधीनस्थ दीवानी श्रदालतों की भाषा हिन्दी होगी श्रौर इन श्रदालतों में जो श्रावेदन पत्र दिये जायंगे श्रोर जो कार्रवाइयां होंगी उन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि वर्तमान कानून और नियमों के अनुसार ऐसी भाषा या लिपि का प्रयोग, जो इस समय व्यवहार में त्रा रही है, करते रहने की अनुमति उन शासन त्रादेशों के अनुसार रहेगी जो प्रान्तीय सरकार समय-समय पर जारी करे।

> बी० एन० झा, चीफ से केटरी।

(२) [संख्या ४६८६(७)/३--१७०-४७, तारील ८ ग्रक्तूबर, १६४७, सामान्य प्रशासन विभाग]

संयुक्त प्रान्त की गवर्नर उन ग्रधिकारों के ग्रनुसार जो उन्हें जाब्ता फौजदारी, १८१८ (ऐक्ट ५, सन् १८६८ का) की ४४८ वीं धारा से प्राप्त हैं, यह घोषणा करती है कि तत्सम्बन्धी अन्य पूर्व घोषणाओं को रद्द करते हुये उपरोक्त जाब्ते के प्रयोजन के लिये संयुक्त प्रान्त की सरकार द्वारा शासित प्रदेशों के अन्तर्गत, संशोधित गवर्नमेंट श्राफ इन्डिया ऐक्ट, सन् १९३५ के अर्थ में जो हाई कोर्ट हैं उन अदालतों के अतिरिक्त, प्रत्येक अदालत की भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी मानी जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि वर्तमान कानून और नियमों के अनुसार ऐसी भाषा या लिपि का प्रयोग, जो इस समय व्यवहार में थ्रा रही है, करते रहने की श्रनुमति उन शासन श्रादेशों के श्रनुसार रहेगी जो प्रान्तीय सरकार समय-समय पर जारी करे।

that we take to some anticipated in pass of from configurations.

बी० एन० झा, चीफ सेकेटरी।

88

(2)

संख्या ६४६४/३--१७०(७)-१६४२

प्रेषक,

श्री भोलानाथ झा, ग्राई० सी० एस०,

चीफ सेकेंटरी,

उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में

उत्तर प्रदेश के सब विभागों के ग्रध्यक्ष, डिवीजनों के कमिश्नर,

जिला श्रफसर ग्रौर ग्रन्य प्रमुख दफ्तरों के ग्रधिकारी।

दिनांक लखनऊ, २६ श्रक्तूबर, १६५२ ई०।

विषय—देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में

महोदय,

सामान्य प्रशासन विभाग

श्रवतुबर सन् १६४७ में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिन्दी को इस राज्य की राजभाषा मान लिया था। इस निर्णय को श्रमल में लाने के लिए इस विभाग के सर्कुलर नं० ४६८६/३—–१७०–४७, दिनांक ८ श्रवतुबर, १६४७ में विस्तार पूर्वक श्रादेश जारी किये गये थे। उस समय से श्रव तक इस विषय में काफी उन्नति हो गई है और स्थिति में भी कुछ बदलाव हो गया है जो इस तरह है:

- (१) उस सर्कुलर में यह बताया गया था कि कार्यवाही इस ढंग से की जाये कि परिवर्तनकाल में काम में खराबी न होने पाये और सुविधा भी कम से कम हो। सर्कुलर को जारी हुये पांच साल हो गये हैं, तब से समय-समय पर इस विषय में आदेश भेजे गये हैं और उन पर आपने कार्यवाही भी की है। सरकार को खास तौर पर इस बात का ध्यान रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो हिन्दी नहीं जानते हैं या अच्छी तरह नहीं जानते उनको उसे सीखने के लिये काफी समय दिया जाय। इस सम्बन्ध में जो जानकारी विभागों से मिली है उससे यह मालूम होता है कि इस समय लगभग दो फीसदी सरकारी नौकरों को छोड़ कर सभी कर्मचारी हिन्दी सीख गये हैं।
- (२) इस प्रदेश की विधान सभा में सब काम हिन्दी में ही होने लगा है। इस सम्बन्ध में विधान मंडल ने फरवरी सन् १९५० ई० में एक ग्रिधिनियम (Act) भी पास किया था जिसका नाम Uttar Pradesh Language (Bills and Acts) Act, 1950 है।
- (३) हिन्दी के ऐसे कोष भी जिनमें श्रंग्रेजी के पारिभाषिक (technical) ग्रौर कानूनी शब्दों का सही उल्था हो, बनाने की व्यवस्था सरकार ने की है । कुछ कोष छप भी चुके हैं।
- (४) भारत के संविधान के ग्रनुच्छेद (article) ३४५ में ग्रन्य वातों के ग्रनावा यह लिखा गया है कि राज्य का विधान मंडल राज्य के सभी या किसी सरकारी काम के लिये हिन्दी के उपयोग को कानूनी बनाकर कायम कर सकता है। इस ग्रनुच्छेद (article) के ग्रन्तर्गत प्रदेश के विधान मंडल जे

सन् १६५१ में एक ग्रधिनियम (Act) बनाया है जिसका नाम उत्तर प्रदेश. राजभाषा ग्रधिनियम (Act), १६५१ है ग्रौर जो १२ नवम्बर, १६५१ से लागू हुग्रा है। इसकी एक प्रति नत्थी "क" में इसके साथ है। इस ग्रधिनियम (Act) की धारा २ के ग्रनुसार सरकार को एक विज्ञिष्त निकालनी है। जब वह विज्ञिष्त निकल जायेगी तो जो कुछ काम उस विज्ञष्ति के ग्रनुसार होगा वह हिन्दी भाषा में होगा। इस विज्ञष्ति के निकालने के लिये कार्यवाही हो रही है ग्रौर ग्रलग से ग्रापके पास ग्रादेश पहुंचेंगे।

२—इस पत्र में तो केवल वह हिदायतें हैं जिनके निकालने के बारे में मुख्य मंत्री ने विधान-सभा में तारीख ४ सितम्बर, १६५२ को एलान किया था कि सब सरकारी काम जहां तक मुमिकन होगा हिन्दी में ही होगा। नीचे लिखी हिदायतें उसी के ग्रनुसार हैं:

- (१) उन मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अनुच्छेद (article) ३४६ अरैर ३४७ के अनुसार दूसरी भाषा में काम होने की व्यवस्था है सब मामलों में, जहां तक संभव हो, हिन्दी में ही काम किया जाय। इन अनुच्छेदों (articles) की प्रतिलिप इस पत्र के अन्त में नत्थी "ख" में दी गई है।
- (२) जिन कर्मचारियों ने ग्रभी तक हिन्दी में काम करने की योग्यता प्राप्त नहीं की है वे कुछ समय तक ग्रंग्रेजी में काम कर सकते हैं लेकिन उन्हें जल्दी ही काम करने लायक हिन्दी सीख लेगी चाहिए। इस पत्र की तिथि से ६ महीने के बाद ही सरकार को उन कर्मचारियों के नाम इत्यादि भेजे जावें जो उस समय तक हिन्दी न सीख सके हों। हिन्दी सीखने के लिये इस पत्र की तिथि से एक वर्ष से ग्रधिक समय ग्रब न दिया जायेगा।
- (३) हिन्दी में काम करने के लिये हिन्दी टाइपराइटरों की भी स्रावश्यकता होगी। कुछ हिन्दी टाइपराइटर तो खरीद लिये गये हैं, स्रब से जो टाइपराइटर खरीदे जायं वे हिन्दी के ही हों। इस तरह से हिन्दी टाइपराइटरों की कमी धीरे-धीरे पूरी हो जायेगी।
- (४) इसी प्रकार स्टेनोग्राफरों ग्रौर हिन्दी टाइपिस्टों की भी ग्रावश्यकता पड़ेगी। जो ग्रंग्रेजी के स्टेनोग्राफर इस समय काम कर रहे हैं उनमें से कुछ ने हिन्दी शार्टहैंड भी सील लिया है। बाकी स्टेनोग्राफर हिन्दी शार्टहैंड सील रहे हैं ग्रोर ग्राशा की जाती है कि शोध्र ही वे हिन्दी शार्टहैंड में पूरी तौर से काम कर सकेंगे। यही स्थित टाइपिस्टों के विषय में भी है, ग्रव से जो भी स्टेनोग्राफर ग्रौर टाइपिस्ट भर्ती किये जायं वे प्रधानतया हिन्दी के स्टेनोग्राफर ग्रौर हिन्दी के टाइपिस्ट होने चाहिए।
- (प्र) हिन्दी के माने उस सरल जवान से है जो देश में श्रौर इस प्रदेश में बोली जाती है। लिपि नागरी होगी श्रौर जवान श्रासान श्रौर सरल होगी। पारिभाषिक (technical) शब्द नागरी या रोमन लिपि में लिखे जा सकते हैं।
- (६) ग्रदालतों की भाषा के संबंध में प्र ग्रक्तूबर, १६४७ के सर्कुलर के पैराग्राफ ५ में कुछ हिदायतें लिखी गृई थीं। इस सिलसिले में ग्रौर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए इस सवाल पर विचार हो रहा है।

३--सरकार को ग्राशा है कि इन हिदायतों के ग्रनुसार स प्रदेश में सभी काम शीघ्र ही हिन्दी में होने लगेंगे।

86

४--इस सर्फुलर का श्रृंग्रेजी उल्या (version) इसके साथ है।

भवदीय, भोला नाथ झा, चीफ सेक्रेटरी।

संस्था ६४६४ (१)/३--१७० (७)--१६५२ प्रतिलिपि सिचवालय के सब विभागों को स्रावश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

संख्या ६४६४ (२)/३--१७० (७)-१६५२ उत्तर प्रदेश के एकाउन्टेन्ट जनरल को भी प्रतिलिपि सुचनार्थ प्रेषित ।

> ग्राज्ञा से, भोला नाथ झा, चीफ सेकेटरी, उत्तर प्रदेश।

819

शंख्या ११८७६/३--१७० (२२)-१६४५

प्रेषक,

श्री प्रादित्यनाथ झा, श्राई० सी० एस०,

मस्य सचिव .

सेवा में,

उत्तर प्रदेश शासन ।

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष , डिवीजनों के किमश्नर तथा कलेक्टर इन्चार्ज, झांसी डिवीजन ग्रौर डिप्टी कमिश्नर इन्चार्ज, कुमायूं डिवीजन, जिलाधीश, जिला जज ग्रौर ग्रन्य प्रमल कार्यालयों के ग्रधिकारी।

लखनऊ, दिनांक १ दिसम्बर, १९४४

विषय: राजकीय कार्यों में हिन्दी की प्रगति।

महोदय,

देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को इस राज्य की राजभाषा घोषित हुए स्राठ वर्ष से सामान्य ग्रधिक हो गये हैं। यह घोषणा परिपत्र संख्या ४६८६/३--१७०-४७, दिनांक ८ ग्रक्तूबर सन् १६४७ को की गयी थी। तदन्तर समय-समय पर इस घोषणा को कार्यान्वित करने के लिये आदेश विभाग भेजे गये। अन्तिम ब्रादेश परिपत्र संख्या ८०७०/३--१७० (६)-१६५५, दिनांक ११ जुलाई, सन् १६५५ में मिलेगा।

२--इन ग्रादेशों के ग्रन्सार सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग होने लगा है ग्रौर सरकार के पास आये हुए विवरण-पत्रों से जात होता है कि सभी कर्मचारियों ने हिन्दी में पूरे तौर से काम करने की योग्यता प्राप्त कर लो है, यह संतोष की बात है। ग्रतः ग्रब समय ग्रा गया है कि जो काम ग्रभी ग्रंप्रेजी में हो रहे हैं उन्हें यथासंभव हिन्दी में करने का प्रयत्न किया जाय। इसी संबंध में मुझे यह परिपत्र भेजने का ग्रादेश हुग्रा है।

३--हिन्दी के संबंध में अभी तक जारी हुए परिपत्रों का सारांश सिवधा के लिये नीचे दिया जाता है:

ऋम-संख्या	परिपत्र का दिनांक	परिपत्र का ग्राशय
To be in	<u> च ग्रक्तूबर, १६४७</u>	१—पह घोषित किया गया कि देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी उत्तर प्रदेश की राजभाषा होगी। भविष्य में सरकारी नौकरियों में भर्ती करते समय ग्रन्य सब बातों के समान होते हुए हिन्दी का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों का श्रिषिक ख्याल किया जायगा श्रौर ग्रन्य नौकरियों में भर्ती के लिये भी हिन्दी का कामचलाऊ ज्ञान रखना श्रावश्यक होगा। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये राज्य लोक सेवा ग्रायोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी को ग्रनिवार्य
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	विषय बनाया जायगा ।

क्रम-संख्या परिपत्र का दिनांक

परिपत्र का आशय

- २--सभी कर्मचारियों को चाहिए कि वे हिन्दी का काम-चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लें जिससे कि भविष्य में वे श्रपना सारा कार्य हिन्दी में कर सकें।
- ३--व्यवहार प्रिक्तमा संग्रह (Civil Procedure Code) की धारा १३७ ग्रौर दंड प्रिक्तमा संग्रह (Criminal Procedure Code) की धारा ५५८ के ग्रधीन इस ग्राज्ञम की घोषणा संबंधी विज्ञिष्तियां जारी की गर्यी कि दीवानी ग्रौर फौजदारी ग्रदालतों की भाषा हिन्दी होगी।
- ४--मैनुग्रल म्राफ गवर्नमेंट म्रार्डर्स, खंड १ (पुराना संस्करण) का पैराग्राफ ३८५ निम्नरूप में परिष्कृत किया गया :
 - (क) जनता के नाम श्रदालतों या माल के श्रफसरों की श्रोर से जारी किये जाने वाले सभी सम्मन, घोषणा तथा इस प्रकार के श्रन्य कागज देवनागरी लिपि में होंगे, श्रौर
 - (ख) फौजदारी, दीवानी तथा लगान ग्रौर मालगुजारी की ग्रदालतों में सभी लोग ग्रपने ग्रावेदन-पत्र ग्रथवा ग्रपनी शिकायतें देवनागरी लिपि में देंगे ग्रौर यदि वे हिन्दी न जानते हों तो फारसी लिपि में दे सकेंगे।
- ५—सरकारी कार्यालयों के लिये मान्य भाषा हिन्दी होगी श्रौर सरकारी कार्य तथा पत्र-व्यवहार में इसका उपयोग किया जाएगा। पहिली दिसम्बर, १६४७ से सभी प्रपत्र श्रादि हिन्दी में मुद्रित होंगे श्रौर सरकारी कार्यालयों में सभी साइनवोर्ड, नोटिस श्रादि हिन्दी में होंगे।
- २ ४ जून, १६४८
- ६--सभी विभागाध्यक्षों श्रौर कार्यालयाध्यक्षों को यह निदेश दिये गये कि वे श्रपने श्रधीनस्थ सेवाश्रों में भर्ती के लिये ली जाने वाली परीक्षाश्रों में हिन्दी को एक श्रनिवार्य विषय रखें।
- ३ १८ जून, १६४८
- ७--- त्यायालय की नोटिसें तथा सम्मन देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में प्रकाशनार्थ जारी किये जाने चाहिए।
- ४ १८ दिसम्बर, १६४८
- पह स्पष्ट किया गर्या कि शब्द "हिन्दी" से तात्पर्य देवनागरी लिपि में लिखित इस राज्य की जनता की भाषा से है । विभागाध्यक्षों ग्रादि से पूछा गया कि

कम-संख्या	परिपत्र का दिनांक	
		परिपत्र का ग्राहाय
10		राज्य की विभिन्न सेवाग्रों की परीक्षाग्रों में हिन्दी को एक ग्रनिवार्य विषय बनाने में श्रव तक क्या कार्यवाही की गयी।
	६ फरवरी, १६४६	•• ६समस्त विभागाध्यक्षों को निदेश किया गया कि वे ऐसे कर्मचारियों के नाम ; जो हिन्दी से ग्रनभिज्ञ हों सरकार को भेजें।
	द ग्रगस्त, १६५० 	•• १०यह ग्रादेश दिया गया कि यदि चरित्रपंजियों (Character Rolls) में प्रविष्टियां हिन्दी में की जांय ग्रीर उन्हें महालेखापाल को भेजना हो तो उनके साथ ग्रंपेजी का ग्रनुवाद भी भेजा जाना चाहिए।
	११ जुलाई, १६५२	 ११सभी विभागाध्यक्षों को यह निदेश किया गया कि वे राजकीय तार भेजने के प्रयोजनार्थ राज्य के कई जिलों में प्रारम्भ की गई हिन्दी तार सेवा का उपयोग करें।
ج -	१६ ग्रक्टूबर, १६५२	•• १२यह स्रादेश दिया गया कि यथासंभव सभी कार्य हिन्दी में किया जाय तथा जिन सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान न हो स्रौर हिन्दी में काम न कर सकते हों वे कुछ समय तक तो स्रंपेजी में ही काम करते रहें, किन्तु उन्हें शोध्र ही कामचलाऊ हिन्दी सीख लना चाहिए।
		१३भविष्य में केवल हिन्दी टाइपराइटर ही खरीदे जायं ग्रौर प्रथानतया हिन्दी के ही स्टेनोग्राफर ग्रौर टाइपिस्ट भर्ती किये जायं।
£ 7	१ भ्रप्रैल, १६५४	१४इस पर जोर दिया गया कि राजकीय तार भेजने में हिन्दी तार सेवा का स्रधिकाधिक उपयोग किया जाय ।
१० <u>५</u>	सितम्बर, १६५४	१५यह ग्रादेश दिया गया कि सरकारी काम में जहां तक हो सके वही शब्द काम में लाये जायं जो सरल हों ग्रीर जिनको ग्राम तौर पर लोग समझ सकें।
88 -	१ नवम्बर, १६५४ —————	१६इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि सभी राजकीय कार्य यथासंभव हिन्दी तें ही किये जायं ग्रीर यह बताया गया कि पुराने ग्रंप्रेजी टाइपराइटरों के स्थान पर नये ग्रंप्रेजी टाइपराइटरों के खरीदने की मांग स्वीकार न की जायगी।
		• १७पह भी ग्रादेश दिया गया कि हिन्दी को राजभावा के रूप में कार्यान्वित करने के संबंध में की गई

परिपत्र का ग्राशय परिपत्र का दिनांक क्रम-संख्या की छुमाही रिपोर्ट संबंधित प्रशासकीय प्रगति को १ जनवरी ग्रौर १ को भेजी जलाई विभाग जाय। १८--म्रादेश दिया गया कि यदि ऐसे कोई कर्मचारी हों ३० दिसम्बर, १९५४ १२ जो ग्रब भी हिन्दी से ग्रनभिज्ञ हों तो सरकार को सुचित किया जाय। १६--सभी विभागाध्यक्षों ग्रीर कार्यालयाध्यक्षों को यह ११ जुलाई , १६५५ 83 निदेश किया गया कि वे सरकार द्वारा निर्मित समितियों की, जिनमें गैर सरकारी सदस्य भी हों, कार्यसची तैयार करने में ग्रौर कार्यवाही लिखने में हिन्दी का ही प्रयोग करें यह भी व्यवस्था की गई कि यदि किसी कारण से उक्त किसी समिति की कार्यसची ग्रौर कार्यवाही ग्रंग्रेजी में ही रखना श्रनिवार्य हो तो इस संबंध में पहले ही से सरकार की स्वीकृति ले ली जाय।

४-- खेद की बात है कि उक्त ग्रादेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरणार्थ इस ग्रादेश के होते हुए भी प्रधानतया हिन्दी के ही स्टेनोग्राफर ग्रौर टाइपिस्ट भर्ती किये जायं
कुछ कार्यालयों में प्रधानतया ग्रंग्रेजी के ही स्टेनोग्राफर ग्रौर टाइपिस्ट भर्ती किये जा रहे हैं। इसी
प्रकार राजकीय तार हिन्दी में न भेजे जाकर ग्रधिकतर ग्रंग्रेजी में ही भेजे जाते हैं। कहीं-कहीं
सार्वजनिक नीटिसें भी हिन्दी में प्रकाशित नहीं होती। यही नहीं, दैनिक प्रयोग की पिचयां व पताकायें
ग्रंग्रेजी में ही प्रयुक्त की जा रही हैं। स्पष्ट ग्रादेशों के विपरीत साइनबोर्ड ग्रादि भी ग्रंग्रेजी में होते
हैं। यह ग्रनचित है ग्रौर सरकार ग्राशा करती है कि भविष्य में हिन्दी संबंधी ग्रादेशों का कड़ाई से
पालन किया जायगा।

५—इसके स्रतिरिक्त शासन ने स्रब निश्चय किया है कि राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के निमित्त निम्नलिखित स्रौर उपाय काम में लाये जायं।

६—सरकार द्वारा भेजे जाने वाले परिपत्र—सरकार श्रव से जो भी परिपत्र भेजेगी वे हिन्दी में होंगे। यदि कोई ऐसा परिपत्र भेजना हो जिसका संबंध वित्तीय मामलों से हो तो भी उसे हिन्दी में ही भेजने का प्रयत्न किया जाय। श्रलबत्ता साथ में उसकी एक श्रंग्रेजी प्रति लगा दी जाय।

इसी प्रकार प्रत्येक विभागाध्यक्ष ग्रपने ग्रधीनस्थ कार्यालयों को जो परिपत्र भेजें वे हिन्दी में हों। वित्त संबंधी परिपत्रों के संबंध में उनका ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद भी साथ में लगा दिया जाय। इस तरह वित्त संबंधी परिपत्र भी हिन्दी में बनाने का ग्रभ्यास हो जायगा।

७—द्रुतगामी पत्र—इस प्रकार के श्रादेश पहले से ही मौजूद है कि राजकीय तार भेजने के प्रयोजनार्य राज्य के कई जिलों में प्रारम्भ की गई हिन्दी तार सेवा का श्रधिकाधिक उपयोग किया जाय। (देखिये परिपत्र दिनांक १० जुलाई, १९४२—ग्रौर २१ ग्रप्रेल, १९५४)।

चूंकि द्वतगामी पत्र का मालेख्य तार जैसा होता है इसलिये इसको भी हिन्दी में भेजने में कोई कठिनाई न होनी चाहिये। फिर सामान्य पत्रों की अपेक्षा इनकी संख्या भी बहुत

५ -- अनुस्मारक (रिमाइन्डर) ग्रौर स्वीकार -प्राप्ति (एफनालेजमेन्ट) पत्र -- इस समय ग्रनुस्मारक हिन्दी ग्रौर ग्रंग्रेजी दोनों में ही भेजे जाते हैं। उनको ग्रव हिन्दी ही में भेजन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार स्वीकार-प्राप्ति पत्र भी हिन्दी में ही भेजे जांय। यह ग्रादेश निम्न प्रकार के ग्रनुस्मारकों ग्रौर स्वीकार-प्राप्ति पत्रों पर लागू होंगे:

- (१) सिचवालय से उसके विभिन्न विभागों तथा विभागाध्यक्षों इत्यादि को भेजे जाने वाले ग्रौर विभिन्न विभागों तथा विभागाध्यक्षों इत्यादि से सिचवालय को ग्राने वाले;
- (२) अधीनस्य कार्यालयों से परस्पर आने जाने वाले,
- (३) ऐसे राज्य शासनों को जिनके साथ संविधान के अनुच्छेद ३४६ के अन्तर्गत इस शासन का हिन्दी में पत्र -व्यवहार करने का करार हुआ है, भेजे जाने वाले (इस संबंध में आपको अलग से आदेश परिपत्र सं० १२०४२/३—१७० (३)-१९४०, दिनांक १९ नवम्बर, १९४४ को भेजे जा चुके हैं)।

श्रनुस्मारक ग्रौर स्वीकार-प्राप्ति पत्र के कुछ नमूने "हिन्दी निर्देशिका" में, जिसका उल्लेख नीचे के पैराग्राफ ३० में किया गया ह, ग्रापकी सुविधा के लिये दे दिये गये हैं। श्रावश्यकतानुसार इन प्रपत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है।

६--सामान्य प्रकार के पत्र-व्यवहार, निर्देश तथा टिप्पणी-सामान्य प्रकार के जो भी पत्र-व्यवहार तथा निर्देश किये जायं वे हिन्दी में ही किये जायं। उनसे सम्बन्धित टिप्पण भी हिन्दी में ही लिखे जायं श्रौर दैनिक प्रयोग के श्रपेक्षण-पत्र (requisitions) भी हिन्दी में भरे जायं, उदाहरणार्थ:

- (१) पुस्तकालय तथा श्रभिलेख कक्ष (record room) से पुस्तकें व पत्रावितयां मंगाने के श्रपेक्षण-पत्र श्रौर लेखन सामग्री के श्रपेक्षण-पत्र हिन्दी में भरे जांय ।
- (२) पत्रों की प्रतिलिपि मांगने से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाय ।
- (३) सूचनार्थ तथा प्रावश्यक कार्यवाही के लिये प्रतिलिपि भेजने के लिये पृष्ठांकन हिन्दी में किये जांय।

१०—जनता से प्राप्त स्त्रावेदन-पत्रों का उत्तर—जनता से प्राप्त सभी प्रकार के स्रावेदन-पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाय । स्रभी केवल उन स्रावेदन-पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है जो हिन्दी में प्राप्त होते हैं, किन्तु स्रब उन स्रावेदन-पत्रों का भी, जो देवनागरी लिपि में न हों, उत्तर हिन्दी में दिया जाय । गैर सरकारी संस्थास्रों के पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जाय, यदि उनके पत्र हिन्दी में हों । यदि पत्र स्रप्रेजी में प्राप्त हो तो उसका उत्तर भी, जहां तक हो सके, हिन्दी में दिया जाय ।

११—-एसेम्बली के प्रश्नों के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार तथा टिप्पण (नोटिंग)——
यथासम्भव एसेम्बली के प्रश्नों के सम्बन्ध में सारा पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाय श्रौर
टिप्पण-कार्य भी हिन्दी में हो।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

१२—हिन्दी में प्रपत्र—यह भी श्रावश्यक है कि वे समस्त प्रपत्र (forms) जो श्रभी श्रंपेजी में ही प्रयुक्त होते हैं हिन्दी में श्रन्दित हों। इनके श्रनुवाद के लिये सरकार ने प्रवत्य कर दिया है श्रौर इस सम्बन्ध में श्रापक पास श्रला से परिपत्र भेजा जा रहा है। श्रतएव भिवष्य कर दिया है श्रौर इस सम्बन्ध में श्रापक पास श्रला से परिपत्र भेजा जा रहा है। श्रतएव भिवष्य में कोई भी कार्यालय, वित्त "संबंभी प्रपत्रों को छोड़कर, श्रन्य प्रपत्र श्रंपेजी में मुद्रित न करायें। में कोई भी कार्यालय, वित्त "संबंभी प्रपत्रों को छोड़कर, श्राप्त पत्र के जनको हिन्दी में मुद्रित प्रपत्रों का हिन्दी है। उपलब्ध हो सके। जब तक उनको हिन्दी में मुद्रित प्रपत्रों का हिन्दी क्पान्तर करा लें श्रौर साइक्लोस्टाइल करके उन्हें प्रयुक्त प्रपत्र नहीं मिलते वे उन प्रपत्रों का हिन्दी रूपान्तर करा लें श्रौर साइक्लोस्टाइल करके उन्हें प्रयुक्त कर । यह सुनिश्चित करने के लिये कि वित्त सम्बन्धी प्रपत्रों को छोड़कर सामान्यतया दैनिक प्रयोग करें। यह सुनिश्चित करने के लिये कि वित्त सम्बन्धी प्रपत्रों को छोड़कर सामान्यतया दैनिक प्रयोग के श्रन्य प्रपत्र श्रोजी में किर से मुद्रित न हों, श्रिथीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर के श्रन्य प्रपत्र श्रोजी में किर से मुद्रित न हों, श्रिथीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश को श्रादेश दिये जा रहे हैं कि वे भविष्य में किसी भी श्रवस्था में श्रंप्रेजी में प्रपत्र न छापें। यदि श्रंपेजी में ही छपा कोई प्रपत्र प्रयुक्त करना हो तो वह भी हिन्दी में भरा जाय। उदाहरणार्थ, उपस्थित तथा श्राकिसमक छुट्टी की पंजी (Attendance and Casual leave registers) हिन्दी में भरी जाय। इसी प्रकार प्राप्त, प्रेषण तथा पत्रावली पंजियां भी हिन्दी में भरी जाय।

१३ -- कर्मचारियों के स्रावेदन-पत्र -- यथासम्भव कर्मचारी स्रपने स्रावेदन-पत्र हिन्दी में ही दें। इसी प्रकार उनका उत्तर भी हिन्दी में ही देने का प्रयत्न किया जाय।

१४—-रीतिक अवसरों के निमंत्रण-पत्र तथा कार्यक्रम—-रीतिक अवसरों पर राज्य सरकार द्वारा भेजे जाने वाले निमंत्रण-पत्र हिन्दी में हों। इसी प्रकार विभागाध्यक्षों, कार्या-लयाध्यक्षों द्वारा जो भी निमंत्रण-पत्र भेजे जांय वे भी हिन्दी में ही छपे हों। उनके कार्य-क्रम भी हिन्दी ही में बनाये और छापे जांय। इनके कुछ नमूने "हिन्दी निर्देशिका" के परिशिष्ट ७ में दे दिये गये हैं।

१४—-दौरे का कार्यक्रम—-दौरे के कार्य-क्रम हिन्दी में ही बनाये जाय । सुविधा के लिये ऐसे कार्यक्रम का एक नमूना परिशिष्ट ३ में दे दिया गया है ।

१६—-कैलेन्डर तथा छुट्टियों की सूची—सरकार द्वारा प्रकाशित समस्त प्रकार के कैलण्डर तथा पैंड हिन्दी में हों। इसी प्रकार छुट्टियों की सूची भी हिन्दी में हो। निगोशियेबुल इन्सट्ट मेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत छुट्टियों की विज्ञप्तियां कुछ समय तक हिन्दी और श्रंप्रेजी दोनों में प्रकाशित होंगी, किन्तु कार्यालयों और अधिकारियों के प्रयोग के लिये श्रतिरिक्त प्रतियां केवल हिन्दी में ही छुपेंगी। गवनंमेंट प्रेस द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित १६५५ के कित्यय कैलेण्डर श्रंप्रेजी ही में थे। श्रव से जितने भी कैलेण्डर श्रंथीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश द्वारा छापे जांय वे हिन्दी में हों।

१७——िलफाफों पर पते——िलफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही होने चाहिये। किन्तु कार्यालयों के ग्रंग्रेजी नामों व ग्रधिकारियों के ग्रंग्रेजी पद नामों का ग्रनुवाद न होना चाहिये। ऐसा करना कुछ समय तक इसलिये ग्रावश्यक है कि ग्रभी डाक व तार विभाग इन ग्रंग्रेजी नामों के हिन्दी पर्यायों से भलीभांति परिचित नहीं हैं ग्रौर यह हो सकता है कि पत्र सम्बोधित व्यक्तियों के पास न पहुंचकर ग्रनिधकृत व्यक्ति को मिले। (कुछ दिन पूर्व बिहार में ऐसा ही हुग्रा था, जिसका फल यह हुग्रा कि जिन ग्रधिकारियों के पास चिट्टियां पहुंचनी थीं उन्हें न मिल कर कभी-कभी दूसरे ग्रधिकारियों के पास पहुंच जाती थीं)। कुछ समय बाद जब हिन्दी के पर्याय पूर्ण रूप से प्रचलित हो जांय तब पदनामों के हिन्दी के रूपान्तरों का प्रयोग पता लिखने में किया जाय।

१८——टाइप राइटर—-परिपत्र संख्या ६४६४/३—-१७० (७)-१६५२, दिनांक २६ स्रक्तूबर, १६५२ तथा परिपत्र संख्या ६७६३/३—-१७० (३)-१६५२, दिनांक १ नवम्बर, १६५४ में ये स्रादेश दिये गये थे कि नये टाइपराइटर स्रब हिन्दी लिपि के ही खरीदे जांय । उसमें यह भी बेताया

गया था कि श्रंग्रेजी के नये टाइपराइटर खरीदने के प्रस्ताव शासन को श्रव न भेजे जीय । फिर नी समय-समय पर श्रंग्रेजी टाइपराइटर खरीदने की मांगें श्रा रही हैं। इन मांगों के समर्थन में श्रविकतर ये तर्क दिये जाते हैं:

- (क) पारिभाषिक शब्दों में हिन्दी पर्यायों का स्रभाव,
- (ख) हिन्दी टाइपिस्टों ग्रीर हिन्दी स्टेनोग्राफरों की कमी, धीर
- (ग) दैनिक प्रयोग के प्रपत्रों का अंग्रेजी में होना।
 - क-- के संबंध में यह बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि हिन्दी के पत्र में अंग्रेची पारिभाविक शब्द हिन्दी लिपि में लिखे जा सकते हैं। इसके प्रति-रिक्त श्रव श्रंग्रेजी पारिभाविक शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित हो रहे हैं और इनकी पुस्तिकायें कुछ ही समय में उपलब्ब हो जायेंगी।
 - ख--के विषय में स्थायी अनुबेश यह है कि अब जो भी टाइपिस्ट नियुक्त किये जायेंगे वे प्रधानतया हिन्बी के ही हों। यही नीति स्टेनोग्राफरों के सम्बन्ध में भी है।
- ग-- के सम्बन्ध में उपर्युक्त पैराग्राफ १२ में उल्लेख कर दिया गया है कि खंग्रेजी में मुद्रित प्रपत्र प्रब प्रयुक्त न होंगे । समस्त प्रपत्रों के हिन्बी रूपान्तर तैयार हो रहे हैं श्रीर शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगे ।

ऐसी श्रवस्था में श्रंग्रेजी टाइपराइटर खरीदना श्रावश्यक नहीं कहा जा सकता। श्रतः शासन ने निश्चय किया है कि श्रंग्रेजी टाइपराइटरों की मांग न की जानी चाहिये। शासन के लिये श्रव इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करना संभव न होगा। श्रलबत्ता इस श्रावेश के निम्नलिखित ग्रपवाद है:

- (१) उच्च न्यायालय में न्यायिक प्रयोजनों के लिये तथा किसी विशेष स्थिति में प्रशासकीय प्रयोजनों के लिये,
- (२) अन्य न्यायिक अधिकारियों के ऐसे कार्यों के लिये जिन्हें अंग्रेजी में करना अनिवार्य हो,
- (३) लोक सेवा आयोग के ऐसे कार्य के लिये जिनका अंग्रेजी में किया जाना अनिवार्य हो, उदाहरणार्थ, परीक्षा सम्बन्धी प्रश्त-पत्र आदि,
- (४) महालेखापाल से सम्बन्धित ऐसे कार्यों के लिये जिनका ग्रंग्रेजी में ही करना ग्रंभी आवश्यक है,
- (प्र) यदि कोई नया कार्यालय स्थापित हो, जिसमें ग्रंप्रेजी में कुछ हद तक काम करना श्रावत्यक हो, तथा
- (६) इसी प्रकार के किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिये।

इत दशाश्रों में भी श्रंग्रेजी टाइपराइटर खरीदने की श्रनुमति उसी समय दी जायगी जब काम की मात्रा पर्याप्त हो ।

१६—कार्यालय की मोहरें तथा रबर मुद्रायें—कार्यालय की मोहरें तका रबर मुद्रायें हिन्दी में हों। जहां ऐसा न हो, प्रधिकारी ं की व्यवस्था कर लें। पद नाम ग्रंग्रेजी में हो सकते हैं, किन्तु लिपि देवनागरी हो।

२०—-चपरासियों आदि के बिल्ले—सिचवालय के चपरासियों, जमादारों तथा पुलिस व होम गार्ड के सिपाहियों व श्रन्य सरकारी कार्यालयों के चपरासियों श्रादि के बिल्ले हिन्दी में द्वोना चाहिये। जहां ऐसा न हो रहा हो, इस प्रकार की ब्यवस्था कर ली बाय । २१—हिन्दी के लिये एक पदेन ग्रिधिकारी—सिचवालय विभागाध्यसौ तथा प्रमुख कार्य लयाध्यक्षों के कार्यालयों ग्रादि में हिन्दी की प्रगति समुचित रूप से ही रही है या नहीं यह देखने के लिय प्रत्येक कार्यालय में एक ग्रिधिकारी मनोनीत किया जाय, जो ग्रपने कार्य के ग्रितिकत यह भी देखें कि ज कार्यालय में एक ग्रिधिकारी मनोनीत किया जाय, जो ग्रपने कार्य के ग्रितिकत यह भी देखें कि ज कार्यालय में सुचार रूप से हिन्दी का व्यवहार हो रहा है, ग्रीर हिन्दी के विषय में सरकारी आदेश पूर्णत्य पालन किये जा रहे हैं। ग्रतः प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष ग्रपने ग्रधीनस्थ एक कर्मचारी को जो राज्य के (State Service) के ग्रेड से निम्न ग्रेड का न हो इस कार्य सम्पादन के लिये मनोनीत कर देशे इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखा जाय कि इसके लिये वही पदाधिकारी मनोनीत किया जाय जो ज्ये इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखा जाय कि इसके लिये वही पदाधिकारी मनोनीत किया जाय जो ज्ये (Senior) हो ग्रीर हिन्दी में ग्रिभिक्चि रखता हो, जिससे कि उसके परामर्श के ग्रनुसार ग्राधिकारी ग्रीर कर्मचारी हिन्दी में ग्रुभिकार से काम कर सके।

कार्यालयों के प्रधान निरोक्षक (Chief Inspector of Offices) स्रोर उनके स्रधीनः निरोक्षक भी कार्यालयों का निरीक्षण करते समय यह देखेंगे कि हिन्दी सम्बन्धी स्रादेशों का समृदि पालन हो रहा है।

२२—प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना—प्रत्येक कार्यालय में धीरे एक हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किया जाय, जहां कर्मचारियों को हिन्दी के प्रमाणीकृत कोष, ग्रंपे हिन्दी के कोष, हिन्दी की निर्देश पुस्तकें, हिन्दी को वे पुस्तकें जो राजकीय कार्य करने में प्रत्यक्ष प्रयव्या परोक्ष रूप से उपयोगी हों, हिन्दी ग्राख्यायें, हिन्दी बजट तथा गजट की प्रतियां, हिन्दी ग्रालेखन की पुस्त ग्रादि उपलब्ध हो सकें। ये पुस्तकालय हिन्दी ग्रध्ययन-केन्द्र का भी काम करेंगे ग्रार वहां सरकार कर्मचारी ग्रुगमता से हिन्दी ज्ञानीपार्जन कर सकेंगे। इस प्रकार के पुस्तकालय कर्मचारियों में न केंब हिन्दी ग्रुगमता से हिन्दी ज्ञानीपार्जन कर सकेंगे। इस प्रकार के पुस्तकालय कर्मचारियों में न केंब हिन्दी पढ़न ग्रीर सपझने की ग्रिशिच पदा करेंगे ग्रिपतु उनकी कार्य-दक्षता को भी बढ़ाने में सहायक होंगे विभागाध्यक्षों ग्रीर ग्रन्थ प्रधिकारियों के पास जो धनराशि प्रासंगिक (contingencies) व्यय लिये है उसमें से समय-समय पर इन पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें खरीदनी चाहिये। इसके ग्रितिक शासन द्वारा प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें तथा हिन्दी विषय की ग्रुन्य चुनी हुई पुस्तकें एकत्रित करना चाहिये।

२३—हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा हिन्दी टाइप सीखने की सुविधा—उन सरका कर्मचारियों को, जो हिन्दी स्टेनोग्राफी या हिन्दी टाइपराइटिंग सीखना चाहें, तथा उन टाइपिस्टों स्टेनोग्राफरों को, जो ग्रपनी स्पीड बढ़ाना चाहें, निम्न सुविधायें दी जायं :—

- (१) दपतर के घंटों में हिन्द ीटाइप सीखने की सुविधा,
- (२) कार्यालय के टाइपराइटरों पर टाइप सीखने की सुविधा,
- (३) स्टेनोग्राफरों को दफ्तर के घंटों में स्टेनोग्राफी का ग्रभ्यास कायम रखने व बढ़ की सुविधा,
- (४) हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखने वालों को दपतर में देर से श्र तथा जल्दी छोड़ने की श्रनुसति देना,
- (प्र) हिन्दी टाइप व हिन्दी स्टेनोग्राकी सीखने के लिये ग्रध्ययन छुट्टी (Studiesuc) दिये जाने की व्यवस्था । फन्डामेंटल कल्स के नियम ५४ के ग्रन्त निर्मित नियमावली (Subsidiary rules) के नियम १४६-ए में व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारियों की वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक (technical तथा ग्रन्य प्रकार के विशिष्ट शिक्षण के लिये ग्रुतिरिक्त छुट्टी स्वीकृत की जा सकते हैं। साधारणतया यह छुट्टी कुझ विशेष विभागों—जैसे जन-स्वास्थ्य विभाग, निर्मित विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को दी जाती है, किन्तु सरकार को ग्रिधिकार कि ग्रन्य कर्मचारियों को भी यह सुविधा दिये जाने का ग्रादेश दे, यदि सरकार

विचार में विशिष्ट पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये उसको ऐसी छुट्टी देना सार्वजनिक हित में हो। अतः सरकार ने यह निश्चय किया है कि हिन्दी टाइप व हिन्दी स्टेनोग्राफो सीखने के लिये जो प्रस्ताव सरकार के पास आयेंगे उन पर सहातु-भूति से विचार किया जायगा और लोक सेवा के हित को ध्यान में रखते हुये यया-सम्भव उनको स्वीकार करने का प्रयत्न किया जायेगा। सचिवालय के प्रशासकीय विभाग उन प्रस्तावों को यथाशी व्र वित्त विभाग से परामशं लेकर तय करेंगे श्रीर यदि आवश्यकता होगी तो सामान्य प्रशासन विभाग से भी परामशं करेंगे।

२४—-हिन्दी की प्रगति में विशेष सहायता देने वाले कर्मवारियों को प्रोत्साहन—हिन्दी में श्रव्छी टिप्पणी लिखने या श्रालेख्य तैयार करने वाले कर्मवारियों को प्रोत्साहन दिया जाय। उदाहरणार्थ, उनकी चरित्र पंजियों (Character Rolls) में इस श्राशय की प्रविष्टियां की जायं कि वे हिन्दी की प्रगति में विशेष सहायता दे रहे हैं। इसी प्रकार उन कर्मवारियों की भी जो हिन्दी की प्रगति में अथवा सरकारी काम के लिये उसके प्रचार में विशेष योग दें, प्रोत्साहन दिया जाय। हिन्दी सम्बन्धी इन प्रविष्टियों पर पदोन्नति के समय विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

२४—-भारत सरकार के राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग—भारत सरकार ने भी अब अपने राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने की व्यवस्था की है और इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद ३४३ के खंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ५ दिसम्बर, १९५५ को एक आदेश जारी किया है जिसका नाम संविधान (राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दो भाषा) आदेश, १९५५ है। इस आदेश का व्योरा "हिन्दी निर्देशिका" में दे दिया गया है।

२६--- अन्य विशेष आदेश--अपर कहे गये विभिन्न आदेशों के स्रतिरिक्त सिवास्य के लिये कुछ और विशेष आदेश पृथ्ठांकन में दिये गये हैं।

*२७—उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा श्रायोग को यदि श्रापत्ति न हो तो वे श्राने श्रधीनस्थ कर्मचारियों के लिये उपरोक्त श्रादेश, जहां तक लागू हों, कृपया जारी कर दें।

†२८--(१) कार्यालयों के प्रधान निरीक्षक (Chief Inspector of offices) से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त पैराग्राफ २१ के सम्बन्ध में श्रावश्यक कार्यवाही करें।

‡(२) अवीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्रो, उत्तर प्रदेश से यह अनुरोध किया जाता है कि वह इस परिपत्र में उल्लिखित अनुदेशों के विपरीत कोई सामग्री अंग्रेजी में न छापें जब तक कि शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दे दी गयी हो । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के पैराग्राफ १२ के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

२६—यह परिपत्र केवल उन बातों से ही संबंधित नहीं है जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है। उल्लिखित राजकीय कार्यों में तो हिन्दी प्रयुक्त करना ही है किन्तु इसके यह प्रयं नहीं कि प्रन्य कार्य, जिनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है, हिन्दी में न किये जायं। प्रच्छा होगा कि यदि प्रन्य प्रकार के कार्यों में भी हिन्दी इस्तेमाल को जाय, क्योंकि ग्रन्ततः हिन्दी हो समस्त राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होनी है ग्रीर उसको पूर्णक्षेण ग्रयनाना है। ग्रतएव जितनी जल्दी ग्रव सारा कार्य हिन्दी में होने लगे उतना ही ग्रच्छा होगा।

^{*}केवल उच्च न्यायालय श्रीर लीक सेवा श्रायोग के लिये।

क्रेंकेवल कार्यालयों के प्रधान निरोक्षक के लिये।

[‡]केवल श्रधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री के लिये।

३०—हिन्दी निर्देशिका—सरकार यह अनुभव करती है कि अन्य कठिनाइयों के साथसाथ उपयुक्त पारिभाविक शब्दावली के अभाव में हिन्दी में आलेख्य तथा टिप्पणतैयार करते समय कर्मसाथ उपयुक्त पारिभाविक शब्दावली के अभाव में हिन्दी में आलेख्य तथा टिप्पणतैयार करते समय कर्मबारी प्राय: अंग्रेजी में ही सोचर्न तथा अपने विचार व्यक्त करने के लिये बाध्य होते हैं। तत्पश्चात् उनका
बारी प्राय: अंग्रेजी में ही सोचर्न तथा अपने विचार व्यक्त करने के लिये बाध्य होते हैं। इस कठिनाई
हिन्दी ख्पान्तर तथार करने का प्रयत्न किया जाता है जिससे भोलिकता नष्ट हो जाती है। इस कियो
को दूर करने तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की सुविधा देने के लिये
शासन ने एक पुस्तिका, "हिन्दी निर्देशिका" तथार करवाई है, जिसमें हिन्दी के सम्बन्ध में निकाले गये
शासन ने एक पुस्तिका, "हिन्दी निर्देशिका" तथार करवाई है, जिसमें हिन्दी के सम्बन्ध में टिप्पण और आलेख्य लिखने तथा अनुवाद करने के कुछ सुझाव, हिन्दी
आवेशों का विवरण, हिन्दी में टिप्पण और आलेख्य लिखने तथा अनुवाद करने के कुछ सुझाव, हिन्दी
संप्रयुक्त होने वाली शब्दावली, हिन्दी की निर्देश पुस्तकों की सुची इत्यादि संग्रहीत हैं। इस पुस्तिका
मं हिन्दी की प्रगति बढ़ाने के शासकीय आदेशों का सारांश भी दिया गया है। इस परिपत्र के साथ
मं हिन्दी की प्रगति बढ़ाने के शासकीय आदेशों का सारांश भी दिया गया है। इस परिपत्र के साथ
निकाल गये आदेश भी इसमें समाविष्ट कर दिये गये हैं। इस पुस्तिका की एक प्रति अतिरिक्त प्रतियों
निकाल गये आदेश भी इसमें समाविष्ट कर दिये गये हैं। इस पुस्तिका की एक प्रति अवोगी सिद्ध होगी।

३१—हिन्दी माध्यन द्वारा विचारों की सुगमता से श्रिभिव्यक्ति—हिन्दी भाषा एक सरल भाषा है, भारत की ग्रपार जनता की भाषा है। इसीलिये इसे इस प्रदेश की राजभाषा का स्थान ही नहीं ग्रपित संघ की राजभाषा का भी स्थान दिया गया है। यह भाषा पूर्ण विकसित है। का स्थान ही नहीं ग्रपित संघ की राजभाषा का भी स्थान दिया गया है। यह भाषा पूर्ण विकसित है। ग्रत्या प्रत्या की सकती है। श्रीभव्यक्ति सुगमता से हो सकती है।

३२—उपसंहार—विदेशी शासन अन्त होने के बाद विदेशी भाषा का प्रयोग आधिक समय तक होते रहना सभी की अप्रोतिकर लगेगा। कुछ समय तक तो अप्रेजी का कुछ न कुछ प्रभाव बना रहना एक प्रकार से अनिवार्य ही था। इसलिये जब सरकार ने अक्तूबर, १६४७ में हिन्दी को राज-भाषा घोषित किया तो यह स्वष्ट कर दिया था कि अप्रेजो को जगह हिन्दी का प्रयोग शनैः शनैः किया जायगा जिससे कि राजकीय कार्य में आवश्यकता से अधिक अड़बन न पड़े। तब से अब द वर्ष से अधिक हो गये हैं और अप्रेजो का प्रयोग, उन अनिवार्य कार्यों को छोड़ कर, जिनका उल्लेख भारत के संविधान में हैं, सरकारो कार्य में अब यथासम्भव न होना चाहिये।

३३—सरकार को स्राज्ञा है कि हिन्दी को राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त करने की नीति को भली प्रकार फलीभूत करने में सभी कर्मवारी स्रपना पूर्ण सहयोग देंगे।

भवबीय, स्रादित्यनाथ झा, मुख्य सचिव ।

सं० ११८७६ (१)/३—१७० (२२)-१९४५ "हिन्दी निर्देशिका" को एक प्रति के साथ, प्रतिलिपि सिचवालय के समस्त विभागों को, धावश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती ै।

的现在分词 化自己自由 自由主义 自由自己主义之

२—-कुछ समय हुन्रा जब कि सचिवालय के विभिन्न विभागों के सचिवों ने सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित किया था कि कुछ मदों को छोड़ कर प्रायः सभी काम हिन्दी में किया जा सकता है। जिन मदों में हिन्दी में काम होना इस समय सम्भव नहीं है, उनकी सूचियां भी साथ में आई थों। अतएव सचिवालय के विभिन्न विभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उनत सूचियों में उल्लिखित मदों को छोड़ कर सभी काम यथासम्भव हिन्दी में करना प्रारम्भ कर हैं। यदि उन सब के अन्तर्गत पूरा काम हिन्दी में करने में असुविधा हो, जैसी कि कदाचित होगी, तो शनैः शनैः हिन्दी में काम करने वाले मदों को छांट लिया जाय और उनको हिन्दी में करना शुरू कर दिया जाय।

३---यह विशेष ग्रादेश इस परिपत्र में बताये हुए ग्रादेशों के ग्रातिरिक्त है। सं० ११८७६ (२)/३---१७० (२२) -१६५५

पृथ्ठांकन सं० ४६८६ (४)/३--१७०-४७, दिनांक = प्रक्तूवर, १९४७ के कब में।

- (१) उत्तर प्रदेश के सभी स्युनिसियल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी और नोटीकाइड एरिया कमेटी के चेयरमैनों ग्रीर प्रेसीडेन्टों;
 - (२) लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस श्रीर श्रागरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के प्रशासकों;
- (३) कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के प्रशासक को भी एक प्रतिलिपि "हिन्दी निर्देशिका" की एक प्रति के साथ सूचनार्थ भेजी जाती है।

नोट--बनारत श्रीर श्रागरा के इन्ध्रवमेंट ट्रस्टों को द ग्रक्तूबर, १६४७ का परिपन्न सालान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं भेजा गया था। उसकी प्रतिलिपि निर्देशिका की परिशिष्ट १ में है।

धाना से,

ग्रादित्यनाथ झा, मुख्य सचिव ।

सं० ११८७६ (३)/३--१७० (२२)-१६५५ वित्त विभाग

"हिन्दी निर्देशिका" की एक प्रति के साथ, प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के महालेखापास को श्री सूचनार्थ भेजी जाती है।

श्राज्ञा से, विविन विहारी लाल,

परिशिष्ट २

प्रकाशित शासकीय परिपत्र, नियमावली तथा समिति की कार्यवाही परिपत्र संख्या १

सं० ग्र-६६१४/१६--२३२-१६४४

प्रेषक,

श्री ब्रादित्य नाथ झा, ब्राई० सी० एस०, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त जिला ग्रधिकारीगण । लखनऊ, दिनांक २० सितम्बर, १६५५ विषय—-२ ग्रक्तूवर, १६५५ को गांधी-जयन्ती के उपलक्ष में उत्सव ।

महोदय,

सूचना विभाग। मुझे यह सूचित करने का श्रादेश मिला है कि राष्ट्रिपता महात्मा गांधीजी की जयन्ती राज्य भर में पूर्व वर्षी की भांति इस वर्ष भी भारतीय इतिहास के एक महान् एवं शुभ पर्व के रूप में सनाई जाय।

२--सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश को २ श्रक्तूबर के समारोहों का भार सौंपा गया है। फिर भी मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि इस दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रायः इस भांति हो सकती है---

- (१) सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाय।
- (२) जयन्ती के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी के बड़े स्राकार के सुन्दर चित्र को कार्यालय स्रियं संस्था के प्रमुख कक्ष में रख दिया जाय, जहां २ स्रक्तूबर के दिन कार्यालय के कर्मचारियों स्रथवा बौक्षिक संस्थाओं के विद्याधियों स्रौर स्रध्यापकों की उपस्थिति में चित्र का विधिपूर्वक स्रनावरण किया जाय। सभी विभागाध्यक्ष, स्रायुवत, जिला स्रिधिकारी, जिला जज, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, थाने के इंचार्ज, कालेज स्रथवा स्कूल के प्रिसिपल या हेड सास्टर स्रौर स्रन्य सभी कार्यालयों के सुख्य स्रविकारी स्वयं ही इस चित्र के स्रनावरण समारोह को सम्यन्न करें, जब तक कि वे स्रनिवार्यतः स्रन्यत्र व्यस्त न हों।
- (३) प्रत्येक कार्यालय ग्रथवा संस्था के प्रधान ग्रधिकारी ग्रपने भाषण में महात्या गांधी के जीवन एवं उनके कार्यों का संक्षेप में परिचय दें, ग्रौर शांति एवं साम्प्रदायिक एकता तथा सादे जीवन के उन ग्रादशों के विषय में कर्मचारियों, विद्यार्थियों ग्रादि को समझायें, जिनके लिये गांधी जी ने जीवन भर प्रयत्न किये। ये ऐसे ग्रादर्श हैं, जिनसे सरकारी कर्मचारियों ग्रौर उन समस्त व्यक्तियों को सतत प्रेरणा सिलनी चाहिये, जो स्वतंत्र भारत के योग्य नागरिक बनना चाहते हैं। स्वावलम्बन एवं ग्रात्मिनर्भरता के सिद्धान्तों पर विशेष बल दिया जाना चाहिये। पंववर्षीय योजना ग्रौर उसके लाभ तथा ग्रल्प बचत ग्रान्दोलन का भी उल्लेख किया जा सकता है जिनमें स्वेच्छापूर्वक योग देने का भी उनसे ग्रनुरोध किया जाय, क्योंकि इससे उनका ग्रपना ग्रौर राष्ट्र दोनों का ही हित होगा।
- (४) इस स्रवसर पर खादी के प्रचार स्रोर खादी हुंडियों की विकी के लिये विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिये क्योंकि खादी गांधी जी को सबसे स्रधिक प्रिय थी। खादी हुंडियां डाकखानों से प्राप्त की जा सकेंगी।

३--में यह भी कहना चाहूंगा कि जिला श्रधिकारी तथा श्रन्य श्रधिकारी उपर्युक्त कार्यक्रम में ऐसा कोई भी कार्य सिम्मिलित कर सकते हैं, जो इस श्रवसर के उपयुक्त समझा जाय।

४--- श्रापके जिले के लिये इस श्रवसर पर व्यय करने के निर्मित्तु १०० ६० की घनराशि स्वीकृत की गई है। लेखा व्योरा, इस विषय पर गत वर्ष प्रसारित सरकारी श्रादेश सं० श्र-८०२८/१९---१६३-१९४४, दिनांक १६ सितम्बर, १९४४ के श्रनुच्छेद ४ के निर्देशानुसार होना चाहिये।

> भवदीय, स्रादित्य नाथ झा, मुख्य सचिव ।

सं० ग्र-६६१५ (१)/१६---२३२-१६५५

सूचनार्थ एवं श्रावश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:--

(१) उत्तर प्रदेश के समस्त डिवीजनों के किमश्नरों तथा उन कलेक्टरों को, जिनके ग्रधीन डिवीजन रखे गये हैं।

(२) उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त विभागाध्यक्षों तथा कार्यालयों के प्रधान ग्रिध-कारियों को।

(३) उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बोर्डों के सभापतियों तथा नगरपालिकाओं के अध्यक्षों और प्रशासकों को ।

सं० ग्र-६६१५ (२)/१६--२३२-१६५५

सूचनार्थ एवं स्रावश्यक कार्यवाही हेतु सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश को प्रतिलिपि प्रेषित । सरकार के प्रधान कार्यालय प्रथवा अन्यत्र तद्विषयक विविध व्ययों के लिये, यदि ऐसा कोई व्यय हो, उनको ४,४०० प्रये की धनराशि दी गई है।

सं० अ-६६१५ (३)/१६---२३२-१६५५

सचिवालय के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित।

सिचवालय प्रज्ञासन विभाग गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विधान भवन में गांधी-जयन्ती समारोह मनाने की व्यवस्था करेगा। एतदर्थ ५०० रु० की धनराज्ञि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में किये गये व्ययों का विस्तृत विवरण सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश की समारोह के बाद अविलम्ब भेज दिया जाय।

ग्राज्ञा से, ग्रादित्य नाथ झा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।

सं० ग्र-६६१५ (४)/१६---२३२-१६५५ वित्त विभाग

सूभनार्थ एवं श्रावस्थक कार्यवाही हेतु महागणक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रतिलिपि प्रेषित । श्राजा से,

ग्राज्ञा स,
एम० चक्रवर्ती,
सहायक सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

परिपत्र संख्या २

संख्या ४७२८ एस० (२०)/५४

प्रेचक.

श्री म्रादित्य नाय मा, ग्राई० सी० एस०,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के सब विभागों के ग्रध्यक्ष, डिवीजनों के कमिश्नर, जिला ग्रफसर ग्रौर

ग्रन्य दफ्तरों के ग्रधिकारी।

लखनऊ, दिनांक २६ सितम्बर, १६५४।

विषय : खादी हुन्डी।

महोदय,

सचिबालय ासन विभाग (भ्रविष्ठान)

राष्ट्रिपता महात्मा गांधी के जन्म-दिवस के अवसर पर, खादी और ग्राम उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग मंडल ने इस वर्ष २ ६०, ४ ६०, १० ६०, २५ ६०, ४० ६० और १०० ६० की हुंडियों का प्रवन्ध किया है जिनको खरीद कर उनके बदले में, सर्व सेवा संघ द्वारा प्रमाणित किसी भी खादी भंडार या सेन्स इम्पोरियम में सूती, ऊनी और रेशमी खादी ली जा सकती है। इन हुंडियों का प्रयोग श्रागामी ३१ मार्च तक किया जा सकता है।

२--सरकार की श्रोर से इसके पहले भी सरकारी कर्मचारियों के लिये यह सुझाव दिया गया था कि वे खादी को अपनायें। इस वर्ष गांधी जयन्ती के उपलक्ष में खादी हुंडियों की विकी सरकारी ढंग से हो रही है जिसते सरकारी कर्मचारियों को खादी खरीवने में सुविधा हो। खादी के प्रयोग से लाखों दिर माइयों श्रौर बहुनों को जीविका का सहारा भिलता है। इस विषय में सरकारी कर्मचारियों से यह विशेष श्राशा की जाती है कि वह खादी को अपनायेंगे श्रौर दफ्तर में खादी के वस्त्र का प्रयोग करेंगे। ऐसा करने से उनका अनुकरण श्रौर लोग भी करने लगेंगे।

३—इस विवय में गत २३ सितम्बर को सिचवालय में एकत्रित कर्मचारियों को मुख्य मंत्री जी ने जो सीख दी उसका एक विवरण संलग्न है जिसे शायव श्राप लाभप्रद पायें। श्राशा है कि श्रापके कार्यालय में भी इसी के श्रावार पर कर्मचारिणण इस पुनीत श्रवसर का लाभ उठा कर खादी खरीदना चाहेंगे।

म्रापका विश्वासपात्र, म्रादित्य नाथ झा, मुख्य सचिव ।

सरकारी कर्मचारियों में लादी हुन्डियों की बिक्री

मुख्य मंत्री द्वारा उद्घाटन

कल रात को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बीच खादी हुन्डियों की बिकी का उब्घाटन करते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने कहा कि वर्गभेद मिटाने तथा श्राम बेकारी दूर करने के लिये खादी गांधी जी का एक महामन्त्र है। इस श्रवसर पर विवान भवन में एकत्र हुये मंत्रियों, सचिवों, गजटेड तथा नान-गजटेड श्रधिकारियों में स्वेच्छापूर्वक श्रधिक से श्रविक पये की खादी की हुन्डियां खरीदने की होड़ लग गई। प्रायः सभी मन्त्रियों तथा मुख्य सचिव में २५० २० श्रीर श्रन्य सचिवों ने १२५ २० की खादी हुडियां खरीदना स्वीकार किया।

इस वर्ष गांधी जयन्ती से खावी हुंडियों की बिक्री को सरकार द्वारा प्रेरित एक ब्रान्वोलन का रूप देने पर मुख्य मंत्री ने प्रसन्तता प्रकट की ब्रीर कहा कि खावी के प्रयोग से बाबू वर्ग ब्रीर ग्रामीण भेव मिट गया है। विवेशी शासन काल में, सरकारी कर्मचारी श्रपने को एक विशिष्ट वर्ग का समझते ये ब्रीर ब्राज भी उनमें यह धारणा कुछ सीमा तक बनी हुई है। पंडित पन्त ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिये सरकारी ब्रीर ब्रासरकारी व्यक्तियों के बीच की यह खाई बूर होनी ही चाहिये ब्रीर इसके लिये खाबी से, जो स्वतंत्रता का परिधान है, ब्रिधिक ग्रच्छा कोई ब्रग्य सामन नहीं है। यदि जनता ब्रीर सरकार के बीच समानता की यह भावना ब्रा जाय तो शासन की शक्ति हजार गुनी बढ़ सकती है।

मुख्य मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि पिछले दिनों में खादी का प्रयोग न करने की कमी को पूरा करने के लिये वे खादी का अधिकाधिक प्रयोग करें। उन्होंने यह आशा प्रकट की कि शुरू में विधान भवन का अत्येक कर्मचारी अपने निजी तथा परिवार के उपयोग के लिये अधिक से अधिक खावी खरीदेगा। पन्त जी ने कहा कि सिववालय में जो कुछ आज होता है उसका जिलों में अनुकरण किया जाता है। अतएव हमारा यह कार्य राज्य भर के सरकारी कर्मचारियों का पथ-प्रदर्शन करेगा।

श्रन्त में पंडित पन्त ने कहा कि मैं उस दिन की कामना करता हूं जब सरकारी कर्मचारी खादी के अलावा श्रीर किसी वस्त्र का उपयोग न करेंगे। उन्होंने श्रनुरोध किया कि वे श्रामे श्रपने लिये केवल खादी ही खरीदें, यद्यपि में उन्हें अपने मौजूदा वस्त्रों का परित्याग करने की राय नहीं देता। खादी के उपयोग से सरकारी कार्यालयों को एक नया गौरव प्राप्त होगा और जनता में सरकारी कर्मचारी लोकप्रिय बन सकेंगे।

सिववालय के कर्मचारियों के लिये उनके प्रतिनिधियों द्वारा यह निश्चय किया गया कि खाबी हुन्जियों की खरीव के लिये विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में मुख्य सिवव २५० ० ग्रीर सिवव, संयुक्त सिवव इत्यादि १२५ ०, उपसिवव ७० ६०, ग्रानुसचिव तथा सहायक सिवव ५० ०, ग्राधीक्षक तथा पर्सनल श्रिसस्टेंट २५ ६०, स्टेनोग्राफर व ग्रपर डिवीजन सहायक १० ०, लोग्रर डिवीजन सहायक ६ ० ग्रीर जूनियर डिवीजन सहायक ६ ० ग्रीर जूनियर डिवीजन सहायक ४ ० की खादी खरीवें।

मुख्य पंत्री ने सिववालय की महिला कर्मचारियों को भी यथासम्भव खाबी का उपयोग करन की राय वी।

परिपन्न संख्या ३

संख्या ४२२०/११-ए--६६-१६४३

प्रेषक,

श्री कुलदीप नारायण सिंह, श्राई० ए० एस०, सचिव,

उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

समस्त जिलाधीश,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक २० मार्च, १९५३ ई०।

विषय:--स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की मंत्रियों इत्यादि तक पहुंच।

महोदय,

नगरपालिका (क) विभाग।

मुझे यह कहने का भ्रादेश हुआ है कि सरकार को ऐसे उदाहरण जात हुये हैं कि स्थानीय निकायों के कर्मचारी नौकरी श्रथवा व्यक्तिगत मामलों के संबंध में श्रपनी शिकायतों के प्रतिकार के लिये सरकारी सिचवालय में मंत्रियों, उप-मंत्रियों, सभासिचवों तथा सिचवालय के श्रिधिकारियों के पास पहुंचते हुये पाये गये हैं। वर्तमान सरकार, जहां कहीं ग्रौर जब भी ग्रावश्यकता पड़ती है, शिकायतों को दूर करने के लिये सदैव तत्पर रहती है। किन्तु प्रशासकीय कार्यक्षमता तथा जनहित के लिये स्थानीय निकायों की सेवाग्रों में ग्रनुशासन बनाये रखना ग्रत्यावश्यक है। सम्बन्धित उच्च म्रिधिकारियों की जानकारी के बिना तथा पहले से समय निश्चित किये बिना मेंत्रियों के पास सीधे जाने से व्यर्थ ही समय नष्ट होता है ग्रौर शक्ति का ग्रयव्यय होता है। इससे जिस प्रयोजन के लिए भेंट की जाती है उसके ग्रविलम्ब साधन में भी सहायता नहीं मिलती। मंत्रियों इत्यादि से मिलने के पूर्व समय निश्चित कर लेने से यह लाभ होता है कि वे उस मामले के संबंध में तैयारी कर लेते हैं जिस पर उन्हें बातचीत करना होता है। इस सूचना के स्रभाव में भेंट के समय उठाये गये प्रश्नों का उत्तर सोच विचार कर देना संभव नहीं होता। पहले से तैयारी किये विना संबंधित प्रश्न के बहुत से पहलुग्रों पर उस समय बातचीत नहीं की जा सकती । फलतः उनके संबंध में म्रागे चल कर पत्र-व्यवहार करना म्रावश्यक हो जाता है । इस प्रकार उन्हीं के मामलों के म्रान्तिम निर्णय में विलम्ब हो जाता है। सम्बन्धित ग्रेधिकारियों द्वारा मंत्रियों इत्यादि से मिलने की प्रथा में पीडित कर्मचारियों के दिष्टिकोण से भी व्यावहारिक लाभ है, क्योंकि तब उनके समक्ष ग्रनावश्यक तथा ग्रसंगत बातें नहीं रखी जायेंगी ग्रौर इस प्रकार उनका ग्रमूल्य समय नष्ट न हो सकेगा।

२--- अतएव में ब्रापसे यह निवेदन करता हूं कि ब्राप अपने जिले के समस्त स्थानीय निकायों के ग्रध्यक्षों को यह ग्रादेश दे दें कि वे ग्रपने ग्रधीनस्थ कर्मचारियों को यह सचित करें कि वे सम्बन्धित स्थानीय निकायों के प्रेसीडेंट चेयरमैन की प्रनुमति के बिना नौकरी से सम्बन्धित किसी निजी ग्रथवा सामान्य मामले के सम्बन्ध में मंत्रियों, उप-मंत्रियों, सभासिववीं श्रयवा सिचवालय के ग्रधिकारियों के पास न जायें, श्रौर न उनसे पहले से समय निश्चित विना तथा सम्बन्धित ग्रिधिकारियों से ग्रनुमित प्राप्त किये विना मिलें। यदि कर्मचारी इस प्रकार की भेंट करने की अनुमति सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा न प्राप्त कर सके तो उसे इसके एक प्रार्थना-पत्र देना चाहिये जो नाम से मंत्री इत्यादि को संबोधित नहीं किया जायगा किन्तु सम्बन्धित सरकारी विभाग के सचिव को भेजा जायगा।

३—स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के ऐसे प्रयत्नों को नितान्त निरुत्साहित किया जाय जिनसे हैं सरकार के समक्ष निर्णय के लिए श्राने वाले श्रपने व्यक्तिगत मामलों के सम्बन्ध में निजी प्रकार से श्रथवा विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा सरकार पर प्रभाव डालना चाहते हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों के नैतिक श्राचरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है श्रीर सरकार इस प्रकार के किसी व्यवहार को श्रसन्तोषजनक समझती है। इसका तुरन्त श्रन्त होना चाहिये।

४--मुझे स्राप से यह भी निवेदन करना है कि स्थानीय निकायों के स्रध्यक्ष स्रपने स्रधीनस्थ कर्मचारियों में उपर्युक्त स्रादेशों को इस चेतावनी के साथ परिचालित करें कि यदि वे उनका पालन न करेंगे तो वे स्रनुशासन की कार्यवाही के भागी होंगे।

> श्रापका विश्वासपात्र, कुलदीप नारायण सिंह । सचिव ।

संख्या ४२२० (१)/११-ए--६६-१६५३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा ग्रावश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित--

- (१) समस्त अध्यक्ष, जिला बोर्ड, उत्तर प्रदेश ।
- (२) नगरपालिकाओं के समस्त ग्रध्यक्ष, प्रशासक, उत्तर प्रदेश।
- (३) श्रध्यक्ष, विकास बोर्ड, कानपुर ।
- (४) इम्प्र्वमेंट ट्रस्टों के ग्रध्यक्ष, लखनऊ, इलाहाबाद, ग्रागरा ग्रौर वाराणसी।
- (५) अधिसूचित क्षेत्र समितियों (नोटीफाइड एरिया कमेटियों) के समस्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (६) नगर क्षेत्र सिमितियों (टाउन एरिया कमेटियों) के समस्त ग्रध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संख्या ४२२० (२)/११-ए--६६-१६५३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सुचनार्थ प्रेषित---

- (१) समस्त डिवीजनों के कश्रिश्नर, उत्तर प्रदेश।
- (२) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक (Examiner, Local Fund Accounts), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- (३) मुख्य इंजीनियर, स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग, उत्तर प्रदेश , लखनऊ ।
- (४) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा संचालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (५) ग्राम तथा नगर नियोजक (Town and Village Planner), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (६) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ।
- (७) संचालक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश ।
- (८) सचिवालय के समस्त विभाग।

श्राज्ञा से, कुलदीप नारायण सिंह, सचिव ।

परिपत्र संख्या ४ ंसंख्या ख-४५६४/१५--१०६१-१६५१ THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

श्री ग्रानन्द नारायण सप्रू, ग्राई० सी० एस०,

सेवा में.

शिक्षा संचालक,

उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद।

लखनऊ, दिनांक १२ जून, १९५२।

महोदय,

मुझे श्रापका घ्यान शासन के श्रर्व-सरकारी पत्र, दिनांक ४ श्रक्तूबर, १९५१ ई० की श्रोर ब्राकवित करने का ब्रावेश हुन्ना है जिसमें ब्रापंसे यह ब्रनुरोध किया गया था कि ब्रापंके ब्रयीन सब कार्यालयों में पत्र-व्यवहार, कार्यालयों की टिप्पणियां ब्रीर ब्राजायें ब्रादि, हिन्दी भाषा में तुरन्त ही विभाग। प्रारम्भ फर ही जायं।

२--पिछले तीन चार महीनों में शासन को एक विशेष प्रसंग पर जिला विद्यालय निरीक्षकों से पत्र-व्यवहार करना पड़ा था। उनके यहां से ऋाये हुये उत्तर यद्यपि छोटे-छोटे थे, तथापि वे प्राधिकतर ग्रंग्रेजी भाषा में ये। हिन्दी टाइपराइटरों की कमी के कारण पत्र-व्यवहार करने में कुछ कठिनाई श्रवश्य हो सकती हैं। किन्तु कुछ पत्र जो हाथ से लिखे हुये ग्राये थे वे भी ग्रंग्रेजी ही में ये। इतसे यह स्पष्ट है कि ग्रापके प्रधीन कार्यालयों में ग्रधिकतर कार्य तथा पत्र-व्यवहार श्रंग्रेजी में हो रहा है श्रीर हिन्दी में कार्य होना उस गित से नहीं आरम्भ हुआ है जैसा कि होना चाहिये या । ज्ञासन को खेद है कि इस प्रकार वैभागिक ग्रधिकारी इस सम्बन्ध में ज्ञासन के श्रादेश का पालन उचित रूप में नहीं कर रहे हैं।

३--उपर्युक्त परिस्थिति में मुझे आपसे यह कहने का आदेश हुआ है कि आपके कार्यालय में तथा शिक्षा विभाग के जिन कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करना श्रारम्भ नहीं हुआ है या जहां पूरी तौर से हिन्दी में कार्य नहीं हो रहा है वहां तुरन्त ही सब काम करने में (ग्रयित् कार्यालय की टिप्पणियों, धावेश इत्यावि में) हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाय । जिन कार्यालयों में हिन्दी के टाइपराइटर नहीं है वहां पत्र-व्यवहार, जहां तक सम्भव हो, हिन्दी में किया जाना चाहिये। किन्त जहां हिन्दी में टाइपराइटर हैं वहां सभी पत्र-व्यवहार भी हिन्दी भाषा में हुन्ना करें।

४--इस सम्बन्ध में प्रापसे प्रनुरोध किया जाता है कि ग्राप ग्रपने वैभागिक ग्रधिकारियों से यह तचना बाप्त करिये कि वे अपर के ब्रावेशों का पर्णरूप से पालन कर रहे हैं।

४--इस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न सूची में लिखे हुये ग्रविकारियों को भेजी जा रही हैं। यवि धावके खबीन कुछ प्रधिकारियों के नाम इस सूची में खट गये हों तो ग्राप कृपया शीध्र ही इस बादेश को प्रतिलिपि उन अधिकारियों को भेजने का कष्ट कीजिये।

भववीय,

श्रानन्द नारायण सप्रु सविव ।

शिक्षा (ख)

संलग्न--(१) तारीख ४ श्रक्तूबर, सन् १६५१ ई० क श्रर्थ-सरकारी पत्र की प्रतिलिपि।

Berne Control of the control of the

the Carry one's proposed on minute in the last

to the real part of (serving) by the total by the total approach

(२) इस पत्र की १०० ग्रतिरिक्त प्रतिलिपियां ।

संख्या ख-४५६५ (१)/१५—१०६१–१६५१ प्रतिलिपि शिक्षा (क) तथा शिक्षा (क-२) विभागों से स्टिन स्टेन्ट २

प्रतिलिपि शिक्षा (क) तथा शिक्षा (क-२) विभागों को उचित कार्यवाही के लिए प्रेवित।

संख्या ख-४५६५ (२)/१५--१०६१-१६५१

प्रतिलिपि संलग्न सूची में लिखे हुये शिक्षा विभाग के प्रधिकारियों को राजाज्ञा का पालन करने के लिए भेनी जाती है।

> त्राज्ञा से, श्रानन्द नारायण लत्रू, सविव ।



परिपत्र सं० ४

सं० १२०४२/३--१७० (३)-१६४०

प्रेषक,

श्री ब्रादित्य नाथ झा, ब्राई० सी० एस०, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के विभागाध्यक्ष, डिबीजनों के किमश्नर तथा कलेक्टर इन्चार्ज, जिलाधीश, जिला जज तथा ग्रन्य कार्यालयों के प्रमुख ग्रिधकारीगण।

लखनऊ, दिनांक १५ नवम्बर, १६५५।

विषय:—-उत्तर प्रदेश शासन श्रौर बिहार राज्य, मध्य प्रदेश राज्य तथा मध्य भारत राज्य शासन के बीच होने वाले शासकीय पत्र-व्यवहार में केवल हिन्दी भाषा ही के प्रयोग किये जाने का करारनामा।

महोदय,

सामान्य प्रशासन विभाग भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४६ में निम्निलिखित व्यवस्था है:—— ३४६—संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत "एक राज्य ग्रीर दूसरे के भाषा, एक राज्य ग्रीर दूसरे राज्य के बीच में बीच में ग्रथवा राज्य ग्रीर

बीच में प्रथवा राज्य ग्रीर संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा।

। ग्रविक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच

परन्तु यदि दो या ऋषिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग को जा सकेगी।"

के लिए, राजभाषा होगी;

२--उपर्युक्त ग्रनुच्छेद के प्रतिबन्धात्मक खंड (proviso) के ग्रनुसार तथा बिहार राज्य, मध्य प्रदेश राज्य तथा मध्य भारत शासन की सहमित से उत्तर प्रदेश शासन ने ग्रभी हाल ही में उक्त राज्य शासनों से यह करार किया है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश राज्य शासन तथा उक्त राज्य शासनों के बीच होने वाले समस्त पत्र-ज्यवहार में हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जायगा।

३—तदनुसार श्रापसे मुझे यह श्रनुरोध करने का श्रादेश हुग्रा है कि भविष्य में बिहार राज्य शासन, मध्य प्रदेश राज्य शासन तथा मध्य भारत राज्य शासन के श्रिधिकारियों से पत्र-व्यवहार करने में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाये। यह भी श्रनुरोध है कि श्राप श्रपने श्रधीनस्थ श्रधिकारियों तथा कार्यालय श्रध्यक्षों को भी उपर्युक्त सरकारी निश्चय के श्रनुसार कार्य करने की सूचना दे दें।

४--- ग्रन्य राज्यों से तथा उनके ग्रधिकारियों से सीधे (direct) पत्र-व्यवहार करने के विषय में जो ग्रलग से ग्रादेश निकलते थें, वे इस परिपत्र से प्रभावित (affected) न होंगे।

भवदीय,

म्रादित्य नाथ झा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सं० १२०५२(१)/३--१७०(३)-१६५०

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त विभागों को सूचनार्थ तथा उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित।

सं० १२०५२(२)/३--१७०(३)-१९५०

प्रतिलिपि-

- (१) मुख्य मन्त्री के निजी सचिव, (२) मंत्रियों के वैयन्तिक सहायक, (३) उप-मंत्रियों, ग्रौर (४) सभा सचिवों

को सूचनार्थं प्रेवित।

सं० १२०५२(३)/३—-१७०(३)-१९५० प्रतिलिपि एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

ग्राज्ञा से, ग्रादित्य नाथ झा, म्ख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

परिपत्र सं० ६

प्रेषक,

श्री सिट्ठनलाल मीतल, बी० ए०, एल-एल० बी०, सचिव, मध्य भारत शासन, न्याय विभाग, ग्वालियर।

सेवा में,

श्री मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, लखनऊ।

ग्वालियर, दिनांक ५-११-१९५५।

विषयः—उत्तर प्रदेश राज्य शासन व मध्यभारत राज्य शासन के बीच होने वाले समस्त शासकीय पत्र-व्यवहार हिन्दी आधा में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

न्याय

उपरोक्त विषयक श्रापका पत्र-क्रमांक ६३८२/३—१७०(३)—१६५०, दिनांक विभाग। २२ श्रगस्त, १६५५, जो श्रापने मुख्य सचिव, मध्यभारत शासन को सम्बोधित कर के भेजा है, प्राप्त हुग्रा। उत्तर में श्रादेशानुसार निवेदन है कि मध्य भारत शासन को यह जानकर वड़ा हर्ष है कि उत्तर प्रदेश शासन ने संविधान के श्रनुच्छेद ३४६ के श्रधीन मध्य भारत शासन के इस प्रस्ताव पर कि उक्त दोनों राज्यों में पत्र-ध्यवहार के लिए शासकीय भाषा के रूप में हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाय, जो सन् १६५० में ही उत्तर प्रदेश शासन के पास प्रेषित किया गया था श्रीर जिस पर उन्होंने प्रयत्न करने के प्रतिवन्ध के साथ स्वीकृति दी थी, श्रव पूर्ण सहमति देने का निश्चय किया है, जो स्तुत्य है। इस विषय पर किसी रीतिक करारनामें की श्रावश्यकता नहीं है। शासन का केवल बृढ़ निश्चय हो इस दिशा में पर्याप्त है।

भवदीय, मिट्ठन लाल मीतल, सचिव, मध्य भारत शासन ।

परिपत्र (त्र्र्य्धंशासकीय) सं० ७

संख्या ४--५५५५-५४

संयुक्त संचालक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रिय बन्ध,

दिनांक, २६ सितम्बर, १६५४।

गत वर्षों में तथा वर्तमान वर्ष में वसूल किये गये पंचायतकर और दान में प्राप्त समस्त धन का श्रिधिकांश श्रव भी पंचायतों के वैयक्तिक लेखों में जमा है। यद्यपि पंचायतों ने श्रव तक श्रपनी सामर्थ्य तथा बल के अनुसार सराहनीय कार्य किये हैं, फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि पंचायतें अपने श्रापको कहीं श्रोधिक उपयोगी तथा जनता की सच्ची सेवा करने वालो संस्थाएं प्रमाणित करें। ऐसा उस समय होगा जब वे श्रपने पूरे धन को ऐसे ठोस कार्यों पर श्रविलम्ब व्यय कर वें जो जनसाधारण के हित तथा लाभ पर स्राघारित हों या जिनकी मांग ग्राम सभा के स्रधिकांश सदस्य करते रहे हों।

मुझे ब्राज्ञा है कि कम से कम इस व को जिले को योजना का ब्राधार ग्राम सभाग्रों से प्राप्त प्रस्ताव ही रहे होंगे। प्राम सभाग्रों के प्रस्ताव श्रधिकतर श्राप के तथा उच्च श्रधिकारियों के परामर्श पर ही ब्राधारित होंगे। इन प्रस्तावों में से ऐसी किसी योजना को छांट लेना ब्राप के लिए कठिन नहीं होगा, जिसको श्रमदान, पंचायत कोष से उपलब्ध धन तथा श्रनुदान रूप में प्राप्त शासकीय धन को मिला कर ग्रविलम्ब पूरा किया जा सके, जिसके द्वारा उस गांव के या उस क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को या म्रधिकांश निवासियों को कुछ न कुछ म्राराम पहुंच सके, किसी न किसो प्रकार का लाभ हो सके, म्रौर जो स्थायी उन्नति का साधन हो सके। इस प्रकार की योजना के क्रनुसार हो श्रमदान का क्रान्दोलन सफल बनाया जाय । पंचायत कोष में उपलब्ध धन व्यय किया जाय ग्रौर शासकीय ग्रनुदान प्राप्त किया जाय । में प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत की सफलता इस समय इसी में समझूंगा कि वह ग्रपने धन का ज्ञी झातिज्ञी झ अर्थात् देर से देर ३१-१-५५ तक पूरा-पूरा सदुपयोग कर लें। जिले के पंचायत मंत्रियों में से कुछ ऐसे मंत्रियों को पुरस्कार देने का भी मेरा विचार है, जो अपने क्षेत्र की पंचायतों के धन का इस प्रकार सर्वप्रथम सदुपयोग कर लेते हैं। संलग्न नोट में मैने कुछ ऐसे सुझाव देने का प्रयास किया है जिनके ग्रपनाने से धन का भी सदुपयोग हो सके।

पंचायतों द्वारा लगाया हुम्रा तथा वसूल किया गया कर एक प्रकार का चन्दा है । ग्राम सभाम्रों के सदस्य कर-रूप में अपनी सामूहिक उन्निति के कार्य करने के लिये यथाशक्ति दान देते हैं। इस सिद्धान्त को हम तभी प्रमाणित कर पायेंगे जब कि ग्रामीणों से वसूल किये गये धन की एक-एक पाई उनकी इच्छानुसार उनके हित को योजनास्रों पर स्रोर उनकी स्रावश्यकतास्रों को पूर्ति पर स्रविलम्ब ही व्यय हो जाये।

इस प्रकार व्यय करने से अवश्य ही हम भविष्य में पंचायत-कर की स्रोर तथा पंचायत की संस्था की ग्रोर श्रद्धा ग्रौर विक्वास उत्पन्न कर सकेंगे । ग्रतएव मेरा ग्रापसे यह ग्रनुरोध है कि ग्राप तुरन्त उप-र्युक्त स्रादेशों का पालन करें स्रौर संलग्न नोट में कथित सुझावों के स्रतुसार योजना बना कर वैयक्तिक लेंखे से धन प्राप्त कर के, श्रमदान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दे कर के ग्रौर शासकोय ग्रनुदान प्राप्त करके कोई दृढ़ रचनात्मक कार्य करें।

समस्त पंचायत मन्त्री,

भवदोय. गंगा सिंह चुणामणि

पंचायत राज विभाग. उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:--

१--समस्त जिला पंचायत श्रिधकारियों तथा सहायक जिला पंचायत श्रिधकारियों को सूचनार्थ एवं भ्रावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। २--समस्त पंचायत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश सरकार

पशु-पालन विभाग

संख्या जी० ई० सी० २/१२-ई--५४२-५४ लखनऊ, १८ जनवरी, १६५५

प्रस्ताव

गो-संवर्द्धन जांच समिति, उत्तर प्रदेश का १९५४ का पठित प्रतिवेदन

विचार--सरकार द्वारा विधान सभा की १२ दिसम्बर, १९५२ को दिये गये वचन का म्रनुसरण करते हुए सरकार ने भारत के संविधान की धारा ४८ के म्रनुसार म्रावश्यक उपायों को निर्धारित त्रीत लागू करने के पूर्व प्रारम्भिक रूप से "गो-संवर्द्धन जांच समिति" के नाम से एक समिति नियुक्त की। संविधान की घारा ४८ इस प्रकार है :--

"राज्य कृषि तथा पशुपालन को स्राधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग पर संगठित करने का प्रयत्न करेगा ग्रौर विशेषतः पशु जातियों को सुरक्षित रखने तथा गायों, बछड़ों, श्रमशोल तथा दुधारू पशुग्रों का बंध करने के लिए ग्रावश्यक कार्यवाही करेगा।"

सरकार इस मूल्यवान प्रतिवेदन के लिए सिमिति के ग्रध्यक्ष तथा सदस्यों की ग्राभारी है। इस ग्रवसर पर वह इस कार्य में किये गये परिश्रम तथा श्रध्यवसाय का प्रशंसात्मक उल्लेख करती है।

समिति की सिफारिशों पर सरकार ध्यानपूर्वक विचार कर रही है।

श्राज्ञा—यह श्राज्ञा दो जाती है कि यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

यह भी स्राज्ञा दी जाती है कि प्रतिवेदन स्रौर प्रस्ताव की प्रतियां जन साधारण में विकय की जायं ।

ग्राज्ञा से, के० सी० मित्तल, सचिव।

कार्यालय स्मृति-पत्र उत्तर प्रदेश सरकार ै

सचिवालय प्रशासन विभाग (म्रधिष्ठान)

संख्या १४८६-एम/२०—१६४३ लखनऊ, ११ अप्रेल, १६४३

कार्यालय समृति-पत्र

विषय:--सेकेटेरियट की डाक के वितरण का प्रवन्ध।

इस समय सेकेटेरियट को डाक सिंचवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान) द्वारा जनरल पोस्ट श्राफिस की खिड़की पर रोज दो बार, एक बार पूर्वान्ह ग्रीर फिर दूसरी बार ग्रपरान्ह में ली जाती है। पूर्वान्ह में प्राप्त डाक सिंचवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान) में छांटी जाने के बाद सेकेटेरियट को सभी विभागों को उसी दिन बांट दो जाती है। किन्तु ग्रपरान्ह की डाक ग्रपरान्ह में कुछ देर से प्राप्त होती है ग्रीर फलस्वरूप सिंचवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान) के लिए उसको उसी दिन छांट कर बांट देना संभव नहीं हो पाता।

२—अब यह निश्चय किया गया है कि सिचवालय प्रशासन विभाग (श्रिधिष्ठान) श्रपरान्ह की डांक भी उसी दिन बांट दिया करें। यह भी निश्चय किया गया है कि सिचवालय प्रशासन विभाग (श्रिधिष्ठान) डांक को पोस्ट श्राफिस की खिड़कों से २ वर्ज दिन में भी प्राप्त कर लिया करें। तदनुसार डांक घर के श्रीधिकारियों की राय से निम्नलिखित प्रवन्ध किये गये हैं, जिनके श्रन्तर्गत उक्त निर्णय श्रीर कितिपय सम्बन्धित बातें श्राती हैं। यह प्रवन्ध तुरन्त लागू होंगे—

१—साधारण डाक—जो सचिवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान) द्वारा पोस्ट श्राफिस की खिड़की से प्राप्त की जाती है।

३--इस श्रेणी की डाक में निम्नलिखित को छोड़ कर सेक्रेटेरियट की ग्रन्य सभी डाक सिम्मिलित है --

- (क) रिजस्टर्ड चीजें,
- (ख) डी० ग्रो० पत्र जो सेकेटेरियट के ग्रफसरों के पते से हों,
- (ग) निजी पत्र जो ग्रफसरों ग्रौर कर्मचारियों के हों,
- (घ) एक्सप्रेस डेलिवरी (द्रुतगामी पत्र),
- (ङ) तार।

४—सिचवालय प्रशासन विभाग (श्रिधिष्ठान) का प्रतिनिधि पोस्ट ग्राफिस के सभी

- (१) ६ और ६-३० बजे पूर्वान्ह के बीच,
- (२) २ बजे श्रपरान्ह में,
- (३) ४ बजे ग्रपरान्ह में ।

जनरल पोस्ट ग्राफिस की खिड़की से डाक लेगा।

४——पोस्टमास्टर, लखनऊ से इस बात की प्रार्थना की गयी कि डाक, विशेष कर श्रन्तिम डाक,

६—सचिवालय प्रशासन विभाग (ग्रिघिष्ठान) प्रथम डाक को छांट कर सेकेटेरियट के सभी विभागों को १०-३० बजे पूर्वान्ह तक बांट देगा। उसी प्रकार दूसरी डाक भी सचिवालय प्रशासन विभागों को १०-३० बजे पूर्वान्ह तक बांट दो जायगी। विभाग (ग्रिघिष्ठान) द्वारा छांट कर ३-३० बजे ग्रपरान्ह तक बांट दो जायगी।

७—तोसरी डाक भी प्राप्त होने के तुरन्त बाद उसी भांति सिचवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान) ढारा छांटी जायगी। यदि भूल से मंत्रियों, उप-मंत्रियों ग्रोर सभासिचवों के पत्र सिचवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान) में डाक के साथ प्राप्त हो गये हों तो वे सिचवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान) में डाक के साथ प्राप्त हो गये हों तो वे सिचवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान) हारा ४–३० ग्रपरान्ह को ग्रपरान्ह के बीच बांट दिये जायेंगे। शेष पत्र सिचवालय प्रशासन विभाग डाक को उसी दिन विभाग (ग्रिधिष्ठान) हारा नहीं बांट जायेंगे, बित्क सिचवालय का प्रत्येक विभाग डाक को उसी दिन विभाग (ग्रिधिष्ठान) छारा नहीं बांट जायेंगे के लिए सिचवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान) छांटी हुई डाक को ग्रपने विभाग का चपरासी भेजेगा ग्रीर सिचवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान) छांटी हुई डाक को ले जाने के लिए तैयार रखेगा।

५—जिन दिनों सेकेटेरियट बन्द हो, किन्तु डाकखाना खुला हो, सिचवालय प्रशासन विभाग (म्रिघिष्ठान)डाकखाने से डाक लाने के लिए प्रबन्ध करेगा ग्रौर डाक को छांट कर सेकेटेरियट खुलने (म्रिघिष्ठान)डाकखाने से डाक लाने के लिए प्रबन्ध करेगा ग्रौर डाक को छांट कर सेकेटेरियट खुलने के दिन १०-३० बजे पूर्वान्ह तक विभागों को बांटने के लिए तैयार रखेगा। यह प्रबन्ध उन दिनों भो के दिन १०-३० बजे पूर्वान्ह तक विभागों को बांटने के लिए तैयार रखेगा। यह प्रबन्ध उन दिनों भो को दिन एक हो बार (२ बजे ग्रपरान्ह) डाक देता हो।

६—संकेटेरियट के वे विभाग, जो विधान भवन (नये ब्लाक को सम्मिलित करके) के भूगृहादि (premises) के बाहर स्थित हैं, अपनी रोज की तथा छुट्टो में प्राप्त डाक को ले जाने के
लिए अपने चपरासी को सचिवालय प्रशासन विभाग (अधिष्ठान) में उपयुक्त समय पर, अर्थात् कार्य
लिए अपने चपरासी को सचिवालय प्रशासन विभाग (अधिष्ठान) में उपयुक्त समय पर, अर्थात् कार्य
के सभी दिनों १०—३० वजे पूर्वान्ह, ३—३० और ५ वजे अपरान्ह तथा छुट्टो के दिनों ३—३० वजे
अपरान्ह, भेज कर डाक मंगाने का प्रवन्ध करेंगे।

१०—सचिवालय प्रशासन विभाग (म्रिघिष्ठान) केवल उन्हीं पत्रों को खोलेगा जिनमें विभाग के नाम का कोई संकेत न हो। वे पत्र, जिन में विभाग का संकेत हो, किन्तु उस विभाग के विशेष उप-विभाग का संकेत न हो, उस विभाग के किसी एक ऐसे उपविभाग को भेज दिये जायेंगे, जिसे सम्बन्धित विभाग इस प्रकार के पत्र प्राप्त करने के लिए नामांकित करे।

२--रजिस्टर्ड चीजें

११—-रजिस्टर्ड चीजें इस समय डाकियों द्वारा सेकेटेरियट के ग्रफसरों ग्रथवा विभागों को, जैसी भी दशा हो, कार्य के दिनों १०–३० बजे पूर्वान्ह ग्रौर ३–३० बजे ग्रपरान्ह के बीच एक बार बांटी जाती हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वर्तमान प्रवन्ध ठीक ढंग से चल रहा है।

३--डी॰ ग्रो॰ पत्र--जो सेक्रेटेरियेट के ग्रफसरों के नाम से सम्बोधित रहते हैं-

१२—(१) पोस्ट ग्राफिस के ग्रधिकारी इन पत्रों को, ग्रफसरों के दफ्तर या घर के पते पर, जैसा कि उन पर लिखा गया हो, ग्रपने डाकियों द्वारा ग्रविलम्ब भेजने का प्रवन्ध करेंगे। किन्तु सेकेटेरियट में छुट्टो के दिनों वे पत्र, जिनमें ग्रफसरों के घर का पता न हो, डाकियों द्वारा सिववालय प्रशासन विभाग (ग्रधिष्ठान) को दे दिये जायेंगे ग्रौर सिववालय प्रशासन विभाग (ग्रधिष्ठान) ग्रह्या-वश्यक पत्रों को पत्र पाने वालों के घर बांटने का प्रवन्ध करेगा। साधारण डाक, सिववालय प्रशासन विभाग (ग्रधिष्ठान) द्वारा, दूसरे कार्य के दिन प्रथम डाक के साथ बांटी जायगी, जब तक कि सेकेटेरियट के किसी ग्रफसर ने सिववालय प्रशासन विभाग (ग्रविष्ठान) से ग्रपनी डाक ग्रपने चपरासी द्वारा मंगाने के लिए पहले से ही प्रवन्ध न कर लिया हो। ऐसी स्थिति में चपरासी को देने के लिए डाक १ ग्रौर ३–३० बजे ग्रथरान्ह के बीच में तैयार रहेगी।

(२) वे पत्र, जो डािकयों द्वारा पत्र पाने वालों (या उनके वैयिक्तक सहायकों, श्रथवा उनके निजी स्टाफ के सदस्यों) को, उनके उपलब्ध न रहने पर न दिये जा सकते हों, सिचवालय प्रशासन विभाग (श्रि विष्ठान) द्वारा पत्र पाने वालों के घर भेज दिये जायेंगे । शेष पत्र सिचवालय प्रशासन विभाग (श्रि विष्ठान) को दे दिये जायेंगे । इन पत्रों में श्रावश्यक पत्र सिचवालय प्रशासन विभाग (श्रि विष्ठान) द्वारा दूसरे कार्य के दिन पहली डाक के साथ बांटे जायेंगे ।

टिप्पणी--सिचवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान) सभी डाक को साधारण डाक समझेगा जब तक कि पत्र के कवर पर संकेत न हो कि वह श्रावश्यक है ।

४--- अफसरों तथा कर्मचारियों को सम्बोधित वैयक्तिक तथा निजी पत्र

१३—-इस प्रकार के पत्र वर्तमान हिदायतों के क्षेत्र के बाहर हैं। किन्तु यह उल्लेख कर दिया जाता है कि इस प्रकार के पत्र पोस्ट म्राफिस के म्रधिकारियों द्वारा उनके म्रपने नियमों म्रौर विनियमों के म्रनुसार बांटे जा रहे हैं।

५--द्रुतगामी (एक्सप्रेस डेलिवरी) पत्र

१४——ऐसे पत्र जो सेकेटेरियट के अफसरों के नाम या पदनाम के पते से हों, तार घर के अधिकारियों द्वारा पत्र पाने वालों को या तो उनके दफ्तर में, यदि वे वहां उपस्थित हों, या उनके घर पर दिये जायंगे । सिचवालय प्रशासन विभाग (ग्रिधिष्ठान), सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस, लखनऊ को सेकेटेरियट के अफसरों की एक ऐसी अद्यावधि सूची तैयार करके भेजेगा, जिसमें उनके निवास-स्थान का भी पता हो । इस सूची में ज्योंही कोई संशोधन किये जायंगे, त्योंही वे उक्त अफसर को सूचित कर दिये जायंगे । इस सूची का नया संस्करण उक्त अफसर को प्रत्येक तीसरे मास जनवरी, अप्रैल, जून और अक्तुबर में दिया जायगा ।

६--तार (टेलीग्राम)

१४——सेकेटेरियट के अफतरों को उनके नाम या पदनाम से सम्बोधित तारों के सम्बन्ध में भी वहीं प्रबन्ध लागू रहेंगे, जो द्रुतगासी-पत्र के सम्बन्ध में लागू हैं।

७--सामान्य

१६--सिचवालय के विभागों, मिन्त्रयों, उपमंत्रियों ग्रौर सभासिचवों के स्टाफ में काम करने वाले ग्रौर ग्रफसरों के स्टेनोग्राफर डाक पत्रों को लेने से इस ग्राधार पर इनकार न करेंगे कि दिन का कोई निश्चित काल बीत गया है।

द--डािकयों एवं डाक कर्मचारियों का विधान भवन में प्रवेश

१७--डाकिये ग्रौर डाक के ग्रन्य कर्मचारी, जब वे डयूटी (duty) पर हों, बिना रोक हर समय विधान भवन में प्रवेश कर सकेंगे, जब कि भवन का मुख्य प्रवेश द्वार खुला हो ।

कालिका प्रसाद भागंव,

मुख्य सचिव ।

प्रेषित :

- (१) सचिवालय के समस्त विभाग,
- (२) मन्त्रियों के वैयक्तिक सहायक,
- (३) समस्त उप-मंत्री,
- (४) समस्त सभासचिव,
- (५) सेकेटेरियट के समस्त श्रफसर ।

राज्यपाल का संदेश

"झंडा दिवस कोष" में उदारतापूर्वक दान देने की राज्यपाल की श्रापील

राज्यपाल, श्री कर्नैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने उत्तर प्रदेश की जनता से "झंडा दिवस कोष" में उदारतापूर्वक दान देने की श्रयील की है ।

झंडा दिवस ७ दिसम्बर को मनाया जायेगा । राज्यपाल महोदय ने इस श्रवसर के लिये निम्नलिखित संदेश भेजा हैं--

"सात दिसम्बर हमारा झंडा दिवस है। इस श्रवसर पर हमें ग्रयनी नौ सेना, वायु सेना तथा स्थल सेना के सदस्यों की सेवाग्नों का स्मरण हो ग्राता है, जिन पर हमें गर्व है। प्रत्येक वर्ष, जो स्थल सेना के सदस्यों की सेवाग्नों का प्रति ग्रीर ग्रिधिक कृतज्ञ होते जा रहे हैं, जिन लोगों ने भूतकाल में बीत रहा है, के साथ हम उन सदस्यों के प्रति ग्रीर ग्रिधिक कृतज्ञ होते जा रहे हैं, जिन लोगों ने भूतकाल में हमारे देश के मान तथा मर्यादा की रक्षा की, कर रहे हैं तथा भविष्य में करते रहेंगे।

झंडा दिवस हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे हम विशिष्ट ढंग से सुरक्षा सेवा के प्रति, उसके कार्यों, सेवाग्रों एवं उद्देश्यों के लिये अपनी भावनाग्रों को व्यक्त कर सके ।

ग्रतः मेरा उत्तर प्रदेशकी जनता से अनुरोध है कि वे ग्रयनी शक्ति भर झंडा दिवस कोष में दान देने के लिये ग्रागे बढ़ें, जिससे भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके कुटुम्बों एवं सुरक्षा सेवा के वर्तमान सदस्यों को लाभ पहुंचे । मेरा विश्वास है कि उदारतापूर्वक तथा पूर्ण हृदय से इस ग्रनुरोध को पूरा किया जायेगा।"

कनैयालाल माणिकलाल मुन्शी

नियमावली

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रतिथि नियमावली, १९५४

उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य श्रतिथियों के लिये ग्रावास तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधाग्रों के नियम

- १--(१) इन नियमों को "उत्तर प्रदेश राज्य श्रतिथि नियमावली, १६५४" कहा
- (२) भाग १ में दिये हुये नियम केवल उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो इन नियमों के प्रधीन "राज्य श्रितिथि" समझे जायेंगे । भाग २ में दिये हुये नियम उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो राज्य श्रितिथि नहीं समझे जायेंगे ।

भाग १

राज्य स्रतिथि

- २--(१) सामान्यतया निम्नलिखित अभ्यागत राज्य प्रतिथि समझे जायेंगे--
 - (क) भारत में विभिन्न राज्य सरकारों के राज्यपाल,

(ख) भारत सरकार के मंत्री,

(ग) भारत में विभिन्न राज्य सरकारों के मन्त्री,

- (घ) विशिष्टजन (भारतीय और विदेशीय)—कोई विशेष व्यक्ति इस श्रेणी के अन्तर्गत स्नाता है अथवा नहीं यह राज्य सरकार निश्चय करेगी ।
- (२) इन श्रतिथियों के साथ श्राने वाले उनके परिवार के सदस्य भी राज्य श्रतिथि समझे जायेंगे।
- (३) श्रतिथिगण के साथ श्राने वाले श्रधिकारियों श्रौर नौकरों के लिये वास-स्थान का भी प्रबंध किया जायगा।
- ३— जब तक कि राज्य सरकार के मुख्यालय, लखनऊ में नियमितरूप से कोई "राज्य स्रतिथि-गृह" न बन जाय, राज्य सरकार के मुख्यालय, लखनऊ में स्राने वाले राज्य स्रतिथियों के वासस्थान के लिये निम्न सुविधास्रों की व्यवस्था की जायगी:—
 - (१) राज्य सरकार के मुख्यालय, लखनऊ में ग्राने वाले राज्य ग्रतिथियों के वास-स्थान के लिये राज्य सरकार यथासम्भव किसी भवन/भवनों ग्रथवा उसके/उनके किन्हीं भागों को नियत कर देगी।
 - (२) यदि किसी भी समय खंड (१) में व्यवस्थित वास-स्थान अपर्याप्त प्रतीत हो तो जहां तक हो सकता है, प्रथम श्रेणी के किसी होटल में उनके ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था कर दी जायगी ।
 - (३) राज्य स्रतिथियों पर जो भी व्यय होगा, स्रौर जिसमें होटल का व्यय भी सिम्मिलित है, उसे राज्य सरकार उठायेगी ।
 - (४) वास-स्थान की वास्तिविक स्रावश्यकता से कम ३ दिन पूर्व राज्य स्रितिथि को ऐसे स्थान के संरक्षण के लिये गवर्नमेंट इस्टेट स्राफिसर को पत्र स्रथवा तार द्वारा सूचित करना चाहिये ।

टिप्पणी—इस राज्य में ग्राने वाले राज्य श्रितिथियों के साथ कैसा शिष्टाचार बरतना बाहिये इस सम्बन्ध में पृथक नियमावली है।

४--(१) यदि राज्य स्रतिथि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के स्रतिरिक्त किसी स्रन्य जिले के मुख्यालय में जायें, तो वे सामान्यतया सरिकट हाउस अथवा निरीक्षण-गृह में ठहराये जायेंगे । पुरुवाराय में आव, ता व सामान्यतया सरायाद होजा अवसा मिला है है । उत्पाद आवा । वहां वास–स्थान अपर्याप्त अथवा अप्राप्य होने की दशा में जहां तक सम्भव होगा, नगर के प्रथम श्रेणी के किसी होटल में, उनके ठहरने का समुचित प्रबंध किया जायगा।

(२) उन दशाश्रों में जबिक स्रितिथि सरिकट हाउस स्थवा निरीक्षण-गृह में ठहराये गये हों, राज्य सरकार उनके ठहरने तथा भोजन का सारा व्यय उठायेगी। यदि उनके ठहरने की व्यवस्था किसी होटल में की गयी हो तो भी पूरा व्यय राज्य सरकार ही वहन करेगी।

५--- म्रातिथि के लिये वास-स्थान की वास्तव में जब भावश्यकता हो तो उससे कम से कम ३ दिन पूर्व ऐसे स्थान के संरक्षण के लिये संबंधित जिला अधिकारी को पत्र अथवा तार द्वारा

सूचना भेजी जानी चाहिये।

६--सरिकट हाउस अथवा निरीक्षण गृह में अतिथि के ठहरने की अविध सामान्यतया ४ दिन से ग्रधिक न होनी चाहिये, किन्तु ग्रसाधारण परिस्थितियों में ग्रतिथि को ऐसी ग्रविध से म्रिधिक दिनों तक ठहरने की म्रनुमित दी जा सकती है, यदि म्रन्य म्रितिथियों के लिये म्रथवा किसी सरकारी प्रयोजन के लिये उस वासस्थान की ग्रावश्यकता न प्रतीत हो । ऐसी ग्रनुमित देने का प्राधिकारी संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट होगा ।

७--- प्रतिथि-गृह, सरिकट हाउस अथवा निरीक्षण गृह में श्रतिथि के नौकरों द्वारा मेज-कुर्सी ग्रादि या ग्रन्य वस्तुर्ग्रों को जो भी क्षति पहुंचेगी उसका उत्तरदायित्व ग्रतिथि पर होगा। इस सम्बन्ध में स्रतिथि से ली जाने वाली धनराशि को स्रतिथि-गृह, सरिकट हाउस स्रथवा निरीक्षण

गृह का प्रभारी ग्रथिकारी निर्धारित करेगा।

५--- स्रतिथि-गृह, सरिकट हाउस अथवा निरीक्षण-गृह के प्रभारी अधिकारी की अनजान में कोई ट्रंक टेलीफोन निकया जायगा। यदि स्रतिथि द्वारा ऐसा कोई टेलीफोन िकया जाय, तो वेइस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में ग्रावश्यक प्रविष्टियां करेंगे श्रौर बिल की प्राप्ति पर टंक-टेलीफोन के व्यय का भगतान कर देंगे ।

ह—-म्रितिथियों की सूचना के लिये म्रितिथ-गृह, सरिकट हाउस म्रौर निरीक्षण-गृहों में नियमावली की एक प्रति टांग दी जायगी।

१०—–जिन ग्रतिथियों को लखनऊ में ग्राने पर परिवहन सम्बन्धी सुविधाग्रों की ग्रावश्यकता हो, उन्हें पहले से गवर्नमेंट इस्टेट ग्राफिसर को भ्रपने ग्राने के समय, स्टेशन, ट्रेन या हवाई जहाज ग्रादि की पूरी सूचना देनी चाहिये। गवर्नमेंट इस्टेट ग्राफिसर ग्रावश्यकतानसार मोटर ग्रथवा ग्रन्य उपयुक्त सर्वारियों की व्यवस्था करेगा भ्रौर ऐसा प्रबंध करेगा कि स्रतिथियों को स्थिति श्रनुकूल रेलवे स्टेशन श्रथवा हवाई श्रड्डे पर, मोटर या सवारियां उपलब्ध हो जायें। मंत्रियों तथा अन्य विशिष्ट जन के साथ शिष्टाचार वरतने (जिसमें उनका स्वागत भी सिम्मलित है) के अनु-देशों पर इस नियम का कोई प्रभाव न पडेगा।

११--गवर्नमेंट इस्टेट ग्राफिसर द्वारा मोटरों की व्यवस्था करने की दशा में उनकी उपलब्धि की शर्तें वहीं होंगी जो सेकेटरियट स्टाफ कार पर लागू हैं और जो एक पृथक् नियमावली से विनियमित होती है। यदि टैक्सियों का प्रबंध किया गया हो तो उनका किराया सरकार देगी।

१२--लखनऊ में ठहरने की अवधि में राज्य अतिथि नगर में आने जाने के लिये स्टाफ कार तथा अन्य सवारियों को, यदि वे उपलब्ध हों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विषय पर पूर्व नियम के उपबन्ध लागू होंगे । यदि टैक्सियों की ग्रावश्यकता हो, तो प्रार्थना क ने पर गवर्नमें इस्टेट म्राफिसर उनकी व्यवस्था करेगा । ऐसी दशा में टंक्सी का किराया सरकार देगी

१३--यि ग्रतिथि लखनऊ के ग्रतिरिक्त ग्रन्य जिलों के मुख्यालय में जायं तो संबंधित जिला मैजिस्ट्रेंट उनके ग्राने-जाने के लिये यथासम्भव सवारियों का प्रबंध करेगा । जो भी खर्चा होगा उसे राज्य सरकार उठायेगी।

भाग २

राज्य ग्रतिथियों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य ग्रतिथि

- १४---(१) राज्य ग्रतिथियों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य व्यक्ति सरकार की ग्रनुमित से ग्रति-रिक्त गृह में ठहर सकते हैं यदि उनके ठहरने के लिये वहां स्थान उपलब्ध हो।
- (२) ऐसी दशा में समय-समय पर प्रचलित शुल्क सूची के अनुसार ठहरने तथा भोजनादि का व्यय अतिथियों द्वारा देय होगा।
- १५—सरकार के आर्देश पर गवर्नमेंट इस्टेट आफिसर, राज्य अतिथियों के अतिरिक्त लखनऊ में आने वाले अन्य व्यक्तियों के भी ठहरने का प्रबन्ध नगर के प्रथम श्रेणी के होटलों में करेंगे। ऐसी दशा में होटल तथा तत्सम्बन्धी अन्य खर्च अतिथियों द्वारा देय होगा।
- १६--इसी प्रकार सरकार के ब्रादेशानुसार जिला ब्रधिकारी राज्य ब्रतिथियों के ब्रतिरिक्त ब्रन्य व्यक्तियों के ठहरने ब्रादि का प्रबन्ध सरिकट हाउस ब्रथवा निरीक्षण-गृह ब्रथवा किसी होटल में करेंगे । ऐसे प्रबन्ध का सारा खर्च ब्रतिथि ही उठायेंगे ।
- १७--(१) लखनऊ में ठहरने की दशा में गवर्नमेंट इस्टेट श्राफिसर ऐसे श्रतिथि को, जिसके वास-स्थान के लिये समुचित प्रबंध करने का उसे सरकार द्वारा श्रादेश प्राप्त हुग्रा हो, मोटर तथा/ ग्रथवा ग्रन्य उपयुक्त सवारियां, जो उस समय उसके पास हों, उपलब्ध करेगा। स्टाफकार ग्रौर सोटर गाड़ियों के प्रयोग सम्बन्धी पृथक् नियमावली के ग्रनुसार ऐसी मोटरों के इस्तेमाल करने का खर्च श्रतिथि स्वयं उठायेंगे। उन सूरतों में जब टैक्सी करनी पड़े, टैक्सी का किराया ग्रतिथि द्वारा देय होगा।
- (२) यदि ग्रतिथि लखनऊ के ग्रतिरिक्त ग्रन्य जिलों के मुख्यालय में जायं, तो संबं-धित जिला मैजिस्ट्रेट जहां तक होगा, उनके ग्राने-जाने के लिये सवारी का प्रबंध करेगा, जिसका खर्च ग्रतिथि स्वयं उठायेंगे।

राज्यपाल की त्राज्ञा से, कालिका प्रसाद भागव, मख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

दिनांक १ जून, १६५४।

सेवा नियम न्याय विभाग

२६ सितम्बर, १६५३

सं० ३४७३/७—-२१३-५१—-भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०६ के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा मिले हुये अधिकारों को काम में लाकर तथा इस विषय के वर्तमान सभी नियमों और आज्ञाओं का अधिकष्मण करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ऐडिमिनिस्ट्रेटर जनरल ऐंड आफिशियल ट्रस्टी के पद के लिये की जाने वाली भर्ती तथा उक्त पद पर नियुक्त व्यक्तियों की नौकरी की वर्तियमन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं—

ऐडिमिनिस्ट्रेटर जनरल ऐंड ग्राफिशियल ट्रस्टी विभाग, १६५३

छोटा नाम ग्रौर प्रारम्भ। १—(१) इन नियमों का नाम "उत्तर प्रदेश ऐडिमिनिस्ट्रेटर जनरल ऐन्ड ग्राफिशियल ट्रस्टी नियम, १९५३" होगा।

(२) यह नियम इस विज्ञप्ति के दिनांक से प्रचलित होंगे।

पद की प्रास्थिति (status)।

२—ऐडिमिनिस्ट्रेटर जनरल ऐन्ड ग्राफिशियल ट्रस्टी का पद गजटेड दर्जे (gazetted rank) का एक निश्चित समय का पद (tenure post) है ग्रीर इसे विशेषज्ञ के पद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें राज्य के ग्रंथीन ग्रंशकालिक (part time) ग्रंसैनिक कर्मचारी के रूप में सेवा-कार्य के लिये नियुक्त किया जाना भी सम्मिलित है।

परिभाषायें

- ३--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियम में--
 - (क) "भारत के नागरिक" का वही ग्रर्थ होगा जो "भारत के संविधान" के ग्रनुच्छेद ५ में दिया हुग्रा है।
 - (ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत के संविधान" से है।
 - (ग) "हाईकोर्ट" का तात्पर्य इलाहाबाद के हाईकोर्ट ग्राफ जुडोकेचर से हैं।
 - (घ) "पद" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ऐडिमिनिस्ट्रेटर जनरल ऐन्ड आफिशियल ट्रस्टी के पद से है।

भर्ती का तरीका

४--पद पर नियुक्ति एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर के की जायगी जो इस नियम के उपबन्धों (provisions) के अनुसार उस पर नियुक्त किये जाने का पात्र हो।

राष्ट्रीयता, श्रधिवास (domicile) तथा निवास-स्थान ।

५--राष्ट्रीयता, श्रिधवास तथा निवास-स्थान (nationality, domicile and residence) सम्बन्धी योग्यता भर्ती के समय प्रचलित नियमों के श्रनुसार होगी।

[इस नियम के जारी किये जाने के समय प्रचलित नियमों की एक प्रति परिशिष्ट में मिलेगी।]

मायु

६--पद पर भर्ती के लिये किसी भी उम्मेदवार की स्रायु ६० वर्ष से ब्रिधिक न होगी ख्रौर यह नियुक्ति इस बात को समुचित रूप से घ्यान में रख कर की जायगी कि उम्मेदवार शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पद पर काम करने वाले व्यक्ति के कार्यकाल (term) को बढ़ाने की दशा में सरकार इस रोक को ढीला कर सकती है।

७--कोई भी व्यक्ति पद पर नियुक्त होने का पात्र तब तक न होगा जब तक कि हाईकोर्ट की सूची में उसका नाम दस वर्ष से कार्य करने वाले ऐडवोकेट के रूप में दर्ज न हो।

पेशे सम्बन्धी योग्यतार्थे।

प्रच-राज्यपाल, हाईकोर्ट से ऐसा परामर्श करने के बाद जो स्रावस्यक समझा जाय, पद पर नियुक्त करेंगे।

नियुक्त करने वाला प्राधिकारी (authority) ।

६--नियुक्त पहली बार सामान्यतः ५ वर्ष के लिये की जायगी; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल, हाईकोर्ट से परामर्श करके, पहिले या बाद के किसी कार्यकाल (tenure) के अन्त में पद के कार्यकाल में ग्रौर ग्राधिक ृद्धि कर सकते हैं जो ५ वर्ष से ग्राधिक न हो।

पद का कार्यकाल

१०—-पद के लिये चुना गया एडवोकेट ग्राम तौर पर ६ महीने के लिये परीक्षण (probation) पर एखा जायगा ग्रौर ऐसी सभी नियुक्तियां सरकारी गजट में विज्ञापित की जायंगी। राज्यपाल किसी भी मामले में, पर्याप्त कारणों के ग्राघार पर, परीक्षण (probation) की शर्त की हटा सकते हैं या उसकी ग्रविध की बढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई वृद्धि की जाने की दशा में वह निश्चित दिनांक बताया जायगा जब तक के लिये वृद्धि स्वीकृत की गयी हो। इस ग्रविध की गणना ५ वर्ष के कार्यकाल में की जायगी।

परीक्षण (probation)।

११—परीक्षण (probation) की स्रविध समाप्त होने पर, परीक्षणी (probationer) राज्यपाल द्वारा उस पद पर दृढ़ (confirm) किया जायगा जिस पर उसकी नियुक्ति हुयी हो, यदि वे उसे दृढ़ किये जाने के उपयुक्त समझें स्रीर उसकी सत्यनिष्ठा (integrity) प्रमाणित (certified) हो। इस प्रकार दृढ़ किया जाना सरकारी गजट में विज्ञापित किया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि परीक्षण (probation) की स्रविध में उसका कार्य या स्राचरण संतोषजनक न रहा हो तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकते हैं स्त्रीर इसके स्राधार पर उसे कोई मुस्राविजा पत्ने का स्रधिकार न होगा।

दृढ़ करना (confirmation)

१२---ऐडिमिनिस्ट्रेटर जनरल ऐण्ड श्राफिशियल ट्रस्टी का मासिक वेतन ४०० रु० या ऐसी रकम होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाय। पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति राज्यपाल द्वारा समय-समय पर नियत (prescribed) रोकों के श्रधीन, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है।

वेतन-क्रम तथा प्राइवेट प्रेक्टिस करने का ग्रधिकार।

१३--पद में ग्रस्थायी रूप से होने वाली रिवितयां (vacancies) भरने के लिये नियुक्तियां उसी रीति से की जायंगी जिसकी व्यवस्था ऋमशः नियम द ग्रीर ६ में की गयी हैं, सिवाय उन दशाग्रों के, जब स्थानापन्न, कार्यकारी रूप से या छुट्टी के कारण रिक्तियां (officiating acting or leave vacancies) हों ग्रीर ऐसी दशाग्रों में उन्हें राज्यपाल स्थायी रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति की सिफारिश पर विचार करके भर सकते हैं।

पदों पर ग्रस्थायी या स्थानापन्न रूप से नियुक्ति।

१४—-ऐसे ऐडिमिनिस्ट्रेटर जनरल, हेड ग्राफिशियल ट्रस्टी पद पर, जिसे स्वास्थ्य-सम्बन्धी सीटिफि हेट पर या ग्रन्य किसी कारण से ग्राधे ग्रौसत वेतन पर छुट्टी स्वीकृत की जाय या जिसे ग्रसाधारण छुट्टी स्वीकृत की जाय या किसी ग्रसाधारण छुट्टी स्वीकृत की जाय या किसी ग्रन्य नियुक्ति के सिलसिले में स्थानान्तरित किया जाय, स्थानापन्न रूप से कार्य

पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति का वेतन। करने के लिये नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति पद का पूरा वेतन पाने का अधिकारी होगा। लेकिन यदि ऐडिमिनिस्ट्रेटर जनरल ऐंड आफिशियल ट्रस्टी हाईकोर्ट, की छुट्टी (vacation) के समय में छुट्टी ले और यदि हाईकोर्ट की ऐसी छुट्टी के समय उसके स्थान पर किसी व्यक्ति (substitute) की नियुक्ति करना आवश्यक हो जाय तो उस दशा में स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति (officiating incumbent) को दिये जाने वाला वेतन और स्थायी रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति कार्य करने वाले व्यक्ति (officiating incumbent) को दिये जाने वाला वेतन और स्थायी रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति को औसत वेतन के स्थान पर दिया जाने वाला छुट्टी वेतन (leave salary) राज्यपाल निश्चित करेंगे।

हटाया जाना श्रौर मुश्रत्तली। १५--एडिमिनिस्ट्रेटर जनरल ऐंड आफिशियल ट्रस्टी को उसके कार्यालय में किसी भी समय दुराचरण या कर्तव्य-विमुख होने (dereliction of duty) के कारण या ग्रन्य पर्याप्त कारणों से हटाने या मुग्रत्तल करने का ग्रिधिकार राज्यपाल ग्रपने लिये सुरक्षित रखते हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ग्रिधिकारी इस प्रकार तब तक न हटाया जायगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में की जाने वाली प्रस्ताबित कार्यवाही के विरुद्ध उसे कारण दिखाने का समुचित ग्रवसर न दिया गया हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि उन दशाख्रों में उसको ऐसा स्रवसर देना स्रावश्यक न होगा :---

- (क) जब वह ऐसे ग्राचरण के ग्राधार पर हटाया गया हो, जिसके फलस्वरूप किसी ग्रपराध लगाये जाने (criminal charge) पर उसका ग्रपराध सिद्ध (conviction) हुआ हो,
- (ख) जब राज्यपाल इस बात से संतुब्द हों कि किसी कारण से सम्बद्ध श्रीधकारी को कारण दिखाने का श्रवसर देना युक्ति-रूप से न्यावहारिक नहीं है श्रीर इस सम्बन्ध में राज्यपाल का निर्णय श्रीतम होगा,
- (ग) जब राज्यवाल इस बात से संतुष्ट हों कि सम्बद्ध ग्रिधकारी को ऐसा श्रवसर देना राज्य की सुरक्षा के हित में उचित श्रीर श्रावश्यक नहीं है, श्रीर इस सम्बन्ध में राज्यपाल का निर्णय श्रंतिम होगा।

छुट्टी, भत्ते ग्रौर नौकरी की ग्रन्य शर्तों का विनियमन । १६--- जस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इस नियम में की गयी है, पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति के वेतन, भत्ते, छुट्टी ग्रौर शास्ति (penalty) लगाये जाने तथा नौकरी की ग्रन्य शतें संविधान के ग्रनुच्छेद ३०६ के प्रतिबन्धात्मक खंड के ग्रधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियम से विनिय-मित होंगी ग्रौर ऐसे नियम में जारी किये जाने तक, उस नियम द्वारा विनियमित होंगी जो गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया ऐक्ट, १६३५ की धारा २४१(२)(बी) के ग्रधीन बनाये गये हैं ग्रौर संविधान के ग्रनुच्छेद ३१३ द्वारा प्रचित्त रखे गये हैं।

समिति की कार्यवाही

मुख्य मंत्री की भ्रध्यक्षता में सामान्य प्रशासन स्थायी परामर्शदात्री सिमिति की दिनांक ११ जून, १९५५ की बैठक की कार्यवाही (संक्षेप में) सभापति द्वारा प्रारंभिक शब्द

(मद संख्या १)

मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि इस मद के बारे में उन्हें कोई विशेष बात नहीं कहनी है। एक सदस्य ने कहा कि सिमित की कार्यसूची ग्रीर उसकी टिप्पणियों की सूचना उनको बिल्कुल नहीं प्राप्त हुयी। मुख्य मन्त्री जो ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में कार्यसूची ग्रीर टिप्पणियों की सूचना सभी सदस्यों की बैठक के दिनांक के काफी पहले मिल जानी चाहिए।

२—समिति को सूचित किया जाय कि सरकार ने खाद्य तथा रसद विभाग श्रौर सहायता तथा पुनर्वास विभाग के श्रफसरों को यू० पी० सिविल सर्विस (इक्जीक्यूटिव ब्रांचों) में भर्ती करने के लिये स्वीकार कर लिया है।

(मद संख्या २)

डा० ईश्वरी प्रसाद ने पूछा कि क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि लाद्य तथा रसद विभाग श्रौर सहायता तथा पुनर्वास विभाग के उन ग्रफसरों की, जिनको उत्तर प्रदेश सिविल सिवस (एक्जीक्युटिव ब्रांच) में भर्ती करने का प्रस्ताव है, ईमानदारी के सम्बन्ध में ख्याति श्रच्छी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय लेकर सम्भवतः सरकार लोक सेवा श्रायोग की श्रवहेलना कर रही है। सुख्य मंत्री ने उन्हें यह वतलाया कि ऐसी वात नहीं है। इस मामले का उल्लेख पहले ही लोक सेवा श्रायोग को कर दिया गया है ग्रौर इस सम्बन्ध में ग्रन्तिम ग्रादेश लोक सेवा ग्रायोग की सम्मित प्राप्त होने के बाद ही जारी किये जायेंगे।

मुख्य सिचव ने सिमिति को यह भी सूचना दी कि खाद्य तथा रसद एवं सहायता तथा पुनर्वास विभागों ने अपने कर्मचारियों को "क", "ख" तथा "ग" तीन श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। ईमानदारी के सम्बन्ध में जिन अफसरों की ऊंची ख्याति थी और जिन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है उन्हें श्रेणी "क" में रक्खा गया है और प्रस्तावित भर्तों के लिए केवल उन्हों अफसरों में से विचार किया जा रहा है। मुख्य सिचव ने यह भी बताया कि प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की सूचियां, जिनमें उनकी अर्हता, सेवा अवधि इत्यादि के बारे में विस्तृत सूचना दी गयी है, सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रकाशित की गयी है। डा० ईश्वरी प्रसाद ने यह सुझाव दिया कि सूची "क" की प्रतियां स्थायी सिमित के सदस्यों में बांटी जानी चाहिए। मुख्य मन्त्री ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

३--किसइनरों को यह ग्रादेश दिया गया है कि वे शासन के प्रत्येक ग्रंगों में दक्षता लाने के निमित्त मौके पर जा कर जांच करें।

(मद संख्या ३)

श्री सुल्तान श्रालम खां ने पूछा कि क्या किम इनर एक महीने में २० दिन दौरे पर रहते हैं? मुख्य सिचव ने उन्हें यह बताया कि कुछ किम इनरों को इतने दिन दौरे पर रहने में किठनाई हो रही है। जैसे डिप्टी किम इनर, इन्चार्ज कुमायूं डिवीजन, महीने में २० दिन तक श्रपने क्षेत्र का दौरा नहीं कर सके क्योंकि उनके क्षेत्र में यातायात के उचित साधन नहीं थे। इसी प्रकार किम इनर, इलाहाबाद डिवीजन भी दौरे पर नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें आ किसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद के प्रिसिपल का काम करना था। मुख्य सिचव ने यह भी बताया कि सामान्यतया किम इनरों को महीने में २० दिन दौरे पर रहने में कोई किठनाई नहीं होनी चाहिए, किन्तु कितपय विशेष परिस्थितयों में नियम में शिथिलता की आवश्यकता हो सकती है।

श्री सुल्तान स्रालम खां ने पूछा कि क्या स्थानीय निकायों के निरीक्षण की जिम्मेदारी स्रव भी किमिन्नरों पर है ? मुख्य सिचव ने बताया कि स्थानीय निकायों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी श्रव जिला मैजिस्ट्रेटों को सौंप दी गयी है। श्री सुल्तान ग्रालम खां ने सुझाव दिया कि श्रच्छा हो यदि स्थानीय निकायों का निरीक्षण पहिले की भांति कमिश्नर ही करें। उत्तर में मुख्य सचिव ने कहा कि किमइनरों की कार्यवाहियों का पुनर्संगठन हो जाने के कारण, उन्हें इस कार्य के लिए समय निकालना बहत कठिन हो गया है।

श्री नौरंगलाल ने पूछा कि सरकार को किमइनरों के दौरे की ग्रविध ग्रौर सीमा का कैसे पता लगता है ? मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि कमिश्नर डायरी रखते हैं श्रीर सरकार को पाक्षिक श्रर्द्ध-सरकारी पत्र भेजते हैं, जिसमें उन के दौरे ग्रौर उनके क्षेत्र की विभिन्न ग्रन्य कार्यवाहियों के बारे में सूचना दी रहती है। श्री नौरंगलाल ने सुझाव दिया कि ऐसे प्रत्येक पाक्षिक ग्रर्द्ध-सरकारी पत्रों की प्रतियां सदस्यों में सूचनार्थ बांटी जानी चाहियें। मुख्य मन्त्री ने दुख प्रगट किया कि पाक्षिक ग्रर्द्ध सरकारी पत्रों की प्रतियां सदस्यों को नहीं दी जा सकतीं, क्योंकि उनमें विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में गोपनीय सूचनायें भी रहती हैं।

डा० ईश्वरी प्रसाद ने विचार प्रगट किया कि पुनर्संगठित प्रशासकीय ढांचे में किसश्नरों की परिवर्तित विचारधारा रखना श्रावश्यक है । उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे श्रपने क्षेत्रों का श्रच्छी तरह दौरा करें, तो राज्य में प्रशासन की क्षमता ग्रौर भी बढ़ जायगी। मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि श्रभों हाल में भारत सरकार के कुछ श्रफसरों ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का दौरा किया ग्रौर उन की रिपोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्टों से सामान्यतया मिलती-जुलती हैं। किन्तु एक मामले में भारत सरकार के ग्रफसरों ने यह बताया कि शिक्षा विभाग राष्ट्रीय प्रसार सेवा ब्लाकों ग्रौर सामुदायिक योजनाग्रों द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्य में सिकय सहयोग नहीं दे रहा है। मुख्य मन्त्री ने कहा कि उन्होंने शिक्षा विभाग का ध्यान इस स्रोर दिलाया स्रोर स्रावश्यक स्रनुदेश स्रवश्य जारी कर दिये गये होंगे । मुख्य मन्त्री ने सदस्यों को यह भी सूचना दी कि भारत सरकार के ग्रफसर, जो इस राज्य के दौरे पर थे, जिलों में किये गये कार्यों से बहुत प्रभावित हुये।

मुख्य मन्त्री ने ग्रागे बताया कि कमिश्नरों के बार-बार दौरा करने से बहुत लाभ हो रहा है। इस बात के ग्रतिरिक्त कि वे जिला श्रफसरों को श्रपनी सम्मति सदा देते रहते हैं, उनकी उपस्थित से स्थानीय समस्यात्रों जैसे जिला मैजिस्ट्रेट श्रौर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के पारस्परिक भेद-भाव के मामलों का ग्रिभिन्नरूप से सन्तोषजनक हल हो जाता है।

श्री नौरंगलाल ने सुझाव दिया कि कमिश्नरों को उनके क्षेत्र में जिला नियोजन सिमितियों की बैठकों में भाग लेने का श्रादेश दिया जाय जिससे कि उनकी उपस्थिति से ऐसी सिमितियों के सदस्य कार्य के प्रति निरन्तर सावधान श्रौर जागरुक रहें। मुख्य सचिव ने कहा कि चूंकि जिला मैजिस्ट्रेट ऐसी समितियों के सभापित होते हैं, श्रतः किमश्नरों को जिला नियोजन सिमितियों की बैठकों में भाग लंने के लिए कहना उनको ग्रसमंजस में डालना होगा। इसके ग्रतिरिक्त यदि कमिश्नर नित्य नियोजन सिमितियों की बैठकों में बार-बार भाग लेंगे तो नियोजन कार्य के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेटों के उत्तर-दायित्व में कमी श्रा जायगी।

मुख्य सचिव ने श्री नौरंगलाल को यह भी सूचना दी कि नियोजन विभाग ने अन्य विभागों की सहपति से यह ब्रादेश जारी किये हैं कि इन सिमितियों में केवल उत्तरदायी ब्रफसरों को ही विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के रूप में मनोनीत किया जाय। फिर भी श्री नौरंगलाल ने यह विचार प्रगट किया कि जिला नियोजन सिमितियों के सदस्यों का किमइन्रों के साथ किसी न किसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करना नितात स्रावश्यक है। इस पर मुख्य मन्त्री ने कहा कि कमिश्नरों को जिलों के दौरे के समय जिला नियोजन सिमितियों के सदस्यों से अरी तक रूप से मिलने के लिए अनुदेश दे दिये जायेंगे।

४--इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा श्रधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती (मद संख्या ४)

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ने बताया कि इस बात की बड़ी शिकायत है कि नौकरी के लिए नामों की सिफारिश करने में इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के कर्मचारी बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बेरोजगारी विशेषकर शैक्षिक संस्थास्रों से निकलने वाले विद्यार्थियों में तेजी से बढ़ रही है। श्री राधाकान्त जी ने स्थिति को स्पष्ट किया श्रीर कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नौकरी के लिए निम्नलिखित ६ प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं:---

१-- उन्मक्त सरकारी कर्मचारी।

२--उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत, बलचिस्तान ग्रौर सिंध के विस्थापित स्थायी सरकारी कर्मचारी।

३--केन्द्रीय सरकार ग्रौर पार्ट "सी" स्टेट के वे कर्मचारी जिनकी छटनी होने की सम्भावना हो, बंटवारा के पहिले के सिंध और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के ऐसे भतपूर्व सरकारी कर्मचारी जिन्होंने देशभिक्त सम्बन्धी कार्यवाहियों के कारण त्यागपत्र दे दिया था या जिन्हें सेवा से हटा दिया गया था, उन्मुक्त कर दिया गया था या बर्जास्त कर दिया गया था ग्रीर पुनर्वासन वित्त प्रशासन के ग्रतिरिक्त कर्मचारी।

४--विस्थापित ग्रस्थायी सरकारी कर्मचारी।

५-- उन राज्यों के जो पाकिस्तान में मिल गये हैं, विस्थापित कर्मचारी माही, कारीकल श्रौर भारत में ग्रन्य फ़ांसीसी बस्तियों से श्राये हुए शरणार्थी।

६--ग्रन्य व्यक्ति।

श्री राधाकांत ने कहा कि उन्मुक्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या ग्रभी भी बहुत है श्रीर इस कारण नौकरी के लिए विभिन्न इक्षिक संस्थाओं से निकले हुए नवयुवकों के नामों की सिफारिश करना ग्रसम्भव है । उन्होंने बताया कि वे भारत सरकार ग्रौर उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए लिख चुके हैं कि इस विषय पर पुनः विचार किया जाय और ४० से ५० प्रतिशत खाली जगहों को नवागन्तुकों द्वारा भरे जाने की अनुमति दी जाय। उन्होंने कहा कि मामला अब भी सरकार के विचाराधीन है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद के पूछने पर श्री राघाकान्त ने बताया कि लोक सेवा श्रायोग (पब्लिक र्सीवस कमीशन), रेलवे, म्राडिटर जनरल, हाई कोर्ट, रक्षा मंत्रालय, एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश के कार्यालय ग्रौर भारत सरकार के ग्रन्य कार्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती से इम्प्लायमेंट एक्सचेंज

का कोई सम्बन्ध नहीं है।

मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि इम्प्लायमेंट एक्सचेंज का संचालन भारत सरकार द्वारा हो रहा है। यद्यपि उन पर होने वाले व्यय का कुछ भाग राज्य सरकार को भी वहन करना पड़ता है । कुछ समय पूर्व जब कि इस संगठन को यथावत् बनाये रखने का निश्चय किया गया था, इस संगठन को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के प्रक्त पर गौर किया गया था। मुख्य सचिव ने कहा कि यद्यपि वे इम्प्लायमेंट एक्सचेंज की पैरवी तो नहीं करते किन्तु वे संगठन को सुदृढ़ बनाने के पक्ष में हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा भर्ती करने की प्रणाली कड़ाई से ग्रपनायी जाय श्रौर इस सम्बन्ध में जो ग्राज्ञा जारी की जा चुकी है उस पर पुनः जोर दिया जाय।

इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के भ्रष्टाचार का डाक्टर प्रसाद द्वारा श्रौर उल्लेख करने पर मुख्य मन्त्री जी ने उन्हें परामर्श दिया कि वे भ्रष्टाचार के विशिष्ट उदाहरण श्री राधाकान्त जी की जानकारों में लावें । मुख्य मन्त्री जी ने डा० प्रसाद को ग्राश्वासन दिया कि श्री राधाकान्त उन मामलों में वैयक्तिक रूप

से कार्यवाही करेंगे।

श्री नौरंगलाल ने सुझाव दिया कि इस पर श्रगली बैठक में विचार किया जाय। उस समय तक श्रीर अधिक सूचनायें प्राप्त हो जायंगी श्रीर श्री राधाकान्त जी को डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी द्वारा बताये गये भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने का ग्रवसर भी प्राप्त हो जायगा। श्री लाल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

परिशिष्ट ३ प्रतिमित ग्रालेख्य प्रपत्र १—शासकीय ग्रादेश

	(1641)
प्रेषक,	
	श्री
	•••••
	••••••••••
सेवा में,	
	उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख ग्रध्यक्ष ।
	लखनऊ, दिनांकित
	यदक्षता श्रर्गल पर रोके गये सरकारी कर्मचारियों के मामलों का वार्षिक पुनरावलोकन ।
	पुनरावलाकन ।

महोदय,

नियुक्ति (क) विभाग।

मुझे यह निवेदन करने का श्रादेश हुश्रा है कि किसी मामले में वेतन वृद्धि रोकने की श्राज्ञा देते समय, ऐसी श्राज्ञा देने वाले प्राधिकारी को फंडामेंटल रूल २४ के ग्रन्तर्गत सब बातों के साथ-साथ यह भी बता देना चाहिये कि किस श्रविध तक के लिये वेतन-वृद्धि रोकी जा रही है। किन्तु दक्षतार्गल पर रोक लगाने की दशा में, नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, श्रर्थात् उस दशा में दंडाज्ञा में यह उल्लेख करना श्रावश्यक नहीं है कि किस श्रविध तक संबंधित सरकारी कर्मचारी को दक्षतार्गल पर रोक रखा जाये। नियमों में ऐसी व्यवस्था न होने से तथा ऐसे मामलों में कालिक पुनरावलोकन करने के बारे में कोई श्रनुदेश न होने के फलस्वरूप कभी-कभी इसकी भी सम्भावना रहती है कि दक्षतार्गल पर सरकारी कर्मचारी श्रधिक समय तक रोक लिये जाते हैं जो न्यायोचित नहीं है, श्रर्थात् उन कारणों के, जिनकी वजह से दक्षतार्गल पर रोक लगायी गई थी, विलीन होने पर भी वह रोक हटाई नहीं जाती। इस प्रकार की देरी दूर करने की दृष्टि से यह श्रावश्यक है कि दक्षतार्गल पर रोक लगाने की श्राज्ञा देने वाले प्राधिकारी उन समस्त कर्मचारियों के मामलों का जो दक्षतार्गल पर रोक लिये गये हैं, वार्षिक पुनरावलोकन करें जिससे कि यह श्रवधारित किया जा सके कि क्या उनके काम में इतना सुधार हुश्रा है, श्रौर क्या साधारणतया वे दोष जिनके कारण दक्षतार्गल पर रोक लगायी थी इस सीमा तक दूर हो गये हैं कि वह रोक हटा ली जाय।

२--में यह प्रार्थना करूंगा कि इस सरकार के नियामक नियंत्रण के अधीन अधिकारियों के सम्बन्ध में पथप्रदर्शन के लिये उक्त निर्णयों पर कृपया ध्यान दिया जाय ।

भवदीय,

मुख्य सचिव।

संख्या (१)

प्रतिलिपि सिचवालय के समस्त विभागों को सूचनार्थ तथा उनके पथप्रदर्शन के लिये

त्राज्ञा से, •••••• मुख्य सचिव।

(7)				
(1)				
	सं०.		•	•

प्रेषक,

थ्री

सेवा में,

सेकेटरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

महोदय,

मुझे श्राप से यह कहने का श्रादेश मिला है कि सहायक जिला पंचायत श्रिधिकारियों के ५१ पदों में से १३ पद १ श्रप्रैल, सन् १९५४ से स्थायी किये गये हैं। इन पदों पर १३ स० जि० पं० श्र० को स्थायी करने का प्रश्न शासन के समक्ष प्रस्तुत है।

२—स० जि० पं० ग्रधिकारियों की नियुक्ति एवं सेवा संबंधी नियम नहीं बने हैं। उनका चुनाव करने के हेतु कमीशन की सहमित से शासकीय पत्र संख्या ११६६२/पं० रा० वि० (१)—-१२३-१०, दिनांक २३-१२-५० में उिल्लिखत नियम निर्धारित किये गये थे। उक्त नियमों के ग्रन्तर्गत ४६ स० जि० पं० ग्रधिकारियों का चुनाव पंचायत निरीक्षकों के मध्य से पदोन्नति दे कर एक निर्वाचन समिति द्वारा किया गया था जिनके नाम कमीशन के पास शासकीय पत्र सं० ३२८६/पं० रा० वि० (१)—-२५७-५०, दिनांक २४-४-५१ के साथ ग्रनुमोदन के हेतु भेजे गये थे। इस विषय पर कुछ पूछ-ताछ करने के पश्चात् कमीशन ने निर्वाचन समिति के द्वारा चुने हुए स० जि० पं० ग्रधिकारियों के निर्वाचन का ग्रनुमोदन ग्रपने पत्र संख्या जी-१२३३(३)/रेग—-५०-५१, दिनांक ३० नवम्बर, १६५१ द्वारा ग्रन्तिम रूप से किया था।

३—स० जि० पं० ग्रधिकारियों के ग्रवशेष दो पदों पर सीधी भर्ती द्वारा कमीशन की सहमित से सर्वश्री (क) तथा (ख) को नियुक्त किया गया था।श्री (क) विलीनीकृत काशी राज्य के स्थायी जिला प्रधान सेवादल थे। इनकी नियुक्त उक्त ४६ स० जि० पं० ग्रधिकारियों के चुनाव के पूर्व ही हो चुकी थी। श्री (ख) का पद गजटेड है ग्रौर ग्रन्य स० जि० पं० के ५० पद काडर के बाहर है। इस पद का वेतन कम भी २५०—५५० रु० है जब कि शेष स० जि० पं० ग्र० के पदों का वेतन कम २००-४०० रु० है। इसी कारण श्री (ख) के स्थायीकरण के प्रश्न पर इस प्रसंग में विचार नहीं किया जायगा। उनके स्थायीकरण का विषय ग्रलग से शासन के विचारधीन है। यहां पर केवल श्री (क), विलीनीकृत काशी राज्य के स्थायी कर्मचारी तथा ग्रन्य १२ स० जि० पं० ग्रधिकारियों को स्थायी करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

४—-ग्रब सवाल यह है कि स० जि० पं० ग्रिधिकारियों का स्थायीकरण किस विधि के ग्रधीन किया जाय। उपर्युक्त शासकीय पत्र, दिनांक २३-१२-५० के ग्रन्तगंत यह निर्धारित किया गया था कि स० जि० पं० ग्र० का निर्वाचन ग्रन्य ग्रावश्यक बातों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदारों के पदों पर नायब तहसीलदारों को पदोन्नति देने के सम्बन्ध में लागू नियमों के ग्राधार पर किया जायेगा। ग्रतएव यह उचित ही जान पड़ता है कि उनका स्थायीकरण भी उसी विधि के ग्रधीन किया जाय जो तहसील-दारों के स्थायीकरण के विषय में लागू होती है।

५—तहसीलदारों के विषय में लागू विधि के ग्रन्तर्गत निर्वाचन समिति द्वारा तथा कमीशन के परामर्श के बाद ग्रन्तिम रूप से निर्वाचित तहसीलदारों को दो साल के लिये परीक्षण पर रख दिया जाता है। इसी बीच में इनको कुछ वैभागिक परीक्षाएं पास करनी होती हैं। उकत दो साल का परीक्षण समाप्त होने पर, जो तहसीलदार वैभागिक परीक्षाएं पास कर लेते हैं तथा जिनका कार्य उनकी चरित्र पुस्तिकाएं देखने से संतोषजनक समझा जाता है, वे उसी क्रम में स्थायी कर दिये जाते हैं जिस कम में निर्वाचन समिति द्वारा तथा कमीशन के परामर्श से उनकी सूची बनायी जाती है। यदि उनमें से किसी तहसीलदार का कार्य परीक्षणकाल में ग्रसंतोषप्रद पाया जाता है ग्रथवा वह वैभागिक

परीक्षा पास करने में ग्रसमर्थ रहता है, तो उसका परीक्षण-काल कुछ समय के लिये ग्रौर बढ़ा दिया जाता है ग्रथवा स्थायीकरण तब किया जाता है जब वह वैभागिक परीक्षा पास कर लेता है।

६—शासन का मत है कि उपर्युक्त विधि का अनुसरण स० जि० पं० अधिकारियों के स्थायी-करण के सम्बन्ध में भी किया जाय। स० जि० पं० अधिकारियों के लिये कोई वैभागिक परीक्षा निर्धारित नहीं है। उनको एक प्रकार का शिक्षण वैभागिक नियमों व अधिनियमों के विषय में दिया जाता है। उसके उपरान्त उनकी परीक्षा होती है और अंक दिये जाते हैं। शासन की राय में यह शिक्षण उनकी वैभागिक परीक्षा के रूप में मान लिया जाय तथा स्थायीकरण के लिये उक्त शिक्षण में ५० प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य कर दिया जाय।

७—स० जि० पं० ग्रधिकारियों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति सन् १६५१ से कार्य कर रहे हैं। ग्रतः उनकी पिछली सेवायें परीक्षण-काल के रूप में मान ली जायं ग्रौर उनकी परीक्षण पर न रखा जाय। यदि किसी स० जि० पं० ग्र० का कार्य कुछ संतोषजनक समझा जाय ग्रथवा उसको शिक्षण की परीक्षा में ५० प्रतिश्चत के ग्रंक न उपलब्ध हुए हों तो उसका कार्य कुछ समय के लिये ग्रौर देखा जाय ग्रथवा उसको फिर से शिक्षण की परीक्षा पास करने का ग्रवसर दिया जाय। कार्य संतोषजनक पाय जाने पर ग्रथवा शिक्षण की परीक्षा में पास होने भर के ग्रंक प्राप्त कर लेने पर उसको स्थायी घोषित कर दिया जाय।

५—इस प्रसंग में एक बात श्रौर ध्यान देने की यह है कि तहसीलदार के पदों के लिये निर्वाचित नायब तहसीलदारों के नाम, उनकी नायब-तहसीलदारी की ज्येष्ठता के कम में रखे जाते हैं। इसके विपरीत स० जि० पं० ग्रधिकारियों के पदों के लिये निर्वाचित पंचायत निरीक्षकों की सूची श्रेष्ठता के कम में बनायी गयी थी। इसका कारण कमीशन को शासकीय पत्र दिनांक २४—४—५१ के परिच्छेद ४ द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था ग्रौर कमीशन ने इस पर कोई श्रापित्त नहीं प्रकट की थी। ग्रतः यह विश्वास किया जाता है कि स० जि० पं० ग्र० का स्थायीकरण उसी कम में किया जायगा जिस कम में उनके नाम चुनाव समिति द्वारा रखे गये थे ग्रौर कमीशन द्वारा ग्रमुमोदित हुए थे।

ग्राप से ग्रनुरोध है कि उपर्युक्त सारी स्थिति को कमीशन के समक्ष प्रस्तुत कर के स० जि० पं० ग्रिधिकारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति के विषय में उनकी सलाह प्राप्त करें तथा तदनुसार शासन को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय,

सचिव।

प्रेषक,

(3)

श्री.....

जिलाधीश,

जालौन।

सेवा में,

सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग,

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

संख्या २४६/१४--६७

दिनांक ७ ग्रक्तूबर, १६५५।

महोदय,

शासकीय स्मृतिपत्र संख्या २८८-एम० जी०/३--६३६-५१, दिनांक २७/२८ सितम्बर, १६५५ के उत्तर में निवेदन है कि श्री 'क' के पुत्र श्री 'ख' को उसके पिता की ग्रविशष्ट कुल पेन्शन १६६ रु० ७ ग्राना का, एकाउन्टेन्ट जनरल, इलाहाबाद की स्वीकृति से २५ ग्रप्रैल, १६५५ को भुगतान किया जा चुका है।

भवदीय, (ह०) जिलाधीश, जालौन।

२-- ऋई-शासकीय पत्र

श्रद्धं शासकीय पत्र संख्या..... विभाग.....

सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ, दिनांकित.....

Яय

मुझे स्राप से यह निवेदन करने के लिये कहा गया है कि स्रापने जो स्थित बतायी है उसे देखते हुए सरकार इससे सहमत है कि श्री 'क' को १४ नवम्बर, १६४४ से ३१ मार्च, १६४६ की स्रविधितक स्रोर भारत सरकार की सेवा में रहने दिया जाय ।

भवदीय,

मुख्य सचिव।

सचिव, भारत सरकार,

गृहमंत्रालय,

नई दिल्ली, २।

3	f	वज्ञ	प्ति	
उत्तर	प्रदे	श	सरव	नार

३——विज्ञप्ति
उत्तर प्रदेश सरकार
विभाग
संख्या
लखनऊ, दिनांक
विज्ञप्ति ;
नियुक्ति
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सिचव की शाखा के उप-सिचव श्री 'क' की नियुक्ति उर शाखा में एक नवनिर्मित ग्रस्थायी पद पर संयुक्त सिचव के रूप में की जाती है।
मुख्य सचिव ।
संख्या
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित—
१—–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
२ उत्तर प्रदेश गुजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने के लिये अधीक्षक, मुद्रण त
लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
३सम्बन्धित ग्रधिकारी । ४तिचवालय प्रशासन विभाग (लेखा) ।
५सचिवालय प्रशासन विभाग (श्रिधिष्ठान) ।
ग्राज्ञा से,
संयुक्त सचिव।
४—–स्मृति-पत्र
उत्तर प्रदेश सरकार
विभाग
विभाग संख्या
लखनऊ, दिनांकित१६ ई
कार्यालय स्मृति-पत्र
विषय
मुझे ब्रादेश दिया गया है कि में ब्रापका ध्यान पार्श्विलिखित पत्र-व्यवहार की ब्रो दिलाऊं ब्रोर ब्रापसे यह पूछं कि इस सम्बन्ध में ब्रापके उन्हर की क्रा
, 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
पत्र संख्या विनांक
tenture
श्री सहायक सचिव।

.58

५--द्रतगामी-पत्र

	•	
प्रेयक		127,000
, श्री		•
	उप सिचव,	
	उत्तर प्रदेश।	(1900) \$ 100
सेवा में,	ra de ser sedetat	1274
		antipp ante
	A Commission of the Commission	super versual Propries
संख्यालखनउ	ਫ਼ ਟਿਜ਼ਾਂਕਿਤ	entropy to the first course and a section of
(41)	7) (4)(((4)((("" O THE STREET
	नियुक्ति (क) विभाग	व्यामात्राची सुरूपाना
श्री श्रय्पास्वामी की उप- दिनांकित	-संचालक के रूप में नियुक्ति से स के कम में।	म्बन्धित सरकारी तार संख्या
पद का वेतन भारतीय काल वेतनकम में विनियक्षित होगा। वेतन भी प्राप्य होगा।	प्रशासकीय सेवा (इंडियन ऐडिम साथ ही पदवारी को २०० रु	निस्ट्रेटिव सर्विस) के वरिष्ट प्रति महीने का एक विशेष
ग्रभी यह पद ग्रस्थायी है	ग्रौर १ जनवरी, १६५६ तक स्वीव	कृत किया गया है।
	इसका निर्गमन प्रधिकृत है)	
	to be the statement	
	har extly any more en	उत्तर प्रदेश सरकार के
	es) des esces de conselsé sejs	उप सचिव।
	A Property of the Contract of	

६—तार
बुतगामी .
सरकारी
होम इन,
नई दिल्ली,
संख्या/नियुक्ति सम्बन्धी श्राप का तार संख्या
पुलिस दिनांकित/श्री 'क' को शीघ्र ही कार्यभार मुक्त करने के प्रबन्ध वि
जा रहे हैं किन्तु यह निश्चय नहीं कि उनकी सेवायें १४ नवम्बर, १९४४ तक अवश्य ही उपलब्ध हो सकेंगी
उपाव
तार करने के लिये नहीं :
लखनऊ, दिनांक
(क ख ग)
उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसचिव,
नियुक्ति (क) विभाग
The second secon
उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति (क) विभाग
संख्या
लखनऊ, दिनांकित१६ ई०
प्रतिलिपि निम्नलिखित को डाक द्वारा पुष्टि स्वरूप प्रेषित :
१भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव, नई दिल्ली।
२ उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस, लखनऊ । कृपया श्री 'क' को शीघ्र ह कार्यभार मुक्त करने के प्रबन्ध किये जायें। भारत सरकार के पत्र संख्या
दिनांककी एक प्रतिलिपि भी सूचनार्थ संलग्न है।
Manual danial B

श्राज्ञा से, श्रनु सचिव।

७-- श्रनुस्मारक

अनुस्मारक		
	संख्या	/३
प्रेषक,		
থী,		
ग्रनु सचिव,		
उत्तर प्रदेश सरकार ।		
सेवा में,		
পী	,	
••••		
	लखनऊ, दिनांक१६	1
	विषय	
THE PARTY NAMED AND ADDRESS OF	SALES STREET, SALES	
	निर्देश	
त्राप का पत्र-संख्या	दिनांक •••••	
नहोदय,		

मुझे आप से यह पूछने का आदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देश के सम्बन्ध में आपके दूसरे पत्र की कब तक आशा की जाय

भवदीय, स्रनु सचिव । सामान्य त्रशासन विभाग।

=--स्वास्थ्यं परीक्षा प्रपत्र

	संख्या।	
	म्रेंचक,	
	श्री,	
	उप-प्तचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ।	
	सेवा में,	
	सिविल सर्जन के सहायक, लखनऊ ।	
	लक्षनऊ, दिनांकित१६ ई	0 1
	महोदय,	
सचिवालय प्रशासन विभाग	सचिवालय के सहायक कर्सचारी श्री 'क' के सम्बन्ध में सूचना मिली है कि वे शीतज्वर पीड़ित होने के कारण काम पर श्राने में श्रसमर्थ हैं। कृपया उनके स्वास्थ्य की परीक्षा करके लिलि कि उन्हें नैयमिक छुट्टी दी जाय या नहीं, श्रीर यदि दी जाय तो कितने दिनों के लिये।	: से खये
(ग्रधिष्ठान)	२श्री 'क' से कह दिया गया है कि ग्रापके पास स्वास्थ्य परीक्षा के निमित्त उपसि	थत
	भववीय,	
	उप सिचव की ग्रोर से	1
	संख्या (१)/२०	
	तात्कालिक श्रनुपालन के लिये प्रतिलिपि श्री 'क' को भेजी जाती है। सूचनार्थ प्रतिलिपिविभाग को भे	2-A
	जाती है।	
TOTAL S	्राप्ता होत्व नामाण के भागमण के मंद्री के हाका हो। विकास के प्राप्ता के उप सचिव की खाजा र	
2.000	the section of the se	

THE PARTY

THE PARTY PAR

€3

६--चैकित्सिक मत का प्रपत्र

	संख्या /२०	
प्रेषक,		
	প্রী,	
सेवा में,	उप सिचव, उत्तर प्रदेश सरकार ।	
	सिविल सर्जन।	

महोवय.	लखनऊ,१६ ई०	1

उत्तर प्रदेश सिववालय के सहायक कर्मचारी श्री 'क' १ ग्रगस्त, १६४४ से चैकित्सिक छुट्टी पर हैं। उन्होंने ग्रब एक ऐसे गैर-सरकारी चिकित्सक का प्रमाण-पत्र दिया है जिसने सिववालय सिकारिश की है कि उनकी छुट्टी १४ नवम्बर, १६४४ तक के लिये बढ़ा दी जाय। कृपया उनके प्रशासन स्वास्थ्य की परीक्षा करके सरकार को उनके विषय में ग्रयना चैकित्सिक मत लिख भेजिये। उक्त विभाग कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी भेजा जा रहा है। इसे कृपया लौटा दीजियेगा। (ग्रिविष्ठान)

२--श्री 'क' से कह दिया गया है कि वे ग्राप के पास स्वास्थ्य परीक्षा के निमित्त उपस्थित हों।

भवदीय,

उप सचिव ।

संख्या (१)/२० तात्कालिक श्रनुपालन के लिये प्रतिलिपि श्री 'क' को भेजी जाती है। सूचनार्थ प्रतिलिपि...... विभाग को भेजी जाती है।

उप सचिव की भ्राज्ञा से।

१०--संसर्गरोध-प्रपत्र

संख्या

120

प्रेषक,

श्रो.....

उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

स्वास्थ्य ग्रधिकारी,

म्युनिसियल बोर्ड,

लखनऊ।

लखनऊ ,----१६ ई०।

महोदय,

सिववालय प्रशासन विभाग (श्रिधिट्यान) सिववालय के सहायक कर्नचारी श्री 'क' ने यह सूचना दी है कि उनके घर में किसी को चेचक निकल श्राई है। कृपया रोगी की परीक्षा करके सरकार को बताइये कि श्री 'क' को संसर्गरोच पर रखना श्रावश्यक है या नहीं, श्रीर यदि है, तो कितने दिनों के लिये ?

२--श्री 'क' का पता यह है:

भवदीय, उप सचिव।

संख्या

(१)/२०

सूचना ग्रौर ग्रावश्यक कार्यवाही के लिये श्री 'क' को प्रतिलिपि भेजी जाती है।

२--यदि छुट्टी स्वीकृत हो जाय तो छुट्टी समाप्त होने के दो दिन पूर्व ग्राप को स्वास्थ्य
ग्रियकारी क पास विसंक्रमण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये स्वयं जाना होगा।

संख्या

(२)/२०

प्रतिलिपि. विभागं को भी सूचनार्थ भेजी जाती है।

उप सचिव की ग्राज्ञा से।

११—— इौरे का कार्यक्रम डाक्टर सम्पूर्णानन्द, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के कोरे के कार्यक्रम

[देखिये ''निर्देशिका" का पैराग्राफ ४५ (१०)]

१७-१२-५५ . लखनऊ से प्रस्थान (रेल से) . १०-५ रात्रि १६-१२-५५ . वारागसो में ख्रागमन . ६-३७ पूर्वान्ह १६-१२-५५ . लखनऊ में ख्रागमन . ४-५५ पूर्वान्ह २०-१२-५५ . लखनऊ से प्रस्थान (रेल से) . ६-०० रात्रि २१-१२-५५ . लखनऊ से प्रस्थान (रेल से) . ५-४६ पूर्वान्ह २१-१२-५५ . हापुड़ में ख्रागमन . ५-४६ पूर्वान्ह २१-१२-५५ . हापुड़ में ख्रागमन . ५-३० प्रपरान्ह २२-१२-५५ . मुरादाबाद से प्रस्थान . ५-३० ख्रपरान्ह २२-१२-५५ . मुरादाबाद से प्रस्थान . ५-०० ख्रपरान्ह २३-१२-५५ . लखनऊ में ख्रागमन . ५-१० ख्रपरान्ह २३-१२-५५ . लखनऊ में ख्रागमन . ५-१० ख्रपरान्ह २४-१२-५५ . लखनऊ में ख्रागमन . ५-१० ख्रपरान्ह २४-१२-५५ . वाराणसी में प्रस्थान (मोटर से) १२-३० ख्रपरान्ह १४-१२-५५ . वाराणसी में प्रस्थान . १२-३० ख्रपरान्ह १४-१२-५५ . सर्जान के प्रस्थान . १२-३० ख्रपरान्ह १४-१२-५५ . मुर्जान्ह . १५-१०० ख्रपरान्ह १४-१२-५५ . मुर्जान्ह . १०००० ख्रपरान्ह १४-१२-५५ . मुर्जान्ह . १२-१० ख्रपरान्ह १४-१२-५५ </th <th></th> <th>and more than a superior</th> <th></th> <th></th>		and more than a superior		
वाराणसी से प्रस्थान (रेल से) ६-०० रात्रि १६-१२-४४ लखनऊ में ग्रागमन ४-४४ पूर्वान्ह २०-१२-४४ लखनऊ से प्रस्थान(रेल से) ६-०० रात्रि २१-१२-४४ हापुड़ में ग्रागमन ५-४६ पूर्वान्ह हापुड़ से प्रस्थान(मोटर से) ५-४४ पूर्वान्ह मेरठ से प्रस्थान ५-३० प्रयान्ह मेरठ से प्रस्थान ५-३० प्रयान्ह मेरठ से प्रस्थान ५-३० प्रयान्ह मुरादाबाद में ग्रागमन ६-३० प्रयान्ह वरेली में ग्रागमन ६-३० प्रयान्ह वरेली से प्रस्थान (रेल से) ६-१४ रात्रि २३-१२-४४ लखनऊ में ग्रागमन ५-१४ पूर्वान्ह वरेली से प्रस्थान (हवाई जहाज से) ७-३० पूर्वान्ह वारागसी में ग्रागमन ५-३० प्रयान्ह सरसी बांध स्थल पर प्रागमन ५-३० प्रयान्ह सरसी बांध स्थल पर प्रागमन ५-३० प्रयान्ह सरसी बांध स्थल पर प्रागमन ५-०० प्रयान्ह सरसी बांध स्थल से प्रस्थान (मोटर से) प्र-०० प्रयरान्ह सिरसी बांध स्थल से प्रस्थान (मोटर से) प्र-०० प्रयरान्ह सिरसी बांध स्थल से प्रस्थान (मोटर से) प्र-०० प्रयरान्ह सरसी वर्षा से प्रस्थान ६-०० पूर्वान्ह वरोंधा ग्रौर देवरी होते हुये टोंस जल- प्रणाली में ग्रागमन ६-०० पूर्वान्ह टोंस जलप्रणाली से प्रस्थान (मोटर से) इलाहाबाद में ग्रागमन ६-२० प्रपरान्ह हलाहाबाद में ग्रागमन ६-३० प्रपरान्ह इलाहाबाद में ग्रागमन ६-३० प्रपरान्ह	80-85-XX	· लखनऊ से प्रस्थान (रेल से)	. १०-५	रात्रि
२०-१२-४४ लखनऊ से प्रस्थान (रेल से) १-०० रात्रि २१-१२-४४ हापुड़ में आगसन ५-४६ पूर्वान्ह मेरठ में आगसन ५-५५ पूर्वान्ह मेरठ में आगसन ५-३० प्रपरान्ह प्रपरान्ह मेरठ से प्रस्थान ५-३० प्रपरान्ह प्रपरान्ह परेली से प्रस्थान ५-२० प्रपरान्ह प्रपरान्ह परेली से प्रस्थान ५-२० प्रपरान्ह परेली से प्रस्थान ५-२० प्रपरान्ह परेली से प्रस्थान ५-१४ प्रवीन्ह प्रपरान्ह परिल से) १-३० प्रपरान्ह पर्वान्ह पर्वान्ह परिल से प्रस्थान ५-१४ प्रवीन्ह प्रयीन्ह प्रयीन्ह परिल से प्रथान परिल से प्रयान परित्र से प्रयान से प्रयान परित्र से प्रयान से प	१८-१२-४४ .			
२१-१२-५५ हापुड में ब्रागमन हापुड से प्रस्थान (मोटर से) ५-४६ पूर्वान्ह भरठ में ब्रागमन भरठ से प्रस्थान भरठ से प्रस्थान भरठ से प्रस्थान भरठ से प्रस्थान भरादाबाद में ब्रागमन २२-१२-५५ मुरादाबाद से प्रस्थान बरेली में ब्रागमन २२-१० ब्रापरान्ह बरेली से प्रस्थान (रेल से) १३-१२-५५ लखनऊ में ब्रागमन २४-१२-५५ लखनऊ में ब्रागमन लखनऊ से प्रस्थान (हवाई जहाज से) ७-३० प्रवान्ह लखनऊ से प्रस्थान (हवाई जहाज से) ७-३० प्रवान्ह वारागसी में ब्रागमन २२-३० ब्रापरान्ह सिरसी बांध स्थल पर ब्रागमन भन्ग प्रमान्ह सिरसी बांध स्थल पर ब्रागमन भन्ग प्रमान्ह सिरसी बांध स्थल से प्रस्थान (मोटर से) भन्ग प्रपरान्ह सिरसी बांध स्थल से प्रस्थान (मोटर से) भन्ग प्रपरान्ह सिरसी बांध स्थल से प्रस्थान (मोटर से) भन्ग प्रमार्गन भन्ग प्रमार्गन भन्ग प्रमार्गन वरींक्ष ब्रागमन २-०० प्रवान्ह वरींक्ष क्रागमन २-०० प्रवान्ह वरींक्ष क्रागमन २-४५ ब्रापरान्ह वरींक्ष क्रागमन २-४५ ब्रापरान्ह वरींक्ष क्रागमन २-४५ ब्रापरान्ह वरींक्ष जन्मणाली से प्रस्थान (मोटर से) १-३० ब्रापरान्ह इलाहाबाद में ब्रागमन ६-२० ब्रापरान्ह इलाहाबाद में ब्रागमन ६-२० ब्रापरान्ह इलाहाबाद में ब्रागमन ६-२० ब्रापरान्ह इलाहाबाद से प्रस्थान (रेल से) १-२० व्रापरान्ह	१६-१२-५५	. लखनऊ में ग्रागमन	४-५५	पूर्वान्ह
हापुड़ से प्रस्थान (मोटर से)	२०-१२-५५	. लखनऊ से प्रस्थान(रेल से)	00-3	रात्रि
बरेली में ग्रागमन बरेली से प्रस्थान (रेल से) २३-१२-४४ • लखनऊ में ग्रागमन • प्र-१४ पूर्वान्ह लखनऊ से प्रस्थान (हवाई जहाज से) • -३० पूर्वान्ह वारागसी में ग्रागमन • -३० प्रपरान्ह सरसी बांघ स्थल पर ग्रागमन • -३० प्रपरान्ह सिरसी बांघ स्थल पर ग्रागमन • -३० प्रपरान्ह सिरसी बांघ स्थल से प्रस्थान (मोटर से) १२-३० ग्रपरान्ह सिरसी बांघ स्थल पर ग्रागमन • -३० ग्रपरान्ह सिरसी बांघ स्थल से प्रस्थान (मोटर से) ६-०० ग्रपरान्ह मिर्जापुर में ग्रागमन • -७०० प्रपरान्ह निरीक्षणगृह मिर्जापुर में विश्राम • -१०० प्रवान्ह बरौंघा ग्रौर देवरी होते हुये टोंस जल- प्रणाली में ग्रागमन • १-३० ग्रपरान्ह होस जलप्रणाली से प्रस्थान (मोटर से) इलाहाबाद में ग्रागमन • ६-३० ग्रपरान्ह इलाहाबाद से प्रस्थान (रेल से) • -२० रात्रि	78-87-XX	हापुड़ से प्रस्थान(मोटर से) मेरठ में ग्रागमन मेरठ से प्रस्थान	X-XX €-₹0 8-₹0	पूर्वान्ह पूर्वान्ह ग्रयरान्ह
लखनऊ से प्रस्थान (हवाई जहाज से) ७-३० पूर्वान्ह वारागसी में श्रागमन	२२-१२-५५ .	बरेली में ग्रागमन	६-३ 0	ग्रपरान्ह
२४-१२-५५ वाराणसी से प्रस्थान (मोटर से) १२-३० ग्रपरान्ह सिरसी बांध स्थल पर ग्रागमन २-३० ग्रपरान्ह सिरसी बांध स्थल से प्रस्थान (मोटर से) ६-०० ग्रपरान्ह मिर्जापुर में ग्रागमन ७-०० ग्रपरान्ह निरीक्षणगृह मिर्जापुर में विश्राम २५-१२-५५ मिर्जापुर से प्रस्थान ६-०० पूर्वान्ह बरोंधा ग्रौर देवरी होते हुये टोंस जल-प्रणाली में ग्रागमन ३-४५ ग्रपरान्ह टोंस जलप्रणाली से प्रस्थान (मोटर से) ५-३० ग्रपरान्ह इलाहाबाद में ग्रागमन ६-३० ग्रपरान्ह इलाहाबाद से प्रस्थान (रेल से) ६-२० रात्र	२३-१२-५५ .	लखनऊ से प्रस्थान (हवाई जहाज से)	9-30	पूर्वान्ह
२५-१२-५५ . मिर्जापुर से प्रस्थान ६-०० पूर्वान्ह बरौंधा श्रौर देवरी होते हुये टोंस जल- प्रणाली में श्रागमन ३-४५ श्रपरान्ह टोंस जलप्रणाली से प्रस्थान (मोटर से) ५-३० श्रपरान्ह इलाहाबाद में श्रागमन ६-३० श्रपरान्ह इलाहाबाद से प्रस्थान (रेल से) ६-२० रात्रि	२४-१२-५५	सिरसी बांध स्थल पर ब्रागमन सिरसी बांध स्थल से प्रस्थान (मोटर से) मिर्जापुर में ब्रागमन	₹ - 00	श्रपरान्ह श्रपरान्ह
टोंस जलप्रणाली से प्रस्थान (मोटर से) ५-३० ग्रपरान्ह इलाहाबाद में ग्रागमन ६-३० ग्रपरान्ह इलाहाबाद से प्रस्थान (रेल से) ६-२० रात्रि	२४-१२-४४	मिर्जापुर से प्रस्थान बरौंधा श्रौर देवरी होते हुये टोंस जल-		felt us
क वर्षां क्षेत्र क्षेत्र रहा बाब किसा उसका हरूपां र हो, इसके बार भी, विकासोद के		टोंस जलप्रणाली से प्रस्थान (मोटर से) इलाहाबाद में ग्रागमन	¥-₹0 ६-₹0	श्रपरान्ह श्रपरान्ह
	२६-१२-४४	THE LIE A PLAYED TRUE MADE AGE TON		IN PERMIS

श्रार० एस० शर्मा, वैयक्तिक सहायक, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, १५ दिसम्बर, १६५५।

परिशिष्ट ४ टिप्पण के कतिपय नमूने

संख्या--१

कम संख्या १३--श्रीमती राजिकशोरी, बहूरानी साहिबा समयर, ग्रयोध्या का दिनांक ११ जनवरी, १९५५ का प्रार्थना-पत्र।

मख्य सचिव

कृपया वि० पत्र एवं उस पर ग्रंकित ग्रपनी ग्राज्ञा देखें।

श्रीमती राज किशोरी, बहूरानी साहिबा समथर ने पुनः एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने यह निवेदन किया है कि समथर के किले में स्थित श्री "राज मंदिर" के वर्तमान प्रबन्धक को कुट्यवस्था के कारण हटा कर उसका प्रबन्ध उन्हें सौंप दिया जाय श्रथवा उचित प्रबन्ध के लिये एक ट्रस्ट कमेटी बना दी जाय। इस संबंध में कृपया पृष्ठ १ से टिप्पणियां तथा श्राज्ञायें देखिये। महाराजा समथर की निजी सम्पत्ति की सूची देने से यह व्यक्त होगा कि उक्त मंदिर "राज्य सम्पत्ति" होने के कारण जिलाधीश झांसी की देखरेख में उस समय तक के लिये रहेगा जब तक दिलीन क्षेत्र (इंक्लेब्ड एरियाज) में स्थित मंदिरों इत्यदि की व्यवस्था के लिये प्रस्तावित ट्रस्ट कायम नहीं हो जाता है। जहां तक प्रार्थिनी को मंदिर का प्रबन्ध सौंपने का प्रश्न है, इस मामले पर समुचित विचार हो चुका है। इस सम्बन्ध में पृष्ठ २ तक मध्य से टिप्पणियां तथा श्राज्ञायें एवं जिलाधीश का १३-४-५१ का पत्र श्रवलोकन करें। ऐसी दशा में वर्तमान प्रबन्ध में परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठता।

२—जहां तक विचाराधीन पत्र के पैराग्राफ १ में "राज मंदिर" को उचित प्रबन्ध के लिये एक ट्रस्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव है, कार्यालय का यह निवेदन है कि जब तक उपर्युक्त ट्रस्ट कायम न हो जिलाधीश ने स्थानीय प्रतिष्ठित सज्जनों की एक कमेटी बना दी है जो एक परामर्श- दात्री संस्था के रूप में है। ट्रस्ट कायम होने में ग्रभी समय है। सरकार ने जिलाधीश की इस कार्यवाही का पूर्ण समर्थन किया है ग्रीर यह स्पष्ट कर दिया है कि जिलाधीश को स्थानीय व्यक्तियों से परामर्श लेने का ग्रधिकार है, कि जु विलोनीकरण के फलस्वरूप प्रबन्ध का उत्तरदायित्व उन्हीं पर

रहेगा।

३---उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुये ग्रब यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित सुझावों पर पहिले ही पूर्ण विचार हो चुका है ग्रौर ग्रब इस पर कोई ग्रन्य कार्यवाही करने की ग्रवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्रादेशार्थ प्रस्तुत ।

(ह० सहायक) (२६-१-४४) मुख्य मंत्री

महाराजा समयर के प्रस्ताव को स्वीकार करने में तो कोई स्त्रापत्ति नहीं प्रतीत होती। जिस प्रस्ताव का उल्लेख पृष्ठ ५-६ में किया गया है वह स्त्रौर ही था।

जिलाधीश को महाराजा का पत्र भेज दिया जाय श्रौर उनकी राय मांगी जाय। ४,००० ६० की श्रामदनी का लेखा कैसे रखा जाय जिससे उसका दुरुपयोग न हो, इसके बारे भी जिलाधीश के सुझाब मांग लिये जायं।

ग्राज्ञार्थ ।

78-1-44

ग्रादित्यनाथ झा

ठीक है। सम्पूर्णानन्द

संख्या २

क्रम्भ संख्या १---नियुक्ति (स्र) विभाग का पृष्ठांकन सं० ब-१६०३ (१)/२-ब---५५, दिनांक १० ग्रक्तूबर, १६५५

भ्रनुसिवव,

कृपया श्री वीरेन्द्र पित यादव, एम०एल०ए० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न* को देखने का कष्ट करें। यह प्रश्न श्रसेम्बली की वर्तमान बैठक के १४ वें गुरुवार श्रर्थात् दिनांक २० श्रक्तूबर, १६४४ के लिखे निर्धारित है।

२—पिछड़ी जातियों के संबंध में जो श्रादेश दिनांक ६ सितम्बर, १९४४ को जारी किये गये हैं उनकी एक प्रतिलिपि नीचे रखी हुई है। जिन कारणों से श्रादेश जारी किये गये उनका उल्लेख दिनांकित ६ सितम्बर, १९४४ के स्वतः पूर्ण पत्र में दिया गया है। इस संबंध में श्रनु सिचव पत्रावली संख्या १४ (११)/ १९४४ के पृष्ठ संख्या १—-१२ पर उद्धृत टिप्पणियां श्रौर श्राज्ञायें को भी देखें। संक्षेप में इन श्राह्मेशों को जारी करने के निम्नलिखित कारण हैं:

३--इस प्रदेश में इस समय पिछड़ी जातियों की दो सूचियां हैं। एक सूची तो सन् १६५० में केन्द्रीय सरकार के ग्रादेशानुसार संविधान के उपबन्धों के ग्रन्तर्गत मन्त्रिमण्डल की एक उप समिति द्वारा बनाई गई थी। दूसरी सूची शिक्षा विभाग द्वारा सन् १६५४ में बनाई गई थी। यह सूची ग्रब भी पिछड़ी जातियों को शिक्षा त्रादि संबंधी सुविधायें देने के काम में लायी जाती है।

४—समय-समय पर नियुक्ति विभाग द्वारा इस स्राशय के स्रादेश जारी किये गये कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समय पिछड़ी जातियों का ध्यान रखा जाय। पर इस विचार से कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त "वैकवर्ड क्लासेज कमीशन" की सिफारिशें उपलब्ब होने के उपरान्त जो पिछड़ी जातियों की सूची बनेगी वह उिल्लिखत दोनों सूचियों का स्थान ले लेगी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जहां तक उक्त स्रादेशों का संबंध है कौन-कौन-सी जातियां पिछड़ी समझी जायंगी। बिल्क इस बात का निर्णय नियुक्त करने वाले स्रिधकारियों पर ही छोड़ दिया गया।

५—चंकि "बैकवर्ड क्लासेज कमीशन" की सिफारिशें उपलब्ध होने में कुछ समय लगने की संभावना थी ग्रीर चंकि यह भी सम्भव था कि किसी जाति को एक ग्रधिकारी पिछड़ी जाति समझे तथा उसी जाति को दूसरा ग्रधिकारी पिछड़ी न समझे यह ग्रावश्यक समझा गया कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिये कौन-कौन-सी जाति पिछड़ी समझी जाय इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाय। परिणाम-स्वक्रप ग्रावश्यक ग्रादेश दिनांक ६ सितम्बर, १९४५ के पत्र में जारी किये गये।

६—उक्त पत्र में जारी किये गये ब्रादेशानुसार उन १५ जातियों को, जिनकी सूची इस पत्र की ब्रानुसूची "क" में दी हुई है, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिये पिछड़ी समझा जायगा । यह सूची वहाँ है जो १६५० में बनाई गई थी ।

७—दिनांक ६ सितम्बर, १९४५ के पत्र में जो श्रादेश जारी हुये हैं वे गोपनीय नहीं हैं। उक्त श्रादेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि "बैकयर्ड क्लासेज कमीशन" की सिफारिशें उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप जो पिछड़ी जातियों की सूची बनेगी वह उक्त पत्र की श्रनुसूचियों ("क" श्रीर "ख") में दी हुई पिछड़ी जातियों की सूचियों का स्थान ग्रहण कर लेगी। ऐसी परिस्थित में उक्त पत्र को सदन के सामने प्रस्तुत करने में कार्यालय को कोई श्रापत्ति नहीं दीख पड़ती है। स्वीकृति के लिये श्राक्तिय प्रस्तुत है।

^{*}क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ६ सितम्बर, १६५५ को एक परिपत्र Chief Secretary ने सभी विभागीय श्रध्यक्षों को भेजा है जिसमें backward classes की उन १० जातियों का उल्लेख किया गया है जिसको कि सरकार ने Public Service के लिए पिछड़ा माना है? यदि हां, तो क्या सरकार उस परिपत्र की सूची मेज पर रक्खेगी?

द--पिछड़े वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो श्रन्य श्रादेश जारी हुये हैं, उनकी एक-एक प्रति भी प्रस्तुत है।

(ह० सहायक)

28-20-44

मुख्य मंत्री

प्रस्तुत उत्तर ग्रौर उस संबंध में ऊपर का नोट कृपया देख लें।

२--जब इस ६ सितम्बर, १६५५ के परिपत्र का आलेख्य मुख्य मंत्री की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत हुआ था उस समय इस परिपत्र को गोपनीय रखने का विचार था और इसी कारण उसे "Confidential चिह्नित किया गया था और परिपत्र की इबारत में भी यह लिखा गया था कि इसे गोपनीय रक्खा जाय। उस समय मुख्य मंत्री ने परिपत्र के आलेख्य पर स्वीकृति देते हुये निम्न minute लिखा थाः

"But I don't see how we can keep the matter confidential. How can we say that we help certain classes and at the same time refuse to divulge their names? Such a reply can hardly be given to an Assembly question"

सिवनय निवेदन है कि मुख्य मंत्री का यह विचार उचित ही था श्रौर वास्तव में इन जातियों की सूची पहले भी गोपनीय न थी बिल्क वह एक पुस्तिका में भी छापी गयी थी जो विधान मंडल के सदस्यों में वितरित हुई थी। परिणाम-स्वरूप, परिपत्र के श्रालेख्य से, "Confidential" चिन्ह हटा दिया गया था श्रौर उसकी इवारत में से भी उसकी गोपनीय रक्खे जाने का श्रादेश निकाल दिया गया था।

३—ऐसी स्थिति में इस परिपत्र की प्रति विधान सभा की मेज पर रखने में कोई स्रापित्त प्रतीत नहीं होती। वस्तुतः मुख्य मंत्री के "मिनट" में ऐसे प्रश्न के पूछे जाने की सम्भावना निहित थी जिसको सब भी बीरेन्द्रपति यादव ने पूछा है।

(ह॰ ग्रनु सचिव)

28-20-44

यदि कोई यह प्रश्न करे कि इन १५ जातियों के चुनने का क्या ग्राधार है तो इसका क्या उत्तर होगा? हाल में ऐसा भी तो एक परिपत्र गया है कि पुलिस S. I. S के चुनाव में जो जातियां ग्रब तक ली जाती थीं वह ग्रव भी ली जायं। उसकी भी प्रति चाहिये।

१६-१०-४४

मुख्य मंत्री

सम्पूर्णानन्द

(१) १५ जातियों को चुनने का ग्राधार—-िपछड़ी जातियों की सूची बनाने का प्रश्न ग्रगस्त, सन् १६५० में उठा था। उस समय मंत्रिमण्डल ने यह निश्चय किया कि एक समिति, जिसमें शिक्षा मंत्री (ग्रब मुख्य मंत्री) होंगे इन जातियों की सूची निर्धारित करें। उस समय मुख्य मंत्री (तब शिक्षा मंत्री) ने १६ जातियों की एक सूची बनाई थी जो मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत हुई थी। उस सूची में नट जाति भी शामिल थी, किन्तु बाद में नट जाति परिगणित जातियों में हामिल की गई ग्रौर पिछड़ी जातियों की सूची से निकाल दी गयी। इससे उस सूची में केवल १५ जातियां रह गयीं, जिसमें तब से कोई परिवर्तन नहीं हम्रा है।

इन १६ (श्रव १५) जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में रखने के कारण मुख्य मंत्री (तब गृह मंत्री) ने श्रपने ७ ग्रगस्त, १९५० के "भिनट" में बताये थे। उस मिनट की प्रतिलिपि पत्रावली के अन्त में है। उसके साथ मंत्रिमंडल के नोट की भी एक प्रतिलिपि है।

(२) पुलिस S.Is के चुनाव के लिये पिछड़ी जातियां—मांगे गये परिपत्र की एक प्रतिलिपि (पहले ब्रादेशों के साथ) पत्रावली के ब्रन्त में रख दी गयी है ।

२--मुख्य मंत्री द्वारा स्वीकृत प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपियां विद्यान सभा को यथाविद्य कार्रवाई के लिये भेज दी गयी है। उसकी म्रतिरिक्त प्रतियां पत्रावली के मन्त में हैं।

स्वामी क्रिके गते हैं, एंड पर अस्थापी हैं । इन्हों '?३ एपेडी परों च १३ ते वे बे वे पे पे को को दबादी करना है। सहायक जिन्हा पंजाब की महाभी की निवृद्धित साहि से अस्थाप में बारी तक जोई दिया (सर्वित रामा) गृही सर्वे हैं। बोक सेवा कारोप की कर्माति में पहरण विवार नहां था कि सहायक

rengen ofe ofe rech recifie to paid and the type name to week neight

तमा संबाधक प्रवास्थल को संबद गोराव्य जावेद को दर्शियन बच्चे विधित है। विधित विकास मार्थिक विधित

१६-१०-४४। (ह० ग्रनु सचिव)।

सम्पर्णानन्द ।

184-09-38

संख्या ३

ऋम-संख्या ४, ६--संयुक्त संचालक पंचायत राज के ग्रर्द्धशासकीय पत्र ग्रनु सचिव,

इस पत्रावली में सहायक जिला पंचायत स्रधिकारियों के स्थायीकरण का प्रश्न विचाराधीन है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिये संयुक्त संचालक से यह स्रनुरोध किया गया था कि वह इस विषय पर स्रपने प्रस्ताव की निम्नांकित सूचना के साथ शासन को भेजे:

- (१) इन ग्राधिकारियों के पूर्व इतिहास पर पुलिस की जांच की रिपोर्ट।
- (२) सिविल सर्जन का इनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।
- (३) इनके कार्य पर रिपोर्ट।

वि० प० में संयुक्त संचालक का प्रस्ताव ग्रंकित है। उपर्युक्त (१) तथा (२) के सम्बन्ध में संयुक्त संचालक ने वि० प० २ में लिखा है कि सर्वश्री (क ख) तथा श्री (ग घ) को छोड़ कर शेष ४६ सहायक जिला पंचायत ग्रधिकारी पंचायत निरीक्षक के पद पर स्थायी हैं तथा उनकी चरित्र की जांच एवं सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की परीक्षा उसी समय हो चुकी है, जब वे पंचायत निरीक्षक-पद पर स्थायी किये गये थे। सर्वश्री (क ख) तथा श्री (ग घ) के विषय में सं० सं० का कथन है कि उनके सम्बन्ध में उक्त पुलिस की रिपोर्ट ग्रथवा सिविल सर्जन के प्रमाण-पत्र का प्रश्न इस समय नहीं उठता। जहां तक (३) का सम्बन्ध है, सं० सं० ने सम्बन्धित सहायक जिला पंचायत ग्रधिकारियों की चरित्र वर्तियां भेजी हैं।

२—सहायक जिला पंचायत म्रधिकारियों के कुल ५१ पदों में से १३ पद १ म्रप्रैल, १९५४ से स्थायी किये गये हैं, शेष पद म्रस्थायी हैं। इन्हीं १३ स्थायी पदों में १३ स० जि० पं० म्र० को स्थायी करना है। सहायक जिला पंचायत म्रधिकारियों की नियुक्ति म्रादि के सम्बन्ध में म्रभी तक कोई नियम (सिवस रूल्स) नहीं बने हैं। लोक सेवा म्रायोग की म्रन्मित से यह तय किया गया था कि सहायक जिला पंचायत म्रधिकारियों के पदों पर जो नियुक्तियां की जायं वे केवल पंचायत निरीक्षकों के मध्य से निर्वाचन करने के पश्चात् पदोन्नित देकर ही की जायं। यह भी तय किया गया था कि यह निर्वाचन तहसीलदारों के पदों पर नायव तहसीलदारों की पदोन्नित देने के सम्बन्ध में लागू नियमों के म्राधार पर होगा तथा निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखते हुए एक निर्वाचन समिति द्वारा किया जायेगा:—

- (१) पंचायत निरीक्षक के पद पर कम से कम एक वर्ष का अनुभव,
- (२) व्यक्तित्व तथा चरित्र,
- (३) प्रतिभा, चतुरता, श्रनुभव तथा शक्ति, दौरा करने की शक्ति को मिला कर,
- (४) सेवाग्रों का पिछला रिकार्ड.
- (४) शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएं,
- (६) पंचायतराज ऐक्ट तथा रूल्स,
- (७) क्षेत्र में गिये गये विकास सम्बन्धी कार्य,
- (प्र) पंचायत निरीक्षकों पर नियंत्रण तथा मार्ग प्रदर्शन की क्षमता,
- (६) कार्यों के विकास के लिये कल्पना-शक्ति।

उपर्युक्त निश्चय के भ्रनुसार भूतपूर्व बोर्ड भ्राफ रेवेन्यू के सीनियर मेम्बर बी० डी० भडकामर तथा संचालक पंचायतराज श्री भगवत नारायण भागव को सम्मिलित करके निर्मित निर्वाचन सिमिति ने भ्रप्रैल सन् १९५१ में १६७ पंचायत निरीक्षकों का साक्षात्कार करने के पश्चात् उनमें से सर्व श्रेष्ठ ४६ व्यक्तियों को सहायक जिना पंचायत ग्राधिकारियों के पदों पर पदोन्नित देने के लिये निर्वाचन किया। इन ४६ व्यक्तियों को स० जि० पं० ग्र० के पद पर नियुक्त करने के पूर्व लोक सेवा ग्रायोग की भी ग्राप्ति प्राप्त की गयी थी। निर्वाचन सीमित चुने हुए ४६ व्यक्तियों की व्यव्हता उनकी श्रेष्ठता के ग्राधार पर निश्चित की थीन कि उनकी पंचायत निरीक्षक पद की व्यव्हता के ग्राधार पर। इस ग्रोर भी लोक सेवा ग्रायोग ने कोई ग्रापित नहीं की।

३--त० जि० पं० छ० के झवशेय दो पदों पर सीधी भर्ती द्वारा झायोग की झनुमित से सर्व-श्री (ग, घ) तथा श्री (क, ख) को नियुक्त किया गया था। श्री (ग, घ) विलीनीकृत काशी राज्य के स्थायी जिला प्रधान सेवादल थे। इन की नियुक्त उपर्युक्त स० जि० पं० छ० के निर्वाचन से पहले ही हो चुकी थी। श्री (क, ख) का पद गजटेड है तथा स० जि० ० छ० के शेष ५० पदों के काडर से बाहर है। इस पद का वेतन-क्रम भी २५०--- ५०० ठ है जबिक झन्य ५० पदों का वेतन कर २००--४०० ० है। इसी कारण वर्तमान प्रस्ताव में सं० सं० ने श्री (क, ख) के स्थायी करण के प्रश्न पर विचार नहीं किया। सं० सं० ने लिखा है कि उनकी स्थायी घोषित करने का प्रस्ताव शासन की सेवा में थक् से भेजा गया है। यह प्रस्ताव मंत्री, स्वशासन के विचाराधीन है।

४— अब कृपया विचाराधीन पत्रों में अंकित सं० सं० के स० जि० पं० अ० के स्यायीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव का अवलोकन करें। सं० सं० ने कुछ ५० स० जि० पं० अ० में से १३ व्यक्तियों को जिनको वे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, स्थायीकरण के लिये चुना है। इस चुनाव के फलस्वरूप सं० सं० ने ३७ स० जि० पं० अ० का अतिक्रमण प्रस्तावित किया है। सं० सं० का कथन है कि स्थायीकरण का आधार कर्मचारियों की विभिन्न वर्षों की चरित्र पुस्तिकाओं की रिपोर्ट, गत रिफेशर कोर्स में प्राप्त ग्रंक तथा उनकी कार्यक्षमता रखा गया है। इसके पूर्व की सं० सं० के वि० प० में अंकित स्थायीकरण के प्रस्ताव पर कार्यालय अपनी टिप्पणी दे, कार्यालय का यह निवेदन है कि डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग्स इंक्शयरी कमेटी की रिपोर्ट के अर शासन के निश्चय के अनुतार "श्रेष्टता के आधार पर चुनाव" के इन पदोन्नति के सनय ही किया जायेगा, स्थायीकरण के लिये इस रीति से चुनाव करने का कोई प्राविधान नहीं है। स० जि० पं० अ० का "श्रेष्टता के आधार पर चुनाव" पहले ही किया जा चुका है। अतः सं० सं० का वि० प० में अंकित स्थायीकरण का प्रस्ताव, जो "श्रेष्टता के आधार पर किये गये चुनाव" के अशीन है तथा जिसके परिणानस्वरूग ३७ ज्येष्ट स० जि० पं० अ० का स्थायीकरण के लिये ग्रांतक्रमण होता है, उथयुक्त नहीं जान पड़ता।

प्र-- प्रबं प्रश्न यह है कि फिर किस विधि के अवीन से जि० पं० प्रे का स्थापीकरण किया जाय। इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि सं० जि० पं० प्रे के पद तहसीलदारों के पदों से वेतन-क्रम अदि की दृष्टि से करीब बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। इसी कारण शासन ने पहले ही यह निश्चय किया था कि सं० जि० पं० प्रे के पदों पर नियुक्त करने के लिये तहसीलदारों के पदों पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में लागू नियमों का अनुसरण किया जाय। ऐसी अवस्था में यह उचित ही जान पड़ता है कि से जि० पं० प्रे के स्थायीकरण के विश्व में भी वही नियम व विधि अपनायी जाय जो तहसी नदारों के स्थायीकरण में लागू होती है।

६--राजस्व विभाग से ग्रज्ञासकीय तौर पर पूछने से ज्ञात हुग्रा है कि निर्वाचन समिति द्वारा तथा लोक सेवा ग्रायोग के परामर्श के बाद ग्रंतिम रूप से चुने हुए तहसीलदारों के पदों के लिये ग्रभ्य-थियों को दो साल के लिये परीक्षण पर रख दिया जाता है। इस बीच में इन ग्रभ्ययियों को निम्त-लिखित परीक्षायें पास करनी होती हैं ---

- (१) वैमागिक परीक्षा,
- (२) घुड़सनारी की परीक्षा,
- (३) खजाने के कार्य की परीक्षा ।

उक्त दो साल का परीक्षण समाप्त होने पर जो तहसीलदार उपयुँ क्त तीनों परीक्षायें पास कर लेते हैं तथा जिनका कार्य उनकी चरित्र पुस्तिकाओं के देखने से संतोषजनक समझा जाता है, उनको स्थायी कर दिया जाता है। एक बार निर्वाचन समिति द्वारा तथा श्रायोग के परामर्श के बाद चुने हुए तहसीलदारों में से स्थायीकरण के समय फिर छटनी या श्रेष्ठता के श्राधार पर चुनाव नहीं किया जाता। यदि उनमें से किसी तहसीलदार का कार्य इस सीमा तक श्रसंतोषजनक समझा जाता है कि उसको तहसीलदार के पद के लिये सर्वथा श्रयोग्य समझा जाता है तो उसको श्रातिकित नहीं करते, बिल्क उसे नायब-तहसीलदारी के पद पर प्रत्यावित करने की कार्यवाही करते हैं। जिस तहसीलदार का कार्य परीक्षणकाल में केवल इतना श्रसंतोषजनक पाया जाता है, उसको तहसीलदार के पद के लिये सर्वथा श्रयोग्य तो नहीं समझा जाता, किन्तु उस समय स्थायीकरण के लिये पूर्णतया योग्य नहीं समझा जाता; तो उसका परीक्षणकाल बढ़ा दिया जाता है। बढ़े हुए परीक्षणकाल में कार्य संतोषजनक होने पर उसको स्थायी कर दिया जाता है। उपर लिखी हुई सब या एक परीक्षा परीक्षणकाल के भीतर न पास कर सकने पर भी परीक्षणकाल बढ़ा दिया जाता है तथा स्थायीकरण तभी किया जाता है जब वह श्रमुक परीक्षा पास कर लेता है।

७—इसके ग्रितिरिक्त उक्त परीक्षाग्रों में प्राप्त ग्रंकों का स्थायीकरण के लिये केवल इतना महस्व है कि स्थायी किये जाने वाले तहसीलदार को सिर्फ उत्तीर्ण होने भर के ग्रंक प्राप्त करने होते हैं।

द—स० जि० पं० प्र० के स्थायीकरण के सम्बन्ध में सं० सं० ने तहसीलदारों के स्थायीकरण के विषय में लागू नियम विधि के विपरीत "श्रेष्ठता के ग्राधार पर" चुनाव किया है तथा रिफ्रेशर कोर्स में प्राप्त ग्रंकों को भी इस चुनाव का एक ग्राधार माना है। रिफ्रेशर कोर्स एक प्रकार
का शिक्षण है जिसमें वैभागिक ग्रंधिनियम व विनियम के विषय में पहले शिक्षण दिया जाता है तदुपरान्त परीक्षा ली जाती है। यह परीक्षा विभाग द्वारा ली जाती है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन
है कि सं० जि० पं० ग्र० के पंचायतराज ग्रंधिनियम व नियम के ज्ञान की परीक्षा चुनाव समिति
के समक्ष पहले ही हो गई है। "कृपया पृष्ठ ५ पर 'क' देखें"। ग्रतः यदि स्थायीकरण के समय
ऐसी परीक्षा की फिर ग्रावश्यकता समझी जाय तो वह परीक्षा तहसीलदारों की वैभागिक परीक्षा के रूप
में ही होनी चाहिये ग्रंथित इस परीक्षा में प्राप्त ग्रंकों को कोई विशेष महत्त्व इस प्रकार का नहीं बेना चाहिये
कि एक जूनियर सहायक जिला पंचायत ग्रंधिकारी ग्रंपने सीनियर से ग्रंधिक ग्रंक रिफ्रेशर कोर्स में पाने
के कारण स्थायी कर दिया जाय ग्रार सीनियर व्यक्ति छोड़ दिया जाय।

६— प्रतः निष्कषं यह है कि प्रस्थायी स० जि० पं० प्र० की सूची में से ज्येष्ठता के प्राधार पर प्रथम १३ व्यक्तियों को स्थायी किया जाय यि उनका कार्य उनकी चित्र प्रस्तिका देखने से संतोष-प्रद जान पड़े तथा यि उनको रिफेशर कोर्स में उत्तीणं होने भर के ग्रंक मिल गये हैं। यदि किसी स० जि० ं० ग्र० का कार्य इतना ग्रसंतोषजनक समझा जाय ग्रथवा वह रिफेशर कोर्स में पास होने भर के ग्रंक न प्राप्त कर सकें तो उसका कार्य कुछ समय के लिये ग्रौर देखा जाय। इस बीच में उनको यह निर्देश दिया जाय कि वह ग्रपना कार्य सुधारें ग्रथवा परीक्षा पास कर लें। इस ग्रवधि के समाप्त होने पर यदि स० जि० पं० ग्र० का कार्य संतोषजनक पाया जाता है ग्रथवा वह परीक्षा पास कर लेता है, तो उसे स्थायी कर दिया जाय। यदि किसी व्यक्ति का कार्य इतना ग्रसंतोषजनक है कि वह स० जि० पं० ग्र० के पद के लिये सर्वया ग्रयोग्य समझा जाय तो उसको ग्रतिक्रमित करने के बजाय उसको पंचायत निरीक्षक के पद पर प्रत्यार्वीतत करने की कार्यवाही की जाय। यह न किया जाय कि एक व्यक्ति जिसका कार्य दूसरे जूनियर व्यक्ति के कार्य से कुछ कम ग्रव्छा हो छोड़ दिया जाय तथा उसके स्थान पर जूनियर व्यक्ति को स्थायी किया जाय।

१०—कुल ५० स० जि० पं० ग्र० को उनकी नियुक्ति की तिथि से सन् १६५१ में ही परीक्षण पर पुनरावेशों के प्रसारित होने तक रख दिया गया था। • ग्रतः १३ स० जि० पं० ग्र० को, जिनको स्थायी करने का निश्चय किया जाय, ग्रब परीक्षण पर रखने की ग्रावश्यकता नहीं।

११--इसके पहले कि स्थायीकरण के प्रस्ताव का कार्यालय निरोक्षण करे यह आवश्यक है कि इस बात पर निर्णय कर दिया जाय कि स० जि० पं० अ० के स्थायीकरण में कौन-सी विधि का अनुसरण किया जायेगा। गत पृष्ठ पर परिच्छेद ६ में निवेदित विधि का अथवा संयुक्त संचालक पंचायत राज के द्वारा प्रस्तावित विधि का। इस प्रसंग में यह निवेदन करना भी उचित है कि स० जि० पं० अ० के नियुक्ति अधिकारी सचिव, स्वशासन हैं। इस विषय में ग्रंतिम निर्णय लेने के पूर्व नियुक्ति विभाग की सलाह लेना आवश्यक होगा। अतः सचिव महोदय देख लें। तदुपरान्त नियुक्ति विभाग की पत्रावली भेजी जाय।

दिनांक १५-८-५५

(ह० सहायक)

संख्या ४

कम संख्या ३५--प्रशासक-संगीत विद्यापीठ, लखनऊ का पत्र १३-६-५५ । कम संख्या ३६--ज्ञाप दिनांक २७ जून, १६५५, लखनऊ खजाना ।

संचालक

कृपया विचाराधीन पत्र का ग्रवलोकन करें।

संचालक भली प्रकार जानते हैं कि मैरिस कालेज, लखनऊ के स्तर को उठाने के निमित्त केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार के बीच यह निर्णय हुग्रा है कि इसे ग्रकादमी का रूप दिया जाय । ग्रतः यह निश्चित रूप से तय हुग्रा कि केन्द्रीय सरकार २५ हजार रुपये का वार्षिक ग्रनुदान इसके उत्थान के प्रति देगी ग्रौर इतना ही घन प्रान्तीय सरकार भी जमा करेगी।

२--विगत १९५४ में केन्द्रीय सरकार ने २५ हजार रुपये प्रान्तीय सरकार को दिया ग्रौर इतना ही धन प्रान्तीय सरकार ने भी इस मद के लिये निर्धारित किया जो संचालक के नाम पर पर्सनल लेजर में जमा कर दिया गया । यह धन केवल ग्रकादमी बनाने में व्यय किया जा सकता था।

३—वि० पत्र से विदित होता है कि उपर्युक्त धन में से २७,५०० रुपया कालेज के ग्रध्यापकों के बकाया वेतन के भुगतान के निमित्त निकाला गया श्रौर १,००० रुपया वसन्तोत्सव मनाने के लिये व्यय हुग्रा। यद्यपि यह निर्धारित धन केवल श्रकादमी के निमित्त ही व्यय किया जा सकता था श्रौर केन्द्रीय सरकार ने यह भी ग्रंकित कर दिया था कि यदि श्रकादमी न बनी तो प्रान्तीय सरकार को यह धन वापस करना होगा फिर भी इस मद में से २८,५०० रु० का व्यय कर लिया गया। जिन कारणों से यह धन निकालना पड़ा वह विचाराधीन पत्र में प्रशासक ने सूचित किया है।

४--यह तो सत्य है कि भात खंडे संगीत विद्यालय की परिस्थित संतोषजनक न होने के कारण ही एक प्रशासक को नियुक्त करना पड़ा । ग्रध्यापकों का वेतन कई मास से वितरण नहीं किया जा सका था। उन सब में ग्रसंतोष फैल रहा था। विद्यालय का वातावरण ऐसा था कि उसे बन्द करने पर बाध्य होना पड़ता। ग्राथिक परिस्थित ऐसी डगमगाई थी कि संचालन के लिये एक ग्रनुभवी व्यक्ति की ग्रावश्यकता पड़ी। इन्हीं परिस्थितियों में उस धन का सहारा लेना पड़ा। ग्रब चूंकि उपर्युक्त कथित धन व्यय हो ही गया है ग्रतः उसे नियमित करना ग्रावश्यक है ग्रीर प्रशासक को सूचित कर देना है कि भविष्य में इस धन को किसी भी मद के लिये न निकाला जाय।

कम संख्या ३६-

विचाराधीन पत्र में कोषाध्यक्ष ने यह जानना चाहा है कि उस ५०,००० रुपये में से जो ३१ मार्च, १९५४ को जमा हुम्रा था कितना धन व्यय हुम्रा म्रथवा कितना शेष है। इसका सर्टिफिकेट प्रशासक द्वारा ही दिया जा सकता है। जो कि उनके पर्सनल लेजर के नाम से है। म्रतः पत्रावली उन्हें भेज दी जाय म्रौर प्रार्थना की जाय कि कृपया उस सर्टिफिकेट की तीन प्रतिलिपियां बनवा कर दो खजाने को सीघे भेज दें म्रौर एक इस कार्यालय को सूचनार्थ भेजें।

पत्रावली वापस भ्राने पर वित्त विभाग को (वि० पत्र १) के सम्बन्ध में उनकी स्वीकृति के लिये भेजी जायगी।

(ह० सहायक)

मैंने पृष्ठ २६ से देखा। पृष्ठ २६-३० पर जो कार्यवाही प्रस्तावित की गई है वह सर्वया उचित है और इस सम्बन्ध में इतना में और स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार से कालेज के पुनस्संगठन के लिये जो रुपया मिला था, उसमें से वहां के वेतन भोगियों पर खर्च करना कई दृष्टियों से समीचीन था। कालेज को उत्तर प्रदेश शासन ने जिस समय श्रपने श्रधीन लिया उस समय शासन को उसकी स्थिति का पूरा परिचय था। एक बार उक्त विद्यालय को अपने हाथ में ले लेने के बाद वहां के कर्मचारियों का बकाया वेतन देना ही था, चाहे वह बकाया भारत सरकार से प्राप्त श्रनदान से दिया जाता श्रथवा उसके लिये उत्तर प्रदेश शासन विशेष अनुदान देता। बकाया तो देना ही था और यदि बकाया नं दिया जाता तो जैसा कि उस समय कालेज में एक प्रकार की हड़ताल की ख्राशंका उठ खड़ी हुई थी ख्रौर यह भी ख्राशंका हुई थी कि उसके कतिपय ख्यातनामा संगीतज्ञ कालेज छोड़कर चले जायेंगे, चले जाते । वैसी स्थिति में पुनस्संगठन का मूल प्रश्न ही खत्म हो जाता'। निदान, कालेज का पुनस्संगठन हो सके श्रौर पुनः वह नया जीवन प्राप्त कर सके इसके लिये आवश्यक था कि उसका बकाया वेतन दिया जाता। पुनस्संगिठत कालेज में भी प्रायः यही व्यक्ति काम करते होते ग्रौर पुनस्संगठन के पश्चात् भी इनका वेतन देना ही होता ग्रतः यह कार्य जो किया गया वह केवल इस बात को दृष्टि में रखकर। कालेज में पुनस्संगठन की जो सिमिति बनाई गई है उसकी भी रिपोर्ट लगभग १५ सितम्बर तक शासन के सम्मुख श्रा जायेगी ग्रौर उसके बाद यदि भारत सरकार ने उसे स्वीकार किया तो नवसंगठित कालेज का पूरा खर्चा, श्राधा भारत सरकार देंगी ग्रौर श्राधा उत्तर प्रदेश। इस सम्बन्ध में भारत सरकार का जो पत्र श्राया है मैं उसे एक बार पुनः देखना चाहता हूं, साथ ही प्रस्तावित श्रकेडमी का जो विधान भारत सरकार श्रीर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया गया था उसे भी। जहां तक इस पत्रावली में इस बात का उल्लेख है कि ग्रागे उस धन से किसी प्रकार का व्यय न किया जाय, इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि प्रतिमास वहां के कर्मचारियों को वेतन देने के लिये उत्तर-प्रदेश से मिलने वाली आर्थिक सहायता के पर्याप्त न होने पर तब तक उस घन से कुछ न कुछ लिया जाना आवश्यक होगा जब तक कि इस वर्ष नई मांगों द्वारा कम पड़ने वाला घन स्वीकृत नहीं हो जाता। इसका प्रस्ताव में शीघ्र ही अनुपूरक मांगों की सूची में शामिल होने के लिये भेज रहा हं।

२--पृष्ठ ३१ पर जो सींटिफिकेट मांगा गया है उसके लिये कृपया शिक्षा विभाग के एकाउन्टेन्ट श्री पंत को मेरे पास भेज दिया जाय, ताकि में उसे प्रस्तुत कर सकूं।

27-5-9844

(ह० संचालक)

संख्या ५

कि सं ७ ७८६ - संचालक, गांधी स्मारक निधि का पत्र सं ० एस --- २१२८-५४,

श्रनुसचिव

कृपया वि० पत्र को देखने का कष्ट करें। वि० पत्र से संलग्न सूची को देखने से ज्ञात होगा कि नवम्बर, १६५४ के ग्रन्त तक ११ जिलों में गांधी स्यारक निधि का हिसाब साफ करना बाकी था। उक्त ११ जिलों में जिला बाराबंकी ग्रौर हरदोई भी ज्ञामिल है।

२—क० सं० ७४३ के साथ संचालक, गांधी स्मारक निधि ने उन जिलों की सूची भेजी थी, जिनमें गांधी स्मारक निधि का हिसाब जुलाई, १६५३ के ग्रन्त तक साफ नहीं हो पाया था। इस सूची में जिला बाराबंकी ग्रौर हरदोई का उल्लेख नहीं है। स्पष्ट है कि जुलाई, १६५३ के ग्रन्त तक इन जिलों में गांधी स्मारक निधि का हिसाब साफ हो चुका था। जिलाधीश बारावंकी के पत्र दिनांक २७ जून, १६५३ को देखने से भी पता चलता है कि उस समय तक उन्होंने २५३ ६० का हिसाब जो कि वि० पत्र से संलग्न सूची में दिखाया गया है, साफ कर दिया था। जहां तक हरदोई जिले के निधि के हिसाब का सवाल है जिलाधीश ने ग्रपने पत्र दिनांक २७ जून, १६५३ ग्रौर पृष्ठांकन दिनांक १३ ग्रगस्त, १६५३ में संचालक, गांधी स्मारक निधि को स्थित स्पष्ट कर दी है। ग्रतएव यह स्पष्ट नहीं है कि वि० पत्र से संलग्न सूची में संचालक ने इन जिलों का क्यों उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में संचालक, गांधी स्मारक को लिखा जाय।

३——वि० पत्र से संलग्न सूची को देखने से ज्ञात होता है कि वहराइच जिले में रसीद बुक सं० १६१६६-बी का हिसाब साफ करना शेष है। इस सम्बन्ध में अनु सचिव कृपया क्रम सं० ७८३ को देखने का कच्ट करें। जिलाधीश बहराइच ने इस रसीद बुक के नच्ट-श्रव्ट हो जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नानपारा द्वारा दिये गये आवश्यक प्रमाणपत्र को संचालक, गांधी स्मारक निधि के पास भेज दिया है। अतएव यह स्पष्ट नहीं है कि इस सम्बन्ध में संचालक अब और क्या कार्यवाही चाहते हैं। संचालक को इस सम्बन्ध में लिखा जावे।

४—वि० पत्र से संलग्न सूची को देखने से ज्ञात होता है कि विजनौर जिले में रसीद बुक सं० ११६१—ए का हिसाब साफ करना शेष है। यह रसीद बुक श्री 'क' को दी गयी थी। क० सं० ७८० में जिलाधीश विजनौर ने लिखा था कि श्री 'क' के विरुद्ध कोई कानूनी कायंवाही नहीं की जा सकती, लेकिन इस सम्बन्ध में सभापति, जिला कांग्रेस कमेटी को जिन्हें यह रसीद बुक दी गयी थी लिखा जा रहा है। क० सं० ७८२ में जिलाधीश ने यह सूचित किया कि कांग्रेस दफ्तर में आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण सभापति, जिला कांग्रेस कमेटी, इस रसीद बुक की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष पर डालने में असमर्थ हैं। अतएव जिलाधीश ने संचालक, गांधी स्मारक निधि से यह प्रार्थना की थी कि इस रसीद बुक को निरस्त किया जाय। अतएव यह स्पष्ट नहीं है कि इस सम्बन्ध में संचालक अब और क्या कार्यवाही चाहते हैं। संचालक को इस सम्बन्ध में लिखा आय।

५—वि० पत्र से संलग्न सूची को देखने से ज्ञात होता है कि उन्नाव जिले में ६५० रु० का हिसाब साफ करना बाकी है। उक्त ६५० रु० में १५० रु० श्री 'क, ख' को जमा करना है तथा ५०० रु० श्री 'ग' 'घ' को जमा करना है। क० सं० ७५१ पर जिलाधीश बिजनौर के पत्र को देखने से पता चलता है कि ६५० रु० केवल श्री 'क ख' को ही जमा करना था। इस पत्र में जिलाधीश ने लिखा था कि चूंकि श्री 'क' लापता हैं ६५० रु० को वसूल करना सम्भव नहीं है। ग्रातएव जिलाधीश ने इस रुपये को बट्टेखाते करने की प्रार्थना की थी। संचालक के ग्रनुसार श्री 'क ख' की केवल १५० रु० जमा करना था तथा बाकी ५०० रु० श्री 'ग घ' को जमा करना था। इसलिये स्थित स्वष्ट नहीं है। जिलाधीश को लिखने से पहले संचालक को इस सम्बन्ध में स्थित स्वष्ट करने को लिखा जावे। स्वीकृति के लिये श्रालेख्य प्रथम प्रस्तुत।

६—-जिलाधीश स्रागरा, स्रलीगढ़, गोरखपुर, कानपुर स्रौर जालौन को लिखा जाय कि वे ग्रपने जिले के निधि सम्बन्धी हिसाब को शोघ्र साफ करने का प्रयास करें। स्वीकृति के लिये ग्रालेख्य द्वितीय प्रस्तुत ।

७-- कि सं ७५७ के कि में वि० पत्र से संलग्न सूची की एक प्रतिलिपि प्रधान मंत्री, उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी को ग्रावश्यक कार्यवाही के हेतु भेजी जावे। स्वीकृति के लिये ग्रालेख्य तृतीय प्रस्तुत।

 ५ - मुजदकरनगर जिले के सम्बन्ध में ग्रमुसचिव कृपया संलग्न पत्रावली ५११-१६५१ के पृष्ठ ४६-५० पर नोट देखने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर-- महायक)

3-3-44

संख्या ६

क्रम सं० ६——जिलाधीश, इलाहाबाद का पत्र सं० २६०१/ग्रार० ए० वि० पत्र , दिनांक २० सितम्बर, १६५५ ई०। ग्रनु सचिव

कृपया विचाराधीन पत्र (क्रम सं० ६) देखिये।

२—इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् जून, १६४६ में भारत सरकार द्वारा समस्त प्रान्तीय सरकारों एवं चीफ किमश्नरों को इस आश्रय के निदेश प्रेषित किये गये थे कि सरकारो पत्रों में "आपका आज्ञाकारी सेवक (I have the honour to be Sir, your most obedient servant)" वावयांश लिखने के बजाय "भवदीय (yours faithfully)" का प्रयोग तुरन्त आरम्भ कर दिया जाय। भारत सरकार का इस आश्रय का पत्र कम संख्या १ पर है।

३—पूर्व परिपाटो के अनुसार सरकारी पत्र समाप्त करने का रूप परतंत्रता का द्योतक समझा गया। अतः भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त पैराग्राफ में विणित निदेश जारी किये जाने के बाद इस राज्य की सरकार ने उक्त संशोधन को अंगीकृत कर लिया व इस सम्बन्ध में समस्त विभागाध्यक्षों को आवश्यक आदेश अनिवार्य रूप से पालन करने के हेतु जारी कर दिये। देखिये सरकारी परिपत्र सं० ४०३६/३—४७-४८, दिनांक २५ जून, १६४८ जो कम सं० २ पर है।

४—वि० पत्र जिलाधीश, इलाहाबाद ने यह पूछा है कि क्या उक्त ग्रादेश जारी किये जाने के बाद विशेषकर सरकारी पत्र को प्रारम्भ करने के विषय में भी कोई निदेश प्रचारित हुये हैं। जहां तक ग्रंप्रेजी में सरकारी पत्रों को प्रारम्भ करने के रूप का सम्बन्ध है, उसमें कोई संशोधन ग्रथवा परिवर्तन करना ग्रावश्यक नहीं समझा गया। इस सम्बन्ध में कृपया पृष्ठ २ पर ग्रंकित टिप्पणियां तथा श्राज्ञाय देखिये। यहां पर यह भी उल्लेख करना ग्रावश्यक है कि राज्यभाषा हिःदी हो जाने से ग्रधिकांश सरकारी पत्र-व्यवहार हिन्दी में होने लगा है ग्रीर हिन्दी में सरकारी पत्र प्रारम्भ करने में ऐसी कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होगी, कारण कि हिन्दी में सरकारी पत्र लिखने में ग्रंग्रेजी वाक्यांश (I have the honour to) का ग्राश्रय लेने की ग्रावश्यकता नहीं रह जाती। ग्रतः जिलाधीश को सूचित कर दिया जाय कि ग्रंग्रेजी में सरकारी पत्र प्रारम्भ करने के रूप में कोई संशोधन नहीं हुग्रा है ग्रीर उस समय तक उसका रूप वही रहेगा जब तक कि इसके विपरीत कोई ग्रन्य ग्रादेश जारी न किये जायं। ग्रालेख्य स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत।

(ह० सहायक)

संख्या ७

संचालक/सिचव

कृपया पृष्ठ २ ग्रौर ३ पर दी गई टिप्पणियों को देखें । इस समय जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि ग्रस्थायी सरकारी कर्मचारियों को ग्रग्रिम यात्रिक भत्ता दिया जाय या नहीं । इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

श्रभी हाल हो में सूचना विभाग में संचालक के पद का निर्माण हुश्रा है। इसके पहले सचिव ही संचालक थे। सूचना विभाग के कार्यालय में सचिवालय की कार्य प्रणाली के श्रनुसार ही काम हो रहा है। श्रत एव इनका रूप उसी प्रकार है जैसा कि सचिवालय में सम्मिलित डेबलपमेंट किमश्नर, डाइरेश्टर, गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री, गवर्नमेंट स्टेट श्राफिसर, किमश्नर खाद्य व रसद विभाग श्रादि के कार्यालयों का है।

२——सूचना मंत्री, उप-मंत्री, सभा-सचिव के ग्रर्विलयों का वेतन ग्रीर भत्ता इसी विभाग से विया जाता है। सिवव के ग्रिविस्त संचालक, उपसंचालक, सहायक संचालक, सहायक सिवान प्रकाशन ग्रिविकारों, रेडियो इंजोनियर, ग्राकिसर इंचार्ज फोटोग्राफी इत्यादि के ग्रधीनस्थ चपरासियों से इस विभाग का पूरा सम्पर्क है। फिर तीन ग्रधी अभे श्रीर १४२ व्यक्तियों के वेतन, भत्ते ग्रीर प्रासंगिक व्यय का हिसाब-किताब भो इसी विभाग में होता है। प्रकाशन ग्रीर प्रचार ही इस विभाग के मुख्य कर्त्तव्य हैं। जिला सूचना ग्रधिकारियों द्वारा तथा प्रकाशन ग्रीर क्षेत्र प्रचार कार्यक्रमों द्वारा लोक कल्याण सम्दन्शी बाता से जनता को श्रवगत कराने के लिये इस विभाग को ग्रग्रसर रहना पड़ता है। इसिलए बहुवा सूचना विभाग के ग्रधिकारियों को सरकारी कार्य से बाहर जाना पड़ता है ग्रीर तब उनके ग्रवंलियों को ग्रिविम भत्ता देने की ग्रावश्यकता पड़ती है। कभी-कभी तो थोड़े समय में ग्रिग्रिम धन देने के लिये प्रबन्ध करना पड़ता है।

३--सचना संचालन कार्यालय के लगभग ६० प्रतिशत कर्मचारी ग्रभी ग्रस्थायी हैं। सचि-वालय के विभागों में यहां की ग्रपेक्षा स्थायी कर्मचारी कहीं ग्रधिक हैं। पहले जो कर्मचारी सरकारी कार्य के हित में बाहर दौरे पर भेजे जाते थे उनको साधारण रूप से प्रिग्रम भत्ता खजाने से निकाल कर दे दिया जाता था। नियम २४२ (क) फाइनेन्शियल हैन्डबुक, खंड ५, भाग १ के अनुसार अस्थायी कर्मचारी ग्रग्रिम यात्रा भत्ते के ग्रधिकारी नहीं हैं। सचना विभाग में प्रायः सभी कर्मचारी जो दौरे पर भेजे जाते हैं ग्रस्थायी हैं। विभाग के ग्रन्य कर्मचारियों को भी प्रदर्शिनी तथा पत्रों को छपवाने ग्रादि के प्रबन्ध में बाहर जाना पड़ता है । यदि उनको श्रग्निम यात्रा भत्ता न दिया जाय तो बाहर जाने में श्रसमर्थ हो जाते हैं। सचिवालय में इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिये विशेषतया नैनीताल के संबंध में, सचिवालय प्रशासन (लेखा) विभाग ने ग्रभी केछ दिन हुये ग्रपने कार्यालय स्रादेश संख्या ए-४७५६/२०-ए--१२५-१९५४, दिनांक २९ स्रप्रैल, १९५५ द्वारा सचिवालय के समस्त विभागों को सुचित किया है कि वित्त विभाग के परामर्श से यह निर्णय हो चुका है कि ग्रस्थायी सरकारी कर्मचारियों को भी त्रप्रिम भत्ता दिया जा सकता है यदि सचिवालय का कोई ग्रन्य स्थायी कर्मचारी उनकी जमानत के लिये खड़ा हो । इस संबंध में जो स्थायी कर्मवारी जमानत देता है उसे एक निर्धा-रित बांड (bond)भरना पड़ता है । जब सिववालय प्रशासन विभाग की भांति सूचना विभागको भी ठीक उसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है श्रौर जब सूचना विभाग का संयुक्त कार्यालय सिववालय की कार्यविधि का ही अनुसरण करता है, तो उपर्युक्त २६ अप्रैल, १६४५ का श्रादेश स्पष्टतया उसपर भी लागू होना चाहियँ। इसी श्राधार पर सरकारी कार्य से नैनीताल गये हुये कर्मचारियों को ऋष्रिम भता दिया गया है। इस संबंध में पूछने पर वित्त विभाग ने यह बताया कि यदि सूचना संचालन कार्यालय सचिवालय का एक भाग है तो निस्तंदेह वे स्रादेश उस ५र भो लागू होंगे। इस के साय हो वित्त विभाग ने भी कहा कि वे इस विषय पर कोई सम्मति नहीं दे सकते क्योंकि इस बात का निर्णय कि सूचना संचालन कार्यालय सिचवालय का भाग है या नहीं वह स्वयं ही करें। मेरी सम्मित में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये उक्त निर्णय का अनुसरण करने के सिवाय कोई वूसरा उपाय नहीं है।

४--यदि कहा नाय कि वित विभाग के परिपत्र संख्या ए-१८८१/१०--१५ (१)-५५, दिनांक ३० म्रप्रैल, १६४४ के म्रत्सार चपरासियों म्रौर नानगजटेड कर्मचारियों को म्रप्रिम भत्ता इम्प्रैस्ट से दिया जा सकता है तो इस बात का ग्राश्वासन कैसे हो कि इम्प्रैस्ट से दिये हुये ग्रग्रिम धन को ग्रस्थायी कर्मचारी लौटा ही देंगा । ग्रतएव ग्रस्यायी कर्मचारा को इम्प्रैस्ट से भी ग्रग्निय घन देना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में भी स्थायी कर्मचारी से बांड भरवाना आवश्यक है। सूचना विभाग में १,००० रु० का क्षरकारी श्रविम धन स्वीकृत है। छोटे-छोटे प्रासंगिक व्ययों के लिये बराबर श्रिपम धन दिया जाता है। इसलिये वह धन नानगजटेड कर्मचारियों श्रौर चपरासियों को नैनीताल भौर दूसरे स्थानों को जाने भौर वहां ठहरते के संबंध में भ्रिप्रिय मार्ग व्यय के लिये पर्याप्त नहीं है। ऐसी परिस्थित में मेरी यह निश्चित घारणा है कि सूचना विभाग में भी इस संबंध में वही कार्यवाही की जाय जो वित विभाग ने सचिवालय के ग्रन्य समस्त विभागों के लिये निश्चित किया है। फिर चाहे डाइरेक्टरेट हो या सचिवालय का कोई विभाग हो. अप्रिम धन देने के विषय में सिद्धांत तो समान रूप से एक ही माल न पडता है। यह तो मानी हुई बात है कि प्रचार, प्रदिश्तनी तथा प्रकाशन संबंधी कार्यों के निमित्त यहाँ सरकारी कार्य से दौरे हुआ ही करते हैं। अतएव यदि सचिवालय के कर्मचारी की किसी स्थायी कर्मचारी को जनानत पर अप्रिम भता मिल सकता है तो यहां भी निश्चित रूप से वैसा ही होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जो कठिनाइयां इस विभाग में बराबर सामने श्राती रहती हैं उनका निराकरण होना असंभव है, और फलतः उसकी कार्य-प्रगति में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जायगी । उपर्युक्त प्रस्ताव से यदि संचालक भ्रौर लिचव सहस्रत हो तो यह पत्रावली वित विभाग को सचनार्थ दिला दी जाय और उल्लिखित प्रशासकीय कठिनाइयों को इर करने का यदि कोई दूसरा उपाय हो तो बिल विभाग बताने की कपा करे।

8 = 6 - 6 E X X

(ह॰ सहायक सचिव)

परिशिष्ट प्र

(श्वंतरकालीन)

कतिपय पदनामों के हिन्दी पर्याय १--राज्यपाल, मंत्री, इत्यादि

Governor राज्यपाल Chief Minister मख्य मंत्री Minister for Finance, Power, वित्त, शक्ति, वन तथा सहयोग मंत्री Forests and Co-operation. Minister for Agriculture and कृषि, सहाय्य तथा पुनर्वासन मंत्री Relief Rehabilitaand tion. Minister for Excise and ग्रावकारी तथा पंजीयन संत्री Registration. Minister for Planning, Health, नियोजन, स्वास्थ्य, उद्योग तथा रसद मंत्री Industries and Civil Supplies. Minister for Revenue and Trans-राजस्व तथा परिवहन मंत्री port. Minister for Justice and Local न्याय तथा स्वज्ञासन मंत्री Self-Government. Minister for Education and शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री Harijan Sahayak. सूचना तथा सिचाई मंत्री Minister for Information and Irrigation. Minister for Public Works सार्वजनिक निर्माण मंत्री Minister for Labour and Social श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री Welfare.

Deputy Minister . . . जप-मंत्री Parliamentary Secretary . . सभा-सिचव

२--वियान मंडल के पदाधिकारी

Chairman सभापित Speaker . . . ग्रध्यक्ष Deputy Chairman . . . उप-सभापित Deputy Speaker . . . उपाध्यक्ष

३--- सचिवालय के पदाधिकारी

Secretary ... सचिव Private Secretary to C. M. .. मुख्य मंत्री के निजी सचिव Joint Secretary ... संयुक्त सचिव

उप सचिव Deputy Secretary ... ग्रन् सचिव Under Secretary ... कार्याधिकारी विशेष Officer on Special Duty सहायक सचिव Assistant Secretary वयक्तिक सहायक Personal Assistant ग्रधीक्षक Superintendent सहायक ग्रघीक्षक Assistant Superintendent प्रवर वर्ग सहायक Upper Division Assistant वरिष्ठ सेवा सहायक Superior Service Assistant प्रवर कोटि लिपिक Upper Grade Clerk टिप्पणीक तथा ग्रालंखक Noter and Drafter ग्रवर वर्ग सहायक Lower Division Assistant ग्रवर कोटि लिपिक Lower Grade Clerk निर्देश लिपिक, निर्देश लेखक Reference Clerk Register Keeper पंजीपाल Record Keeper ग्रभिलेख पाल Treasurer कोषाध्यक्ष लेखापाल Accountant Despatcher परिप्रेषक Camp Assistant शिविर सहायक त्वरांकक, ग्राश् लिपिक Stenographer **Typist** टकक Copyist प्रतिलिपिक Storesman भांडागारिक Stationery Clerk लेखन सामग्री लिपिक Care Taker श्रवधाता Council House Guard विद्यान भवन रक्षक Inferior Staff निम्न कर्मचारिवर्ग Orderly ग्रदली Peon चपरासी

४--विभागाध्यक्ष ग्रादि

1. Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh.

¥-1

2. Chief Engineer, Irrigation

Branch, Uttar Pradesh.

3. Chief Engineer, Public
Works Department
(Building and Roads),
Uttar Pradesh.

4. Chief Engineer, Electricity Branch, Uttar Pradesh.

5. Inspector-General of Police, Uttar Pradesh. माल बोर्ड के सर्चिव, उत्तर प्रदेश।

चीफ इंजीनियर (मुख्य ग्रिभियंता), सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश । चीफ इंजीनियर (मुख्य ग्रिभियंता), सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क) उत्तर प्रदेश।

चीफ इंजीनियर (मुख्य स्रभियंता), विद्युत् विभाग, उत्तर प्रदेश।

पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल, उत्तर प्रदेश।

6. Inspector-General of Prisons, Uttar Pradesh.

7. Chief Engineer, Local Self-Government Branch, Uttar Pradesh.

8. Director of Agriculture, Uttar Pradesh.

9. Registrar, Co-operative Societies, Uttar Pradesh.

10. Director of Anima1 Husbandry, Uttar Pradesh.

11. Director of Land Records, Uttar Pradesh.

12. Secretary, Legislature, Uttar Pradesh.

13. Development Commissioner, Uttar Pradesh.

14. Cane Commissioner. Uttar Pradesh.

15. Transport Commissioner, Uttar Pradesh.

16. Entertainment and Betting Tax Commissioner. Uttar Pradesh.

17. Custodian of Evacuee Property, Uttar Pradesh.

18. Director of Colonization,

Uttar Pradesh.

19. Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh.

20. Commissioner, Sales Tax, Uttar Pradesh.

21. Director of Education, Uttar Pradesh.

22. Land Reforms Commissioner, Uttar Pradesh.

23. Director of Information, Uttar Pradesh.

24. Director of Harijan Welfare, Uttar Pradesh.

25. Electrical Inspector, U. P.

कारावास के इंसपेक्टर जनरल, उत्तर प्रदेश ।

चीफ इंजीनियर (मुख्य म्रिभयंता), स्वायत्त शासन, इंजीनियरिंग विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश ।

पश पालन विभाग के संचालक, उत्तर प्रदेश।

भू-ग्रभिलेखों के संचालक, उत्तर प्रदेश।

विधान मंडल के सचिव, उत्तर प्रदेश।

विकास कमिश्नर, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नर, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश।

परिवहन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश।

मनोरंजन तथा बाजी कर कमिश्नर, उत्तर प्रदेश।

निष्कांत सम्पत्ति के संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

उपनिवेशन के संचालक, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाग्रों के संचालक, उत्तर प्रदेश।

बिकी कर कमिश्नर, उत्तर प्रदेश।

शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश।

भमि व्यवस्था कमिश्नर, उत्तर प्रदेश।

सुचना संचालक, उत्तर प्रदेश ।

हरिजन कल्याण के संचालक, उत्तर प्रवेश।

इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश।

27.	Registrar, High Court Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh. Conservator of Forests Commissioner of Excise,	रिजस्ट्रार, हाईकोर्ट । वन विभाग के चीक कंजरवेटर (मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश। वन विभाग के कंजरवेटर (संरक्षक)। ग्रावकारी कमिश्नर, उत्तर प्रदेश।
	Uttar Pradesh. Director of Industries, Uttar Pradesh.	उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश।
	Inspector-General of Re- gistration, Uttar Pradesh.	रजिस्ट्रेशन विभाग के इंसपेक्टर जनरह उत्तर प्रदेश।
32.	Secretary, Public Service Commission, Uttar Pradesh.	सिचव, लोक सेवा श्रायोग, उत्तर प्रदेश।
33.	Advocate-General, Uttar Pradesh.	
34.	Superintendent, Printing and Stationery, Uttar Pradesh.	ग्रधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश
35.	Labour Commissioner, Uttar Pradesh.	श्रम किम्हिनर, उत्तर प्रदेश ।
36.	District Officer	जिलाघीश
	District Judge	जिला जज
	Chief Inspector of Offices	कार्यालय प्रघान निरीक्षक

परिशिष्ट ६

(ग्रन्तरकालीन)

उत्तर	प्रदेश	सचिवालय	के	विभागों व	ने	नामों	के	हिन्दी पर्याय	1
				4	-		-		

	गर्भ के किया के हिन्दा प्रयाय
1 2	वैभागिक संख्या
1. Revenue (A) Department	१क माल(क) विभाग
2. Revenue (B) Department	१ख माल(ख) विभाग
3. Revenue (C) Department	
4. Revenue (D) Department	0 = -(-)
5. Appointment (A) Depart-	२क नियुक्ति (क) विभाग
ment.	
6. Appointment (B) Department.	२ ख नियुक्ति (ख) विभाग
7. General Administration Department.	३ सामान्य प्रशासन विभाग
8. Cultural Affairs and Scientific	
Research Department.	ं वार्षित स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्
9 Medical (A) Department	विभाग।
9. Medical (A) Department 10. Medical (B) Department	५क चिकित्सा (क) विभाग
11. Home (Criminal) Depart-	५ च चिकित्सा (ख) विभाग
ment.	६ गृह (फौजदारी) विभाग
12. Judicial (A) Department	10 T (-) 6
13 Judicial (B) Department	७क न्याय (क) विभाग ७ख न्याय (ख) विभाग
14. Home (Police-A) Depart-	
ment.	प्र-⊶क गृह (पुलिस-क) विभाग
15. Home (Police-B) Depart-	दख गृह (पुलिस-ख) विभाग
ment.	न व पृष्ठ (नुग्यतन्त्र) विमान
16. Home (Police-C) Depart-	५ग गृह (पुलिस-ग) विभाग
ment.	. 56 (3,) 14,114
17. Home (Police-D) Depart-	५ घ गृह (पुलिस-घ) विभाग
ment.	26 (2)
18. Local Self-Government	६ स्वायत्त शासन विभाग
Department.	
19. Finance (Accounts)	१० क वित्त (लेखा) विभाग
Department.	
	१० ख वित्त (बजट) विभाग
ment.	
21. Finance (Expenditure	१० इ१ वित्त (ब्यय नियंत्रण-१) विभाग
Control-I) Department.	
22. Finance (Expenditure	१० इ.२ वित्त (व्यय नियंत्रण-२) विभाग
Control-II) Department.	
23. Finance (Expenditure	१० ङ३ वित्त (व्यय नियंत्रण-३) विभाग
Control-III) Department.	
24. Finance (General-I)	१०ज१ वित्त (सामान्य-१) विभाग
Department.	

१०--ज २ वित्त (सामान्य-२) विभाग (General-II) 25. Finance Department. १०-- वत्त (सेवायें ग्रौर बिकी-कर) (Services and 26. Finance विभाग। · Sales Tax) Department. वित्त (निरीक्षण, मितव्ययता ग्रौर पुनसँगठन) (Inspection, Eco-27. Finance विभाग। Reorganiznomy and ation) Department. वित्त (नियोजन तया संताधन) विभाग (Planning 28. Finance Resources) Department. ११--क नगरपालिका (क) विभाग। 29. Municipal (A) Department ११--ख नगरपालिका (ख) विभाग। 30. Municipal (B) Department कृषि (क) विभाग 31. Agriculture (A) Department १२--क कृषि (ख) विभाग 32. Agriculture (B) Department १२--ख सहकारी विभाग 77--T 33. Co-operative Department ग्राम सुवार विभाग (सहकारी विभाग १२--घ Development 34. Rural में विलोनीकृत)। Department (Merged with Co-operative Department). पश पालन (क) विभाग १२--डः (A) 35. Animal Husbandry Department. १२-- च मत्स्य पालन विभाग (पशु पालन 36. Fisheries Department विभाग से सम्बद्ध)। Animal (Attached to Husbandry Department). 37. Agriculture (C) Department कृषि (ग) विभाग १२---छ माल (वन) विभाग 38. Revenue (Forest) Depart-88 ment. 39. Education (A) Department शिक्षा (क) विभाग १५--क शिक्षा (ख) विभाग 40. Education (B) Department १५--ख 41. Education (C) Department शिक्षा (ग) विभाग १५--ग जन-स्वास्थ्यं विभाग 42. Public Health Department १६ 43. Legislative विधान विभाग न्याय Department 20 विभाग से सम्बद्धी। [Attached to Judicial (A) Department] 44. Industries (A) Department उद्योग (क) विभाग १८--क 45. Industries (B) Department उद्योग (ख) विभाग १८---ख 46. Industries (C) Department उद्योग (ग) विभाग १८--ग 47. Industries (Establishment) उद्योग (ग्रधिष्ठान) विभाग १5 Department. 48. Information Department ... 38 सूचना विभाग 49. Secretariat Administration २०--डः सचिवालय प्रशासन (ग्रविष्ठान) (Establishment) विभाग ।

२० -- क सचिवालय प्रशासन (लेखा) विभाग

Department.
50. Secretariat Administration

(Accounts) Department.

51	. Language Department	
52	Home (Jails) Department	२१ भाषा विभाग
53	Public Works (A)	
23	Deportment (A)	२३ क सार्वजितिक निर्नाग (क) विभाग
EA	Department.	
54	Public Works (B)	२३ख सार्वजनिक निर्माण (ख) विभाग
	Department.	
55.	Accounts Section (P. W. D.)	लेबा श्रनुभाग, सार्वजनिक निर्माण
		विभाग।
56.	Power (A) Department	२३पो ए विद्युत (क) विभाग
57.	Power (B) Department	२३—-पो बी विद्युत (ख) विभाग
58.	Budget Section, Electricity	वजट श्रनु राग, विद्युत (अ) विनाग
59.	Irrigation (Establishment)	२३प्राई ई सिंचाई (म्रिबिड्टान) विभाग
	Department.	ररश्राइ इ ।ताचाइ (श्रावकान) विसाग
60	Irrigation (Works)	23 मार्च बच्च रिकार्च (रिकार्डण) रिकार्डण
٠٠.	Department.	२३म्राई डब्लू सिंचाई (निर्माण) विभाग
61	Budget Section, Irrigation	
62	Government Estate	बजट श्रनुपाग, सिचाई राज्य सम्पत्ति विभाग
UL.	Department.	राज्य सम्पात्त ।वमाग
63		
	Confidential Department	२५ गोपन विभाग
04.	Harijan Sahayak Depart-	२६ हरिजन सहायक विभाग [शिक्षाः
	ment [Attached to Edu-	(ग) विभाग से सम्बद्ध]।
-	cation (C) Department].	~ ~ /
65.	Rationing Department	२७ रार्शानग विभाग (खाद्य तया रसद
	(Merged in the Food and	विभाग में विलीनीकृत)।
	Civil Supplies Depart-	
	ment).	
66.	Economics and Statistics	२८ग्रयं तथा संख्या विभाग
	Department.	() 0
67.	Food and Civil Supplies	२६क खाद्य तथा रसद (क) विभाग
	(A) Department.	
68.	Food and Civil Supplies	२६ ख खाद्य तथा रसद (ख) विभाग
	(B) Department.	
69.	Food and Civil Supplies	२६ग खाद्य तथा रसद (ग) विभाग
	(C) Department.	
70.	Transport Department	३० परिवहन विभाग
71.	Relief and Rehabilitation	३१क सहायता तथा पुनर्वासन (क) विभाग
	(A) Department.	
72.	Relief and Rehabilitation	३१ ख सहायता तथा पुनर्वासन (ख) विभाग
	(B) Department.	
73	Relief and Rehabilitation	३१ग सहायता तथा पुनर्वासन (ग) विभाग
13.	(C) Department.	
71	Relief and Rehabilitation	३१ घ सहायता तथा पुनर्वासन (घ) विभाग
14.	(D) Department.	
	(D) Department.	

75. Evacuee Property Depart-	निष्कांत सम्पत्ति विभाग [सहायता तथा
ment Attached to	पुनर्वासन (क) विभाग से सम्बद्धी।
Relief and Rehabilitation	
(A) Department].	
76. Agriculture Engineering	३२क कृषि इंजीनियरिंग विभाग
Department.	
77. Panchayat Raj Department	३३ पंचायत राज विभाग
78. Petition Department	३४ ग्रम्पर्यना विभाग
79. Planning Department	३५ नियोजन (प्लानिंग) विभाग
80. Labour (A) Department	३६क श्रम (क) विभाग
81. Labour (B) Department	३६ ख श्रम (ख) विभाग
82. Election Department	निर्वाचन विभाग
83. Social Welfare Department	
84. Housing Department	समाज कल्याण विभाग
Louding Dopartiment	३७ निवास विभाग

परिशिष्ट ७

रीतिक अवसरों का कार्यक्रम और निमंत्रण-पत्र के नमूने

गांधी जयन्ती उत्सव

उत्तर प्रदेश सिचवालय

[शुक्रवार, २ अक्तूबर, १६५३, प्रातःकाल, ६-१५ बजे]

(स्थान-टेनिस लान, विधान भवन)

गांधी जयन्ती उत्सव उत्तर प्रदेश सचिवालय [शुक्रवार, २ ग्रक्तूबर, १६५३, प्रातःकाल, ६–१५ बजे] स्थान—टेनिस लान, विधान भवन

कार्य-क्रम

- प्रातः ६-१५ श्री राज्यपाल महोदय ग्रायेंगे। (राज्यपाल महोदय के पंडाल में प्रवेश होते ही पी० ए० सी० बैन्ड राष्ट्रीय गीत बजायेगा ग्रीर उपस्थित लोग खड़े हो जायेंगे।)
 - ६-१७ बन्दे-मातरम्--भातखंडे संगीत विद्यापीठ द्वारा।
 - ६-२५ चित्र का ग्रनावरण— राज्यपाल महोदय द्वारा चित्र को पुष्पों की माला पहिनाया जाना।

nair is they is not but helps

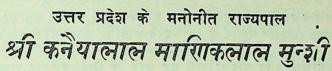
६-३० महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का गायन।

६-४० महात्मा गांधी का रेकार्ड किया हुम्रा प्रवचन।

६-४५ राज्यपाल महोदय का भाषण।

६-५५ पी०ए०सी० बैन्ड राष्ट्रीय गीत बजायेगा श्रौर उपस्थित लोग खड़े हो जायेंगे।

(उत्सव समाप्त)



का राजभवन, लखनऊ में शपथ-ग्रहण करने का

कार्य-कम

सोमवार, २ जून, १६५२

-> मुख पृष्ठ

उत्तर प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल श्री कनैयालाल माणिकलाल मुन्शी

का राजभवन, लखनऊ में शपथ-ग्रहण करने का

[तोमवार, २ जून १६५२]

मुबह के १० बजे से १०--१५ तक---मेहमान श्रायेंगे ग्रौर दरबार हाल में बैठाये जायेंगे। १०--२०----मुख्य सचिव दरबार हाल में श्रपनी जगह पर ग्रा जायेंगे।

१०--२०---माननीय नुख्य मंत्री ग्रौर माननीय मंत्रीगण दरबार हाल में ग्रपनी-ग्रपनी जगहीं पर बैठेंगे।

१०--२३---माननीय चीफ जस्टिस दरबार हाल में स्रपनी जगह पर बैठेंगे। १०--२४----श्रीमती लीलावती मुंशी दरबार हाल में स्रपनी जगह पर बैठेंगी।

१०--२४---मनोनीत राज्यपाल महोदय श्रौर पर्सनल स्टाफ लौज के पास वाले बैठक में इकटठा होंगे।

१०-२७--म नोतीत राज्यपाल महोदय ग्रीर पर्सनल स्टाफ जलूस में नीचे लिखे हुये कम से बैठक से दरबार हाल को जायेंगे।

चोबशर ए०-शि०-सी० (द्वितीय)

चोबदार ए०-डो०-सी० (प्रथम)

मनोनीत राज्यपाल महोदय राज्यपाल के सेक्रेडरी

मनोगीत राज्यपाल महोदय के दरबार हाल में प्रवेश होते ही सशस्त्र कान्सटेबुलरी की तीसरी बढालियन राष्ट्रीय गीत बजायेगी ।

मंच के पास पहुंचने पर जलूस के दोनों ग्रंग पुड़कर एक-दूसरे के सामने खड़े होंगे। मनोनीत राज्यपाल महोदय के मंच पर बैठ जाने पर पर्सनल स्टाफ अपनी-अपनी जगहों पर हो जायेंगे।

(बैन्ड के राष्ट्रीय गीत बजाने और जलूस के दरबार हाल में पहुंचने पर सब उपस्थित लोग खड़े हो जायेंगे और मतोतीत राज्यपाल महोदय के स्थान-प्रहण करने पर श्रपनी-श्रपनी जगहों पर बैठ जायेंगे।)

मुख्य सिचव मंच की ग्रोर चलेंगे ग्रीर कार्यवाही शुरू करने के लिये मनोनीत राज्यपाल

महोदय की म्राज्ञा लेंगे।

(इसके बाद कार्यवाही शुरू होगी।)

मनोनीत राज्यपाल महोदय श्रपनी जगह से उठ कर मंच के सामने श्रायेंगे।

मुख्य नंत्री राष्ट्राति का ग्रविगत्र पढ़ेंगे, जिसके ग्रतुसार श्री कर्तयालाल माणिकलाल मुंत्री उत्तरप्रदेश के राज्यपाल नियक्त किये गये हैं।

मानतीय चोक जिस्टम तब मनोतीत राज्यपाल महोदय को शपथ देंगे श्रीर मनोतीत राज्य-पाल महोदय शपय प्रहण करेंगे और उस पर प्रपते हस्ताक्षर करेंगे।

इसके बाद महामान्य राज्यपाल ग्रपनी जगह पर बैठ जायेंगे।

मुखा सचिव कार्यवाही समाप्त करने के लिये महामान्य राज्यपाल की श्राज्ञा लेंगे। कार्यवाही समाप्त होगी।

कार्यवाही के समाप्त होने पर महामान्य राज्यपाल पर्सनल स्टाफ के साथ जलूस में उसी तरह से बाहर जायेंगे जैते वे अन्दर आये थे।

(उपस्थित त्रोग अपती-अपती जगहों पर खड़े ही जायेंगे और जल्स और माननीय मह्य मंत्री श्रीर माननीय नंत्रियों के दरबार हाल से चले जाने तक खड़े रहेंगे।)

इसके बाद चीक जस्टिस, मानतीय मुख्य मंत्री श्रीर माननीय मंत्रीगण श्रीर मुख्य सचिव बाहर जायेंगे।

१--शपथ विषि के बाद "बैंक्वींटंग हाल" में स्वागत होगा।

२--दरबार हाल से बाहर जाने पर महामान्य राज्यपाल "लौज" के सामने वाले मैदान में "गार्ड-ग्राफ-ग्रानर" का निरीक्षण करेंगे ग्रीर उसके बाद "लौज" में ग्राकर श्रीमती मुंशी सहित "बैंक्वटिंग हाल" को पधारेंगे श्रौर मेहमानों से मिलेंगे।

३---"बैंक्वॉटग हाल" में स्वागत के समय बैन्ड चुते हुये गीत बजायेगा।

निमंत्रण-पत्र

मान्यवर,

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पवित्र जयन्ती २ ग्रक्तूबर, १९५४ को ६ बजे प्रातःकाल विधान भवन में मनायी जांयगी। गृह मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी गांधी जी के चित्र का ग्रनावरण करेंगे।

श्रापसे प्रार्थना है कि उत्सव में सिम्मिलित होने की कृपा करें।

लखनऊ; दिनांक २६ सितम्बर, १६५४ विनीत, श्रादित्य नाथ झा, मुख्य सचिव

नोट---क्रुपया द-५० तक ग्रपना स्थान ग्रहण कर लें।

परिशिष्ट ५

(ग्रंतरकालीन)

प्रशासकीय शब्दावली

नोट--विभागों के नाम तथा ऋषिका रेयों के पदनाम ऋन्य परिकाब्ट म दिये हुये हैं।

A

Abeyance		म्रास्थगन
Ab initio		श्रारम्भतः
Abolition		उन्मूलन
Abolition of post		पद-उत्सादन, पद तोड़ना
Acknowledgment		प्राप्ति-स्वीकरण
Act	***	कार्य, ग्रधिनियम
Ad hoc		तदर्थ
Ad infinitum	16.5	यात्रदनन्ति -
Adjourn		स्थगन
Adjourn sine die		म्रदिन स्थगन
Adjudicator		ग्रभिनिर्णायक
Adjustment		समाधान
Adult		वयस्क
Adult suffrage		वयस्क मतदान
Advisory		मंत्रणा-परामर्शदात्री
Advisory Council		मंत्रणा परिषद
Affidavit		शपथ-पत्र
Affiliate		ग्रनुबद्ध करना
Age		ग्रवस्था, वयस, ग्रायु, युग
Agenda		कार्यावलि
Age of retirement	• •	सेवा निवृत्ति वयस
Allegation		मिथ्याभियोग
Allotment	•••	प्रतिदेशन, प्रदेशन, बंट, बांट
Allowance	• •	भत्ता
Allowance, superannuation	• •	वयोधिक भत्ता
Alternative	••	विकल्प, वैकल्पिक
Amendment	••	संशोधन
Amnesty	• •	
Anomaly	• •	क्षमा घोषणा
Annex		विधि विरोध, ग्रनियम
Annual review	• •	ग्रनुलग्न करना
Annuity	••	वाधिक पुर्नावलोकन
Antecedent	• •	वार्षिक वृत्ति
Anticipated	• •	पूर्व वृत्ति
	• •	प्रत्याशित

nue		प्रत्याशित राजस्व
		भ्रष्टाचार विरोधी
		ग्रपील, पुनर्वाद •
		उप-सांत्वना, प्रसादन
		परिशिष्ट
		श्रावेदन-पत्र, प्रयोग, प्रयुक्ति
	AND DESIGNATION OF THE PERSON	श्रनुमोदन
	A COLUMN	राज-साक्षी
		मध्यस्थ, पंच
		सभा
		श्रभिहस्तांकन, नियतन, सौंपना
		संलग्न करना
		साक्षयांकन, ग्रमित्रमाणन
		लेखा-परीक्षा, श्रंकेक्षण
	+ Dete	प्रमाणित
		प्राधिकृत करना
		ग्रधिकार, प्राधिकार, प्राधिकारी, ग्रधिकार-पत्र
		प्रतीक्षा करना
	D	
	Б	ALL TO ADMINISTRATION OF
		मत पत्र
	• •	मत पेटी
		नवच्छात्र
		विधेयक, हुन्डी, विपत्र
		परिषद्, समिति
		सद्भावना
		बंध
-		भंग, उल्लंधन
		शांतिभंग .
		श्राय-व्ययक
		उप-विधि
	C	
1000		C Telescope and another service of
	••	परिकलन, गणन, गणना
	••	निरस्त करना
••	-	श्रभ्यर्थी, उम्मीदवार
• •		प्रकरण, मामला
• •		ग्राकस्मिक
• •	•••	प्रत्यादेश
• •	in the second	जनगणना
	more and	उपकर
		चरित्र
		चरित्रपंजी, शील विवरण, ग्राचरणाविल
••		श्रिभयोग, कार्यभार
		B CC

Charged			प्रभृत
Circular			परिपत्र
Circumstance			परिस्थिति
Citation		• •	उद्धरण
Citizen			नागरिक
Civil			ग्रसंनिक
Claim			दावा, ग्रभ्ययंन
Clarification			स्पष्टीकरण
Classification			वर्गीकरण
Clause			खंड
Code	• • •		संहिता
Colonization			उपनिवेशन
Column			स्तम्भ
Command			समादेश
Commission	**	• •	म्रायोग -
Commissioned			विनियुक्त
Communication		• •	संचार
Compensation			प्रतिकर
Competent		• •	कार्यकुशल
Competent author	rity	••	सक्षम प्राधिकारी
Competent court	• •	• •	सक्षम न्यायालय
Complaint	•		परिवाद, शिकायत
Compliance			श्रनुपालन, श्रनुवर्तन
Compulsory		• •	भ्र निवार्य
Concurrence		• •	सहमति
Condition		••	उपाधि, शर्त
Conduct	••	• •	म्राचरण
Confidential	••	• •	गुप्त, गोपनीय
Confirmation		• •	स्थायीकरण, दृढ़िकरण, पुट्टीकरण
Consent		• •	सहमति
Consideration	••	• •	विचार
Consistent	• •	,.	संगत
Constituency	• •		निर्वाचन क्षेत्र
Consultation	• •		संमंत्रण, विमर्श
Contradiction		••	प्रतिवाद, प्रत्युक्ति
Contribution	• •	• •	भ्रं शदान
Controversial		••	विवादास्पद
Correspondence	• •	• •	पत्र-व्यवहार
Corresponding		• •	तत्स्थानी
Corrigendum	••	• •	शृद्धि-पत्र
Countercharge			परिषद
Countercharge	• • •		प्रत्याभियोग
Cut	C		प्रति- हस्ताक्षर
Cut	***	• •	कटौती - रे
Cut motion		• •	कटौती प्रस्ताव

		D	
Date, out of			ग्रनद्यतन
Date, up to			श्रद्यावधि, श्रद्यावधिक
Declare			घोषित करना
Declaration			घोषणा
Decree			श्राज्ञप्ति, डिक्री
Decreed			विहित
Deed			विलेख
De facto			वस्तुतः
De jure			नियमतः, विधितः
Demarcation			सीमांकन
Demobilization			सैन्य वियोजन
Demotion			पदावनति
De novo		• •	पुनरारम्भ, नये सिरे से
Deposit			निक्षेप, जमा करना, घरोहर रखना
Deputation, on			प्रतिनियुक्ति पर
Detailed			सविस्तर
Detention	••		निरोध, नजर बन्दी
Determine	• •		ग्रवधारित करना
Diary	••	•	वैनंदिनी
Discipline	• •		श्रनुशासन
Disciplinary Discretion	• •		श्रनुशासिक .
Dismissal	• •	•••	स्विववेक
	• •		पदच्युति
Disposal Dispute	•	• •	निस्तारण
Disputed		••	वाद विवाद
Due	• •		विवाद ग्रस्त
Duty			देय, प्राप्य
Duty		E	यथाविधि, यथोचितरूप से
Efficiency			कार्य-क्षमता, प्रगुणता, दक्षता
Efficiency bar			दक्षता रोघ
Eligible			पात्र
Embezzlement			गबन, ग्रपहरण
Emergency			संकटकाल, श्रापात
Enactment			विधायन
Enclaves			श्रंतरक्षेत्र
Enclosure		• •	संलग्नक, सहपत्र
Encouragement			प्रोत्साहन
Endorsement			पृष्ठांकन, ग्रनुमोदन
Equitable			न्याय 💮 💮
Estate			ग्रास्या न
Everlasting			काल व्यापी

Exception Excise Executive Exemption Ex officio Ex parte Explanation Ex post facto Expressly		 	ग्रपवाद ग्रावकारी कार्यकारी, कार्यकारिणी, कार्यपालिका मुक्ति, उन्मुक्ति पदेन एक पक्षीय व्याख्या, स्पष्टीकरण कार्योत्तर स्पष्टरूप से
Favourable Federation File Finance Fine Fitness Flag Foregoing Formula Forward Fund Fund sinking		G	स्रनुकूल संघ नस्ती, पत्रावली वित्त स्रर्थ-दंड, जुर्माना स्रारोग्यता पताका पूर्ववर्ती सूत्र स्रग्रप्रेषित करना निधि निक्षेप निधि
Generality Gist Glossary Grade Grant Gratification Gratification, ille Gratuity Grievance Guarantee Guard Guardian Guidance	egal	H	व्यापकता भाव, सारांश शब्दावली कोटि, कोटिबद्ध करना ग्रनुदान परितोषण, प्रतोष ग्रवंध परितोष, ग्रपप्रदान, घूस उप-दान व्यथा, शिकायत प्रत्याभूति रक्षापाल ग्रभिरक्षक, संरक्षक मार्ग-प्रदर्शन
Habeas corpus Hereby Hint Holding		•••	बंदी प्रत्यक्षीकरण एतद्द्वारा संकेत जोत

Honorarium			मानदेय
House		• •	
House of Parlia	ment		सदन, गृह संसद
House Trespass		Section 1	
and pass		i	गृहातिऋमण *
Identification		-	
	• •	••	पहिचान, ग्रभिज्ञ न
Illegal Illicit	••	•••	- प्रवं ष
Immediate	• •		ग्रवर्म्य, ग्रवंघ
Imminent	• •		तुरन्त, भ्रविलम्ब
	• •	••	प्रत्यासन्न, ग्रासन्न
Implied	• •	• •	गभित
Import	••		ग्राशय, ग्रमित्राय, ग्रायात
Imposed			ग्रारोपित
Inadmissible	••	• •	श्रप्राह्म
Inauguration		••	ज्व्वाटन विवास करिया है ।
Incentive	• •		त्रोत्साहन
Incharge	••		कार्यभारी, प्रभारी
Incidental	• •		प्रासंगिक
Inconsistent	• •		अ संगत
Increment	.• •	The 18 St. 18	वेतनवृद्धि
Incumbent	••	1.01	पद्धारी
Indiscretion Index	••		स्रविचार, स्रिविक
Index Indirect	••	••	श्रनुक्रमणिका .
	••		ग्रप्रत्यक्ष
Indispensible Inefficient	••		त्रपरिहार्य
In fact	• • 198		फार्याक्षम
	••	1997	तथ्यतः, वास्तव में
Informal	• •	••	ग्रविधिकः ग्रनौपचारिक
Infringement	••		उल्लं घ न
Injunction	1.33		निवेवाज्ञा, समावेश
Inoperative	• 199	A PORT	ग्रप्रवृत्त
Inopportune	••	F8	श्रसामियक, श्रनाकाल, श्रप्राप्तिकाल
Instruction	• •	• •	श्रनुदेश सब बातों के साथ-साथ
Inter alia	••	9 192	सर्व बाता के साथ-साथ ग्रंतरिम
Interim	· 1	1.11.11	श्रतारम श्रयं निरूपण
Interpretation		•	
Inter se			परस्पर भॅट, संदर्शन, साक्षात्कार
Interview	••	•	
In toto	•		पूर्गतया पुरःस्थापित करना
Introduce	• •	• •	
Ipso facto			स्वयमेव, स्वतः ए व श्रनियमितता
Irregularity	••		श्रान्यामतता श्रप्रास्ताविक
Irrelevant	• •	STATE OF	श्रप्रास्ताविक निष्काशित करना, जारी करना, निर्गमन,
Issue	• •		
			बाद प्रश्न

Item			मद
Item	•• 40.30	j	
Joint			संयुक्त
Judge			न्यायाधीश
Junior			कनिष्ठ
Jurisdiction	THE RES		क्षेत्राधिकार
Judicial			न्यायिक, व्यावहारिकी
Just			न्यायोजित
Justification			ग्रौचित्य
		**	
		K	
Keeper			रक्षापाल
Kind	107.54		प्रकार
Know			जानना
Knowledge			ज्ञान
Knowingly			जानबूझ कर
		L	
Lapse	100		व्यपगमन
Law			विधि
Law, according to	HE IN THE		विधिवत्
Law, established	by		विधि विहित
Law, question of			विधि प्रश्न
Law, substantive			तात्विक विधि
Law, violation of			विधि ग्रतिक्रमण
Lawful			वैधिकी
Lease			पट्टा
Leave			खुट्टी
—Casual			श्राकस्मिक छुट्टी
—Disability			ग्रसामर्थ्य छुट्टी
—Earned	1.		उपाजित छुट्टी
-Maternity	••		प्रसूतिका छुट्टी
—Medical			चैकितितक छट्टी
—Privilege		• •	म्रिधिकार सुट्टी
-Preparatory	to retiremen	t	निवृत्ति पूर्व को छुट्टी
-Quarantine	••	••	संसर्गरोघ खुट्टी
—Regular	••	• •	नैयमिक छुट्टी
—Study	• •	••	ग्रध्ययन छुट्टी
Legal	• •		वैघ्
Restraint	* 1	• •	ग्रासंघ
Legislation	••	••	विधान
Legislature	••	••	विधान मंडल
Lessee		• •	पट्टबारी
Lessor	•	••	पट्टदाता
Levy	• •	• •	कर लगाना

Letter			
—Demi-officia	1	••	पत्र
—Express	и	••	श्रर्द्ध-शासकीय पत्र
-Official	• •		द्रुतगामी पत्र
-Un-official	••		शासकीय पत्र
Licence		• •	विशासकीय पत्र, ग्रसरकारी-पत्र
Lock-out	• •		अनुज्ञाप्त
Lock-out	• •		तालाबंदी
		M	
Mala fides			
Manifesto	• •		कुभावना
Manuscript	••		घोषणा-पत्र
Margin	• •		हस्तलेख
Marked	••		उपांत
Matter	• •	••	म्रंकित, चिन्हित
Maximum	••		मामला, वाद विषय
Mediation		• •	ग्रिघिकतम
Medium			मध्यस्थता
Memo	••		माध्यम
Memorandum	• •		ज्ञाप
Mental	••		स्मृति-पत्र, ज्ञापन
			भानसिक
Mental-equipmen	ι		मानसिक विकास
Merged Minutes			विलोनोकृत
		••	मिनिट, टिप्पणी, संक्षिप्त कार्य-विवरण वृत्त
Misconstruction			मिथ्याबोध "
Modification	* • · · · ·	••	परिष्कार
Monopoly Motion	• •		एकाधिकार
MOUOII	•.4	••	प्रस्ताव
		N	
AT 11		100	
Negligence	• •		प्रमाद
Neutrality	• •		तटस्थता
Nominated	••	4.0	मनोनीत
Non-bailable	•,•		अप्रतिभाव्य
Non-cognizable	• •		अनुसंधेय, ब्रहस्तक्षेप्य
Non-recurring	••		भ्रनावर्तक म
N. B	••	••	ग्रवधेय
Note	• •	1000	टिप्पणी.
Notification			विज्ञप्ति
Nuisance	• •		कंटक
Nuisance, Public		• •	लोक कंटक
		O	
Obligatory		19:05	म्रनिवार्य
Occupier			ग्रध्यासी

0			कब्जा, पेशा, उपजीविका, ग्रध्यासन
Occupation	• •	• •	पद, कार्यालय
Office			पदाधिकारी
Office-bearer		A SECTION OF	कर्मचारी
Official			स्थानापन्न
Officiating	••		विकल्प
Option			म्रादिष्ट
Ordered			
Ordinance		••	प्रध्यादेश
Original	. •		मौलिक
Otherwise		amount.	ग्रन्यथा
Overdue			कालातीत
Overruled			निराहत
Overtime			ग्रिंघसमय
Ownership			स्वामित्व .
O WHOLDIN-P			10
		P	
		AND ADDRESS OF	े ि चेरित अगरात किया गया
Paid			वैतनिक, शोधित, भुगतान किया गया
Parliament		• •	संसद
Parole			श्रभिवचन
Partial			त्रांशिक
Partiality			पक्षपात
Part-time			ग्रंशकालिक
Passed			पारित
Passport			पारपत्र
Pending			विचाराधीन
Per contra			प्रतिकूल रीति से
Per se			स्वयमेव
Perusal			श्रवलोकन
Petition			याचिका
Plan			योजना
Planning		To the same of	नियोजन
Plebiscite			जनमत ग्रहण
Poll			मतदान
Portfolio		Section States	ग्रामात्य-कार्य विभाग
D 4	•		पद, तैनात करना
Post Predecessor		•••	पुर्वाधिकारी
	•••	•••	विशिष्ट ग्रिधिकार
Prerogative	• •	• •	निर्धारित
Prescribed	iana		
Press Commun	ique	• (•	प्रेस विज्ञप्ति
Prima facie	• •	•••	प्रत्यक्षतः
Priority		• •	प्राथम्य
Privilege		• •	विशेषाधिकार
Probation	••	••	परीक्षणकाल
Procedure			प्रिक्रया

Proceeding Proclamation Prohibited Promotion Promulgated Pro rata Prorogue Provident Provident fund Provision Provisional Purport		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	कार्यवाही उद्घोषणा निषिद्ध पदोन्नति प्रख्यापित प्रमुपाततः सत्रावसान पूर्वोपायी पूर्वोपायी निधि उपबन्ध, व्यवस्था ग्रस्थायी, ग्रन्तरकालीन
Qualification			श्रर्हता, योग्यता
Qualified			ग्रहताप्राप्त, योग्यताप्राप्त
Quarterly			त्रैमासिक
Quarantine			निरोधा, संसर्गरोध
Quasi			ग्रधं
Quorum			कार्यवाहक संख्या, गण-पूर्ति संख्या
Quota			श्रभ्यंश
Quotation		• •	उद्धरण
		R	
Ratification			सत्यापन
Rationalization			ग्रभिनवीकरण
Reaction			प्रतिक्रिया
Reappointment			पुर्नानयुक्ति हुन् ।
Reappropriation			पुनः पर्यादान, पुनर्विनियोजन
Rebate			छ,ट
Recently	• •		प्रत्यग्र, ग्रभी हाल में
Recess	• •	• •	मध्यावकाश
Recognition	··-	•	मान्यता
Record	• •	• •	ग्रभिलेख ग्रावर्तक
Recurring	• •	••	श्रावर्तक स्रावर्तक व्यय
Recurring charge	S	- 1 To 10	विमोचन
Redemption	••	17.50	प्रत्यार्पण
Refund	• •		पंजी
Register			नैयमिक
Regular	••	and the same	विनियम
Regulation			फिर से रखना, पुनः नियुक्त करना, बहाल करना
Reinstate	•	THE PARTY	ग्रस्वीकार कीजिये
Reject	• •		प्रत्युत्तर, प्रतिवादी
Rejoinder		1 15 15 FM	

Remarks			श्रभ्युवित
Remedy			उपचार
Reminder			ग्रनुस्मारक
Remission	•		छ्ट, परिहार
Remittance			विप्रेषण
Remuneration			पारिश्रमिक
Repeal			विखंडन करना
Repetition			पुनरुक्ति
Report			प्रतिवेदन
Rescind			श्रपखंडन करना
Respectively	THE WAR		क्रमात, यथाक्रम, क्रमशः
Resumption			पुनरारम्भ
Retirement			सेवा निवृत्ति
Return			विवरण-पत्र, विवरणी
Reversion			प्रत्यावर्तन
Review	• •		पुनरवलोकन, पर्यवलोकन, पुनर्विलोकन
Revision	• •		पुनरीक्षण 💮
Revocation			खण्डन
Roll			पंजी, भ्रावलि
Roll, character			चरित्र पंजी, श्राचरणावलि
Ruling	• •	• •	व्यवस्थान, व्यवस्था .
Rumour			जनरव, जन प्रवाद
		S	

Sanction			स्वीकृत कीजिये	, सम्मोदन
Schedule			श्रनुसूची	
Scrutiny			परिनिरीक्षण	
Secretary			सचिव	
Section			धारा, श्रनुभाग	10.0
Secular			धर्म निरपेक्ष	34 50
Sender			प्रेषक	
Senior			ज्येष्ठ	
Session			सत्र	
Sir	_ • •		श्रीमन्	4.
Sir, Dear	•••	•••	त्रिय महोदय	
Sitting	•••	••	बैठक	
Slip	• •	an separate	पर्ची	2020
Specific	••	1000	विशिष्ट	
Specified	• •	•	निर्दिष्ट	
Staff		••		
Statutory	• •			ग्रमला
Status quo	• •	The state of the s	वैधानिकी	
Stipend	••		यथास्थित	
	•	T. Plant	छात्र वेतन	
Style			पद्धति	
Style of writing			लेखन-पद्धति	

Regulation Remetate Reject Rejeinder

0-11:			
Subordinate	• •		श्रधीनस्थ
Subsidy			राज सहायता
Substantially			तत्वतः •
Substantive			स्वनिष्ठ, मौलिक
Suffrage			मताधिकार
Summons	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		श्राह्वान
Superior			वरिष्ठ
Supersession			ग्रतिक्रमण, ग्रवक्रम
Supreme			सर्वोच्च
Supreme Comman	nd		सर्वोच्च समादेश
Supreme Court			उच्चतम न्यायालय
Surety			प्रतिभू .
Suspend			निलम्बन करना
			ारान्यम परमा
		T	
Tag			नत्थी करना
Technical	• •		प्रविधिक, पारिभाषिक
Technique			प्रविधि
Temporary			श्रस्थायी
Tenant	••		श्रसामी, काश्तकार
Tender			निविदा-पत्र
Tender advice			परामर्श देना
Term			श्रवधि, शर्त
Testimonial			प्रमाण-पत्र
Timely			सामयिक, श्रनुकाल
Title			श्रागम, शीर्षनाम
Township	• •		उप-नगर
Training		,,	प्रशिक्षण
Transport			परिवहन
Treat		,.	व्यवहार करना; उपचार करना
Treat Urgent	.,		शोघ्र कार्यवाही कीजिये
Trend			प्रवृति
Treatment			उपचार
Transaction			व्यवहार, लेन-देन
Trespass			श्रतिक्रमण
Tribunal			न्यायाधिकरण
True copy			प्रमाणित प्रतिलिपि
Typist			टंकक
TJP150			
		U	
			-Server name
Unanimous	••	•	सर्वसम्मत, एकमत
Unauthorized	• •	• •	ग्रनधिकृत
Unclaimed	• •	• •	ग्रस्वामिक
Under considerati	on		विचाराधीन
Under investigation	on	• •	विचारणाधीन, ग्रनुसंधानाधीन

Unit			एकक
Unlawful			ग्रवैध
Unpaid			ग्रवैतनिक
Untenable			ग्रमान्य
Uphold			पुष्टि करना
Up-to-date			ग्रद्यावधि, ग्रद्यतन, ग्रद्यावधिक
Urgent			भ्रावश्यक
0-8		v	
Vacancy			रिक्ति, रिक्त स्थान
Vacant			रिक्त
Valid			न्यायोचित, वैध
Valuation			मूल्यांकन
Verbal			मौिखक
Verbatim			शब्दशः, पदानुपद
Verification			प्रमाणीकरण
V.I.P.(very imp	ortant pers	sonages)	विशिष्ट जन
Vested			विहित
Vigilance			प्रतिजागर
Vocation			व्यवसाय
Void			निरर्थक, निष्फल, विफल
Volume			बंड
Voluntary			ऐच्छिक
Voted			मतदेय
Voted Expendi	ture		मतदेय व्यय
Voucher			साधनपत्र, प्रमाणक
		W	
Wages			भृत्ति, मजदूरी
Wage Living			निर्वाह मजदूरी
Warrant			ग्रधिपत्र
Welfare			कल्याण, हितकारी
Wholetime			पूर्णकाल
Will			दित्सापत्र, रिक्थ-पत्र
Withdrawal			निवर्तन
Witness			साक्षी
Worker			कर्मकर
Workshop			कर्मशाला
Writ			ग्राज्ञा-पत्र, लेख
Wrongful			श्रन्याय्य, सदोव

परिशिष्ट ह

(ग्रन्तरकालीन)

Attached to

कार्यालय के प्रयोग के लिये वाक्यांश

A

Above mentioned ... उपर्यक्त Abstract statement of cases निर्वातत (व्यवहृत) प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण disposed of. Acknowledge receipt प्राप्ति स्वीकार कीजिये Action as at 'A' above 'क' पर प्रस्तावित कार्य करिये Action—departmental वैभागिक कार्यवाही Adjourned sine die ग्रदिन स्थगित प्रशासनीय अनुमोदन प्राप्त किया जाय Administrative approval may be obtained. Administrative functions प्रशासनीय कृत्य (सं०) All concerned to note सभी सम्बन्धित व्यक्ति इसे ध्यान में रक्खें Allotment of funds धनदिष्टि Appear for interview समक्ष-भेट (साक्षात्कार) के लिये उपस्थित होइये Application may be rejected म्रावेदन-पत्र म्रस्वीकार किया जाय Approved as proposed प्रस्ताव ग्रनमोदित 'क' में उल्लिखित ग्रापत्तियों को छोडकर Approved subject to the शेव ग्रनमोदित । observations at 'A' ग्राज्ञानसार संशोधित ज्ञापन प्रस्तृत किया A revised memorandum is put up as desired. जाता है। ग्रवशिष्ट कार्य-विवरण Arrears statement जैसा कि ऊपर दिया है As above यथा निदेशित As directed यथाशीघ्र As early as possible As far as possible ... यथासम्भव जहां तक व्यवहार्य हो, यथाव्यवहाय As far as practicable यथा ग्रावश्यक As may be necessary यथा परिष्कृत As modifiedके सम्बन्ध में As regards यथा ग्रपेक्षित As required यथा पुनरोक्षित As revised यथास्थिति, यथावस्था, यथाप्रसंग As the case may be जैसा कि प्रकरण की ग्रवस्था विशेष में ग्रपेक्षित As the circumstances of the case may require. ग्रन्तकालीन प्रबन्ध के लिये उस स्थान पर नियक्त A substitute may be appointed as an interim arrange-की जाय। ment. सदा की भांति As usual येन केन प्रकारेण, किसी भी दशा में At any rate से संलग्न

Attention is invited to Circular nodated At the instance of the A.G Await	परिपत्र सं ० दिनांक की श्रोर ध्यान श्राकित किया जाता है। महालेखापाल के श्रनुरोध से प्रतीक्षा की जिए श्रोर टीका की प्रतीक्षा की जिये श्रीर प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जिए उत्तर की प्रतीक्षा की जिए
В	
Better accept the proposal Break in service By order of the Governor By return of post By virtue of office	बेहतर है कि इस प्रस्ताव को मान लिया जाय सेवा-कम भंग राज्यपाल के स्रादेशानुसार लौटती डाक से पदेन
C	
(To) Call for recommendations.	सिकारिशें मांगना
Case is closed now Case is to be reviewed	प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही ग्रय समाप्त हो गई है प्रकरण पर फिर विचार करना है प्रकरण का पुनरवलोकन होना है
Channel of correspondence Character and antecedent of a Government servant.	पत्र-व्यवहार का मार्ग सरकारी कर्मचारियों का चरित्र ग्रौर पूर्ववृत्त
Circulate and then deposit Circulate and then file Communication, means of Confidential record	कर्मचारियों को दिखाकर यह जमा किया जाय कर्मचारियों को दिखाकर इसे नत्थी किया जाय संचारताथन (सं०) गोपनीय ग्रभिलेख
Consultation with F. D. is necessary.	वित्त विभाग से परामर्श ग्रावश्यक है
Contempt of Court (The) Contention is untenable Context, particular Copy applied for Copy enclosed for ready reference.	न्यायालय ग्रवमान (सं०) तर्क ग्रसमर्थनीय है प्रसंग विशेष ग्रावेदित प्रति, मांगी गई प्रति तत्काल निर्देश के लिये प्रति संलग्न
Copy forwarded to	को प्रति भेजी गई
Copy with a spare copy forwarded to the Collector for information.	प्रति एक ग्रतिरिक्त प्रति के साथ कलेक्टर को सूचन्हार्थ प्रेषित ।
Correspondence resting with your D. O. letter no	त्र्रापके ग्रर्धशासकीय पत्र सं

D

Day-to-day administrative दैनिक प्रशासनीय कार्य work. Delay is regretted विलम्ब के लिये खेद है Departmental action वैभागिक कार्यवाही Deposited in record room ग्रभिलेख कक्ष में जमा किया गया Deputation to foreign service ... वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति Despatch परिप्रेषित कीजिए Discrepancy in accounts लेखा विभेट Discrepancy to be reconciled ... विभेदों का समाधान किया जाय Discuss विमर्श की जिए Dismissed बरल्वास्त किया गया, पदच्युत Draft as amended यथासंशोधित आलेख्य Draft for approval स्वीकृत्यर्थ ग्रालेख्य, ग्रनुमोदनार्थ ग्रालेख्य Draft reply as suggested above जैसा कि ऊपर बतायाँ गया है, उत्तर का श्रालेख्य तैयार कीजिए। During the pendency of the मकदमें के विचाराधीन की ग्रविध में case. F Early orders are solicited शीघ्र ग्रादेशों की प्रार्थना की जाती है Efficiency of administration प्रशासन कार्यक्षमता, प्रशासन कार्यपट्ता (सं०) Efficient successful and सुचार एवं सफल कार्य-संचालन के लिये working. Enquiry to be completed and जांच पूरी की जाये श्रीर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया report submitted. (To) Examine the proposals "क" में व्यक्त विचारों को दृष्टिकोण में रखते in the light of observations हए प्रस्तावों की परीक्षा कीजिए। at 'A'. Exclusive jurisdiction ग्रनन्य क्षेत्राधिकार (सं०) Executive power ... कार्यपालिका शक्ति (सं०) Ex officio पदेन Ex parte statement एक पक्षीय बयान Explained in your memoran-ग्रापके ज्ञापन में स्पष्ट किया गया dum. Explanation be called for स्पष्टीकरण मांगा जाय Explanation should be obtained स्पष्टीकरण मांगा जाय Ex post facto sanction कार्योत्तर स्वीकृति Expressly enjoined प्रत्यक्ष विहित Extra-curricular activities पाठयेतर कार्य उद्धरण लिया जाना चाहिये Extract should be taken राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन (सं०) Extra-territorial operations

F	
Failing which serious action	न करने पर कठोर कार्यवाही की जायगी
will be taken.	
Fair copy	स्वच्छ प्रति
File	नत्थी कीजिए, पत्रावली
Financial irregularities	वित्तीय ग्रनियमितताए
For approval	श्रनुमोदन के लिये, स्वीकृत्यर्थ
For comments	ग्रालोचनार्थ
For communication to all	सम्बन्धित व्यक्तियों के सूचनार्थ
concerned.	
For compliance	ग्रनुपालनार्थ
For consideration	विचारार्थ
For disposal	निस्तारण के लिये
For enquiry and report	जांच ग्रौर प्रतिवेदन के लिये
For an expression of opinion	मत की ग्रभिव्यक्ति के लिये
For guidance	पथ-प्रदर्शनार्थ
For information and necessary	सूचनार्थ तथा ग्रावश्यक कार्यवाही के लिये
action.	
For the purpose in question	प्रश्नास्पद प्रयोजन के लिये
For perusal and return	ग्रवलोकन करने ग्रौर लौटाने के लिये
For ready reference	तत्काल निर्देश के लिये
For such action as may be	ऐसी कार्यवाही के लिये जो भ्रावश्यक प्रतीत हो
considered necessary.	
For suggestions	सुझावों के लिये
Forwarded for consideration	विचारार्थं प्रेषित
Forwarded for orders	ग्रादेशार्थ प्रेषित
Forwarded for compliance	तत्काल ग्रनुपालनार्थं प्रेषित
Functions administrative	प्रशासनीय कृत्य (सं०)
Further orders will follow	ग्रागे ग्रीर ग्रादेश भेजे जायंगे
G	2 * C
Government desire that	सरकार चाहती है कि
Government consider it desira-	सरकार वांछनीय समझती है कि
ble that.	1 C
Government are of the opinion	सरकार का मत है कि
that.	
Governor is pleased to direct	राज्यपाल निदेश देते हैं
Governor is pleased to sanction	राज्यपाल स्वीकृति देते हैं
H	
Held in abeyance	श्रास्यगित रक्खी गई
Herewith enclosed	इसके साथ संलग्न है
I	
I am directed to	मस्रे निदेश है कि
I am desired to	निवेदन है कि
It is submitted	मुझे निदेश है कि निवेदन है कि निवेदन है कि
I have the honour	सादर
I have the hone at the	

Immediate action	
In accordance with orders	तत्काल कार्यवाही
In an existing vacancy	ग्रादेशों के श्रनुसार
In case of doubt	विद्यमान रिक्त स्थान में
In certain cases	संश्यात्मक दशा में
Incidentally it may be	कतिपय ग्रवस्थाग्रों में
Incidentally it may be observed In compliance with your	प्रसंगवश यह भी कहा जा सकता है कि
memorandum no.	अप्रापके ज्ञापन सं का अनुपालन करते हुए
In consequence of	
Inconsistent with orders	परिणामस्वरूप
In continuation of my letter	श्रादेशों से ग्रसंगत
In continuation of my letter Incumbent of an office	मेरे पत्र के क्रम में
In due form	पदधारी
In favour of	विधिवत्
	के पक्ष में
In inviting your attention to	की स्रोर स्रापका ध्यान स्राष्ट्रब्ट करते हुए
In partial modification of In preference to	का ग्राशिक संशोधन करते हुए
In persuance of	की श्रपेक्षा
In response to	क् अनुसार
Instructions are awaited	्के उत्तर में
In supersession of	श्रनुदेश की प्रतीक्षा है
In support of	का श्रतिक्रमण करके
In these circumstances it is	के समर्थन में
requested that.	इन परिस्थितियों में यह प्रार्थना की जाती है कि
In the course of time	
	कालात
In the interest of public service.	लोकसेवा के हित में
In the light of the facts	उक्त तथ्यों के म्राधार पर
mentioned above.	
	मूलरूप में
In this connexion I have to	इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि
state that.	
In this manner	एतद्, इस प्रकार ठीक है
Is in order	
Is referred to	को निर्दिष्ट है
Issue as modified	यथापरिष्कृत पत्र जारी कीजिए
Issue immediate reminder	तत्काल ग्रनुस्मारक भेजिए
Issue of this is authorized	इसका निर्ममन ग्रिधिकृत है
It has since been decided that	तब से यह निश्चित किया गया है कि
It will be appreciated if	बड़ी कृपा होगी यदि बड़ा उपकार होगा यदि
J	No. of the last of
Joined duty	कार्यभार ग्रहण किया
Judgment in appeal	श्रपील का निर्णय
Justification for the proposal	इस प्रस्ताव का ग्रोचित्य
addition for the brokens	

685		
Keep pending Keep with the file	विचाराधीनं रक्खा जाय इसे पत्रावली में रिखये	
Last pay certificate Let Appointment Department be consulted.	ग्रन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र नियुक्ति विभाग से परामर्श करें	
M		
Maintenance of discipline (To) Make interim arrange-	श्चनुशासन बनाये रखना श्रंतर्कालीन प्रबन्ध करना	
ments. (To) Make reference to	इस विषय में सरकार को लिखिये	
Government on this point. Marginally noted Matter may be referred to	प्रार्श्व लिखित, उपांत लिखित यह विषय संचालक को भेजा जाय	
Matter is under consideration May be considered May the Department be	विषय विचाराधीन है विचार किया जाय विभाग को तदनुसार सूचना दो जाय	
informed accordingly. May I know when orders in the reference may be expected. Memorandum under reference Mentioned above	क्रुयया बतलाइये कि पत्र पर श्रादेश कब तक प्राप्त हो सकेंगे । निर्देशित ज्ञापन उपर्युक्त	
N		
No action necessary. File Null and void	कोई कार्यवाही स्रावश्यक नहीं है । नत्थी कीजिए । व्यर्थ स्रौर विफल, प्रवृत्तिहीन	
Olisations have been dealt	्रत्रापत्तियों पर विचार कर लिया गया है। ************************************	
Objections have been dealt with.		
Observations made above Obtain formal sanction Office submits Office proposes Office regrets	ऊपर कही गई बातें ग्रौपचारिक/रोतिक स्वीकृति प्राप्त कीजिए कार्यालय निवेदन करता है कार्यालय का प्रस्ताव है कार्यालय खेद प्रकट करता है, कार्यालय की दु:ख है।	
Office suggests Office to note carefully	कार्यालय का सुझाव है कार्यालय इसे सावधानी से देखें	

इसके विपरीत

प्रत्युत

On the contrary ... On the other hand

On relief by . . . द्वारा पद मुक्त किये जाने पर Orders passed म्रादेश दिये गये । P Personal attention is required वैयक्तिक ध्यान की ग्रावश्यकता है Please discuss कृपया विमर्श कीजिए Please give early attention to... ...को सर्व प्राथम्य दोजिए Please put up previous papers कृपया पूर्व पत्रों को प्रस्तुत कीजिए Please refer to letter no. कृत्या पत्र सं. . . देखिये Please take a special note of ... कृपया इस पर विशेष ध्यान दीजिए Please treat it as most urgent ... कृपया इसे ग्रत्यन्त ग्रावश्यक समझिए Practically experienced प्रयोग निपुण Preference, in order of ग्रधिमानकम Provision shall apply mutatis ...उपबन्ध यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा mutandis. Published for general informa-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए ग्रविस्चित tion. Purporting to be done कर्त्मभिप्रेत (सं०) R Receipt—acknowledge प्राप्ति स्वीकार कीजिए पहले दी जा चकी मान्यता वापस ले ली जायभी Recognition already granted will be withdrawn. Reimbursement of medical चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति charges. ग्रस्वीकृत कीजिए Rejected Remarks--adverse ... प्रतिकल अभ्युक्तियां Removed from office कार्यच्यत Reply not yet received उत्तर ग्रभी तक प्राप्त नहीं हुग्रा पञ्चात् दर्शी प्रभाव, श्रनुदर्शी प्रभाव Retrospective effect यथोचित रूप से पृष्ठांकित करके लौटाया Returned duly endorsed नियामक नियंत्रण Rule making control (A) Ruling from Govern-भारत सरकार से व्यवस्था प्राप्त कीजिए ment of India should be obtained. S स्वीकृत कीजिए Sanction Sanctioned as proposed यथाप्रस्तावित स्वीकृत Sanction is hereby accorded एतदद्वारा स्वीकृति दी जाती है देख लिया । नत्थी कीजिए। Seen. File

Self-contained note Self-contained note is put up So far as practicable Speak Subject matter Subject to the approval of Submitted for information Submitted for orders Submitted for approval Submitted for perusal Submitted with reference to the orders on the previous page. T	स्वतः पूर्णं टिप्पणी स्वतः पूर्णं टिप्पणी प्रस्तुत है यथासाध्य इस सम्बन्ध में बात करें वाद-विधय, ग्रिभियेय स्वीकृत उपाश्रित सूचनार्थं प्रस्तुत ग्राज्ञार्थं प्रस्तुत ग्राज्ञार्थं प्रस्तुत, ग्रनुमोदनार्थं प्रस्तुत ग्रवलोकनार्थं प्रस्तुत पूर्व पृष्ठ पर ग्रादेश के ग्रनुसार प्रस्तुत किया
Temperate and courteous language.	संयत ग्रौर विनीत भाषा
Tentative proposal	परीक्षणार्थ प्रस्ताव, ग्रनुभूत्यर्थ प्रस्ताव, काम- चलाऊ प्रस्ताव।
Territorial jurisdiction The undersigned is directed The question at issue There is no reason to interfere. There is no cause to modify the orders already passed. U	प्रावेशिक क्षेत्राधिकार (सं०) प्रधोहस्ताक्षरी को यह निदेश है कि विवादवस्तु, विवाद विषय हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। जो स्राज्ञा दी जा चुकी है उसमें संशोधन करने का कोई कारण नहीं है।
Under intimation to this office Under paragraph	इस कार्यालय को सूचना देते हुए परिच्छेद के श्रधीन श्रविलम्ब श्रपेक्षित
Vested interest Voted expenditure	निहिताधिकार मतदेय व्यय
Weeding list With reference to your letter Y	निर्दान सूची ग्रापके पत्र के उत्तर में, ग्राप के पत्र के सम्बन्ध में
Yours faithfully	भवदीय, भवन्निष्ठ सद्भावी।

परिशिष्ट १० हिन्दी निर्देश पुस्तकों

(क) कोष

पुस्तक का नाम लेखक प्रकाशक १--संविधान की पारि-भारत सरकार मद्रणालय, भाषिक शब्दावली। नई दिल्ली। २--दि कन्सालिडेटेड ग्रेट डा० रघबीर इंटरनेशनल एकेडमी इंग्लिश इंडियन श्राफ इंडियन कल्चर. डिक्शनरी ग्राफ नागपूर। टेक्नीकल टर्म्स (खंड १, २)। ३--शासन शब्दकोष महापंडित राहल सांकृतायन हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद। ४--म्रांग्ल-हिन्दी पर्याय श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव, विशेष शब्दकोष । कार्याधिकारी, भाषा विभाग, उतर प्रदेश शासन। ५--दि ट्वैन्टियेथ सेंच्री श्री भंडारी इंग्लिश-हिन्दी डिक्शनरी (भाग १-५)। ६--ग्रारक्षिक शब्दावली श्री रामचन्द्र वर्मा तथा नागरी प्रचारिणी सभा, श्री गोपालचन्द्र सिंह वाराणसी। ७--स्थानिक परिषद् शब्दावली। प--प्रामाणिक हिन्दी कोव श्री राम चन्द्र वर्मा ६--वृहत् हिन्दी कोष ज्ञान मंडल, काशी १०--संक्षिप्त हिन्दी शब्द नागरी प्रचारिणी सभा, काशी। सागर। ११--दि स्टूडेन्ट्स इंग्लिश-संस्कृत डिक्शनरी। वामन शिवराम ग्राप्टे मोनियर विलियम्स १२--संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी।

पुस्तक का नाम

लेखक

प्रकाशक

(ख) विविध

१३---हिन्दी निर्देशिका

उत्तर प्रदेश सरकार।

१४ -- ग्रंग्रेजी वाक्यांशों के हिन्दी पर्याय

१५---ग्रच्छी हिन्दी

रामचन्द्र वर्मा

१६---हिन्दी बजट साहित्य तथा हिन्दी गजट की भी प्रतियां देखी जानी चाहिये। इनके ग्रध्ययन से वित्त तथा प्रशासन सम्बन्धी ग्रनेक शब्दों का ज्ञान हो जायेगा।

१७---हिन्दी में प्रकाशित शासकीय रिपोर्ट भी हिन्दी का ज्ञान बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होंगी।

१८--राजकीय शब्दकोष

श्री गोपालचन्द्र सिंह

नागरी प्रचारिणी सभा,

वाराणसी।

१६---शासन शब्दकोष

श्री हरिहर द्विवेदी

२०---व्यावहारिक शब्दकोष

श्री रामनाथ शर्मा

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

